राष्ट्रीय संस्करण CopyRight - Jagran.com

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 147

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, मंगलवार, 5 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

एनबीए अकादमी के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं हरसिमरन

>> 14

लोग मर रहे हैं और सरकारें नाकाम हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम टिप्पणी ▶ लोगों को मरने के लिए छोड़ देना सभ्य समाज की पहचान नहीं, प्रदूषण से घटी उम्र, यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन

अब कहीं पराली जली तो सचिव से लेकर प्रधान तक होंगे जिम्मेदार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोगों की उम्र घट रही है, लोग मर रहे हैं और सरकारें नाकाम हैं। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, यह जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। किसी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता। सोमवार को दिल्ली और एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण के हाल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की। इसी के साथ कोर्ट ने पराली और कूड़ा जलाने पर तत्काल रोक का आदेश देते हुए कहा कि ऐसी एक भी घटना को अदालत के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। कोर्ट ने युद्ध स्तर पर प्रदूषण रोकने के उपाय लागू करने का आदेश देते हुए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को बुधवार को तलब किया है। इस बीच, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने भी पंजाब और हरियाणा को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की हिदायत दी है। कचरा जलाने के मामलों पर रोक नहीं लगा पाने पर दिल्ली सरकार को भी पीएमओ ने फटकारा है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की पीठ ने वायु प्रदूषण रोकने में नाकाम रही केंद्र व राज्य की सरकारों तथा नगर निगमों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली घुट रही है। दिल्ली में लोग घरों में भी प्रदूषण से सुरक्षित नहीं हैं। घर के अंदर एक्यूआइ 500-600 से ऊपर पहुंच गया है। हर साल यही होता है। इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकारें व नगर निगम अपनी ड्यूटी में नाकाम हैं। एक अक्टूबर से तीन नवंबर तक की सेटेलाइट इमेज देखने से पता चलता है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर पराली जली है। विशेषतौर पर चार जिलों तरनतारन, संगरुर, पटियाला और फिरोजपुर में। हरियाणा में हालात इससे थोड़ा बेहतर रहे हैं। वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण से लोगों की उम्र घट रही है। यह जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वह दिल्ली न आएं। लोगों को काम करना है, दिल्ली खाली नहीं की जा सकती।

आप इसे एयर इमरजेंसी क्यों कहते हैं? यह इमरजेंसी से भी बुरा है। इमरजेंसी के दिनों के हालात इससे बेहतर थे।

- जस्टिस अरुण मिश्रा

ऑड-इवेन का उद्देश्य व फायदा बताएं

सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-इवेन योजना पर दिल्ली सरकार से कहा है कि वह शुक्रवार तक रिपोर्ट दाखिल करे कि इस योजना का क्या उद्देश्य है और इससे क्या फायदा हुआ। सरकार पिछली बार की तुलना करते हुए रिपोर्ट दे। यह भी बताए कि ऑड-इवेन से लोग तिपहिया ऑटो और टैक्सी का प्रयोग बढ़ा देते हैं, ऐसे में ये वाहन ज्यादा संख्या में सड़क पर आ जाते हैं तो फिर योजना का उद्देश्य कैसे पूरा होता है। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी में ऑटो और टैक्सी में ईंधन के तौर पर सीएनजी का इस्तेमाल होता है, जो स्वच्छ ईंधन है।

तय करनी होगी जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार के उल्लंघन को देखते हुए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। किसी भी किसान को इस आधार पर पराली (फसल अवशेष) जलाने का अधिकार नहीं है कि उसके पास अगली फसल के लिए कम वक्त है। ऐसे किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है, जो दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। जहां पराली जलती है, उसके पड़ोसी राज्य भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में स्टेट मशीनरी से ग्राम पंचायत स्तर तक सभी की जवाबदेही बनती है। यह दुष्कृति (टार्ट) का अपराध है, जो दंडनीय है।

अदालत के निर्देश

- आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई मालवाहक डीजल वाहन दिल्ली में न घुसे
- दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और ढहाने पर एक लाख का जुर्माना। अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार
- दिल्ली-एनसीआर में कूड़ा जलाने पर 5000 का जुर्माना। खुले में कूड़ा नहीं डाला जाएगा
- दिल्ली-एनसीआर में बिजली कटौती नहीं हो, ताकि जनरेटर का इस्तेमाल न करना पड़े। अगले आदेश तक जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक
- जाम से बचाने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा, सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा
- कोर्ट के फैसले का टीवी मीडिया, थाना, तालुका और तहसील स्तर पर व्यापक प्रचार हो
- दिल्ली व अन्य राज्य तीन हफ्ते में बताएं कि ऐसी स्थिति से बचने के कौन से उपाय किए जाएं

हालात थोड़ा सुधरे, राहत का इंतजार

नई दिल्ली-2नवंबर को दोपहर 1 बजकर 35 मिनट पर लिए गए चित्र में रायसीना हिल पर प्रदूषण के कारण लुप्त रहा राजपथ व इंडिया गेट का एक नजारा। ध्रुव कुमार

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अब भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली में सोमवार को प्रदूषण के स्तर में रविवार की तुलना में कमी आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 416 दर्ज हुआ, जो रविवार को 494 था। अगले दो दिनों में दिल्ली में तेज हवा से हालात में और सुधार की उम्मीद है। हरियाणा और पंजाब में भी प्रदूषण में कमी आई है। (पेज-2, 5 भी देखें)

पराली जलने पर लगे पूरी रोक : कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्यों के मुख्य सचिव, डीएम, तहसीलदार, संबंधित थाना और पूरी पुलिस व प्रशासनिक मशीनरी सुनिश्चित करे कि उनके यहां पराली न जले। एक भी घटना हुई तो सब जिम्मेदार माने जाएंगे। पराली जलने से हो रहा प्रदूषण टार्ट के तहत अपराध है। ऐसे में पंजाब, हरियाणा और उप्र के मुख्य सचिव बताएंगे कि इसे रोकने में नाकाम रहने पर क्यों न राज्यों से हर्जाना वसूला जाए। कोर्ट ने कहा, सभी ग्राम प्रधान और थाने सूची तैयार करेंगे कि कहां-कहां किस-किस ने पराली जलाई। तीनों राज्य और दिल्ली सरकार स्थिति को काबू करने के लिए तत्काल कदम उठाए। दिल्ली सरकार और विभिन्न नगर निगम तत्काल प्रभाव से बिना देरी के कचरा प्रबंधन के इंतजाम करें। कोर्ट के आदेश पर पर्यावरण मंत्रालय की संयुक्त सचिव, ईपीसीए के अध्यक्ष भूरेलाल और आइआइटी के प्रोफेसर पीठ के समक्ष हाजिर हुए और उन्होंने प्रदूषण से निपटने के उपाय बताए।

सरोकार

पटियाला की संध्या की जिंदगी में नया सवेरा

पटियाला : ट्रक यूनियन के पास झोपड़-पट्टी में रहने वाले बच्चे आर्थिक तंगी के कारण भीख मांगने को मजबूर हैं। इस बस्ती में सवेरा लेकर आई है संध्या। सड़कों पर भीख मांगना छोड़ दसवीं तक पढ़ाई की अब इंजीनियर बनने की तैयारी कर रही है। (पेज-11)

जागरण विशेष

समझ लूं, फिर समझाऊंगा इस दोस्ती का फलसफा...

नई दिल्ली : 81 वर्षीय रतन टाटा और 27 वर्षीय शांतनु नायडु की जुगल जोड़ी सोशल मीडिया पर छा रही है। रतन टाटा के ऑफिस में उप महाप्रबंधक शांतनु उनके सबसे चहेते सहयोगी और सलाहकार हैं। कम दिलचस्प नहीं इनकी दोस्ती का किस्सा। (पेज-11)

सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन को भी तैयार भाजपा

नई दिल्ली : महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए संवैधानिक रूप से सिर्फ चार दिन का वक्त बाकी है लेकिन सियासी अनिश्चितता के चलते तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। भाजपा अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दबाव में आने को तैयार नहीं है। भाजपा की ओर से साफ कर दिया गया है कि भाजपा शिवसेना की उचित मांगों को मानने के लिए तैयार है लेकिन शिवसेना को भी यह स्वीकार करना होगा कि बड़ी पार्टी भाजपा है। खासकर तब जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार की ओर से बार-बार बोला जा रहा है कि उन्हें तो विपक्ष में बैठने का जनमत मिला है। संकेत है कि अगले चार दिनों में स्थिति बदलेगी और राजग सरकार का गठन होगा वरना भाजपा राष्ट्रपति शासन के लिए भी तैयार है। (पेज-4)

आरसेप को भारत की ना

नहीं बनी बात ▶ भारत के बगैर आगे बढ़ेंगे 15 देश, समझौता अगले वर्ष

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

दुनिया के सबसे मजबूत ट्रेड ब्लॉक के तौर पर उभर रहे आरसेप में भारत ने शामिल होने से इन्कार कर दिया है। बैंकॉक में सोमवार को आरसेप वार्ता के लिए 16 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने दो-टूक कह दिया कि मौजूदा वैश्विक हालात व समझौते के प्रारूप में उसके हितों व मुद्दों को पूरा स्थान नहीं दिए जाने की वजह से भारत इसमें शामिल नहीं होगा। अब एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 15 बड़े देश आरसेप यानी रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम से गठित होने वाले मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाएंगे।

बैठक में मोदी ने कहा, भारत आरसेप में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ना तो गांधी के सिद्धांत और ना ही मेरा जमीर इसमें शामिल होने की इजाजत दे रहे हैं। पीएम ने उन देशों को लताड़ भी लगाई जो भारत पर इस समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश में हैं। उन्होंने यह बताने में कोई गुरेज नहीं किया कि अब वे दिन नहीं है जब बड़ी शक्तियां भारत पर वैश्विक सौदेबाजी का दबाव बनाने में सफल हो जाती थीं। माना जा रहा है कि सस्ते आयात से अपने उद्योग धंधों को बचाने के प्रति समझौते में खास प्रावधान नहीं होने की वजह से ही भारत ने इससे बाहर रहने का फैसला किया है।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने बताया कि पीएम ने स्पष्ट किया कि हम गांधी जी के इस सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं कि जब भी इस तरह का कोई फैसला करना हो तो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को होने वाले फायदे या नुकसान पर सोचना चाहिए। यह समझौता भारत के गरीब तबके पर विपरीत असर छोड़ सकता है।

आरसेप के शीर्ष नेताओं की तरफ से जारी बयान में कहा गया है भारत की तरफ से कुछ अहम मुद्दे हैं जिनका समाधान नहीं निकल पाया है। आरसेप के सदस्य इन मुद्दों को सुलझाने के लिए बात करेंगे ताकि सभी पक्षों की सहमति के मुताबिक आगे का रास्ता निकल सके। भारत की तरफ से तो इस तरह से बताया गया है कि आरसेप के लिए उसने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। सचिव (पूर्व) सिंह ने कुछ ऐसा ही इशारा किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया व थाइलैंड के नेताओं ने कहा, भारत के लिए इस समझौते में शामिल होने का रास्ता खुला रहेगा। बहरहाल, आरसेप के सदस्य शेष 15 देश अगले वर्ष इसे लागू करने से संबंधित समझौता करेंगे। (पेज-3 भी देखें)

बैंकाक में सोमवार को आरसेप के इतर ईस्ट एशिया समिट के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद (बाएं) के पास से निकलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मौके पर चीनी प्रधानमंत्री ली कछ्यांग भी मौजूद रहे। हाल ही में मलेशिया ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया था। एएफपी

उद्योग जगत ने की तारीफ

नई दिल्ली : आरसेप पर भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले की उद्योग जगत और किसान संगठनों ने जमकर तारीफ की है। दुग्ध उत्पाद कंपनी अमूल ने सरकार के इस निर्णय को मील का पत्थर बताया है। सीआइआइ और फिक्की ने कहा कि हम भारत सरकार के हर उस समझौते के साथ खड़े हैं, जिसमें द्विपक्षीय हितों को ध्यान में रखा गया है। (पेज-12)

प्रधानमंत्री बोले

- गांधीजी के सिद्धांत और मेरा जमीर आरसेप में शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे
- वो दिन गए जब वैश्विक समझौतों के लिए भारत पर रहता था बड़ी शक्तियों का दबाव

ये होंगे आरसेप में

चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, विएतनाम, थाइलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर व कंबोडिया

यह होगा असर

- चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों को बड़ी चोट लगेगी, क्योंकि उनकी नजर भारत के विशाल घरेलू बाजार पर थी
- भारत की लुक-ईस्ट नीति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आसियान के 10 सदस्य आरसेप के चलते ही पिछले कुछ वर्षों से भारत के प्रति ज्यादा उदारता दिखा रहे थे

इसलिए बाहर रहने का फैसला

- आम भारतीयों के जीवन और उसके जीवनयापन के साधनों पर इस समझौते से पड़ने वाले असर को देखते हुए लिया गया
- आरसेप का मौजूदा मसौदा पत्र इसके मूलभूत सिद्धांतों के मुताबिक नही, भारत कुछ बुनियादी मुद्दों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता
- कारोबारी घाटे में कटौती करना और भारतीय सेवाओं व निवेश के लिए समान मौका मिलना भारत की इन दोनों प्रमुख मांगों पर सदस्यों ने गंभीरता नहीं दिखाई

कश्मीर में ग्रेनेड हमले में एक की मौत, 38 घायल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कश्मीर में सामान्य होते हालात से हताश आतंकियों ने सोमवार को श्रीनगर में खुली दुकानों को बंद कराने के लिए हरि सिंह हाईस्ट्रीट में ग्रेनेड हमला किया। इसमें खिलौने बेचने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, सीमा सशस्त्र बल (एसएसबी) के तीन जवानों समेत 38 लोग जख्मी हो गए। घायलों में से चार की हालत गंभीर बनी हुई है।

दोपहर करीब 1:25 बजे लाल चौक से 200 मीटर की दूरी पर अमीराकदल पुल के पार हरि सिंह हाईस्ट्रीट में लोगों की भारी भीड़ थी। गनीखान बाजार में जाने वाले रास्ते के बाहरी छोर पर रेहड़ी वाले सामान बेच रहे थे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग खरीदारी में जुटे थे। भीड़ में ही मौजूद आतंकी ने एक बंद दुकान के शटर के पास खड़े एसएसबी जवानों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका, जो रेहड़ी वालों के पास गिरा और जोरदार धमाके के साथ फट गया। विस्फोट की आवाज सुन क आसपास मौजूद पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के जवान मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूत्रों ने बताया, 38 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया। 10 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि 27 अस्पताल में भर्ती हैं।

सुरक्षाबलों ने शहर के कई क्षेत्र खंगाले पेज>>6

कर्मचारियों के लिए न्यूनतम नौ घंटे काम का प्रस्ताव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आपातकालीन स्थितियों में एक दिन में करना पड़ सकता है 16 घंटे तक काम
- वेतन संहिता कानून, 2019 के नियम बनाने को सरकार ने मांगे सुझाव

न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम नौ घंटे काम करना पड़ सकता है। वेतन संहिता कानून के लिए बनाए जा रहे नियमों से पहले श्रम मंत्रालय की ओर से इस बाबत सुझाव मांगे गए हैं। एक माह बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल केंद्र में कर्मियों के लिए सप्ताह में 42 घंटे का नियम है।

वेतन संहिता कानून अगस्त में संसद से पास हो चुका है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, वेतन संहिता, 2019 की धारा 13 (उपधारा 1, उपबंध ए) के तहत कर्मियों को न्यूनतम 9 घंटे काम करना होगा। आपात स्थितियों में एक दिन में 16 घंटे तक काम करना पड़ सकता है।

न्यूनतम वेतन का निर्धारण पत्नी, दो बच्चों वाले परिवार के पालन पोषण, प्रति व्यक्ति रोजाना 2700 कैलोरी वाले भोजन व 66 मीटर कपड़े की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। वेतन का 10 फीसद खर्च खाने-कपड़े, 20 फीसद ईंधन, बिजली, अन्य खर्चों, 25 फीसद बच्चों की पढ़ाई, इलाज, मनोरंजन तथा आपातकालीन मदों पर माना जाएगा। वेतन का निर्धारण महानगरीय, गैर-महानगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती के आधार पर होगा।

महंगाई भत्ते की गणना 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले : महंगाई भत्ते की गणना हर वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले की जाएगी। वेतन से किसी कटौती के बारे में कर्मचारी को पहले सूचित करना होगा। कटौती के बाद इंस्पेक्टर-सह-फैसिलिटेटर को 10 दिन के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। कर्मचारी को प्रदत्त अग्रिम धन की वसूली किस्तों में की जाएगी जो वेतन के पचास फीसद से ज्यादा नहीं होगी।

हफ्ते में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश जरूरी : कर्मी को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी होगा। असामान्य स्थिति में दस दिन बाद ये अवकाश देय होगा। साप्ताहिक अवकाश का दिन रविवार के अतिरिक्त होने पर वेतन की गणना ओवरटाइम की दर से होगी।

111 कार्य उच्च कौशलयुक्त, 320 कौशलयुक्त : वेतन संहिता में 111 कार्यों को उच्च कौशलयुक्त, 320 को कौशलयुक्त में शुमार किया गया है। 127 कार्यों को अर्द्ध-कुशल, 123 को अकुशल कर्मियों लायक माना गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी के लिए कोई निजता ही नहीं बची

- छत्तीसगढ़ में आइपीएस अधिकारी के फोन टेपिंग पर शीर्ष अदालत का सख्त रुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता और उनके परिजनों के फोन टेप कराने की छत्तीसगढ़ सरकार की कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, 'किसी के लिए भी निजता नहीं बची है।'

जस्टिस अरुण मिश्र और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कड़े लहजे में कहा, 'इस तरह से करने की क्या जरूरत है? किसी के लिए कोई निजता बची ही नहीं है। इस देश में आखिर क्या हो रहा है? क्या किसी व्यक्ति की निजता का इस तरह हनन किया जा सकता है? किसने और किस कारण से यह आदेश दिया? विस्तृत हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी जाये।' शीर्ष अदालत ने आइपीएस अधिकारी के वकील के खिलाफ अलग से एफआइआर दर्ज जाने किए जाने पर भी नाराजगी जताई और जांच पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

पीठ ने मुकेश गुप्ता के अधिवक्ता महेश जेठमलानी से कहा, इस मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम घसीट कर इसे सियासी रंग नहीं दिया जाये। अदालत ने याचिका से बघेल का नाम हटाने को कहा।

गुप्ता 2015 में नागरिक आपूर्ति घोटाले की जांच के दौरान गैरकानूनी तरीके से फोन टेपिंग और भारतीय टेलीग्राफ कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोपित हैं। शीर्ष अदालत ने 25 अक्टूबर को राज्य सरकार को गुप्ता और उनके परिजनों के फोन सुनने या टेप करने से रोक दिया था और गुप्ता को उसके खिलाफ दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। हालांकि, अदालत ने गुप्ता के खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी रद करने से इन्कार कर दिया।

हाईकोर्ट में साबित नहीं हुआ था-किसने बनवाई थी मस्जिद

नई दिल्ली : जिस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद पर सारे देश की निगाहें हैं, उसे किसने बनवाया था यह बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में साफ नहीं हो पाई थी। मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था या औरंगजेब ने यह साबित नहीं हुआ था। फैसला देने वाले हाईकोर्ट के तीन जज भी इस मुद्दे पर एक मत नहीं थे। (पेज-7)

मैक्डोनाल्ड्स के सीईओ ईस्टरब्रुक बर्खास्त

न्यूयॉर्क : अमेरिका की दिग्गज फास्ट फूड चेन मैक्डोनाल्ड्स ने एक कर्मचारी से शारीरिक संबंधों के आरोप में सीईओ स्टीव ईस्टरब्रुक को निकाल दिया है। कंपनी ने इसे अपनी नीतियों का उल्लंघन माना है। ईस्टरब्रुक का कहना है कि संबंध आपसी सहमति से बनाए गए थे। अब मैक्डोनाल्ड्स यूएसए के प्रेसिडेंट क्रिस केंपकिंस्की कंपनी के सीईओ होंगे। (पेज-12)

बदलाव

कल आइपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लाया जा सकता है प्रस्ताव, बीसीसीआइ के अध्यक्ष गांगुली लेंगे अंतिम फैसला

पावरप्लेयर से बदल सकती है आइपीएल की सूरत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) दुनिया की सबसे सफल क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) में बड़े बदलाव की योजना बना रहा है। बोर्ड बुधवार को मुंबई में होने वाली आइपीएल गवर्निंग कांउसिल की बैठक में लीग के अगले संस्करण में 'पावर प्लेयर' का नियम लाने का प्रस्ताव पेश कर सकता है, जिस पर बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली अंतिम फैसला लेंगे। इस नियम के तहत टीमें मैच में कभी भी विकेट गिरने या ओवर खत्म होने के बाद एक खिलाड़ी को बदल सकती हैं।

पता चला है कि आइपीएल संचालन टीम के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने कुछ माह पहले पारंपरिक अंतिम-11 के साथ कुछ करने के इरादे से एक नोट तैयार किया था। इस नोट के अनुसार, पावर प्लेयर की अवधारणा का उपयोग किया जा सकता है। यह अवधारणा अंतिम-11 का हिस्सा नहीं रहने वाले ऐसे खिलाड़ी को ओवर के बाद या विकेट गिरने के बाद आने वाले खिलाड़ी या गेंदबाज की जगह बदलने की स्वीकृति देती है।

प्रतीकात्मक फोटो

बीसीसीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इस पर अंतिम फैसला बीसीसीआइ अध्यक्ष करेंगे। वह आइपीएल चेयरमैन बृजेश पटेल और अन्य पदाधिकारियों से इस पर चर्चा करेंगे। इसे लेकर कई कारकों को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है।' हालांकि, गांगुली के एक करीबी सूत्र ने कहा कि इस प्रस्ताव पर संदेह है क्योंकि यह क्रिकेट के मूल व्याकरण को बदल सकता है। अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। आइपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सदस्य इस प्रस्ताव के अलावा 2019 आइपीएल की समीक्षा करेंगे। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि आगामी सत्र को और लोकप्रिय कैसे बनाया जाए।

ये है पावर प्लेयर का प्रस्ताव

- बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि हम ऐसी स्थिति पर विचार कर रहे हैं जहां टीमें अंतिम-11 की बजाय 15 खिलाड़ियों को डग आउट में बैठाएं
- इस प्रस्ताव की अहम बात यह है कि मैच के दौरान विकेट गिरने के बाद या ओवर खत्म होने के बाद कोई भी टीम प्रत्येक पारी में एक खिलाड़ी को बदलकर मैदान में उतार सकती है
- अधिकारी ने कहा कि सोचिए कि किसी टीम को छह गेंदों पर 20 रन चाहिए और आंद्रे रसेल अंतिम-11 में नहीं हैं लेकिन वह अंतिम-15 में हैं क्योंकि वह पूरी तरह से फिट नहीं थे। इस नियम से वह ऐसी स्थिति में मैदान पर आ सकते हैं और बड़ा शॉट लगाकर मैच बदल सकते हैं
- इसी तरह किसी टीम को आखिरी ओवर में अगर छह रन बचाने हैं और उसके पास जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी डगआउट में बैठे हैं। ऐसे में कोई कप्तान क्या करेगा? वह बुमराह को 19वां ओवर खत्म होने के बाद लेकर आएगा और फिर आप जानते ही हैं। इस नियम में मैच को बदलने का दम है

देशभर में इंडिगो का सर्वर ठप, एयरपोर्ट पर लगी लंबी कतारें

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोमवार सुबह विमानन कंपनी इंडिगो का सर्वर डाउन होने से बड़ी संख्या में हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से यात्रियों को बोर्डिंग पास नहीं दिए जा सके, जिसके चलते देश भर के एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें देखने को मिलीं। कंपनी ने स्वयं देशभर में सर्वर ठप होने की जानकारी दी और लोगों से सहयोग की अपील की। बता दें कि देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो का घरेलू बाजार में 48.2 फीसद हिस्सा है।

दिन में करीब दो बजे कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया, 'सोमवार सुबह एक घंटे से कम के लिए देशभर के एयरपोर्ट पर सर्वर डाउन की समस्या आई। यात्रियों को इससे होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। फिलहाल हमारी सभी उड़ानें और चेक-इन सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहे हैं।' इससे पहले 11.30 बजे के आसपास कंपनी ने कहा था कि सभी एयरपोर्ट पर सर्वर डाउन हैं। इसके चलते उड़ानें प्रभावित होने की आशंका है। गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

तेलंगाना में महिला तहसीलदार को दफ्तर में जिंदा जलाया

हैदराबाद, प्रेट्र : तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुरमेट गांव में महिला तहसीलदार विजया रेड्डी (30) को दफ्तर के अंदर जिंदा जला दिया गया। सोमवार दोपहर बाद हुई इस घटना में महिला अधिकारी को बचाने में ड्राइवर समेत दो कर्मचारी झुलस गए। घटना को अंजाम देने वाला हमलावर भी 50-60 फीसद झुलस गया है। तीनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक हमलावर का भूमि विवाद से संबंधित मामला था, जिसे लेकर उसने तहसीलदार से संपर्क किया था, लेकिन निपटारा नहीं होने से वह खफा था।

संभागीय राजस्व अधिकारी अमरेंदर कुमार ने बताया कि स्थानीय युवक के. सुरेश ने इस घटना को सोमवार दोपहर बाद 1.30 बजे अंजाम दिया। घटना के समय महिला अधिकारी अपने चैंबर में अकेली थीं। मोटर साइकिल से कार्यालय आने के बाद हमलावर सीधे अधिकारी के कमरे में गया और उनके ऊपर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी।

तहसीलदार विजया रेड्डी की फाइल फोटो। प्रेट्र

बचाने में दो कर्मचारी भी झुलसे, एक गंभीर, हमलावर भी बुरी तरह जला

रचाकोंडा के पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत ने बताया कि महिला अधिकारी के चिल्लाने पर उनका सहायक और ड्राइवर चैंबर की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक लपटों में घिरी विजया चैंबर से बाहर आकर जमीन पर गिर पड़ीं। दोनों कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर घटना को अंजाम देकर कार्यालय से भागा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर गिर पड़ा। उन्होंने कहा, हमलावर ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा।

चैंबर से सुनाई दी तेज आवाज पेज>>5

40 फीसद महिला यात्रियों ने (कुल यात्रियों की तुलना में) बसों में सफर किया ऑड-इवेन के पहले दिन। सोमवार शाम चार बजे तक डीटीसी की बसों में 8,27138 यात्रियों ने सफर किया। इनमें से 3,35751 महिलाएं थीं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 5 नवंबर 2019

पहले दिन सफल रहा ऑड-इवेन, घटा प्रदूषण

प्रदूषण से जंग ▶ 15 लाख कारें सड़कों पर नहीं उतरीं, कहीं नहीं लगा जाम, दिनभर में कटे महज 192 चालान

सिसोदिया और गहलोत ने योजना को सफल बनाने पर दिल्ली की जनता को दी बधाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

ऑड-इवेन पहले दिन सफल रहा। दिल्ली के लोगों ने पूरा साथ दिया। सुबह से ही लोगों ने नियमों का पालन किया। कहीं जाम नहीं लगा। दोपहर तक महज 192 चालान कटे। दिल्ली सरकार का दावा है कि सोमवार को प्रदूषण कम हुआ है, जिसमें ऑड-इवेन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि 15 लाख कारें दिल्ली की सड़कों पर नहीं उतरीं। ऑड-इवेन को सफल बनाने के लिए पांच हजार वालंटियर और चार सौ टीमें लगाई गई हैं। डीटीसी और क्लस्टर की मिलाकर 5500 बसें सड़कों पर हैं। इसके अलावा 650 अतिरिक्त बसें भी उतारी गई हैं। दिल्ली सरकार ने दो हजार बसों की मांग की थी, लेकिन 650 बसें ही मिल सकी हैं। बसों का रजिस्ट्रेशन अभी जारी है।

14 नवंबर तक चलने वाले ऑड-इवेन के पहले दिन की स्थिति के बारे में दिल्ली सचिवालय में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी दी। उन्होंने योजना को सफल बनाने पर दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण कल के मुकाबले बेहद कम हुआ है। इसमें ऑड-इवेन का भी योगदान है। पूरे उत्तर भारत में इस समय स्मॉग की गहरी चादर छाई है। दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण था और दम घुट रहा था। लोगों ने ऑड-इवेन से प्रदूषण को जवाब दिया है। एक जनवरी 2016 व उसके बाद दूसरे ऑड-इवेन में भी लोगों ने पूरा सहयोग दिया था। आज तीसरा ऑड-इवेन का पहला दिन था और सभी जगह स्थिति सामान्य मिली। अधिकारियों को सकारात्मक रुख रखने का निर्देश दिया गया था। सोमवार को 192 चालान कटे। यातायात पुलिस ने 170, परिवहन विभाग ने 15, एसडीएम व अन्य ने सात चालान काटे।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 30 लाख गाड़ियां चलती हैं, जिनमें से 15 लाख सड़कों पर नहीं उतरीं। 100-200 चालान कोई बड़ी बात नहीं है। प्रदूषण पर इसका भी एक असर है। हालांकि प्रदूषण बढ़ने और घटने के कई कारण हैं, लेकिन सोमवार को हवा सुधरी है। रविवार से बहुत बेहतर हुई है। रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 1000-1200 से लेकर 1600 तक था। औसत 800 था। सोमवार सुबह एक्यूआइ सुबह छह बजे 562, दोपहर दो बजे 152 और शाम चार बजे 93 रहा। आज काफी फर्क पड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट की पहल का स्वागत : मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। हमसे जो आंकड़ा मांगा गया है, वह देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाकी राज्यों के मुख्य सचिव को जैसे तलब किया है, वह बेहतर है। हम चार-पांच राज्य मिलकर रास्ता निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम शुक्रगुजार हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से उस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं।

सोमवार को शाम 4:30 बजे रायसीना हिल से राजपथ और इंडिया गेट का नजारा। इसमें इंडिया गेट भी दिखाई दे रहा है। ध्रुव कुमार

ओला-उबर ने बढ़ाया सरचार्ज कैब मिलने में हुई परेशानी

जासं, नई दिल्ली : ऑड-इवेन के पहले दिन ओला व उबर द्वारा सरचार्ज बढ़ाने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अधिक किराया चुकाना पड़ा। वहीं, बुक किए जाने के बाद भी टैक्सियां मिलने में परेशानी हुई। इसकी बानगी सोमवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली। यहां कोई एप से कैब बुक करने की कोशिश कर रहा था तो कोई ऑटो चालक से अधिक पैसे नहीं लेने की बात कह रहा था। रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सियों के लिए इंतजार कर रहे लोगों ने बताया कि पहले के मुकाबले अब घर तक पहुंचने के लिए 50 से 100 रुपये अधिक लग रहे हैं। जहां पहले 12 किलोमीटर की दूरी तक के लिए 150 रुपये लगते थे, वहीं अब 200 रुपये तक किराया लिया जा रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही कैब बुक करनी शुरू कर दी थी, फिर भी कैब नहीं मिल पा रही है। ओला व उबर की कैब मिलने में हो रही परेशानी के कारण ऑटो व काली-पीली टैक्सी वालों ने मनमाना किराया वसूला।

हवा चलने से एयर इंडेक्स गिरा

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज हुई है। सोमवार को प्रदूषण के स्तर में रविवार की तुलना में कमी आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार सोमवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 494 दर्ज हुआ। मौसम वैज्ञानिकों ने संकेत दिए हैं कि अगले दो दिनों में दिल्ली में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी तो प्रदूषण के स्तर में और भी गिरावट आएगी। हालांकि दिल्ली में सोमवार के दिन हवा चलने के बाद भी खतरनाक श्रेणी में प्रदूषण का स्तर बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। मंगलवार को भी प्रदूषण के स्तर में कमी आने की उम्मीद है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी से गिरकर खराब श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने बताया कि इसके बाद सात नवंबर को दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा।

दिल्ली-एनसीआर का एयर इंडेक्स

जगह	3 नवंबर	4 नवंबर
दिल्ली	494	407
फरीदाबाद	496	403
गाजियाबाद	491	440
गुरुग्राम	486	370
नोएडा	430	498
ग्रेटर नोएडा	495	430

शुक्रवार तक जारी रहेगा स्वास्थ्य आपातकाल

जासं, नई दिल्ली : पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) की तरफ से ग्रैप (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान) के तहत एक नवंबर को लगाए गए सभी तरह के प्रतिबंधों को शुक्रवार आठ नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत दिल्ली व एनसीआर में हॉट मिक्स प्लांट पर भी प्रतिबंध की मियाद को बढ़ा दिया है। इसके अलावा कोयले और जैव ईंधन के साथ ही उन सभी उद्योगों को बंद रखने का फैसला किया गया है जो प्राकृतिक गैस के बजाय किसी प्रदूषणकारी ईंधन से चलाए जा रहे हैं। ईपीसीए के अध्यक्ष भूरेलाल ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के नेतृत्व में प्रदूषण पर निगरानी कर रही टास्क फोर्स के साथ बैठक हुई। इसमें प्रदूषण के हालात की समीक्षा की गई है। इसमें पाया कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में सभी तरह के प्रतिबंधों को आठ नवंबर तक जारी रखना जरूरी है। दो और तीन नवंबर को हुई बारिश ने दिल्ली के वातावरण में नमी को भी प्रदूषक कणों के साथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमें स्थानीय स्तर के प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

ये प्रतिबंध रहेंगे लागू

- हॉट मिक्स प्लांट व स्टोन क्रशर (पत्थर तोड़ने वाले संयंत्र) एनसीआर के सभी जिलों में आठ नवंबर तक बंद रहेंगे।
- कोयले और ईंधन से चलने वाले सभी उद्योग फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़ और भिवाड़ी में शुक्रवार तक बंद रहेंगे।
- इसके अलावा सर्दियों पूरे मौसम में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

केजरीवाल बोले, दिल्ली के लोग मिलकर प्रदूषण को हराएंगे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि ऑड-इवेन पर बहुत अच्छा समर्थन मिला है। दिल्ली की जनता ने इसका अच्छे से पालन किया है। हम लोगों ने मिलकर ढाई माह में डेंगू को हराया है। मुझे भरोसा है कि दिल्ली के लोग मिलकर प्रदूषण को भी हराएंगे।

उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर भारत में इस समय धुंध की गहरी चादर छाई हुई है। गहरा प्रदूषण भी है। हम लोग दिल्ली में प्रदूषण को लेकर काफी चिंतित हैं। हम हरसंभव कदम उठा रहे हैं। बाहर से पराली का जो धुंआ दिल्ली आ रहा है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली के अपने प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम मास्क बांट रहे हैं। वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड-इवेन शुरू किया है। पूरी दिल्ली में इसका पालन हो रहा है। दिल्ली में 30 लाख कारें हैं। सोमवार को 15 लाख कारें सड़कों पर नहीं उतरीं, जिससे प्रदूषण पर असर पड़ा है। दिल्ली के लोगों ने ऑड-इवेन का जबरदस्त समर्थन किया है।

केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर विज्ञापन पर खर्च करने की बात पर राजनीति कर रहे हैं। वह झूठ फैला रहे हैं। दिल्ली के विज्ञापन का बजट ही 150 से 200 करोड़ है। अभी भी पैसा काफी पड़ा है। हमने विज्ञापन का पैसा डेंगू के खिलाफ अभियान पर खर्च किया। क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या लोगों को मरने देना चाहिए था? डेंगू का दिल्ली का अभियान अनूठा है। हम लोगों ने 10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट अभियान से डेंगू पर काबू पाया। दिल्ली के लोगों के प्रयास के कारण दिल्ली में डेंगू कम हुआ, जबकि दुनिया में डेंगू के मामले बढ़े हैं। सिर्फ दिल्ली में कम हुए हैं। इसके लिए प्रकाश जावडेकर को दिल्ली के लोगों की तारीफ करनी चाहिए न कि उनके इतने बड़े प्रयास को कमजोर करना चाहिए।

मथुरा रोड स्थित निवास से साईकिल से दिल्ली सचिवालय जाते मनीष सिसोदिया। जागरण

ओला, उबर, टैक्सी और ऑटो चालक न बढ़ाएं किराया : मुख्यमंत्री

ओला, उबर, टैक्सी और ऑटो चालकों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आग्रह किया है कि वे किराया न बढ़ाएं और न ही ओवरचार्जिंग करें। ऐसा करने पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऑड-इवेन में 30 लाख में से 15 लाख वाहन सड़क पर नहीं उतरेंगे तो प्रदूषण कम होगा ही। जब सारी दिल्ली ऑड-इवेन का समर्थन व पालन कर रही है, ऐसे में भाजपा विरोध कर रही है, यह ठीक नहीं है। दिल्ली के लोग प्रयास कर रहे हैं और भाजपा विरोध कर रही है। यह ठीक नहीं है। दिल्ली के लोगों के प्रयास का साथ देना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ट्रैफिक पुलिस से अपील करता हूं कि वह ऑड-इवेन का पालन कराएं व लोगों को सहयोग करें। जरूरत महसूस हुई तो उपराज्यपाल से बात भी करूंगा।

योजना पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने केजरीवाल सरकार के ऑड-इवेन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि अगर प्रदूषण को कम करने में ऑड-इवेन इतनी ही सफल योजना है तो इसमें इतनी कैटेगरी क्यों बनाई गईं? सरकार ने ऑड-इवेन उस समय क्यों नहीं लागू किया जब प्रदूषण बहुत अधिक था? करोड़ों रुपये खर्च करके केजरीवाल सरकार ने 50 लाख मास्क बांटने की घोषणा की थी, लेकिन जब स्कूल ही बंद कर दिए गए हैं तो मास्क कहां गए? सरकार ये मास्क झुग्गी-झोपड़ियों, अनधिकृत कॉलोनियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को क्यों नहीं दे रही है?

उन्होंने कहा कि ऑड-इवेन योजना में बहुत खामियां हैं, जिससे साबित होता है कि केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण दूर करने के लिए पांच साल तक कुछ नहीं किया। ऑड-इवेन के बहाने अपने काम को छिपाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली सरकार को पहले परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं है।

नियम का विरोध करने उतरे गोयल, कटा चार हजार का चालान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

ऑड-इवेन के पहले ही दिन इस पर जमकर सियासत हुई। भाजपा नेता विजय गोयल ने ऑड नंबर की गाड़ी सड़क पर उतारकर योजना का विरोध किया तो दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गोयल के आवास पर पहुंचकर ऑड-इवेन पर उनका समर्थन मांगा। इस पर गोयल ने उनसे प्रदूषण को लेकर कई सवाल किए। दोनों के बीच 15-20 मिनट की बातचीत हुई।

राज्यसभा सदस्य विजय गोयल ने रविवार को घोषणा कर दी थी कि ऑड-इवेन का विरोध करेंगे। तय कार्यक्रम के तहत गोयल इवेन वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ी लेकर चल दिए। कार पर ऑड-इवेन के विरोध में नारे लिखे हुए थे। गोयल के साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश व प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना मौजूद रहे। घर से करीब 200 मीटर आगे बढ़ने पर जनपथ रोड पर गोयल को यातायात पुलिसकर्मियों ने ऑड-इवेन का उल्लंघन करने पर रोक लिया। राजीव कुमार (हेड कांस्टेबल, यातायात पुलिस) ने गोयल ने लाइसेंस मांगा। इसके बाद चार हजार रुपये का चालान किया गया। गोयल ने कोर्ट चालान करने के लिए कहा। इस पर गोयल का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर चालान काट दिया गया।

विजय गोयल का चालान कटने के बाद उनके घर से फोन आया कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत घर पर पहुंच गए हैं। इस पर विजय गोयल भी घर लौटे। गहलोत ने उन्हें गुलदस्ता देकर प्रदूषण के खिलाफ जंग में सहयोग मांगा। गोयल ने सवाल दागते हुए कहा कि ऑड-इवेन लागू करने से पहले दिल्ली के सांसदों से बातचीत क्यों नहीं की गई? गहलोत ने कहा कि ऑड-इवेन से दिल्ली के प्रदूषण में कमी आएगी। इसलिए उन्हें भी सहयोग करना चाहिए। गोयल लगातार सवालों दागते रहे। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों, ओला-उबर और टैक्सी को इस नियम से बाहर किया गया है। फिर इससे कितना फायदा होगा? इस पर गहलोत ने कहा कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषण पर दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठा सकती है। ऑड-इवेन के माध्यम से दिल्ली के प्रदूषण में कमी आएगी।

ऑड-ईवन के दौरान जनपथ पर अपनी कार का चालान कटवाते विजय गोयल। जागरण

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पूछे ये सवाल

- यदि प्रदूषण पराली से है तो ऑड-इवेन का क्या फायदा?
- 90 फीसद प्रदूषण के स्थानीय कारण हैं, दिल्ली सरकार ने काम क्यों नहीं किया?
- स्मॉग टॉवर-वैक्यूम क्लीनर क्यो नहीं लाए?
- पांच हजार बसें क्यों नहीं आईं?
- दोपहिया 25 फीसद प्रदूषण फैलाते हैं, ओला, उबर, टैक्सी और महिला ड्राइवर, बस ई-रिक्शा सबको छूट तो ऑड-इवेन किसलिए?
- 1300 करोड़ रुपये पर्यावरण सेस की राशि का उपयोग प्रदूषण को खत्म करने के लिए क्यों नहीं किया?

कार पूल कर ऑफिस गए सीएम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

राजधानी में सोमवार से ऑड-इवेन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कार पूल करके और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साइकिल से दिल्ली सचिवालय स्थित अपने ऑफिस पहुंचे। दोनों ने दिल्लीवासियों से इस मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस स्थित अपने आवास से कार पूल करके अपने दफ्तर के लिए निकले। उनके साथ मंत्री गोपाल राय और सत्येंद्र जैन भी थे। केजरीवाल ने सुबह लोगों से ऑड-इवेन का पालन करने की अपील भी की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'नमस्ते दिल्ली! प्रदूषण कम करने के लिए आज से ऑड-इवेन शुरू हो रहा है। अपने लिए अपने बच्चों की सेहत के लिए और अपने परिवार की सांसों के लिए ऑड-इवेन का जरूर पालन करें। कार शेयर करें। इससे दोस्ती बढ़ेगी, रिश्ते बनेंगे, पेट्रोल बचेगा और प्रदूषण भी कम होगा।' उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली के लोग ऑड-इवेन का समर्थन कर रहे हैं। एक-दो ही चालान हो रहे हैं।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि पराली जलने से काफी प्रदूषण हो रहा है। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगले 10 दिन तक इसका पालन जरूर कर सकते हैं। यह सबके फायदे के लिए है। उन्होंने कहा कि ऑड-इवेन स्कीम में दिल्ली सरकार के मंत्रियों को छूट नहीं दी गई है। हम अधिकतर लोगों से इस मुहिम में समर्थन देने की अपील कर रहे हैं।

वहीं, परिवहन व राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत अपने ओएसडी (राजस्व) आरके सैनी के साथ कार पूल कर दफ्तर पहुंचे। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सचिवालय पहुंचने के लिए मेट्रो का सहारा लिया। खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन की कार का नंबर इवेन है इसलिए वह सोमवार को कार से ही दफ्तर पहुंचे।

वकीलों की हड़ताल में भी हुआ बवाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

तीस हजारी अदालत में शनिवार को पुलिस और वकीलों के बीच हुए बवाल के बाद सोमवार को सभी अदालतों में वकील हड़ताल पर रहे। हाई कोर्ट, तीस हजारी, कड़कड़डूमा और साकेत अदालत में हड़ताल का पूरा असर दिखा। राउज एवेन्यू और पटियाला हाउस में भी हड़ताल के चलते काम प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वकील बाजू पर सफेद बिल्ला पहनकर पहुंचे। हड़ताल के दौरान वकीलों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिसकर्मी और आम जनता से मारपीट की घटनाएं भी सामने आईं। वहीं, कवरेज को पहुंचे मीडिया कर्मियों से भी बदसुलूकी की गई। उनका कहना है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे हड़ताल पर रहेंगे।

राजधानी के वकीलों ने सोमवार को प्रदर्शन कर घटना पर रोष जताया। इस दौरान अलग-अलग अदालत परिसर व उसके बाहर बवाल भी हुआ। इसमें पुलिस कर्मियों से मारपीट, लोगों और मीडिया कर्मियों से बदसुलूकी की घटनाएं भी सामने आईं। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर दिनभर वायरल होते रहे। वकीलों की हड़ताल एक दिन के लिए तय थी, लेकिन अब वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का एलान कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले दिए एक आदेश में कहा था कि कोई भी बार एसोसिएशन एक दिन से ज्यादा हड़ताल नहीं कर सकती। इस फैसले का जिक्र पिछले दिनों हाई कोर्ट ने भी किया था।

> तीस हजारी कोर्ट में वकीलों पर फायर करने वाले पुलिस कर्मियों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, सभी जिला अदालतों में हड़ताल जारी रहेगी। सभी वकीलों से अपील है कि आंदोलन के दौरान वे शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखें।
> -महावीर शर्मा, अध्यक्ष कोआर्डिनेशन कमेटी

सोमवार को वकीलों की हड़ताल के दौरान मारपीट की कई घटनाएं सामने आईं। तीस हजारी में एक महिला पत्रकार का मोबाइल छीन लिया गया और अन्य मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की गई। साकेत कोर्ट के बाहर बाइक सवार एक पुलिस कर्मी से वकीलों ने मारपीट की। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। एक अन्य वीडियो में साकेत अदालत के बाहर एक ऑटो वाले को पीटते हुए वकील दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, ऑटो वाले के वीडियो बनाने पर वकीलों का गुस्सा उस पर उतरा। कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर के बाहर भी एक पुलिसकर्मी से मारपीट और महिला मीडियाकर्मी से बदसलूकी की घटना हुई। इसके अलावा एक बाइक सवार युवक को पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दोनों पुलिस अधिकारियों को हटाया गया

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

तीस हजारी मामला

तीस हजारी कोर्ट मामले में विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था (उत्तरी) संजय सिंह व उत्तरी जिले के एडिशनल डीसीपी हरेंद्र कुमार सिंह को पद से से हटा दिया गया। दोनों अगले आदेश तक कामकाज नहीं देखेंगे। विशेष आयुक्त कानून एवं व्यवस्था (दक्षिण) आरएस कृष्णैया को उत्तरी की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों अधिकारियों को हटाने की जानकारी पुलिस आयुक्त ने देर शाम दिल्ली हाई कोर्ट को दे दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने तीस हजारी बवाल मामले की जांच कर छह हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। इस बीच इन दोनों अधिकारियों को पद से हटाने का रविवार को आदेश दिया था। सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की लगातार बैठकें चलती रहीं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शनिवार को तीस हजारी में वकीलों पर लाठी चार्ज और चैंबरों में तोड़फोड़ की घटना विशेष आयुक्त संजय सिंह की अनुपस्थिति में हुई। ऐसे में संजय सिंह को इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा दिल्ली पुलिस आदेश पर पुनर्विचार के लिए हाई कोर्ट जाने पर विचार विमर्श कर रही है। आला अधिकारी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों व वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मिलकर अपनी बात रखने पर भी विचार कर रहे हैं, ताकि दोनों अधिकारियों को अदालत से कुछ राहत मिल सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की तेजी से जांच की जा रही है, जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मारपीट करने व कानून अपने हाथ में लेने के सुबूत मिलेंगे, उन्हें किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ बर्खास्तगी जैसी सख्त विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। इधर सोमवार को हड़ताल के दौरान मारपीट व आम जनों से मारपीट की घटनाओं के बाद जिला अदालतों की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। सभी अदालतों के बाहर पैरा मिलिट्री की तैनाती कर दी गई है। साकेत कोर्ट के बाहर बाइक सवार पुलिसकर्मी की एक वकील द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल होने पर यूनियन टेरिटरी कैडर के दिल्ली से बाहर तैनात आधा दर्जन से अधिक वरिष्ठ आइपीएस अफसरों ने ट्विटर पर घटना के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है।

> मुझे दुख है कि हम पुलिस हैं और हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी कोई फैमिली नहीं है। यही नहीं हम लोगों को मानवाधिकार का भी हक नहीं है।
> -मधुर वर्मा, पूर्व प्रवक्ता दिल्ली पुलिस का ट्वीट (वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में डीआइजी हैं)

पूर्व आइपीएस चतर सिंह पारचा आप में शामिल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : पूर्व आइपीएस एवं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चतर सिंह पारचा और सुंदर नगरी से सपा नेता रानी खान ने आप की सदस्यता ग्रहण की। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इन्हें टोपी और पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई।

राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि चतर सिंह पारचा 1977 बैच के आइपीएस अधिकारी रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा में इन्होंने अप्रतिम योगदान दिया। आइबी में 25 वर्षों तक वरिष्ठ पदों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश जैसे स्थानों पर कार्य करते हुए विशिष्ट सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक व राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किए गए। चतर सिंह पश्चिम बंगाल से पुलिस महानिदेशक के पद से 2008 में सेवानिवृत्त हुए। चतर सिंह ने कहा कि संत रविदास मंदिर के मुद्दे को भाजपा ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था।

दीक्षा समारोह

केंद्रीय मंत्री ने डीयू के 96 वर्षों के इतिहास की उपलब्धियों को किया रेखांकित, विश्वविद्यालय ने तीन लाख छात्रों को डिग्री जारी करके रचा इतिहास

डीयू राष्ट्र निर्माण की प्रमुख आधारशिलाओं में से एक : निशंक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 96वें दीक्षा समारोह में विश्वविद्यालय ने तीन लाख छात्रों को डिग्री जारी करके इतिहास रच दिया है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक व विशेष अतिथि के तौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. डीपी सिंह शामिल हुए।

निशंक ने कहा कि डीयू 96 वर्षों की उत्कृष्ट गौरवपूर्ण यात्रा के बाद वर्ष 2022 में स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। हमें विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान करने की एक लंबी यात्रा तय करनी है। इसके लिए डीयू को बधाई देता हूं। यह गर्व का विषय है कि डीयू समानता, न्याय और सामाजिक समन्वय के व्यापक वैचारिक ढांचे के भीतर विभिन्न शैक्षणिक अनुशासनों के तहत सात लाख से अधिक छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। देश-विदेश से छात्रों और शिक्षकों को आकर्षित करते हुए डीयू मन, वचन और कर्म से उत्कृष्टता, अखंडता और ग्रहणशीलता के प्रतीक के रूप में उभरा है। डीयू राष्ट्र निर्माण की प्रमुख आधारशिलाओं में से एक है और भारत में शिक्षा, बौद्धिक उन्नति और ज्ञान सृजन की मजबूत नींव के निर्माण में कार्यरत है।

डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी ने बताया कि डीयू के इतिहास में पहली बार एक साथ तीन लाख छात्रों को डिग्री प्रदान की गई है। पिछले वर्ष करीब दो लाख छात्रों की डिग्री जारी की गई थी। उन्होंने बताया कि समारोह में 700 छात्र मौजूद रहे, जिनमें 300 छात्रों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पदक एवं पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने बताया कि डीयू के करीब 50 हजार स्थायी छात्र एवं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) एवं नॉन कॉलेजिएट वूमेन एजुकेशन बोर्ड के कुल ढाई लाख छात्रों के लिए डिग्री जारी की गई।

प्रोफेसर योगेश त्यागी ने बताया कि डीडीए से दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी में आठ एकड़ जमीन मिली है। इसमें छात्राओं के लिए नया कॉलेज और छात्रावास विकसित किया जाएगा।

प्रोफेसर योगेश त्यागी ने बताया कि डीयू में वर्ष 2014 से 2019 के दौरान 11,603 शोध हुए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान 361 शोध प्रोजेक्ट संचालित हुए। इन पर कुल 272 करोड़ रुपये तक के फंड निर्धारित हैं। साथ ही डीयू को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं मान्यता (नैक) से ए प्लास ग्रेडिंग भी प्राप्त हुई है। कुलपति ने कहा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ डीयू ने 185 करोड़ रुपये के 12 करार किए हैं। इन करार के जरिये कई इमारतों का निर्माण किया जाएगा।

एक हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आए 20 हजार आवेदन : प्रोफेसर योगेश त्यागी बताया कि डीयू में खाली शिक्षकों के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इसमें एक हजार शिक्षकों के लिए 20 हजार आवेदन आए हैं। उन्होंने कहा कि जिन कॉलेज में प्राचार्य नियुक्ति नहीं हुए हैं और शिक्षकों की नियुक्ति भी होनी है, वे कॉलेज अपने यहां पर इनकी नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी करें। साथ ही डीयू में इस वर्ष तीन हजार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है।

डीयू के 96वें दीक्षा समारोह में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक छात्रा को डिग्री देते हुए। साथ में डीयू के कुलपति प्रो. योगेश कुमार त्यागी। जागरण

भाजपा सांसद हंस राज हंस के दफ्तर पर फायरिंग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- सांसद से मिलने के लिए आया था हमलावर, चलाईं तीन गोलियां
- एक गोली दरवाजे पर लगी, पुलिस ने की हमलावर की पहचान

उत्तर-पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र (सुरक्षित) से भाजपा सांसद और प्रसिद्ध सूफी गायक हंस राज हंस के रोहिणी स्थित दफ्तर पर सोमवार को एक शख्स ने फायरिंग कर दी और फरार हो गया। उसने तीन राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें दो हवाई फायरिंग की और एक गोली दफ्तर के दरवाजे में मारी। इससे दरवाजे के शीशे आदि टूट गए। फायरिंग से करीब 15 मिनट पूर्व ही सांसद सहयोगियों के साथ दफ्तर से बाहर निकले थे। पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है।

सांसद हंस राज हंस का रोहिणी सेक्टर-7 में दफ्तर है। बताया जाता है कि सांसद शाम पांच बजे तक अपने दफ्तर में मौजूद थे। इसके बाद वह किसी बैठक में शामिल होने के लिए निकल गए थे। उनके जाने के बाद करीब 50 साल का एक शख्स वहां पहुंचा। वह नशे में था। उसे दफ्तर में कोई नहीं मिला। दफ्तर का दरवाजा बंद था। उसे जब यह पता चला कि सांसद दफ्तर से निकल चुके हैं तो उसने हंगामा श

1.76 लाख रीजनल सर्विस प्रोवाइडर (आरएसपी) हैं रेलवे के देशभर में, जो लोगों को टिकट मुहैया कराते हैं। इनमें से कई गोरखधंधे में लगे हैं। फर्जी मेल आइडी के अलावा वह मिर्ची और एनएमएस जैसे साफ्टवेयर का भी प्रयोग करते हैं।

शांति व समृद्धि के लिए मिलकर काम करेंगे भारत और जापान

मजबूत रिश्ते ▸ प्रधानमंत्री मोदी ने की जापान के पीएम एबी शिंजो से मुलाकात

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर हुई चर्चा

बैंकाक, प्रेट्र : हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए भारत और जापान मिलकर काम करेंगे। क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो की मुलाकात में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा हालात की समीक्षा के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हुई।

आसियान देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने थाइलैंड की राजधानी बैंकाक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एबी शिंजो संग द्विपक्षीय बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की सेना के तेजी से पैर पसारने और बढ़ते आर्थिक दबदबे का मुद्दा बैठक के दौरान प्रमुखता से उठा। विदेश मंत्रालय ने बताया, 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति के साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अन्य देशों में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई।' मोदी और एबी ने स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की दिशा में काम करने का संकल्प ऐसे समय में लिया है, जब क्षेत्र की समुद्री सीमाओं में चीन के बढ़ते दखल को लेकर आसियान के कई सदस्य देशों के बीच चिंता बढ़ी है। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने इस महीने के अंत में भारत और जापान के विदेश तथा रक्षा मंत्रियों के बीच भारत में होने वाली 'टू प्लस टू' वार्ता के बारे में भी बात की।

बैंकाक में सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष शिंजो एबी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। एएनआइ

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, 'अपने मित्र प्रधानमंत्री एबी से मिलना हमेशा शानदार रहा है। आज हमारी मुलाकात बहुत अच्छी थी। हमने अपने देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने सहित कई विषयों पर विमर्श किया।' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया कि दोनों नेताओं ने भारत-जापान 'टू प्लस टू' वार्ता और वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आधार तैयार किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में अगले महीने होने वाले वार्षिक भारत-जापान शिखर सम्मेलन के लिए जापान के प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर वह उत्सुक हैं। मोदी ने भरोसा जताया कि आगामी शिखर सम्मेलन सफल होगा और इससे भारत व जापान के बीच विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी और गहरी होगी। पिछले चार महीनों में मोदी और एबी की यह तीसरी मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेता सितंबर में रूस के व्लादिवोस्तोक में मिले थे। बैठक में मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी हुई।

आतंकी समूहों के खिलाफ म्यांमार का सहयोग अहम : आसियान सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू की से भी मुलाकात की। मोदी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं को विस्तार देने की भारत की तैयारी की जानकारी दी। साथ ही भारत-म्यांमार सीमा पर सक्रिय आतंकी समूहों से निपटने की दिशा में म्यांमार के सहयोग की जरूरत पर भी जोर दिया।

अमेरिका-आसियान बैठक से नदारद रहे शीर्ष नेता : आसियान की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नहीं आने के बाद आसियान देशों के कई नेता सोमवार को अमेरिकी अधिकारियों संग हुई बैठक से दूर रहे। आसियान देशों से केवल थाइलैंड, वियतनाम और लाओस के प्रमुख और कुछ विदेश मंत्री ही बैठक में आए। अमेरिका की ओर से आसियान सम्मेलन में वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन शामिल हुए। इस रवैये के बाद अमेरिका पर दक्षिण एशियाई देशों की अनदेखी का भी आरोप लग रहा है। हालांकि ब्रायन ने इस बात का खंडन किया और कहा कि अमेरिका अपने दक्षिण एशियाई सहयोगियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आसियान 10 देशों का समूह है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल हैं।

आरसेप पर हस्ताक्षर नहीं करना मोदी के मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है : शाह

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि आरसेप समझौते पर भारत के हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और सभी परिस्थितियों में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। एक के बाद एक किए ट्वीट में शाह ने कहा कि इस फैसले से भारत के किसानों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र, डेयरी और विनिर्माण क्षेत्रों को सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा, 'आरसेप पर हस्ताक्षर न करने का भारत का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और सभी परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प का परिणाम है।'

गृह मंत्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्षों से यह कड़ा रुख रहा है कि अगर हमारे हितों का ध्यान नहीं रखा गया तो हम समझौता नहीं करेंगे और यह अतीत की तुलना में स्वागत योग्य कदम है जब कमजोर संप्रग सरकार व्यापार के मुद्दे पर झुक गई थी और राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकी।'

भाजपा का राहुल पर तंज : वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आरसेप के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार की आलोचना किए जाने पर पलटवार किया है। भाजपा ने ट्वीट किया, 'प्रिय राहुल गांधी, लगता है ध्यान यात्रा ने आपको आरसेप पर जगा दिया है।' भाजपा ने कहा, 'कुछ तथ्य दिए जा रहे हैं जो आपकी चयनात्मक भूलने की बीमारी में मदद करेंगे।' सत्तारूढ़ दल ने कहा कि यह कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार थी, जो 2012 में आरसेप वार्ता में शामिल हुई थी।

सज्जन कुमार की जमानत अर्जी पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

▸ सिख विरोधी दंगों में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई है सजा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर विचार करने के लिए सोमवार को तैयार हो गया। सज्जन कुमार ने शीर्ष अदालत से जमानत अर्जी को सुनवाई के लिए शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कुमार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुआई वाली पीठ ने सज्जन कुमार के वकील शेखर नफाड़े की उस दलील का संज्ञान लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा, हम इस पर गौर करेंगे। पूर्व कांग्रेस नेता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उनकी अपील लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत दी जाए। हाई कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद कुमार (73) ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वह फिलहाल जेल में हैं। सज्जन कुमार को 1984 में एक-दो नवंबर को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के राजनगर-एक में सिख समुदाय के पांच लोगों की हत्या और राजनगर-दो में एक गुरुद्वारे को जलाए जाने के मामले में दोषी ठहराया गया था।

सज्जन कुमार फाइल फोटो

पैरोल मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने विकास से कहा, सजा पूरी करो

नीतीश कटारा हत्याकांड

▸ शीर्ष अदालत ने चार हफ्ते की पैरोल मांगने वाली याचिका खारिज की

▸ 25 साल कैद की सजा काट रहा है बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा

नई दिल्ली, प्रेट्र : नीतीश कटारा हत्याकांड में 25 साल कैद की सजा काट रहे विकास यादव के पैरोल मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अपनी सजा पूरी करो। शीर्ष अदालत ने पैरोल देने से इन्कार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। नीतीश कटारा की 2002 में हत्या कर दी गई थी।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने चार सप्ताह का पैरोल मांगने वाली याचिका को खारिज करते हुए यादव से कहा, 'आपको 25 साल कैद की सजा सुनाई गई है, इसे पूरी करो।' इस बीच, पीठ ने यादव की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने बिना किसी राहत के 25 साल कैद की सजा सुनाने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी।

विकास यादव और उसके चचेरे भाई विशाल यादव को कटारा के अपहरण और हत्या के मामले में सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2002 में 16 और 17 फरवरी की रात अपहरण के बाद कटारा की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को विकास की बहन भारती से कटारा के कथित प्रेम संबंधों के चलते अंजाम दिया गया था जो अलग-अलग जाति से थे। इस हत्याकांड के तीसरे दोषी सुखदेव पहलवान को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। विकास यादव ने मामले में विभिन्न आधारों पर पैरोल मांगा था और कहा था कि मामले में वह पहले ही 17 साल से अधिक समय जेल में गुजार चुका है।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

अयोग्यता मामले में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड में ली जाए : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र : कर्नाटक कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया किया कि वह प्रदेश के 17 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के आडियो क्लिप को रिकार्ड पर ले। इस क्लिप में येदियुरप्पा बागी विधायकों के त्याग का जिक्र करते हुए कथित रूप से पार्टी के नेताओं को खरी खोटी सुना रहे हैं, जिनकी वजह से भाजपा की सरकार बन पाई है।

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, वह कांग्रेस की ओर से पेश नवीन सामग्री पर विचार के लिए पीठ गठन के बारे में सीजेआइ रंजन गोगोई से बात करेगी। येदियुरप्पा का वह कथित ऑडियो क्लिप शुक्रवार को सामने आया था जिसमें वह पार्टी के उन नेताओं के प्रति नाराजगी जता रहे थे जो अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस-जद (एस) के विधायकों को पांच दिसंबर को 15 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए टिकट देने का विरोध कर रहे थे।

अयोग्य घोषित किए गए 17 में से 15 विधायकों की सीटों पर पांच दिसंबर को उपचुनाव होगा। इन विधायकों के त्यागपत्र और विश्वास मत के दौरान सदन से अनुपस्थित रहने की वजह से कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन सरकार गिर गई और येदियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्ता में आई।

मंदी और बेरोजगारी के खिलाफ संसद से सड़क तक संग्राम करेगा विपक्ष

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ कांग्रेस की अगुआई वाली बैठक से राकांपा लापता, तृणमूल की सांकेतिक भागीदारी

▸ वाट्सएप जासूसी कांड की निष्पक्ष जांच की मांग पर राष्ट्रपति को ज्ञापन देगा विपक्ष

विपक्षी पार्टियां आर्थिक मंदी और बढ़ती बेरोजगारी से लेकर किसानों की खराब हालत के मुद्दों पर संसद से सड़क तक सरकार की घेराबंदी करेंगी। वहीं वाट्सएप जासूसी कांड पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने के लिए विपक्षी दल राष्ट्रपति को संयुक्त ज्ञापन सौंपेंगे। विपक्षी दलों ने सरकार पर पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगाया। कांग्रेस की अगुआई में 13 विपक्षी दलों की हुई बैठक में सरकार के खिलाफ संग्राम के इन मुद्दों पर सहमति बनी। हालांकि विपक्षी दलों की इस बैठक में राकांपा शामिल नहीं हुई तो तृणमूल कांग्रेस ने भी अपना एक नुमाइंदा भेजकर केवल सांकेतिक मौजूदगी ही दर्ज कराई। जबकि आम आदमी पार्टी को आमंत्रित की नहीं किया गया था।

कांग्रेस की पहल पर हुई इस बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने की। बैठक में द्रमुक, राजद, तृणमूल कांग्रेस, जदएस, आरएलएसपी, माकपा, भाकपा, आरएसपी, आइयूएमएल, केरल कांग्रेस और एलजेडी के नेता शामिल हुए। सपा और बसपा तो पहले से ही विपक्षी खेमे की बैठकों से दूरी बना ली है।

बैठक के बाद विपक्षी नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। जीडीपी छह साल के निचले स्तर पर है तो उद्योग, निर्यात, कारोबार से लेकर बाजार सभी जगह आर्थिक मंदी का असर है। किसानों को एमएसपी से भी काफी कम दाम मिल रहा है और उनकी हालत बदतर है। इन सब वजहों से बेरोजगारी भी 50 साल के सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। इन मुद्दों पर पांच से 15 नवंबर तक सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर रखी है।

नई दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस की अगुआई में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस दौरान द्रमुक नेता टीआर बालू, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, रालोद नेता अजीत सिंह और एलजेडी नेता शरद यादव। प्रेट्र

विपक्षी दलों ने इन मुद्दों पर संसद के भीतर ही नहीं बाहर भी सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए साझा रणनीति पर सहमति जताई है। मुक्त व्यापार समझौते आरसेप के खिलाफ भी विपक्षी दल मुखर आवाज उठाएंगे। मोदी सरकार को बीते 70 साल की सबसे असंवेदनशील सरकार करार देते हुए आजाद ने कहा कि देश ने कभी ऐसी सरकार नहीं देखी जिसे जनता के तकलीफों की परवाह ही नहीं है।

वाट्सएप जासूसी कांड को लेकर विपक्ष का रुख पूछे जाने पर आजाद ने कहा कि इस बैठक में इसको लेकर चर्चा नहीं की गई। चूंकि यह आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित बैठक थी इसीलिए तय हुआ कि जासूसी कांड पर विपक्षी दल अलग से मंत्रणा कर जल्द ही साझा रणनीति तय करेंगे। लेकिन, बैठक में शामिल एक विपक्षी नेता ने बताया कि जासूसी कांड की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संयुक्त ज्ञापन देने पर विपक्षी दलों में सैद्धांतिक सहमति बनी है।

द्रमुक नेता टीआर बालू ने कहा कि आर्थिक हालत इतने चिंताजनक हैं कि प्रधानमंत्री को विदेश भ्रमण छोड़ स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए। लोकतांत्रिक जनता दल के शरद यादव ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव ने दिखाया है कि जनता आगे बढ़ चुकी है और अब विपक्षी दलों को उनके पीछे लगकर संसद से सड़क तक इस सरकार के खिलाफ संग्राम में उतरना है। वामपंथी दल बैठक में तो मौजूद थे मगर संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में शामिल नहीं हुए।

13 दलों की बैठक में शामिल नेता : बैठक में कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, राजीव शुक्ल, रणदीप सुरजेवाला, द्रमुक के टीआर बालू, एलजेडी के शरद यादव, राजद के मनोज झा शामिल हुए। इनके अलावा आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, रालोद के अजीत सिंह, तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक, जदएस की तरफ से डी कुपेंद्र रेड्डी, माकपा से टीके रंगराजन, भाकपा के डी राजा, विनय विश्वम, आरएसपी के शत्रुजीत सिंह, आइयूएमएल के पीके कुन्हलकुट्टी और केसीएम के जोस के मणि भी बैठक में मौजूद रहे।

आरसेप से भारत के बाहर रहने को कांग्रेस ने बताई अपनी जीत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) मुक्त व्यापार समझौते में शामिल नहीं होने के भारत के फैसले को राष्ट्रहित के लिए संघर्ष करने वाले सभी ताकतों की जीत करार दिया है। साथ ही पार्टी ने इसका श्रेय लेते हुए साफ कर दिया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी के तगड़े विरोध ने भाजपा सरकार को आरसेप समझौते से पीछे हटने के लिए बाध्य किया है।

भारत के अपने हितों के मद्देनजर आरसेप में शामिल नहीं होने के ऐलान के तुरंत बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए पार्टी की यह प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ताकतवर विरोध के चलते किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, छोटे और बड़े व्यवसायों के हितों पर प्रहार के लिए आगे बढ़ी सरकार को अपने कदम रोकने पड़े हैं।

रणदीप सुरजेवाला फाइल फोटो

पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा कि भयंकर बेरोजगारी, डूबती अर्थव्यवस्था, खेती के संकट और आर्थिक कुप्रबंधन के इस दौर में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) भारत के लिए बड़ी विपदा होने वाला था। इससे समझौते का हिस्सा बनते ही भारत सस्ते चीनी वस्तुओं का डंपिंग बाजार बन जाता और देशी उद्योग व कारोबार बर्बाद हो जाते।

'भारत से अरबों डॉलर के रक्षा सौदों पर वार्ता जारी'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी रिपोर्ट में दी है जानकारी

▸ अमेरिका से 16 अरब डॉलर के रक्षा उपकरणों की खरीद कर चुका है भारत

अमेरिका धीरे-धीरे भारत को रक्षा उपकरणों व इससे जुड़े तमाम उत्पादों की आपूर्ति करने वाले देश के तौर पर स्थापित होता जा रहा है। भारत एक दशक पहले तक अमेरिका से किसी भी तरह के रक्षा उत्पादों को नहीं खरीदता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत 16 अरब डॉलर के रक्षा उपकरणों का आयात अमेरिका से कर चुका है। साथ ही आने वाले दिनों में अतिरिक्त अरबों डॉलर के रक्षा उपकरणों की खरीद की बातचीत जारी है। इस बात अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से सोमवार को हिंद प्रशांत क्षेत्र पर जारी रिपोर्ट में हुई है। यह रिपोर्ट तब जारी हुई है जब बैंकाक में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण देशों की बैठक चल रही है।

'मुक्त व खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र' नाम की इस रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि जब से भारत व अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता की शुरुआत हुई है, तब से आर्थिक व रक्षा संबंधों में काफी मजबूती आई है। सनद रहे कि टू प्लस टू वार्ता के तहत दोनों देशों के विदेश व रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। इसकी एक बैठक वर्ष 2018 में हुई थी और अगली बैठक इसी महीने संभावित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक प्रमुख रक्षा सहयोगी के तौर पर भारत ने अमेरिका से 16 अरब डॉलर के हथियारों की खरीद की है और अरबों डॉलर की खरीद की बात हो रही है। उसने यह भी बताया है कि नवंबर, 2019 में दोनों देशों के बीच पहली बार तीनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होने वाला है। इसमें भारत, आस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच बढ़ रहे रक्षा सामंजस्य का भी जिक्र किया गया है। इन चारों देशों के बीच पहली मंत्रिस्तरीय बैठक सितंबर, 2019 में की गई है।

रिपोर्ट में भारत के साथ बढ़ते ऊर्जा सहयोग को लेकर भी महत्व दिया गया है। जिस तरह से भारत कुछ वर्ष पहले तक अमेरिका से कोई रक्षा उपकरण नहीं खरीदता था, उसी तरह से भारत पहले ऊर्जा की खरीद भी नहीं करता था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वर्ष 2018 में भारत ने अमेरिका से 6.2 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पादों की खरीद की है। यह सौदा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। हाल ही में संपन्न पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ऊर्जा से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करने जा रहा है।

चिदंबरम ने ईडी के आरोपों को बताया बेबुनियाद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आइएनएक्स मीडिया डील के मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों को बेबुनियाद बताया। सोमवार को न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण पीठ ने सुनवाई को बुधवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

इस मामले में ईडी ने कहा था कि व्यक्तिगत हित और भ्रष्टाचार के लिए पी चिदंबरम ने बेटे कार्ति चिदंबरम के साथ मिलकर साजिश रची थी और पद का दुरुपयोग करते हुए आइएनएक्स मीडिया को विदेशी संवर्धन निवेश बोर्ड की मंजूरी दिलाई थी। पीठ के समक्ष दाखिल जवाब में चिदंबरम ने कहा कि ऐसे कोई सुबूत पेश नहीं किए गए जिनसे उन पर आरोप साबित हो सकें।

'गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियों पर लगाम जरूरी'

▸ वाट्सएप जासूसी कांड की जांच कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार : पई

बेंगलुरु, प्रेट्र : सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विशेषज्ञ टीवी मोहनदास पई ने सोमवार को कहा कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों ने बाजार पर कब्जा जमा लिया है और अब समय आ गया है कि दुनिया भर में सरकारें इन पर लगाम लगाएं। इंफोसिस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) ने यह भी कहा कि सरकार को वाट्सएप जासूसी कांड की जांच कराकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए।

पई ने कहा कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफार्म ने बाजार पर एकाधिकार कर लिया है। वो जो कुछ भी हो रहा है उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। ये कंपनियां वैश्विक स्तर पर लोगों के दिमाग पर भी नियंत्रण करने की कोशिश कर रही हैं। इनसे निपटने के लिए मानक बनाए जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि इन कंपनियों ने सूचनाओं का भंडारण कर रखा है। इन्हें हम सभी को बताना चाहिए कि वो इन सूचनाओं को मालवेयर या अन्य किसी टेक्नोलॉजी से किसी तरह सुरक्षा करेंगी, ताकि हमारी जासूसी ना हो सके।

मोहनदास पई फाइल फोटो

पई ने कहा कि इन प्लेटफार्म पर असीमित डाटा मौजूद है। इसके माध्यम से ये कंपनियां लोगों की आदतों और उनके शारीरिक और मानसिक स्थिति के बारे में पता लगा रही हैं। यह बहुत ही गंभीर स्थिति है।

उन्होंने कहा कि ये कंपनियां उपयोगकर्ताओं के साथ कांट्रैक्ट (अनुबंध) करती हैं, लेकिन कांट्रैक्ट के जरिए निजता की सुरक्षा नहीं की जा सकती। इनका कांट्रैक्ट भी एकतरफा होता है, वो आप पर नियंत्रण कर लेती हैं और आप पर अपना प्रभाव जमा लेती हैं।

वाट्सएप जासूसी कांड की जांच के लिए एसआइटी बनाने की मांग

मुंबई, प्रेट्र : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने वाट्सएप जासूसी कांड की जांच के लिए एसआइटी गठित करने की मांग की है। उन्होंने इजरायली स्पाइवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर वाट्सएप के जरिए लोगों की जासूसी कराए जाने के मामले पर केंद्र सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की।

अनदेखी की सजा

रेलवे ने देशव्यापी छापेमारी में 11 हजार लोगों के 2801 कंफर्म टिकट रद किए, रेलवे के 59 एजेंट ब्लैक लिस्ट, 528 दलाल गिरफ्तार किए गए

फर्जी आइडी वाले टिकट से सफर में लगा अड़ंगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेलवे की लापरवाही से हजारों यात्री कंफर्म टिकट के बावजूद इस बार अपने घर जाकर दीवाली और छठ नहीं मना पाए। इन लोगों का दोष मात्र इतना था कि इन्होंने आइआरसीटीसी के एजेंट से केवल उनके वास्तविक मेल आइडी का उपयोग करने का अनुरोध नहीं किया था। नतीजतन एजेंट ने फर्जी मेल आइडी से इनका टिकट बुक करा दिया, लेकिन आरपीएफ ने छापेमारी कर ऐसे सभी टिकटों को अवैध घोषित कर ब्लॉक करा दिया। इस कवायद के बावजूद हजारों लोग इसी प्रकार के टिकटों पर यात्रा करने में सफल रहे और आरपीएफ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई।

देश में फर्जी मेल आइडी के जरिये रेलवे टिकटों की बुकिंग का धंधा जोरशोर से चल रहा है। इसे रोकने के लिए आइआरसीटीसी, क्रिस, कामर्शियल विभाग तथा आरपीएफ के अधिकारियों की टीम मिलकर प्रयास कर रही है। पिछले दिनों इस टीम ने आइआरसीटीसी द्वारा नियुक्त प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडरों, रीजनल सर्विस प्रोवाइडरों के अलावा व्यक्तिगत दलालों के यहां छापे डाले, जिससे इनके देशव्यापी नेटवर्क का पता चला है।

ये भोलेभाले लोगों को कंफर्म टिकट प्रदान करने के लिए उनकी फर्जी मेल आइडी बनाते और प्रयोग करते हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए आरपीएफ ने एक मेल आइडी से तीन माह में 14 से अधिक टिकट बुक कराने वालों की धरपकड़ शुरू की। 26 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चले अभियान में फर्जी आइडी पर बुक 28,01 कंफर्म टिकट ब्लॉक कराए गए। इससे 11 हजार से ज्यादा लोगों का न सिर्फ पैसा बर्बाद हुआ, बल्कि वे दीवाली और छठ मनाने अपने घर भी नहीं जा पाए। हालांकि इसी प्रकार के 15,426 टिकट वाले 60 हजार से ज्यादा लोगों को यात्रा करने से रेलवे नहीं रोक पाई। हालांकि इनके एजेंट आरपीएफ के शिकंजे में आ गए हैं। इन्होंने बुकिंग के लिए 2720 मेल आइडी का इस्तेमाल किया था।

प्रतीकात्मक फोटो

देश में 1.76 लाख आरएसपी, कई गोरखधंधे में लगे

रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि देश में 1.76 लाख रीजनल सर्विस प्रोवाइडर (आरएसपी) हैं। इनमें से कई इस गोरखधंधे में लगे हैं। फर्जी मेल आइडी के अलावा मिर्ची और एनएमएस जैसे साफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। एजेंट से टिकट बुक कराते वक्त उन्हें ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनका टिकट उनके द्वारा प्रदत्त मेल आइडी से ही बुक कराया जाए। छापेमारी के 519 मामलों में 528 व्यक्तिगत एजेंट गिरफ्तार किए गए, जबकि 37 फरार हो गए हैं। इस दौरान गड़बड़ी में शामिल 65 आरएसपी की पहचान की गई है। जिसमें से 59 को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इनमें 17 उत्तर रेलवे व 13 उत्तर-मध्य रेलवे के हैं।

मिर्ची मामले में बिंद्रा की जमानत अर्जी पर ईडी ने दाखिल किया जवाब

मुंबई, एएनआइ : गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के साथ कथित लेनदेन में गिरफ्तार रंजीत सिंह बिंद्रा की जमानत अर्जी पर ईडी ने सोमवार को जवाब दाखिल कर दिया। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 अक्टूबर को बिंद्रा को गिरफ्तार किया था और विशेष अदालत से उसकी हिरासत मांगी थी। इसके बाद बिंद्रा को सात नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मिर्ची को मुंबई में संपत्ति कब्जाने में बिंद्रा ने जहां कथित तौर पर मदद की थी वहीं रियल इस्टेट से उसने बहुत पैसा भी कमाया था।

बिंद्रा की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए ईडी ने कहा, उसने आपराधिक कृत्यों से पैसा कमाया है। मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत वह प्रथम दृष्टया दोषी है। मामले की जांच महत्वपूर्ण स्थिति में है और इस समय बिंद्रा को जमानत दी जाती है तो वह इसे बाधित कर सकता है। चूंकि वह जांच के तरीकों से अवगत है, ऐसे में वह अन्य संदिग्ध लोगों को गिरफ्तारी से बचने में मदद कर सकता है। ईडी ने बिंद्रा के अलावा अब तक हारून अलीम यूसुफ, हुमायू मर्चेंट और रिंकू देशपांडे को गिरफ्तार किया है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

2014 में भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव में आठ महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें पांच जीती थीं। कांग्रेस ने 10 और झामुमो ने सात महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और दोनों पार्टियों की एक-एक उम्मीदवार जीतीं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 5 नवंबर 2019

सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन को भी तैयार भाजपा

नहीं बन रही बात ▶ सरकार गठन के लिए संवैधानिक रूप से सिर्फ चार दिन का वक्त बाकी, लेकिन शिवसेना के आगे झुकने को नहीं तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए संवैधानिक रूप से सिर्फ चार दिन का वक्त बाकी है, लेकिन भाजपा अब शिवसेना के दबाव में आने को तैयार नहीं है। नेतृत्व की ओर से साफ कर दिया गया है कि भाजपा शिवसेना की उचित मांगों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन शिवसेना को भी यह स्वीकार करना होगा कि बड़ी पार्टी भाजपा है। खासकर तब जबकि राकांपा नेता शरद पवार की ओर से बार-बार बोला जा रहा है कि उन्हें तो विपक्ष में बैठने का जनमत मिला है। संकेत है कि अगले चार दिनों में स्थिति बदलेगी और राजग सरकार का गठन होगा वरना भाजपा राष्ट्रपति शासन के लिए भी तैयार है।

सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अपनी तरफ ने उन्होंने दो बार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को फोन कर जीत और दीवाली की बधाई दी है, लेकिन शिवसेना की ओर से केवल सार्वजनिक बयानबाजी की जा रही है। उनकी तरफ से बातचीत या फिर औपचारिक रूप से कोई शर्त भी नहीं रखी गई है। बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शिवसेना को बहुमत का रुख समझते हुए सामने आकर बातचीत करनी चाहिए। उसे इसका भी अहसास होना चाहिए कि भाजपा की संख्या शिवसेना से दोगुनी है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा उप मुख्यमंत्री पद के साथ राजस्व मंत्रालय भी देने को राजी हो सकती है, लेकिन अब तक शिवसेना की ओर से कोई औपचारिक बात की ही नहीं गई है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा गृह और शहरी विकास मंत्रालय शिवसेना को देने पर राजी नहीं होगी।

परोक्ष रूप से शिवसेना को 1999 की भी याद दिलाई जा रही है जब भाजपा 56 सीटों पर थी और शिवसेना लगभग 70 पर। पर्याप्त संख्या में निर्दलीय भी जीते थे, लेकिन तब भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की ओर से ढाई-ढाई साल के मुख्यमंत्री पद की शर्त रखी गई थी, जिसे शिवसेना ने नकार दिया था। 11-12 दिन की तकरार के बीच उस राकांपा ने कांग्रेस को समर्थन देकर संयुक्त सरकार बनाई थी जिस कांग्रेस से बाहर होकर शरद पवार ने अलग पार्टी बनाई थी। यानी जिद की वजह से छींका कांग्रेस के हक में फूटा था। इस बार स्थिति और भी पेंचीदा है। सोमवार को कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद भी शरद पवार ने दोहराया है कि उन्हें विपक्ष में बैठने का जनमत मिला है। दरअसल उन्हें यह स्वीकार नहीं कि शिवसेना के हाथ कमान सौंपी जाए।

ध्यान रहे कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा के पक्ष में यह है कि राज्यपाल सरकार गठन के लिए पहले उन्हें बुलाएंगे। पर भाजपा कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती है। वह तभी आगे बढ़ेगी जब शिवसेना के साथ बात पक्की हो जाएगी। वरना राष्ट्रपति शासन का खतरा भी मंडरा सकता है।

महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रेट्र

निर्दलीय विधायक का 25 शिवसेना विधायक तोड़ने का दावा

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत के राज्यपाल बीएस कोशियारी से मिलने के बीच धुले में भाजपा नेताओं की एक बैठक में जयकुमार रावल ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी के कई नेता अब दोबारा चुनाव चाहते हैं। जबकि महाराष्ट्र में भाजपा को अपना समर्थन देने की घोषणा कर चुके निर्दलीय विधायक रवि राणा ने दावा किया कि अगली सरकार के गठन के लिए शिवसेना के 25 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर फड़नवीस की सरकार बनी तो करीब दो दर्जन शिवसेना विधायक टूटकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। राणा अपनी पत्नी और लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा के साथ अलग से कोशियारी से मिले। अनुच्छेद 370 को लेकर हाल ही में पार्टी छोड़ चुके मुंबई कांग्रेस के पूर्व प्रमुख कृपाशंकर सिंह ने भी राज्यपाल से मुलाकात की।

सोनिया से मिल के भी पवार ने खत्म नहीं किया सस्पेंस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना की सत्ता की जंग के बीच राकांपा प्रमुख शरद पवार ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अपनी तरफ से सूबे के सियासी सस्पेंस का पर्दा नहीं उठाया। पवार ने राकांपा-कांग्रेस को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलने की बात तो कही मगर शिवसेना-भाजपा के झगड़े में सरकार नहीं बनने पर भविष्य का विकल्प बंद नहीं करने का भी संकेत दे दिया। साथ ही मराठा दिग्गज ने भाजपा-शिवसेना को सूबे में जल्द सरकार बनाने की नसीहत भी दी।

भाजपा और शिवसेना के बीच चल रही जंग में भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने से परहेज नहीं करने का संकेत देते हुए शरद पवार ने साफ कहा कि सोनिया गांधी से दोबारा इसको लेकर उनकी मुलाकात होगी। भाजपा को आंख दिखा रही शिवसेना के रुख को देखते हुए शरद पवार की सोनिया गांधी से सोमवार को हुई मुलाकात सियासी रूप से बेहद अहम रही। शिवसेना को समर्थन देने या नहीं देने के मसले पर पवार ने कांग्रेस नेतृत्व का मन भांपने का प्रयास किया। इस बातचीत में फिलहाल दोनों के बीच यह रणनीतिक सहमति साफ दिख रही कि कांग्रेस-राकांपा सीधे शिवसेना का समर्थन करते दिखाई देने से परहेज करें। साथ ही भाजपा के खिलाफ शिवसेना की आक्रामक सियासत ठंडी भी न पड़े इसके मद्देनजर भविष्य का विकल्प खुला रखने का संकेत दिया जाए।

नई दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात के बाद प्रस्थान करते राकांपा प्रमुख शरद पवार। प्रेट्र

सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शरद पवार ने पत्रकारों को इसका साफ संकेत भी दिया। शिवसेना की ओर से सरकार बनाने का प्रस्ताव मिलने की बातों से इन्कार करते हुए पवार ने कहा कि इसको लेकर हमारी शिवसेना से कोई बात नहीं हुई है। न राकांपा ने शिवसेना से संपर्क किया है और न ही शिवसेना की ओर से हमें कोई प्रस्ताव आया है। पवार ने कहा कि मौजूदा सियासी हालात से उन्होंने सोनिया को रूबरू कराया है। जमीनी सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र की जनता भाजपा के खिलाफ है। मगर सरकार बनाने का नंबर हमारे पास नहीं है। हम जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े उस पार्टी के साथ जाना संभव नहीं है। हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। मगर राज्य में जो हालात हैं उसमें मैं यह भी नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। पवार की यह टिप्पणी भविष्य का विकल्प खुला होने की ओर इशारा कर रही है।

शिवसेना के रुख से जुड़े सवाल पर पवार ने कहा कि भाजपा-शिवसेना को जल्द सरकार बना लेनी चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि भाजपा को लेकर शिवसेना का रुख काफी आक्रामक है। राकांपा प्रमुख ने उनके दोबारा मुख्यमंत्री बनने की अटकलों को खुद ही खारिज कर दिया। सियासी झगड़े की वजह सूबे में क्या राष्ट्रपति शासन ही विकल्प रह गया है? इस पर पवार ने कहा कि सरकार बनाना शिवसेना और भाजपा की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन एक ओर महाराष्ट्र के लोग तमाम समस्याओं से जूझ रहे और दूसरी तरफ ये दोनों पार्टियां अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं।

मप्र में भाजपा विधायक ने कहा-मैं कमलनाथ सरकार से संतुष्ट

सौरभ पांडेय, शहडोल : मध्य प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। झाबुआ उप चुनाव की हार और पवई विधायक की सदस्यता समाप्त होने से भाजपा विधायकों की संख्या कम हो गई है, वहीं अब ब्यौहारी से भाजपा विधायक शरद कोल के सरकार समर्थित बयान ने पार्टी की मुसीबत और बढ़ा दी है। कोल ने कहा, 'मैं कमलनाथ सरकार से संतुष्ट हूं और साहब (सीएम कमलनाथ) के ही साथ हूं।'

विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए कोल ने यह भी कहा, 'मैंने भाजपा नहीं छोड़ी है। मेरी प्राथमिक सदस्यता भाजपा की है। पार्टी ने भी अभी तक मेरी सदस्यता समाप्त नहीं की है। इसलिए मेरी गिनती भाजपा की सदस्यता वाले विधायकों में होगी।' इस बीच भाजपा संगठन ने कोल से पूरी तरह दूरी बना ली है। इस बात को विधायक भी स्वीकार रहे हैं। कोल का कहना है कि स्थानीय भाजपा संगठन ने मुझसे दूरी बनाई है, लेकिन प्रदेश स्तर का संगठन मेरे संपर्क में रहता है। कभी बैठकों के लिए फोन आ जाता है, लेकिन पिछले तीन-चार महीनों में मैं भाजपा की किसी संगठनात्मक बैठक का हिस्सा नहीं बना। मैं अब स्वतंत्र हूं। मैं किस पार्टी में हूं, किसमें नहीं, इस बात का राजफाश जल्द ही होगा। दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में कई चौकाने वाली बातें सामने आएंगी। कोल के इस बयान के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है।

'सीमांत इलाकों में बुनियादी ढांचे को कर रहे मजबूत'

जागरण संवाददाता, देहरादून

▶ पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह बोले-तेजी से चल रहा है काम

▶ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क निर्माण पर विशेष फोकस

केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने कहा कि सीमांत इलाकों में बुनियादी ढांचे की मजबूती पर काम किया जा रहा है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के निर्माण पर पर्यावरणीय मानकों का अड़ंगा जरूर लगा, लेकिन अब काम रफ्तार पकड़ चुका है।

रविवार को उत्तराखंड की स्थापना की 19वीं वर्षगांठ पर आयोजित सैन्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए जनरल वीके सिंह ने कहा कि एक वक्त था जब सेना के आधुनिकीकरण की रफ्तार बहुत धीमी थी। बोफोर्स के बाद नयी आर्टिलरी गन के लिए भारतीय सेना को तीन दशक का लंबा इंतजार करना पड़ा। अब प्राथमिकता के आधार पर जरूरतें पूरी की जा रही हैं और आधुनिकीकरण के काम में तेजी लाई जा रही है।

पूर्व सैनिकों को उत्तराखंड की धरोहर बताते हुए उन्होंने कहा कि जिस देश में सैनिकों का सम्मान नहीं होता, वह देश आगे नहीं बढ़ सकता। कहा कि उत्तराखंड के पास पूर्व सैनिकों के रूप में अनुशासित और प्रशिक्षित मानव शक्ति है। इस शक्ति का इस्तेमाल प्रदेश की तरक्की के लिए किया जा सकता है। इन्हें संगठित कर प्राकृतिक आपदा, नदियों के पुनर्जीवन, वन संरक्षण एवं संवर्धन सहित जैसे कार्यों में लगाया जा सकता है। पूर्व सैनिकों की सुविधाओं से जुड़े मामलों पर उन्होंने कहा कि इस पूरे सिस्टम को ज्यादा सुगम बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार इसमें सुधार कर रही है।

देहरादून में सोमवार को उत्तराखंड राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत करते केंद्रीय भूतल एवं परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह। जागरण

उप्र के मंत्री ने प्रियंका और अखिलेश पर की अभद्र टिप्पणी

जागरण संवाददाता, बलिया : उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर विवादित बयान दिया। मंत्री ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका को 'फ्राड की पत्नी' बताया तो अखिलेश को 'अप्रासंगिक नेता।'

बलिया के राजागांव खरौनी में आयोजित ग्राम गौरव सम्मान समारोह में भविष्य निधि घोटाले पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि इस मामले में प्रियंका व अखिलेश ने खुली लूट कहकर सरकार को घेरने की कोशिश की है, जो उचित नहीं है। इसी जवाब में मंत्री ने प्रियंका व अखिलेश पर हमला बोला। बोले, 'प्रियंका एक फ्राड राबर्ट वाड्रा की पत्नी हैं जो खुद घोटाले में जमानत पर हैं।' उन्होंने डायल हंड्रेड का नंबर बदलने पर अखिलेश यादव के बयान पर कहा, 'अखिलेश भविष्य के अजीत सिंह हैं। जिस तरह अजीत सिंह अप्रासंगिक हो गए हैं उसी प्रकार अखिलेश यादव भी अब भारतीय राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश में अप्रसांगिक हो गए हैं।'

हरियाणा के युवाओं के लिए 75 फीसद रोजगार का लाया जाएगा बिल : दुष्यंत

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में निजी व सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं की 75 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस विषय में सरकार जल्द ही बिल लाने जा रही है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। सोमवार को यहां पत्रकारों से चर्चा में दुष्यंत ने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र और गुजरात में लागू बिल का अध्ययन कर रही है। गठबंधन सरकार एक सर्वश्रेष्ठ बिल लाएगी, जिसके तहत हरियाणा के मूल निवासियों के लिए 75 फीसद रोजगार का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए हर दिशा व क्षेत्र में बेहतर काम करेगी।

इससे पूर्व दुष्यंत ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण किया। दुष्यंत दोपहर करीब एक बजे हरियाणा सचिवालय पहुंचे और पांचवें फ्लोर पर स्थित कार्यालय में कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुष्यंत को पदभार ग्रहण कराया और शुभकामनाएं दीं। दुष्यंत इस विधानसभा के सबसे कम उम्र के विधायक हैं, जिन्हें इतनी कम उम्र में डिप्टी सीएम बनने का गौरव हासिल हुआ है।

गर्मजोशी के साथ मिले खट्टर और हुड्डा...: चंडीगढ़ में सोमवार को विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस विधायक दल के नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक-दूसरे का गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। इस दौरान उपमुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। संजय घिल्डियाल

छत्तीसगढ़ के एक लाख कांग्रेसियों और किसानों का काफिला जाएगा दिल्ली

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ के एक लाख कांग्रेसियों और किसानों का काफिला दिल्ली जाएगा। वहां धान की खरीद की दर 2500 रुपये प्रति क्विंटल, बोनस और सेंट्रल पूल में चावल लेने की मांग को लेकर 15 नवंबर को धरना देंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह लक्ष्य रखा है। इस कारण संगठन के 34 जिला कमेटियों को औसतन तीन हजार लोगों को साथ लाने के लिए कहा गया है। भीड़ जुटाने में जिला कमेटियों की मदद बूथ और ब्लॉक स्तर की कमेटियां भी करेंगी। जिला कमेटियों से यह भी कहा गया है कि वे अपने स्तर पर ज्यादा से ज्यादा वाहनों की व्यवस्था भी करें, क्योंकि सड़क मार्ग से दिल्ली कूच किया जाएगा। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ 15 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रही है। हर राज्य के पार्टी के जनप्रतिनिधि, नेता और कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। छग सरकार और कांग्रेस भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर तय मुद्दों से ज्यादा यहां किसानों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है।

उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हरक के नए पैंतरे से सियासत में बढ़ी हलचल

राज्य ब्यूरो, देहरादून

अप्रत्याशित कदम उठाने के लिए चर्चित उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के नए सियासी पैंतरे से सत्ता के गलियारों में हलचल है। मार्च 2016 में विधायकों की खरीद फरोख्त से संबंधित तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग के मामले में सीबीआइ द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिए जाने के बाद अब हरक सिंह रावत मुकदमा वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि रावत का कहना है कि इस संबंध में अभी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। हरक सिंह रावत ने ही इस मामले में सीबीआइ जांच को याचिका दायर की थी, लेकिन पिछले दिनों सीबीआइ द्वारा उनके खिलाफ भी स्टिंग प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर किया था।

मार्च 2016 में प्रदेश की सियासत में उस समय भूचाल आ गया था जब पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कांग्रेस के नौ विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद तत्कालीन हरीश रावत सरकार के सामने सरकार बचाने की चुनौती खड़ी हो गई थी। इस बीच 26 मार्च 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया, जिसमें वह सरकार बचाने के लिए एक चैनल के सीइओ के साथ मध्यस्थता की बात करते नजर आए। इस स्टिंग के सार्वजनिक होने के बाद तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने इसकी जांच सीबीआइ से कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की। सीबीआइ ने अप्रैल 2016 में मामले को अपने हाथ में लेते हुए जांच शुरू कर दी थी। इस बीच अक्टूबर 2019 में सीबीआइ ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ ही कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और निजी चैनल के सीइओ उमेश कुमार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। यह कदम कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के लिए अप्रत्याशित था। ऐसे में अब उन्होंने इस मामले में पैंतरा बदलते हुए मुकदमा वापस लेने के संकेत दिए हैं। हालांकि, कानूनी जानकारों की मानें तो अब हरक सिंह रावत द्वारा मुकदमा वापस लेने का इस मामले में कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है। ऐसे में इस पर पूरी कार्यवाही होगी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि उनकी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। यह राजनीतिक व उसूलों की लड़ाई थी, तब वह लड़ी गई। अब इस मामले में विधि विशेषज्ञों व पार्टी हाईकमान से बात करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

हरीश रावत स्टिंग प्रकरण

▶ सीबीआइ के मुकदमा दर्ज करने के बाद दिए मुकदमा वापस लेने के संकेत

▶ हालांकि इससे सीबीआइ जांच में किसी तरह का कोई असर पड़ने की संभावना नहीं

ज्ञानचंद गुप्ता बने स्पीकर, हुड्डा विपक्ष के नेता

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

पिछली सरकार में भाजपा विधायक दल के सचेतक रहे पंचकूला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता को हरियाणा विधानसभा का नया स्पीकर चुना गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अनुमोदन किया।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा सचिवालय को हुड्डा के कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने तथा उन्हें विपक्ष के नेता का पद सौंपने का अनुरोध पत्र सौंपा गया था। स्पीकर चुने जाने के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने हुड्डा के विपक्ष का नेता बनने की अधिकृत घोषणा की।

गुप्ता के स्पीकर बनने के साथ ही अब यह साफ हो गया कि पूर्व स्पीकर एवं जगाधरी से विधायक कंवरपाल गुर्जर मनोहर सरकार में मंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ज्ञानचंद गुप्ता को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी।

डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नई तारीख : विधानसभा में सोमवार को पहले दिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हो सका। स्पीकर चुने जाने के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए कोई नई तारीख घोषित करने का ऐलान किया। डिप्टी स्पीकर जजपा के कोटे से हो सकता है अथवा भाजपा बिना शर्त समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों में से किसी को डिप्टी स्पीकर का पद सौंप सकती है।

विधायकों को समय से मिलें बिल : मनोहर लाल : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पीकर को बधाई देते हुए कहा कि पिछले पांच सालों में विधानसभा के 15 सत्र और 84 सीटिंग हुई हैं, जिन्हें बढ़ाए जाने की जरूरत है। विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाने के साथ ही प्रदेशव्यापी मसलों पर भी अध्ययन करते हुए अपनी बात सदन में रखनी चाहिए। मनोहर लाल ने स्पीकर से अनुरोध किया कि विधानसभा में जो भी बिल पेश किए जाएं, उन्हें समय से अध्ययन के लिए विधायकों को मुहैया कराया जाना चाहिए।

हरियाणा में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। जागरण

झारखंड विस चुनाव

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुबह ही पहुंच गए मरांडी के आवास, सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया, झामुमो ने कहा-पूरा सम्मान मिलेगा, लेकिन जिद से भाजपा को न हो जाए फायदा

महागठबंधन बचाने के लिए मरांडी को मनाने में जुटी कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में महागठबंधन के स्वरूप पर आफत को लेकर विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ गई है। लालू यादव के हाथ में कमान आने के बाद झाविमो (पी) के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को मनाने की कोशिशें बढ़ीं और कांग्रेस ने यह जिम्मेदारी ली है कि जल्द से जल्द बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन में सुलह करा दी जाए। कोशिश है कि दोनों की मुलाकात भी हो और लोकसभा चुनाव के दौरान जो कसमे-वादे थे वे याद भी दिला दी जाए। सोमवार सुबह ही बाबूलाल मरांडी के आवास पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव पहुंच गए। उन्होंने मरांडी से महागठबंधन में बने रहने का आग्रह किया और इसका संदेश झामुमो तक भी पहुंचाया। अपने व्यवहार नरमी दिखाते हुए शाम में झामुमो ने मरांडी से महागठबंधन में बने रहने की अपील की है और इस बात के लिए सतर्क भी किया है कि कहीं उनके कारण प्रदेश में भाजपा को लाभ ने मिल जाए।

महागठबंधन के लिए सभी प्रमुख पार्टियां एक-दूसरे से त्याग की अपील कर रही हैं और इसके लिए थीम लाइन है- 'बड़ा दिल रखना होगा।' कांग्रेस झामुमो से तो झामुमो झाविमो से यही बात कह रही है। स्पष्ट है कि सभी एक-दूसरे से दावेदारी कम करने की बात कह रहे हैं। वर्तमान हालात में मरांडी की पार्टी झाविमो को अधिक सीट देने की स्थिति में उसी अनुपात में झामुमो और कांग्रेस अपनी सीटें कम करेगा, जिस अनुपात में दावेदारी की गई है।

राजद बना रहेगा, लेकिन वामपंथी किनारे होंगे : महागठबंधन में बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो को शामिल करने का नुकसान वामपंथी दलों को उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस का मानना है कि वामपंथी दलों का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में ही है और इसके लिए पूरे प्रदेश में त्याग नहीं करना चाहिए। वामपंथी अपने बूते सीट जीत जाते हैं, तो उनसे चुनाव के बाद भी समर्थन लेना आसान होगा और अगर नहीं जीतते हैं तो कोई बात ही नहीं। दोनों दलों का हालिया अनुभव यही है कि वामपंथी कैडर दूसरे दलों के लिए मतदान नहीं करते। ऐसे में अब सिर्फ राजद को लेकर ही आगे चलने की बात की जा रही है। इस फॉर्मूले पर झामुमो को मनाना होगा, क्योंकि झामुमो वामपंथी दलों को साथ लेकर चलने की वकालत कर रहा है।

रांची के कांग्रेस भवन में सोमवार को चुनाव समिति की बैठक में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, धीरज साहु, गीता कोड़ा व अन्य। जागरण

समाजवादी पार्टी के तीन प्रत्याशी घोषित

राब्यू, लखनऊ : समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से झारखंड विधानसभा चुनाव में उतरेगी। चुनावी गठबंधन की संभावनाओं पर विराम लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि झारखंड में समाजवादी निर्णायक भूमिका में रहेंगे। चुनाव प्रचार में वरिष्ठ नेताओं को भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। पहली सूची में जिन तीन उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, उसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सारठ से विनोद ठाकुर (सविता), सिन्दरी सीट पर हाफिजुद्दीन अंसारी व नरेश कुमार भारतीय को विधानसभा क्षेत्र छतरपुर (सुरक्षित) से प्रत्याशी बनाया गया है।अन्य उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी।

झारखंड में कमल के कुनबे में 600 से अधिक दावेदार

आनंद मिश्रा, रांची

भाजपा ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पूर्व पार्टी में शामिल होने वालों का खुले दिल से स्वागत किया। कुनबा बड़ा हुआ, तो नतीजा 600 से अधिक दावेदारों के रूप में सामने आया है। जी हां, भाजपा प्रदेश मुख्यालय में विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी करने वालों ने 600 से अधिक बायोडाटा अब तक जमा करा दिए हैं। कार्यालय मंत्री का कक्ष चुनाव लड़ने वालों के आवेदनों से भरा पड़ा है। फोटो के साथ सौंपे गए बायोडाटा में दावेदारों ने क्षेत्र में अपनी सक्रियता को लेकर अखबारों की कटिंग भी लगा रखी है।

सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में टिकट के दावेदारों की भारी भीड़ देखी गई। दावेदार सुबह से रात तक डटे रहे और साथ में आए समर्थक उनके पक्ष में माहौल बनाते रहे। वजह भी स्पष्ट थी कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह, विधानसभा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सह प्रभारी नंद किशोर यादव, प्रदेश सह प्रभारी राम विचार नेताम सहित प्रदेश के तमाम शीर्ष नेता एक साथ प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित थे। सुबह ही यह सूचना भी सार्वजनिक हो गई थी कि शाम पांच बजे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है। जिसे जो मिल रहा था, उसका हाथ पकड़कर अपनी सक्रियता और क्षेत्र में अपनी मजबूती के किस्से सुनाता दिख रहा था। वैसे तो सभी प्रमंडलों से जत्थे पहुंचे थे, लेकिन पलामू और उत्तरी छोटानागपुर से जुड़े लोगों की सर्वाधिक संख्या देखी गई। कई विधायक भी दिखे। राज सिन्हा, मनीष जायसवाल, बिरंची नारायण, गंगोत्री कुजूर, राम कुमार पाहन, सत्येंद्र नाथ तिवारी भी अपने समर्थकों के साथ कभी ऊपर जाते दिखते थे तो कभी नीचे। कुछ लोगों को सूचना मिली कि मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में बैठे हैं तो वे वहां पहुंच गए। पूर्व डीजीपी डीके पांडेय, नूतन तिवारी, मिस्फीका हसन, देवकुमार धान, अनंत प्रताप देव की उपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई थी।

1988 में भारत के ओर से मिली सैन्य सहायता का मालदीव ने आभार जताया है। मालदीव के विजय दिवस की 31वीं सालगिरह के मौके पर विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि भारत ने 'आपरेशन कैक्टस' छेड़कर पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम का तख्तापलट होने बचाया था।

...तो चीन ने ऐसे जीती वायु प्रदूषण से जंग

प्रदूषण के मामले में कभी चीन की स्थिति भारत जैसी हुआ करती थी। महज सात साल पहले चीन के 90 फीसद शहरों में प्रदूषण का स्तर मानकों से ज्यादा था। इससे प्रतिवर्ष लाखों लोग काल कवलित होते थे। चीन ने इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाए और आज उसके शहरों की वायु गुणवत्ता काफी हद तक सुधर गई। भारत के अब तक के कदम कारगर नहीं साबित हुए। पेश है एक नजर

अक्षय ऊर्जा पर ज्यादा जोर

चीन इस समय कोयला की बजाय अक्षय ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर भी बनाया है। 2014 में भारत सरकार कहती थी कि दिल्ली में बीजिंग की तुलना में कम प्रदूषण है। अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने भी अपने आंकड़े के आधार पर यह माना था कि भारत में गर्मियों व मानसून की हवा बीजिंग की तुलना में साफ है। केवल सर्दियों में हवा की गुणवत्ता खराब होती है या कहें बीजिंग की तरह होती है, लेकिन पांच साल में स्थिति बदल गई है। आज दुनिया के 200 प्रदूषित शहरों की सूची से बीजिंग बाहर निकलने को तैयार है।

चीन के कदम

चीन की सरकार ने 2013 में नेशनल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान बनाया और प्रदूषण पर काफी हद तक नियंत्रण पाने में कामयाबी पाई। ग्रीनपीस एयर विजुअल की रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित 30 शहरों में 22 भारत के हैं। दिल्ली व इसके आसपास के शहरों में तो पिछले कुछ दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से 900 के बीच बना हुआ है।

चीनी शहरों में वायु प्रदूषण

2013 में विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में चीन के शहर सबसे ऊपर थे। धुंध की चादर से ढके रहने वाले चीन के शहरों विशेष रूप से बीजिंग के कारण चीन की दुनिया भर में आलोचना होती थी। बीजिंग के लोगों की मास्क लगाई हुई तस्वीरें दुनिया भर में प्रकाशित होती थीं।

बीजिंग पर कारगर योजना

देश की राजधानी बीजिंग सर्वाधिक प्रदूषित शहर था। चीन ने इसपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। यहां और इसके आसपास स्थापित कारखानों में ताले लगा दिए गए। स्टील तथा एल्यूमिनियम के कारखानों में उत्पादन कम कर दिया गया। वर्ष 2014 में प्रदूषण फैलाने वाले लाखों वाहनों को सड़क से हटाया गया। रेड लाइन क्षेत्र घोषित कर सभी वन या हरित क्षेत्र के आसपास निर्माण कार्यों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई।

जारी होता है पूर्वानुमान

चीन में वायु प्रदूषण के स्तर पर नजर रख रही एजेंसी मौसम की तरह पूर्वानुमान जारी करती है। किसी भी एक दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक के 200 के ऊपर जाते ही ब्लू अलर्ट जारी कर दिया जाता है। इसके तहत धूल नियंत्रण संबंधी उपायों के साथ-साथ निजी वाहनों के परिचालन व स्कूली बच्चों की बाहरी गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। बच्चों व बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए विशेष हिदायतें दी जाती हैं। इसके बाद सूचकांक अगर लगातार चार-पांच दिनों तक 200 के ऊपर बना रहता है तो रेड अलर्ट के तहत तत्काल आपातकालीन उपायों की घोषणा कर दी जाती है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार जाने पर स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा हुई।

तुरंत जारी होती है एडवाइजरी

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम व नियंत्रण) प्राधिकरण ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर 27 सितंबर से ही बैठकों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया था। प्राधिकरण ने जब पराली को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए। तब तक पंजाब-हरियाणा के किसान पराली जलाने लगे थे। चीन में प्रदूषण के पूर्वानुमान के तहत ही ऑड-इवेन व कर्मचारियों के वर्किंग शिफ्ट को लेकर एडवाइजारी जारी कर दी जाती है। भारत में ऐसा करने में लेट हो जाता है।

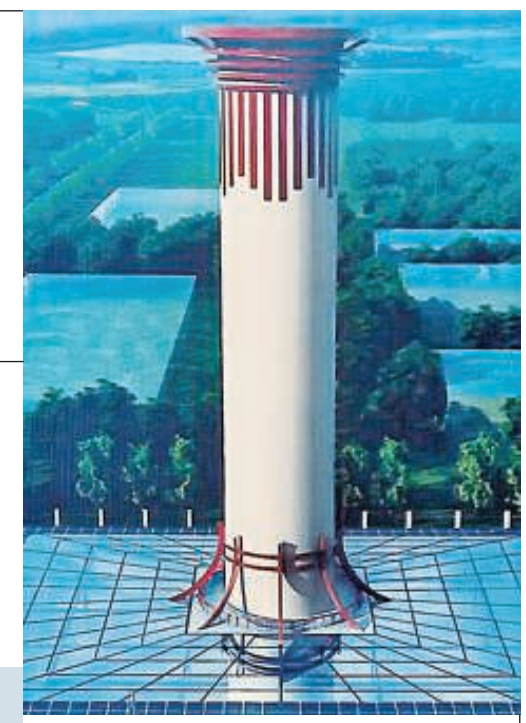

चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर भी बनाया है। फाइल

60 फीसद कम करेगा वायु प्रदूषण

चीन के दावे की मानें तो वह अपने प्रमुख शहरों में वर्ष 2020 तक वायु प्रदूषण के स्तर को 60 फीसद तक कम कर लेगा।

'पराली जलना तुरंत बंद कराएं पंजाब-हरियाणा'

दो टूक ▸ प्रदूषण की भयावह स्थिति को देख पीएमओ ने संभाला मोर्चा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सहित समूचे एनसीआर में प्रदूषण के चलते बनी भयावह स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोमवार को फिर मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने इस दौरान पंजाब और हरियाणा को पराली जलने की घटनाओं के न रुकने पर दो टूक हिदायत दी कि अब ऐसा नहीं चलेगा। पराली का जलना तुरंत बंद कराना होगा। इस दौरान पंजाब ने इसमें कमी का दावा किया, लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ घंटे पहले सेटेलाइट से ली गई तस्वीर ने उनके सारे दावों की पोल खोल दी। तस्वीर में बड़े पैमाने पर पराली जलने के मामले रिपोर्ट किए गए थे।

मिश्रा ने सोमवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की। इनमें तीनों ही राज्यों के मुख्य सचिव मौजूद थे। इसके अलावा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। करीब घंटेभर चली इस बैठक में पीएमओ ने तीनों राज्यों से रविवार को दिए गए निर्देशों पर अमल को लेकर जानकारी मांगी। इस पर पंजाब ने पराली जलने की घटनाओं पर रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारी की तैनाती की जानकारी दी। साथ ही यह भी दावा किया कि घटनाओं में कमी आई है और काफी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। हालांकि वह कोई संख्या नहीं बता पाए कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है। हरियाणा ने भी पराली पर रोकथाम के लिए और ज्यादा टीमें उतारने की जानकारी दी। दिल्ली ने प्रदूषण पर रोकथाम के लिए तीन सौ टीमें उतारने की बात कही। इनके अतिरिक्त करीब 50 टीमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी उतारी हैं।

इस दौरान पीएमओ ने दिल्ली को भी सख्त लहजे में चेताया कि वह सुनिश्चित करे कि कचरा जलाने का एक भी मामला सामने नहीं आए। साथ ही टीमों को प्रदूषण के मामलों की सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं बल्कि कार्रवाई का भी अधिकार दिया जाए। इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया।

इससे पहले प्रदूषण पर सख्त कदम उठाने को लेकर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने भी सोमवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ एक बैठक की। इसमें उन्होंने तीनों राज्यों से योजना के अमल का ब्योरा मांगा। साथ ही पूछा कि जब योजना तैयार थी, तो फिर चूक कहां हुई।

मनोहर विधायकों संग पैदल पहुंचे विधानसभा

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण पर पड़ोसी राज्य जहां एक दूसरे को घेरने में जुटे हैं, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की मंशा से अपने सभी 39 भाजपा विधायकों के साथ पैदल हरियाणा विधानसभा पहुंचे। सीएम निवास से विधानसभा की दूरी डेढ़ किलोमीटर के आसपास है। अपने सरकारी निवास से पैदल निकले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'पर्यावरण बचाओ-भविष्य बनाओ' का नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए। यह न केवल उन्हें अच्छे स्वास्थ्य में मदद करेगा, बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ और हरा-भरा बनाएगा। फसल अवशेष जलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जागरूकता के चलते हरियाणा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

मास्क पहने फोटो पोस्ट करने पर प्रियंका चोपड़ा हुईं ट्रोल

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने पर सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो पोस्ट करने को लेकर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा फिर ट्रोल हुई हैं। यूजर ने अभिनेत्री की आलोचना करने के साथ ही उन्हें भविष्य में सिगरेट नहीं पीने की सलाह भी दे डाली।

दरअसल, प्रियंका इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'द व्हाइट टाइगर' की शूटिंग दिल्ली में कर रही हैं। उन्होंने अपनी मास्क लगाए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। प्रियंका का मास्क खास तरह का है, जिसमें एयर प्योरीफायर लगा है। प्रियंका ने इस तस्वीर को साझा करते हुए प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने लिखा, 'द व्हाइट टाइगर' की शूटिंग का दिन। यहां शूट करना बहुत मुश्किल है। मैं यह सोच भी नहीं सकती कि इन परिस्थितियों में यहां कैसे रह सकते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास एयर फ्यूरिफायर और मास्क है। जो बेघर हैं उनके लिए प्रार्थना करें। सुरक्षित रहें।

जैसे ही प्रियंका ने यह तस्वीर शेयर की वह ट्रोल होने लगीं। एक यूजर ने लिखा, 'दीदी को शादी पर पटाखे भी फोड़ने हैं, दीदी को सिगरेट पीना है और दीदी मास्क पहनकर फोटो डालती हैं। ऐसे कैसे चलेगा दीदी।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सही बात है दीदी आपकी। अब अस्थमा कैसा है आपका? बाकी सिगरेट मत पीना इस टाइम।' एक और यूजर ने लिखा, 'यह लाइनें तब भी याद रखें जब स्मोकिंग करती हैं।' दरअसल, इस वर्ष मियामी में प्रियंका के जन्मदिन पर उनकी, निक और प्रियंका की मां की सिगरेट पीते तस्वीर वायरल हुई थी, तब भी ट्रोलर्स ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई थी। पहले भी 'द स्काई इज पिंक' की शूटिंग के दौरान भी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से प्रियंका और फरहान ने मास्क लगाई हुई तस्वीर साझा की थी।

मास्क पहने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। ट्विटर

प्रियंका गांधी ने लंदन स्मॉग की दिलाई याद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़े हालात को लेकर मची हायतौबा के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानून बनाने का सुझाव दिया है। लंदन स्मॉग की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि वहां 1952 में भयंकर स्मॉग में 12 हजार लोगों की जान चली गई थी। लाखों लोग बीमार पड़ गए थे। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद लंदन में साफ हवा के लिए कानून पास हुआ। उनका इशारा सरकार से हवा को साफ करने के लिए ऐसे ही कड़े कदम उठाने को लेकर था।

भारतीयों की डेढ़ साल तक उम्र कम कर रहा वायु प्रदूषण

हवा में फैला प्रदूषण न सिर्फ आपके दिल और फेफड़ों को बीमार कर रहा है बल्कि आपकी उम्र भी कम कर रहा है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के मुताबिक, हवा में घुल चुके प्रदूषण से किसी भारतीय की उम्र डेढ़ साल तक कम हो जाती है। इस मामले में बांग्लादेश पहले और मिस्र दूसरे स्थान पर है।

जानलेवा हैं कण

अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन से पता चलता है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले 2.5 माइक्रोन से छोटे कण (पीएम) फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं और इससे दिल का दौरा पड़ने, स्ट्रोक्स, सांस संबंधी बीमारियां तथा कैंसर होने का खतरा होता है। पीएम 2.5 प्रदूषण बिजली संयंत्रों, कारों और ट्रकों, आग, खेती और औद्योगिक उत्सर्जन से होता है।

कम होती जीवन प्रत्याशा (वर्ष में)

बांग्लादेश	1.87
मिस्र	1.85
नाइजर	1.80
तजाकिस्तान	1.70
अफगानिस्तान	1.67
नेपाल	1.59
पाकिस्तान	1.56
भारत	1.53
सुडान	1.51
यूएई	1.51

पंजाब में पिछले साल के मुकाबले एक ही दिन सात गुना जली पराली

आशा मेहता, लुधियाना : पंजाब में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर होने के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला जारी है। पिछले दो दिनों में पराली जलाने के मामलों ने पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 4 नवंबर को पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने के मामलों में सात गुणा और 3 नवंबर को तीन गुणा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हैरानी की बात है कि पराली जलाने की सर्वाधिक घटनाएं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के जिला पटियाला, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के जिला बठिंडा, सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के संसदीय क्षेत्र फिरोजपुर और सांसद भगवंत मान के संसदीय क्षेत्र संगरूर में दर्ज की गई हैं। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा ली गई सेटेलाइट तस्वीरें इसकी पुष्टि करती हैं।

मुख्यमंत्री ने जताया दुख

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महिला तहसीलदार की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक अधिकारी ने बताया कि सीएम ने घटना की जानकारी होने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारियों से बात की और हमलावर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

हमलावर बोला, मेरे साथ अन्याय हुआ: एक जांच अधिकारी ने कहा कि सुरेश ने पुलिस को बताया कि वह एक किसान है और अचल संपत्ति के साथ ही सात एकड़ कृषि भूमि का मालिक है। इसमें उसका भाई भी हिस्सेदार है। कुछ समय पहले उसने कृषि भूमि को बटाई पर दिया था, लेकिन बाद में विवाद पैदा हो गया। इससे संबंधित मुकदमा हाई कोर्ट में लंबित था। उसने दावा किया कि भूमि विवाद मामले में उसके साथ अन्याय हुआ था।

चैंबर से सुनाई दी तेज आवाज: एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक चैंबर से एक तेज आवाज सुनाई देने के बाद दफ्तर के अन्य कर्मचारी तहसीलदार के चैंबर की तरफ भागे जहां पर लोगों ने महिला अधिकारी को आग की लपटों में घिरा देखा।

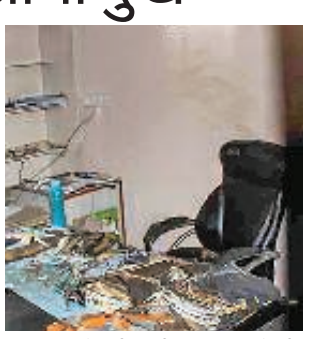

अब्दुल्लापुरमेट की तहसीलदार विजया रेड्डी का दफ्तर, जहां उन्हें जिंदा जलाया गया। प्रेट्र

> सभ्य समाज में इस तरह की घटना अस्वीकार्य है। हम सुनिश्चित करेंगे कि दोषी को कठोर से कठोर सजा मिले।
> -एम महेंद्र रेड्डी, डीजीपी

कर्मचारियों ने किया विरोध-प्रदर्शन : इस घटना के बाद तहसीलदार कार्यालय में अफरातफरी मच गई और अपने काम के लिए लिए आए लोगों के साथ धक्का-मुक्की हुई। घटना से गुस्साए कर्मचारियों ने न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया।

खोखले साबित हुए कृषि मंत्रालय के दावे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ पंजाब व हरियाणा में खूब जली पराली, एनसीआर में नहीं घटा प्रदूषण

▸ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से मांगा सहयोग

पराली प्रबंधन में राज्यों की नाकामी का ठीकरा कृषि मंत्रालय के माथे पर फूट रहा है। ठंड शुरू होने से पहले किए गए उसके दावे खोखले साबित हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धान की पराली जलाने की घटनाओं में मामूली कमी जरूर आई है, लेकिन एनसीआर में प्रदूषण कम नहीं हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि पराली जलाने की घटनाओं में कमी आने के बावजूद प्रदूषण कम नहीं हुआ है। उन्होंने राज्यों से सहयोग की अपील की है।

कृषि मंत्री तोमर ने राष्ट्रीय राजधानी प्रक्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण की समस्या को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि केंद्रीय योजनाओं के चलते पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। तोमर सोमवार को यहां कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के एक समारोह में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के लिए केवल पराली का जलना ही जिम्मेदार नहीं है। राज्य सरकारों से प्रदूषण बढ़ाने वाले अन्य कारकों का भी पता लगाना चाहिए।

दिल्ली समेत एनसीआर में 27 अक्टूबर को दिवाली के बाद से ही धूल और धुएं की मोटी चादर छाई हुई है। वर्ष 2018 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दिल्ली से लगे राज्यों के किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। इसमें किसानों को नई तरह की कृषि मशीनरी मुहैया कराई जा रही है, जो खेतों में बची पराली को हटाने में मदद करेगी। तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसानों को सब्सिडी दी गई।

कृषि मंत्रालय ने अगस्त माह में ही पराली प्रबंधन में अव्वल काम करने का दावा करते हुए एक लिखित बयान जारी किया था। उसके मुताबिक फसल अवशेष प्रबंधन के लिए लगभग 900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ किसानों को दिया गया। इसमें हैप्पी सीडर को जादू की छड़ी की तर्ज पर पेश किया गया। दावा किया गया है 'हैप्पी सीडर को 25 लाख किसानों तक पहुंचाकर पराली जलाने पर पूर्ण रोक लगाई जा सकेगी। फसलों की उत्पादकता में 10 फीसद तक वृद्धि की जा सकेगी। खेती की लागत में कमी आ जाएगी।'

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) का दावा है कि जागरूकता के चलते पंजाब व हरियाणा के 4,500 से ज्यादा गांवों को शून्य पराली जलाने वाले गांवों के रूप में घोषित किया गया है। इसके विपरीत पंजाब के चार जिले फिरोजपुर, पटियाला, संगरूर और तरनतारन पराली जलाने में सबसे आगे रहे हैं। इसी तरह हरियाणा में कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद में पराली जलाने वाले काबू से बाहर रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के पराली के बाबत किसानों को सब्सिडी देने के बयान से तोमर ने असहमति जताई। उन्होंने कहा 'राज्यों को इस बारे में एक सफल नमूना पेश कर बात करनी चाहिए। चालू वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र ने पंजाब को 248 करोड़, हरियाणा को 175 करोड़ और उत्तर प्रदेश को 97.54 करोड़ रुपये की मदद दी है।

मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र

कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर योजनाओं पर उचित तरीके से अमल करने को कहा है। उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकारें इस दिशा में पहल करेंगी। प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर तोमर ने कहा 'प्रदूषण के लिए केवल एक व्यक्ति या एक समुदाय जिम्मेदार नहीं हो सकता है, इस समस्या से उबरने के लिए सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए।'

कॉरिडोर पर पाक की साजिश की आशंका, पंजाब अलर्ट : कैप्टन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▸ कहा, इमरान के शपथ ग्रहण से पहले ही बाजवा ने कैसे कह दी कॉरिडोर की बात

भारत और पाकिस्तान 9 नवंबर को जहां करतारपुर कॉरिडोर खोलने की तैयारियों में जुटे हैं वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुनः आशंका जताई है कि पाकिस्तान द्वारा कॉरिडोर खोलने का फैसला गहरी साजिश के तहत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली थी कि पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू से करतारपुर कॉरिडोर खोलने का विचार चलने की बात कह दी। क्या सेना प्रमुख को सपना आ रहा था कि सरकार यह कदम उठाएगी।

अमरिंदर ने कहा कि पंजाब पूरी तरह अलर्ट है। पड़ोसी देश सिखों की भावनाओं की सहानुभूति लेकर भाईचारे में दरार पैदा करना चाहता है। पंजाबियों को खास तौर पर चौकस रहने की जरूरत है क्योंकि यह सरहदी क्षेत्र है। गुरुद्वारों के दर्शन को लेकर सिख 70 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। इतने वर्षों तक तो पाकिस्तान ने कभी इतना प्यार नहीं दिखाया। निश्चित रूप से यह आइएसआइ का एजेंडा है जिसका उद्देश्य रेफरेंडम-2020 के लिए सिख भाईचारे को प्रभावित करना है और इसे खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी उम्मीद कम ही है कि कॉरिडोर के जरिये पाकिस्तान कोई गलती करने की हिम्मत जुटा पाएगा, लेकिन हमें चौकन्ना रहने की आवश्यकता है।

एनएसजी व एनडीआरएफ की टीमें पहुंचीं पंजाब

पंजाब सरकार की मांग पर एनएसजी और एनडीआरएफ की पांच-पांच टीमें पंजाब पहुंच गई हैं। एनएसजी जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी को देखेगी वहीं, एनडीआरएफ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो, इसकी जिम्मेदारी उठाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सतीश चंद्रा ने इसकी पुष्टि की है।

आयोजन

कोलकाता में आठ नवंबर तक चलेगा आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित, देश-विदेश के 12 हजार प्रतिभागी लेंगे भाग

भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आज से

जागरण संवाददाता, कोलकाता

मंगलवार से कोलकाता में चार दिवसीय भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आइआइएसएफ) 2019 का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए महोत्सव के शुभारंभ को संबोधित करेंगे। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विभागों तथा विज्ञान भारती (विभा) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जाने वाला यह वार्षिक महोत्सव 5 से 8 नवंबर तक चलेगा। इस महोत्सव में देश-विदेश के करीब 12 हजार प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। विज्ञान महोत्सव की प्रमुख गतिविधियां मुख्य रूप से कोलकाता से सटे राजारहाट न्यूटाउन के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर और साइंस सिटी में आयोजित की जा रही है। महोत्सव के दौरान कुछ कार्यक्रम कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीच्यूट, बोस इंस्टीच्यूट और इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ केमिकल बायलॉजी में भी आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव के दौरान 28 से अधिक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे।

यह है कार्यक्रम

5 नवंबर : खगोल भौतिकी विषय सबसे बड़ा शिक्षण कार्यक्रम होगा जिसमें 1,750 से ज्यादा विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।
6 नवंबर : इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा शिक्षण कार्यक्रम होगा और इसमें 950 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।
7 नवंबर : एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा रेडियो किट असेंबलिंग का रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें 400 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।
8 नवंबर : मानव गुणसूत्र का सबसे बड़ा मानवीय चित्र बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी 400 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।

स्टूडेंट साइंस विलेज : विज्ञान महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण स्टूडेंट साइंस विलेज है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों के करीब 2500 स्कूली विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है। इन छात्रों को संसद सदस्यों ने अपने संसदीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चुने गए गांवों से नामांकित किया है। स्टूडेंट साइंस विलेज में शामिल होने के लिए प्रत्येक संसद सदस्यों को पांच छात्रों और एक शिक्षक को नामित किया है।

युवा वैज्ञानिक सम्मेलन : विज्ञान महोत्सव का दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम युवा वैज्ञानिक सम्मेलन है, जिसमें सर्वाधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम में करीब 1500 युवा वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल हो सकते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों से सीधा संवाद कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें अपने पोस्टर और शोध आलेख प्रस्तुत करने का मौका भी मिलेगा। विज्ञान महोसत्व में लगने वाली प्रदर्शनियां भी आकर्षण का केंद्र होंगी।

पुस्तक मेले का आयोजन : विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में पुस्तक मेले का आयोजन भी किया जाएगा। 'विज्ञानिका' नामक विज्ञान साहित्य समारोह इस वर्ष के आइआइएसएफ का एक अन्य आकर्षण होगा, जिसके अंतर्गत विज्ञान संचार की अनेक विधाओं से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस महोत्सव में प्रमुख महिला वैज्ञानिकों और उद्यमियों की विशेष भूमिका होगी।

परमजीत सिंह सरना को मिली पाकिस्तान जाने की अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : भारत-पाक अटारी सीमा पर रोके गए शिरोमणि अकाली दल (दिल्ली) के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना को ननकाना साहिब की यात्रा के लिए पाकिस्तान जाने की दिल्ली हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने सरना के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को निलंबित करते हुए उन्हें हर हाल में 16 नवंबर या इससे पहले वापस लौटने का आदेश दिया। पीठ ने गृह और विदेश मंत्रालय के साथ ही दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा से मामले पर जवाब मांगा है। गुरु नानक देव की 550वें प्रकाशपर्व पर सरना अटारी सीमा के माध्यम से पाकिस्तान जा रहे थे। धार्मिक जुलूस का नेतृत्व कर रहे सरना को इमिग्रेशन अधिकारियों ने इस आधार पर पाक जाने से रोक दिया था कि वह 2012 में दिल्ली में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में आरोपित हैं। पीठ ने याचिका पर अधिकारियों से जवाब मांगते हुए सुनवाई को 22 जनवरी के लिए स्थगित कर दी।

ब्रिटेन से पाकिस्तान पहुंचा सिख श्रद्धालुओं का जत्था

इस्लामाबाद, आइएएनएस : सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानकदेव की आगामी 550वीं जयंती पर पंजाब प्रांत के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में आयोजित होने वाले समारोह में हिस्सा लेने के लिए 178 सदस्यीय सिख प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन से पाकिस्तान पहुंच गया है।

डॉन न्यूज ने सोमवार को बताया कि रविवार को पहुंचने के तुरंत बाद, 178 सदस्यीय समूह गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहिब और शेखूपुरा जिले के गुरुद्वारा सच्चा सौदा के लिए रवाना हो गया। पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने घोषणा की है कि बाबा गुरुनानक की जयंती समारोह पूरे नवंबर भर जारी रहेगा। भारत के साथ-साथ यूरोप और उत्तरी अमेरिका के सिख तीर्थयात्री इस संबंध में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पंजाब इवैक्यूई ट्रस्ट बोर्ड के प्रवक्ता आमेर हाशमी ने कहा कि मुख्य कार्यक्रम 12 नवंबर को करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में होगा। इस बीच, सोने की पालकी के साथ करीब 1,100 सिख तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 31 अक्टूबर को वाघा बॉर्डर से होकर यहां पहुंचा। मंगलवार को करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में पालकी स्थापित की जाएगी। इस बीच, करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन शनिवार को किया जाएगा। यह कॉरिडोर भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को धर्मस्थल की यात्रा करने के लिए पाकिस्तान जाने की सुविधा प्रदान करेगा। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, जिसे मूल रूप से गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है, सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां गुरुनानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।

▸ आज गुरुद्वारे में सोने की पालकी होगी स्थापित

▸ शनिवार को होगा कॉरिडोर का उद्घाटन

49 बुद्धिजीवियों के विरुद्ध दर्ज केस के मामले में अब 13 नवंबर को सुनवाई होगी। मामला उन्मादी हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से संबंधित है। इनमें अपर्णा सेन भी शामिल हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में यह मामला दर्ज किया गया था।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 5 नवंबर 2019

करवरिया बंधुओं सहित चार को आजीवन कैद

फैसला ▶ 23 साल पहले प्रयागराज में पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित सहित तीन की हुई थी हत्या

सभी अभियुक्त लगभग चार साल से जेल में बंद हैं, 7 .20 लाख का जुर्माना भी लगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

बहुचर्चित पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ पंडित हत्याकांड में सोमवार को सजा सुनाई गई। प्रयागराज के अपर जिला जज (एडीजे) पंचम बद्री विशाल पांडेय ने पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, उनके भाइयों पूर्व विधायक उदयभान व पूर्व एमएलसी सूरजभान व फुफेरे भाई रामचंद्र मिश्रा उर्फ कल्लू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। सभी पर कुल 7.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। विभिन्न धाराओं में सुनाई गई सजा एक साथ चलेगी। सभी अभियुक्त लगभग चार साल से जेल में बंद हैं। हत्याकांड 23 साल पहले हुआ था।

31 अक्टूबर को अदालत ने सभी को इस मुकदमे में दोषी ठहराया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए चार नवंबर की तिथि तय की थी। चार नवंबर यानी सोमवार को अदालत की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही एडीजे पंचम की कोर्ट में तमाम अधिवक्ता पहुंच गए। दोपहर लगभग पौने तीन बजे सभी आरोपितों को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद अदालत के सामने बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कम से कम सजा देने और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने अधिक से अधिक सजा देने के तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों के तर्क सुनने और पत्रावली देखने के बाद कोर्ट ने 227 पेज के निर्णय में आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इनकी हुई थी हत्या...

जवाहर यादव उर्फ पंडित

-1996 में 32 वर्ष की उम्र में हत्या। **शिक्षा** : इंटरमीडिएट

राजनीतिक सफर : 1991 में झूंसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, मगर हार गए। 1993 में झूंसी विधानसभा से सपा के टिकट पर जीते। मूलरूप से जौनपुर के बक्शा इलाके के खैरपारा गांव निवासी जवाहर पंडित प्रयागराज के अशोक नगर में रहते थे। उनकी पत्नी तीन बार विधायक रहीं। भाई सुलाकी यादव भी पार्षद थे।

जवाहर यादव। फाइल

यह थी घटना

13 अगस्त 1996 की शाम प्रयागराज स्थित सिविल लाइंस में एके 47 जैसे हथियारों से गोली मारकर पूर्व विधायक जवाहर पंडित सहित तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। फायरिंग में दो राहगीर भी जख्मी हुए थे। जवाहर के भाई सुलाकी यादव की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया था। सीबीसीआइडी लखनऊ ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था, जिस पर अब तक मुकदमा चल रहा था। इस बीच राज्य सरकार ने मुकदमा वापस लेने की संस्तुति भेजी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आरोपितों को सेशन कोर्ट व हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी।

किस धारा में कितनी सजा व जुर्माना

धारा 302/149 : प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व हर पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना। जुर्माने की राशि न देने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास।

धारा 307/149 : प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न देने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास।

धारा 147 : प्रत्येक को दो-दो वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास।

धारा 148 : प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माने की राशि न देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास।

7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम : छह-छह माह का कारावास।

इन्हें हुई सजा

कपिलमुनि करवरिया

उम्र : 55 वर्ष, **शिक्षा** : विधि स्नातक

राजनीतिक सफर : सबसे पहले कौशांबी के जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। फिर 2009 में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव जीते। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से दोबारा मैदान में उतरे, मगर हार गए।

कपिलमुनि करवरिया। फाइल

उदयभान करवरिया

उम्र : 50, **शिक्षा** : इलेक्ट्रानिक्स में बीटेक

राजनीतिक सफर : 1997 में कौशांबी के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। इसके बाद भाजपा के टिकट पर बारा सीट से 2002 में विधायक चुने गए। 2007 में भी बारा से ही विधायक बने। 2012 में शहर उत्तरी विधानसभा सीट से चुनाव हारे। बारा सीट सुरक्षित होने पर उन्हें क्षेत्र बदलना पड़ा था।

उदयभान करवरिया। फाइल

सूरजभान करवरिया

उम्र : 48, **शिक्षा** : स्नातक

राजनीतिक सफर : ब्लॉक स्तर पर राजनीति शुरू की। 2005 में क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीते। उसके बाद कौशांबी के मंझनपुर ब्लॉक के प्रमुख बने। 2007 में एमएलसी बने तो ब्लॉक प्रमुख का पद छोड़ दिया। अपने चचेरे भाई शेष नारायण करवरिया को मंझनपुर का ब्लॉक प्रमुख बनवा दिया।

सूरजभान करवरिया। फाइल

रामचंद्र मिश्र उर्फ कल्लू

उम्र : 66 वर्ष, **शिक्षा** : परास्नातक पेशा : पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौसपुर, कौशांबी में अध्यापक थे, फिर प्रधानाध्यापक हुए। बाद में वीआरएस ले लिया था। सियासत में नहीं उतरे। पूर्व सांसद कपिलमुनि की बुआ के बेटे हैं। कपिलमुनि के करीबी माने जाते हैं।

ठहरो! हमारी जमीन पर है यह सड़क टैक्स देना होगा

सुजीत सरकार, पूर्वी सिंहभूम

- झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में सड़क पर भारी वाहनों से अब पैसा वसूलेंगे विस्थापित
- आरोप-सरकार ने सड़क बनाने के लिए इनकी जमीन तो ले ली पर मुआवजा नहीं दिया

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मुआवजा न मिलने पर भू-स्वामियों ने विरोध का अनूठा तरीका अपनाया है। आरोप है कि सरकार ने सड़क बनाने के लिए इनकी जमीन तो ले ली, पर मुआवजा नहीं दिया। इस कारण विस्थापितों ने खुद यह कदम उठाया है। यहां मऊभंडार किताडीह रेलवे फाटक होकर फुलपाल एनएच 33 तक जाने वाले भारी वाहनों को आठ नवंबर से 100 रुपये शुल्क देना होगा। इसके लिए मऊभंडार विस्थापित रैयतदार बेरोजगार समिति गठित की गई है। घाटशिला एसडीओ के आवास से कुछ दूरी पर इस समिति ने सड़क किनारे बोर्ड लगाकर 8 नवंबर से शुल्क वसूली शुरू करने की बात कही है। वहीं इस मामले से प्रशासन अब तक अनजान है। इस क्षेत्र में यह पहला मामला होगा जब सड़क से गुजरने के लिए वाहनों से विस्थापित पैसा वसूलेंगे।

समिति में 17 भू-स्वामी शामिल हैं। इनका दावा है कि अंबेडकर चौक से फुलपाल तक बनी सड़क रैयती जमीन पर बनी है। पूर्व में यह जमीन एचसीएल आइसीसी कारखाना के वाहनों के लिए दी गई थी। अब इस पर बड़े वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। इससे दुर्घटनाएं होने लगी हैं। प्रशासन से कई बार बड़े वाहनों का परिचालन रोकने की मांग की गई, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। पथ निर्माण विभाग ने गलत ढंग से निजी जमीन पर सड़क बनवा दी है। विस्थापितों का दावा है कि पथ निर्माण विभाग के पास जमीन संबंधित कोई कागजात नहीं है।

सड़क पर बड़े वाहन चलाने के एवज में शुल्क लेने के लिए बोर्ड लगाए जाने की जानकारी नहीं है। अगर किसी ने इस तरह का बोर्ड लगाया है तो उसकी जांच कराई जाएगी। इस तरह बोर्ड लगाना गलत है। इसकी जांच कराई जाएगी।

-अमर कुमार, एसडीओ, घाटशिला

सड़क पर मालिकाना हक रैयतदारों का है। जमीन हमारी है। बड़े वाहनों से शुल्क लेने की जानकारी पूर्व में जिला उपायुक्त व अन्य पदाधिकारियों को दी गई है। प्रशासन इस पर रोक लगाएगा तो उसे पहले सड़क पर भारी वाहनों का परिचालन बंद कराना होगा।

-सुदीप्तो हांसदा, अध्यक्ष, मऊभंडार विस्थापित रैयतदार बेरोजगार समिति

डीसीबी चेयरमैन पर कार्रवाई का रास्ता तय करेगी फॉरेंसिक रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

चिन्मयानंद प्रकरण

चिन्मयानंद प्रकरण में साक्ष्य इकट्ठे करने में जुटे विशेष जांच दल (एसआइटी) ने जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) के चेयरमैन डीपीएस राठौर का लैपटॉप व एक पेन ड्राइव कब्जे में ली है। जिसे जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) लखनऊ भेज दिया गया। अब वहां से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय हो सकेगी।

एसआइटी ने शनिवार को डीसीबी चेयरमैन डीपीएस राठौर से पूछताछ की थी। शक था कि चिन्मयानंद से रंगदारी व छात्रा से दुष्कर्म प्रकरण में उनके पास कुछ वीडियो व फोटो हो सकते हैं। इसी आधार पर उनसे शनिवार रात से रविवार तड़के तक पूछताछ की जाती रही थी। उसी रात को उनका लैपटॉप व पेन ड्राइव भी एसआइटी ने जब्त कर ली। रविवार को दोनों का डाटा खंगाला तो उनमें इस प्रकरण से जुड़े फोटो या वीडियो नहीं मिले। ऐसे में अब लैपटॉप व पेन ड्राइव जांच के लिए लखनऊ भेजी गई है। जांच में पता चल सकेगा कि लैपटॉप या पेन ड्राइव से कोई डेटा डिलीट किया गया कि नहीं। यदि वीडियो, फोटो डिलीट किए जाने की पुष्टि हुई तो उसे रिकवर कराने की कोशिश होगी।

फिलहाल, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि डीसीबी चेयरमैन की इस मामले में क्या भूमिका है। प्रकरण में रविवार को एक पूर्व विधायक से भी पूछताछ की गई थी।

चश्मा अब तक नहीं मिला : एसआइटी इस मामले से जुड़े हर शख्स से पूछताछ कर चुकी, मगर वह चश्मा नहीं मिला जिस पर लगे कैमरे से चिन्मयानंद का वीडियो बनाया गया था। एसआइटी को सात नवंबर को प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करनी है। चश्मा अहम साक्ष्य है, उसका अब तक न मिल पाना छात्रा या चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर असर डाल सकता है। रविवार को पुलिस लाइंस में बने अस्थाई कार्यालय में एसआइटी अपनी रिपोर्ट बनाने में लगी रही। चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह का मोबाइल फोन वापस करने पर मंगलवार को सुनवाई होगी। सोमवार को वकीलों की हड़ताल के कारण तारीख एक दिन के लिए बढ़ा दी गई। ओम सिंह का मोबाइल फोन एसआइटी ने जांच के लिए लिया था। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ओम सिंह ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मोबाइल वापस दिलाने की गुहार लगाई थी, लेकिन उस पर सीजेएम ने पुलिस से रिपोर्ट तलब की थी।

ईओडब्ल्यू ने कब्जे में लिए अहम दस्तावेज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उप्र पीएफ घोटाला

- जेल में दर्ज किए गए आरोपित वित्त निदेशक व महाप्रबंधक के बयान
- बढ़ेगी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की भी धारा

बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों के भविष्य निधि घोटाले की सीबीआइ जांच की सिफारिश करने के साथ ही आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अपनी जांच तेज कर दी है। डीजी ईओडब्ल्यू डॉ. आरपी सिंह ने घोटाले की विवेचना के लिए डीआइजी हीरालाल व एसपी शकीलुज्जमा के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम गठित की है।

ईओडब्ल्यू ने सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के मुख्यालय शक्ति भवन के दूसरे तल स्थित यूपी स्टेट सेक्टर पावर इंप्लाइज ट्रस्ट और यूपीपीसीएल सीपीएफ (कंट्रीब्यूटरी प्रॉविडेंट फंड) ट्रस्ट के सील किए गए कार्यालय को खुलवाकर करीब चार घंटे तक छानबीन की। ईओडब्ल्यू ने ट्रस्ट के सचिव व लेखाधिकारी की मौजूदगी में कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। कई दस्तावेजों को सील भी किया गया है। घोटाले के आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी शिकंजा कसेगा। ईओडब्ल्यू मंगलवार को यूपीपीसीएल के एमडी को प्रार्थनापत्र देकर इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की अनुमति मांगेगा, जिसके बाद एफआइआर में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की जाएगी।

ईओडब्ल्यू ने सोमवार को लखनऊ जेल में निरुद्ध घोटाले के आरोपित पावर कारपोरेशन के तत्कालीन निदेशक वित्त सुधांशु त्रिवेदी और महाप्रबंधक व सचिव ट्रस्ट प्रवीण कुमार गुप्ता से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। ईओडब्ल्यू ने दोनों आरोपितों को सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है। इसके अलावा हजरतगंज कोतवाली में घोटाले की एफआइआर दर्ज कराने वाले सचिव ट्रस्ट आइएम कौशल के बयान भी दर्ज किए गए हैं। ईओडब्ल्यू के विवेचक इंस्पेक्टर दिनेश सिंह समेत अन्य निरीक्षकों ने सोमवार को दिनभर ट्रस्ट के गठन से लेकर कर्मचारियों की भविष्य निधि की रकम निजी कंपनी में निवेश करने तक के सभी दस्तावेजों की गहनता से छानबीन की। माना जा रहा है कि ईओडब्ल्यू कब्जे में लिए गए दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद जल्द ही बिजली विभाग के कई तत्कालीन अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। पूरे मामले में कई बड़ों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

कोटेशन के जरिये डीएचएफसीएल को दी गई रकम : ईओडब्ल्यू ने शुरुआती जांच में ही भविष्य निधि की रकम को निजी कंपनी में ट्रांसफर करने के खेल उजागर होने शुरू हो गए हैं। ईओडब्ल्यू के हाथ एक कोटेशन लगा है, जिसके जरिये भविष्य निधि के अरबों रुपये डीएचएफसीएल में निवेश किए गए। अब ईओडब्ल्यू इस बात की छानबीन में जुट गई है कि आखिर किन नियमों के तहत ऐसा किया गया। कोटेशन में कुछ कंपनियों से ब्याज की दरें लेकर एक कंपनी को चुना गया। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया किन परिस्थितियों में नहीं अपनाई गई।

यह है मामला : बिजलीकर्मियों के जीपीएफ व सीपीएफ के 4122.70 करोड़ों रुपये निजी कंपनी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफसीएल) में असुरक्षित ढंग से निवेश किए गए हैं। मार्च 2017 से दिसंबर 2018 तक यूपी स्टेट सेक्टर पावर इंप्लाइज ट्रस्ट द्वारा जीपीएफ के 2631.20 करोड़ रुपये और यूपीपीसीएल सीपीएफ (कंट्रीब्यूटरी प्रॉविडेंट फंड) के 1491.50 करोड़ रुपये डीएचएफसीएल में फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिए गए थे। इसमें से कुल 1854.80 करोड़ रुपये ही वापस मिल सके हैं। मुंबई हाई कोर्ट द्वारा डीएचएफसीएल के भुगतान पर रोक लगाने के बाद बिजलीकर्मियों के भी 2267.90 करोड़ रुपये फंस गए हैं।

लश्कर कमांडर का कश्मीर में बना भूमिगत ठिकाना ध्वस्त

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- श्रमिक की हत्या, कई लोगों पर हमला करने और दुकान जलाने के मामलों में था वांछित

सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में आतंक का पर्याय बने लश्कर-ए-तैयबा के डिवीजनल कमांडर सज्जाद हैदर उर्फ अबु हैदर के ठिकाने को तबाह करने का दावा किया है। हालांकि ठिकाने से कोई आतंकी नहीं मिला, सिर्फ बर्तन, कंबल और कुछ दस्तावेज मिले हैं। फिलहाल, सज्जाद और उसके साथियों को पकड़ने के लिए सुरक्षाबल लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं। सज्जाद ही वही आतंकी कमांडर है जिसने अगस्त माह के दौरान सोपोर में एक बाहरी श्रमिक को गोली मार कर जख्मी करने के अलावा सितंबर के दौरान तीन सेब व्यापारियों के अलावा ढाई साल की बच्ची को गोली मारकर जख्मी किया था। उसने बंद का फरमान न मानने पर दो नागरिकों की गाड़ियों को भी जलाया था। उसके इशारे पर ही बारामुला में दुकानदारों पर हमले हुए थे।

उत्तरी कश्मीर में यह अपनी तरह का पहला ठिकाना: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस ठिकाने को तबाह किया है वह बराथ सोपोर में एक बगीचे में जमीन खोदकर बनाया था। इस तरह के भूमिगत ठिकाने बीते कुछ सालों से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय आतंकी अपने लिए बना रहे थे। उत्तरी कश्मीर में यह अपनी तरह का पहला ठिकाना है। आतंकियों को शायद छापे की भनक लग गई थी। वह समय रहते ही अपने हथियारों संग वहां से भाग निकले थे। उन्होंने बताया कि सज्जाद आतंकी गुट में भर्ती होने वाले नए लड़कों को यहां लेकर आता था। वह उन्हें शुरू में यहीं पर छिपने का ठिकाना देते हुए हथियारों की ट्रेनिंग भी देता था।

ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार, ठिकाने से मिला गोला बारूद : किश्तवाड़ में रविवार को 26 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस के विशेष दस्ते ने अभियान चलाकर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इसके साथ ही एक ओजीडब्ल्यू (ओवर ग्राउंड वर्कर) को भी गिरफ्तार किया है। दो दिन में सुरक्षा बलों की यह दूसरी बड़ी सफलता है। पुलिस ने ओवरग्राउंड वर्कर आसिफ मुस्तफा के घर से पाकिस्तान में बनी पिस्टल, 54 एके-47 की गोलियां, एक हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर पैड बरामद किए।

सुरक्षाबलों ने श्रीनगर शहर के कई क्षेत्र खंगाले

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

ग्रेनेड हमले के बाद पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शहर की विभिन्न सड़कों और चौराहों पर विशेष नाके लगाए गए हैं जहां तैनात सुरक्षाकर्मी संदेह होने पर किसी भी वाहन और उसमें बैठे लोगों की तलाशी ले रहे हैं। लाल चौक, मगरमल बाग, बटमालू, सराईबाला व आसपास के इलाकों में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के छिपे होने की आशंका के आधार पर तलाशी अभियान भी चलाया। श्रीनगर के एसएसपी हसीब मुगल ने कहा, हमलावर आतंकी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। कुछ अहम सुराग जुटाए गए हैं। मृतक रिंकू सहारनपुर, उप्र निवासी है। जहां ग्रेनेड हमला हुआ है, वहां से एसएसपी श्रीनगर के कार्यालय एक किमी की दूरी पर है।

एक माह में पांचवां ग्रेनेड हमला

28 अक्टूबर : बस स्टैंड के नजदीक बाजार में ग्रेनेड हमले में 19 लोग घायल।

26 अक्टूबर : श्रीनगर के ही काकसराय में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर ग्रेनेड हमले में छह जवान घायल।

24 अक्टूबर : कुलगाम में सीआरपीएफ कैंप के बाहर ग्रेनेड फेंका। एक जवान जख्मी।

5 अक्टूबर : अनंतनाग में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर ग्रेनेड हमले में आठ लोग घायल।

श्रीनगर के हरि सिंह हाईस्ट्रीट बाजार में सोमवार को ग्रेनेड हमले के बाद बिखरा रेहड़ी वालों का सामान। हमले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निवासी की मौत हो गई। 38 लोग जख्मी हो गए। हमले के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षाकर्मी। श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जागरण

जम्मू-कश्मीर से बंगाल लौटे 138 श्रमिक

जागरण संवाददाता, कोलकाता : जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा बंगाल (मुर्शिदाबाद) के पांच श्रमिकों की हत्या के बाद दहशत में डूबे बंगाल के 133 श्रमिक राज्य सरकार के प्रयास से सोमवार को घर लौट आए। इसके अलावा असम के भी पांच श्रमिक कोलकाता लौटे। ट्रेन से उतर कर गृह राज्य की मिट्टी पर पैर रखते ही दहशतजदा श्रमिकों के चेहरे पर सुकून दिखा। राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने स्टेशन पहुंचकर श्रमिकों का हालचाल पूछा। श्रमिकों ने कश्मीर में दहशत के माहौल को बयां करते हुए फिर कभी वहां नहीं जाने की बात कही। कश्मीर के कुलगाम में 29 अक्टूबर की रात आतंकवादियों ने मुर्शिदाबाद जिले के सागरदीघी थाना अंतर्गत बहालनगर गांव निवासी कमरुद्दीन शेख (35), मुर्सलीम शेख (45), रफीक अहमद शेख (45), नइमुद्दीन (42) तथा रफीकुल आलम (23) को गोलियों से छलनी कर दिया था। जबकि जहीरुद्दीन शेख नामक श्रमिक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। घटना के बाद कश्मीर नीति को लेकर विरोधी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया था। हत्याकांड के बाद से कश्मीर में बंगाल के श्रमिक आतंकित थे।

दरबार खुलने पर दिखी डोगरा संस्कृति की झलक

राज्य ब्यूरो, जम्मू

केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू में सोमवार सुबह दरबार खुल गया। दरबार खुलने पर पहली बार डोगरा संस्कृति की छाप दिखी। पहले दिन सचिवालय के निकट श्री रणबीरेश्वर मंदिर के बाहर, विक्रम चौक और कच्ची छावनी में कलाकारों ने कुड नृत्य पेश किया। उप राज्यपाल जीसी मुर्मू सुबह साढ़े नौ बजे सचिवालय पहुंचे। सचिवालय में मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहमण्यम, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी ने उपराज्यपाल के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके बाद उपराज्यपाल ने विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर दरबार मूव के प्रबंधों, विकास कार्यों व सुरक्षा हालात समेत अन्य मुद्दों का जायजा लिया।

दरबार खुलने पर सचिवालय के आसपास और अन्य जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हालांकि आज किसी विपक्षी पार्टी का कोई जम्मू बंद नहीं था, लेकिन पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरबार खुलने पर जम्मू में कोई तामझाम नजर नहीं आया, क्योंकि इस समय विधानसभा नहीं है। विधान परिषद पहले ही भंग हो चुकी है। ऐसे में इस समय कोई मंत्री, विधायक या एमएलसी नहीं है। जम्मू में दरबार खुलने के साथ ही जम्मू में राजभवन और अन्य मूव कार्यालय भी खुल गए।

रियासी, भद्रवाह व अन्य पहाड़ी इलाकों का पारंपरिक नृत्य है कुड : दरबार खुलने पर सचिवालय के निकट कलाकारों ने कुड नृत्य से समा बांध दिया। कुड नृत्य जम्मू संभाग के रियासी, भद्रवाह, बनी व अन्य पहाड़ी इलाकों का पारंपरिक नृत्य है। जम्मू कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के अतिरिक्त सचिव अरविंदर सिंह अमन ने कहा कि तीन जगहों पर कार्यक्रम में करीब 50 कलाकारों ने भाग लिया। इससे डोगरा संस्कृति को बढ़ावा मिला। युवाओं को अपनी विरासत से रूबरू होने का मौका मिला।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में दरबार खुलने पर सचिवालय में केवल तिरंगा फहराता दिखा। अनुच्छेद 370 हटने से पूर्व सचिवालय में दो झंडे फहराए जाते थे। जागरण

नई पारी

चुपचाप काम करने वाले लीगल स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट हैं उपराज्यपाल, जनजीवन सामान्य करना और विकास को प्रोत्साहन की बड़ी जिम्मेदारी

उपराज्यपाल मुर्मू की चुनौतियां शुरू, आतंकवाद सबसे आगे

राज्य ब्यूरो, जम्मू

केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को कूटनीतिक विशेषज्ञ माना जाता है। हालांकि, राज्य की समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। इसमें आतंकवाद से लड़ाई सबसे अहम है। उन्हें राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को शुरू कराने, विधानसभा चुनावों के लिए जमीन तैयार करना, संभागीय पक्षपात को दूर करना और आतंकवाद पर काबू पाते हुए गुमराह युवकों को मुख्यधारा में शामिल करने जैसी समस्याओं से निपटना होगा। इसके अलावा कश्मीर में सामान्य जनजीवन को पूरी तरह बहाल कर विकास व रोजगार को प्रोत्साहित करना भी उनकी जिम्मेदारी होगी।

पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पहले उपराज्यपाल जीसी मुर्मू को चुपचाप काम करने वाला नौकरशाह माना जाता है। यही नहीं, उन्हें कूटनीति बनाने में माहिर भी माना जाता है। कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार आसिफ कुरैशी ने कहा कि मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी हैं। मुर्मू को अच्छी तरह पता है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री क्या चाहते हैं। यहां तीन महीने से बंद जैसा माहौल है, निजी क्षेत्र से जुड़े सैकड़ों लोगों का रोजगार समाप्त हो चुका है, व्यापारी वर्ग परेशान है। वह यहां बाजार कितनी जल्द खुलवाते हैं, रोजगार के अवसर कैसे पैदा करते हैं और बाहर से निजी पूंजी निवेश को किस हद तक आकर्षित कर पाते हैं, यह उनकी प्रशासनिक कार्यकुशलता पर निर्भर करेगा।

कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ मुख्तार अहमद बाबा ने कहा कि जीसी मुर्मू को मोदी-शाह के कश्मीर मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मिशन के तहत उन्हें पहले यहां हालात सामान्य बनाने और फिर राजनीतिक गतिविधियों बहाल कराना है। जब तक यहां मुख्यधारा की राजनीतिक गतिविधियां शुरू नहीं होंगी, तब तक विधानसभा का गठन बहुत मुश्किल है। मौजूदा हालात में नेकां, पीडीपी, पीपुल्स कांफ्रेंस जैसे दलों को बदले समीकरणों में फिर से सियासत करने के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात में उनके लिए यहां नए राजनीतिक चेहरों और संगठनों को तैयार करना जरूरी हो जाएगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले ही कई बार कह चुके हैं कि कश्मीर में एक नया राजनीतिक नेतृत्व शुरू होगा।

मुर्मू से लोगों को बड़ी उम्मीद : फ्रेंड्स ऑफ साउथ एशिया नामक संगठन के संयोजक सलीम रेशी ने कहा कि मुर्मू से लोगों को बहुत उम्मीद हैं। उन्होंने गत शनिवार को बारामुला व अनंतनाग का दौरा किया। इसके पूर्व सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में प्राथमिकताएं गिनाईं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वह अपने एजेंडे को लेकर बहुत स्पष्ट हैं। कश्मीर में आतंकवाद पर काबू पाना, नए लड़कों की आतंकी संगठनों में भर्ती रोकना उपराज्यपाल के लिए सबसे अहम है। अगर वह युवाओं की आतंकी भर्ती पर रोक लगाने में कामयाब रहते हैं तो उनकी अन्य चुनौतियां भी आसानी से पूरी होंगी।

गुजरात में कई मुद्दों पर दिखा चुके काबिलियत : कश्मीर मामलों के एक विशेषज्ञ ने बताया कि जीसी मुर्मू ने अपनी काबिलियत का परिचय इशरत जहां मुठभेड़ कांड, गुजरात दंगों और अमित शाह स्नूपगेट में दिया है। इसलिए उन्हें यहां भेजा गया है।

नागरिक सचिवालय जम्मू में गार्ड आफ ऑनर का निरीक्षण करते जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू। जागरण

ऐसे तय हुए काम के आठ घंटे

औद्योगिक क्रांति के समय कर्मचारी दिन में लगभग 10-16 घंटे काम किया करते थे। 25 सितंबर, 1926 को, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड ने फैक्ट्रियों के काम करने वाले लोगों के लिए हफ्ते में पांच दिन और रोज आठ घंटे काम करने की योजना पहली बार लागू की थी। इसके बाद अमेरिकी संसद (कांग्रेस) ने 1938 में हफ्ते में 44 घंटे के साथ फेयर लेबर स्टैंडर्ड एक्ट पारित किया। 24 अक्टूबर, 1940 को आठ घंटे आखिरकार दुनिया भर के विभिन्न उद्योगों में एक मानक समय में बन गया।

भारत में शुरुआत

बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत में रोज 12 घंटे से आठ घंटे काम करने की योजना लागू कराने में बाबा साहेब आंबेडकर की बड़ी अहम भूमिका थी। उन्होंने 27 नवंबर, 1942 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव रखा था। इस सम्मेलन में शामिल केंद्र और प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधि, नियोक्ता और श्रमिक संगठनों ने सर्वसम्मति से सप्ताह में 48 घंटे के सिद्धांत का समर्थन किया था।

ऐसे बना कानून

आजादी के बाद कारखाना अधिनियम 1948 लागू होने के बाद रोज काम करने के आठ घंटे निर्धारित किए गए। इस अधिनियम के तहत आठ घंटे से ज्यादा काम करने पर अतिरिक्त मजदूरी देने का प्रावधान भी शामिल था। साथ ही कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन अवकाश देने का भी प्रावधान था। 1987 में इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया।

1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसके जनाजे की नमाज भी इसी मस्जिद में पढ़ी गई थी। बाद में उसका शव काबुल ले जाकर दफनाया गया।

रुदौली स्थित विश्व प्रसिद्ध मखदूम साहब की मजार। जागरण

सरयू में खड़े होकर मखदूम साहब ने की थी तपस्या

प्रहलाद तिवारी, अयोध्या : अयोध्या से सटे रुदौली में भी सदियों से सद्भाव की बयार बह रही है। सद्भाव की यह अलख करीब 600 वर्ष पूर्व सूफी संत मखदूम साहब ने जगाई थी। उनके इसी सद्भाव ने रामनगरी और हक की नगरी (रुदौली तब बाराबंकी) के रिश्तों को मजबूती प्रदान की थी। नगर स्थित हजरत शेख मखदूम अहमद अब्दुल हक की दरगाह विश्व में साबरी श्रृंखला का सबसे प्रमुख केंद्र है। मखदूम साहब हर धर्म का सम्मान करते थे। उनकी राम व रहीम में बराबर श्रद्धा थी। सरयू से उनका अगाध प्रेम था। उन्होंने अपनी तपस्या के लिए सरयू नदी को ही चुना। मखदूम साहब ने अयोध्या में मोक्षदायिनी सरयू नदी में एक पैर पर खड़े होकर 40 दिन तक तपस्या की थी। दरगाह के सज्जादा नशीन नैयर मियां बताते हैं कि जिस घाट पर उन्होंने तपस्या की थी, वह काफी दिन तक मखदूम घाट के नाम से जाना गया। उनकी तपस्या का फल रहा कि हजरत अली की तरफ से बतौर इनाम दुआ-ए-हैदरी प्राप्त हुई। मखदूम साहब ईश्वर की इबादत में हमेशा लीन रहते थे। सूफियों का मकसद अमन और प्रेम होता है, जिसकी कई नजीरें हैं। वह बताते हैं कि दरगाह में चलने वाले जामिया चिश्तिया मदरसे से मुहब्बत का पैगाम फैलाया जा रहा है।

नैयर मियां। जागरण

दरगाह में मनाया जाता है बसंत

खानकाह पर बसंत भी मनाया जाता है। कव्वाल सरसों के फूल और आम की बौर लेकर आते हैं। बसंत पर हजरत अमीर खुसरो के गीत गाए जाते हैं। रुदौली स्थित खानकाह की महफिल-ए-समह (सूफी संगीत) पूरी दुनिया में मशहूर है। दरगाह से जुड़े शाह हयात मसूद गजाली बताते हैं कि यहां हिंदी व फारसी में सूफी कलाम प्रस्तुत किया जाता है।

साबित नहीं हुआ था-किसने बनवाई मस्जिद

साफ नहीं स्थिति ▶ हाई कोर्ट में बाबर और औरंगजेब के बीच उलझ कर रह गया था दावा

माला दीक्षित, नई दिल्ली

जिस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद पर सारे देश की निगाहें हैं, उसे किसने बनवाया था यह बात हाईकोर्ट में साफ नहीं हो पाई थी। निर्माण बाबर ने कराया था या औरंगजेब ने यह साबित नहीं हुआ था। एक मत बाबर या बाबर के निर्देश पर उसके कमांडर मीर बाकी के मस्जिद बनवाने का है और दूसरा औरंगजेब के कार्यकाल में मस्जिद बनने का दावा करता है। फैसला देने वाले हाईकोर्ट के तीन जज भी इस मुद्दे पर एक मत नहीं थे। विवादित मस्जिद का निर्माण और निर्माण काल बाबर और औरंगजेब के बीच उलझा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर क्या फैसला देता है।

विवादित ढांचे यानी बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ और किसने कराया। साथ ही क्या उस इमारत को मस्जिद माना जाएगा। इसे लेकर हाईकोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुकदमे में एक बिंदु तय किया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुकदमे में पहला सवाल ही यही था कि जिस इमारत को मस्जिद बताते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, क्या वह मस्जिद थी। अगर वह इमारत मस्जिद थी तो उसे किसने बनवाया था। क्या उसका निर्माण बाबर ने कराया था जैसा कि याचिकाकर्ता सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने मुकदमे में दावा किया है। या फिर इसका निर्माण मीर बाकी ने कराया था जैसा कि धर्मदास (प्रतिवादी नंबर 13) ने कहा है। इस सवाल के जवाब में जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने अपने फैसले में यह तो माना कि विवादित इमारत मस्जिद थी लेकिन साथ ही कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड यह साबित नहीं कर पाया कि इमारत बाबर ने बनवाई थी। और न ही दूसरे पक्षकार ये साबित कर पाये कि इसे मीर बाकी ने बनवाया था। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि इसलिए निश्चित तौर पर यह कहना मुश्किल है कि कब इसका निर्माण हुआ और किसने कराया क्योंकि इस बारे में कोई भी दलीलें और सुबूत नहीं रखे गए। हालांकि अनुमान का सिद्धांत लागू करते हुए उनका मानना है कि विवादित इमारत का निर्माण हो सकता है कि औरंगजेब के काल में 1659 से 1707 एडी के बीच हुआ हो। जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने इस सवाल के जवाब में कहा था कि राजस्व रिकार्ड, अन्य दस्तावेजों, विशेषज्ञों की राय और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, ऐतिहासिक तथ्यों के पहलू से देखा जाए तो पता चलता है कि बाबर के कमांडर मीर बाकी ने पुराना हिंदू मंदिर तोड़कर उस जगह मस्जिद का निर्माण कराया था। जबकि जस्टिस एसयू खान ने इसके जवाब में कहा था कि यह साबित होता है कि विवादित इमारत का निर्माण बाबर या उसके निर्देश पर मस्जिद के तौर पर हुआ था। इसे वास्तव में मीर बाकी या किसी और ने बनवाया इसका महत्व नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस स्थिति में बस यह कहा जा सकता है कि 1934 तक मुसलमानों ने वहां नियमित नमाज की और 1934 से लेकर 22 दिसंबर 1949 तक विवादित स्थल पर सिर्फ शुक्रवार को नमाज की गई। इमारत के लगातार प्रयोग और कब्जे के लिहाज से वहां शुक्रवार की नमाज होना भी पर्याप्त है।

इस मुकदमे में सुनवाई के दौरान विवादित इमारत के बाबर के या बाबर के निर्देश पर उसके कमांडर मीर बाकी की ओर से 1528 में बनवाए जाने पर राम जन्मभूमि पुनरोद्धार समिति की ओर से सवाल उठाया गया था। समिति के वकील पीएन मिश्रा और रंजना अग्निहोत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई दलील में कहा गया था कि बाबर ने मस्जिद का निर्माण नहीं कराया था। न ही मीर बाकी ने निर्माण कराया था। मीर बाकी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। मीर बाकी एक काल्पनिक नाम है। मिश्रा ने विदेशी यात्री निकोलो मनूची जिसे उन्होंने औरंगजेब का कमांडर भी कहा था की किताब हिस्टोरिया डिमोगर (मुगल काल) का हवाला देते हुए कहा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। मनूची ने किताब में लिखा है कि औरंगजेब ने अयोध्या, काशी, मथुरा, मायापुरी (हरिद्वार) में मुख्य मंदिरों को तोड़ा था।

अयोध्या में पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने संभाली कमान

जागरण संवाददाता, अयोध्या

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सरगर्मी के बीच अफवाहों पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया सेल का गठन किया है। अफवाहों को रोकने के लिए फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर आदि सोशल साइट्स पर लगातार नजर रखी जा रही है।

रविवार को व्यापारियों ने शिकायत की थी कि दुकानों के शाम में जल्द बंद होने की सूचना वायरल हो रही है। पुलिस ने इसे अफवाह बताया और व्यापारियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। इस अफवाह से पुलिस निपटी ही थी कि सोशल मीडिया पर एक और संदेश ने पुलिस को परेशानी में डाल दिया। संदेश था कि अयोध्या पर फैसले को लेकर सभी फोन कॉल रिकार्ड होंगे। संदेश वायरल होने के बाद पुलिस के सोशल मीडिया सेल ने इसका खंडन किया। कहा कि सूचना पूरी तरह से भ्रामक और असत्य है। फैसले को लेकर लोगों में व्याप्त भ्रम को दूर करने के साथ ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल सौहार्द बनाए रखने के लिए भी किया जा रहा है। सोशल साइट पर पुलिस के साइबर विशेषज्ञ जनता को लगातार अफवाहों को लेकर जागरूक करने में जुटे हैं। सीओ सिटी अरविंद चौरसिया ने बताया कि जनता अफवाहों पर ध्यान न दे। किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। सुरक्षाकर्मी जनता की हिफाजत के लिए हैं।

विहिप ने अयोध्या को लेकर हित चिंतक अभियान भी रोका : लखनऊ : अयोध्या पर आने वाले फैसले के मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद ने अपनी गाइडलाइन तय कर दी है। फैसला आने से पहले इस विषय पर पदाधिकारियों को कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया है। दूसरी तरफ विहिप का हित चिंतक अभियान भी रोक दिया गया है। विहिप ने नवंबर माह में सिर्फ अवध प्रांत में एक लाख सदस्य बनाने की तैयारी की थी।

रामनाम की तान के साथ में ही गूंज रही अजान

अयोध्या स्थित इब्राहिम शाह की मजार मिश्रित आबादी में है। यहां सभी एक साथ मिलकर सजदा करते हैं। पास में ही मंदिर हैं जहां मंदिर से घंटे-घड़ियालों की आवाज गूंजती रहती है। जीतू निषाद

रविप्रकाश श्रीवास्तव, अयोध्या

फैसला जल्द आने की उम्मीदों के बीच अयोध्या में सौहार्द का रंग और भी चटख दिख रहा है। संभावित चिंताओं से इतर रामनगरी जैसे मन बना बैठी है- नहीं लगने देंगे गौरव पर कलंक। मोहल्लों से लेकर पॉश कॉलोनी हो या घाट से लेकर मिश्रित आबादी वाली तंग गलियां... कहीं रामनाम की तान छिड़ी है तो कहीं अजान गूंज रही है।

क्षणों में तब्दील होते सदियों के सिलसिले की नब्ज भांपने 'दैनिक जागरण' सोमवार को भी निकल पड़ा सौहार्द की गलियां छानने। वक्त करीब आठ बजे। रामनगरी काफी हद तक जाग उठी है, लेकिन कुछ इलाके ऊंघ रहे हैं। हां, चप्पे-चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की फुर्ती एक पल को यह जरूर सोचने पर मजबूर कर गई कि ये नहीं सोए हैं। खैर, मन में उमड़ते-घुमड़ते इन सवालों के बीच कदम खुद ब खुद मंजिल की ओर बढ़ने लगे। कुछ खास की तलाश करते-करते पहुंच गए टेढ़ी बाजार। वक्त करीब नौ बजे पर आ टिका है। हिंदू-मुस्लिम की मिश्रित आबादी वाला यह इलाका खाने-पीने की कई खासियतों के लिए मशहूर है। खासकर चाय की चुस्कियां, पान का बीड़ा।

यहीं चौराहे से कुछ दूरी पर बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी का घर है। लगा, इससे बेहतर स्थान क्या होगा अयोध्या का दिल टटोलने के लिए...। यही सोचकर नुक्कड़ पर जमा अनजान चेहरों के बीच पहुंच गए हम भी। भीड़ में जहां जालीदार टोपी लगाए शकील कुछ साथियों के साथ चर्चा में व्यस्त दिखे तो सैर पर निकले दिनेश गुप्ता बगल में अखबार दबाए खड़े थे। माहौल में वही बेफिक्री, मगर चर्चा में अदालत के संभावित फैसले की ही चहक। सबकी अपनी-अपनी दलील, लेकिन चिंता बस एक-अयोध्या को नहीं लगनी चाहिए किसी की नजर...। गुप्ता जी कहते हैं, लगता है मंदिर बन जाएगा। जवाब में दूसरे पक्ष के शारिक सहमति तो भरते हैं, मगर इस तर्क के साथ कि अदालत दूसरे पक्ष को भी नाराज नहीं करेगी।

वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है। कब दस बज गए पता नहीं चला। लिहाजा, लंबी खिंच रही चर्चा से छिटककर हम बढ़ गए आगे। यहीं से कुछ दूरी पर ही है स्वर्गदार मुहल्ला। हाल-माहौल टेढ़ी बाजार से भी बेमिसाल। इसलिए, क्योंकि इलाके में चौतरफा मंदिर और उनके बीच घिरी है इब्राहिम शाह की मजार। बावजूद इसके कोई सवाल और फसाद नहीं। न घंटे-घड़ियाल से दिक्कत, न मजार की रूहानियत से तकलीफ। हर कोई अपनी इबादत में व्यस्त है। इतना ही नहीं, मजार में मत्था टेकने से हिंदुओं को भी दिक्कत नहीं है। पास में ही हिंदू व्यापारी अटल गुप्ता के भोजनालय पर भीड़ जुटी है। कोई भेद नहीं, चटखारे में दोनों ही वर्गों के लोग मगन दिखे। गुप्ताजी से जय सियाराम के बाद सीधा सवाल, सब ठीकठाक? दुकानदारी में व्यस्तता के बीच उनका जवाब आया-यहां कौनो परेशानी नाय बा, मिश्रित ग्राहकों की तरफ इशारा कर बोले- आप खुदय देख लें...। हम निरुत्तर थे। लिहाजा, बढ़ गए आगे।

अगला ठिकाना भीड़भाड़ वाला श्रृंगार हाट है। पूरा इलाका कार्तिक मेले की तैयारियों से गुलजार है। भेद का भाव दूर-दूर तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ सद्भाव। मुस्लिम मनिहारों की दुकान पर हिंदू बहनें निश्चिंत होकर सुहाग की निशानी खरीदने में मगन दिखीं तो मेले में सजी दुकानों पर मुस्लिम परिवार खरीदारी में व्यस्त है। मंदिर-मस्जिद के विवाद पर जिससे पूछा, बस हां-हां-हां, सबय ठीक बा...। मानो उलझन बन रहे हों हमारे सवाल।

आखिर में हम बढ़ चले उस पग पर जहां दुनिया की नजरें टिकी हैं। यानी मंदिर आंदोलन का मुख्य केंद्र- न्यास कार्यशाला। यहां विश्व शांति के लिए यज्ञ करने पहुंचे चेन्नई के यश शर्मा और छत्तीसगढ़ के शिवम मिलते हैं। चर्चा छिड़ते ही कहने लगे-रामनगरी में अद्भुत शांति मिलती है। अयोध्या की समरसता व अध्यात्म के बारे में जो सुना, बढ़कर पाया। चेहरे पर मंदिर निर्माण की चमक लिए महंत मनमोहन दास तर्क रखते हैं- खाली फोर्स की चर्चा है। फैसला जो भी आए, इस नगरी को स्वीकार्य है। वहीं, तुलसी स्मारक सदन में बलरामपुर से आए श्रद्धालुओं में शामिल सदानंद कहते हैं कि इहां सब ठीक बा...आये हयन तो पइकरमा के बादे जाब...।

काशी मंदिर रामघाट के पास नेपाल से आए श्रद्धालु भजन गाते हुए कार्यशाला की ओर अपनी धुन में बढ़े जा रहे हैं। दल में शामिल साधुवेशधारी अशोक कुमार कहते हैं- अयोध्या का आनंद ही अलग है। रामनगरी से हमारा रिश्ता सदियों पुराना है। इसने शांति और सद्भाव का संदेश दिया है। अशोक हमारे सवालों को जैसे पूर्ण विराम देना चाह रहे हों। बोले, चिंता मत करिए- भगवान भला करेंगे...। श्रद्धा के इस भाव के आगे हमारे सारे सवाल शून्य हैं।

अयोध्या लाइव

- मुस्लिम मनिहारों की दुकानों पर जुट रहीं हिंदू महिलाएं
- हिंदू भोजनालयों पर बेफिक्र होकर चटखारे ले रहे मुस्लिम

फैसले से पहले परिक्रमा को उत्साहित श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, अयोध्या

गोंडा के दुर्गापुर गांव निवासी 62 वर्षीय शिवाकांत 14 कोसी परिक्रमा से एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने परिक्रमा से पहले रामलला, हनुमानगढ़ी, सरयू मैया का दर्शन किया। राम की पैड़ी पर वह विश्राम करते मिलते हैं। उन्हें देखकर समझा जा सकता है कि वह परिक्रमार्थी हैं पर इस बार की परिक्रमा का उत्साह अलहदा है।

कहते हैं... 'जन्मभूमि पर फैसला आने वाला है। इसलिए तय किया कि इस बार परिक्रमा के दिन पहुंचने के बजाय, एक दिन पहले ही अयोध्या चला जाए। भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और परिक्रमा भी। थोड़ा रुककर वह फिर मुखातिब होते हैं... आंखें कब से इस दिन का इंतजार कर रहीं थीं। इस बीच सिद्धार्थनगर जिले से आए चंद्रकिशोर से मुलाकात हुई। बातचीत में वह कहते हैं कि सौभाग्य से इस साल बहुत कुछ खास होने जा रहा है। रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के फैसले से ठीक पहले हो रही 14 कोसी परिक्रमा करने पहुंचे एक-दो नहीं, बल्कि कई लोग ऐसे हैं, जिनके लिए यह परिक्रमा बेहद खास हो गई है। अयोध्या में पहुंचे परिक्रमार्थियों का सोमवार को हनुमानगढ़ी, कनक भवन, सरयू तट पर दर्शन-पूजन का सिलसिला चल निकला है, जो मंगलवार को पूरी रौ में रहेगा।

अयोध्या में राम की पैड़ी पर जुटे श्रद्धालु और सजी दुकानें। जागरण

ड्यूटी के लिए बुलाए गए भरोसे के अधिकारी: अयोध्या : अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले को लेकर प्रशासनिक अमले की बेचैनी समझी जा सकती है। इसीलिए, यहां के हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भरोसेमंद अफसरों को बुलाया गया है। इसकी वजह यह है कि प्रशासनिक अमला किसी प्रकार की चूक नहीं होने देना चाहता। सभी अधिकारियों को एक महीने के लिए बुलाया गया है। इनमें पांच एडीएम स्तर व 10 डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। बाहर से बुलाए जा रहे अमले को रामनगरी के येलो जोन की कमान सौंपी जानी है। इसलिए क्योंकि फैसले के बाद आने वाली भीड़ का रुख येलो जोन की तरफ ही होगा। शासन के निर्देश पर बाहर के अधिकारियों ने आमद शुरू करा दी है। एडीएम स्तर के अधिकारियों में एसडीएम सदर रहे रामसहाय यादव भी हैं, जो मौजूदा समय में मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया हैं। 10 डिप्टी कलेक्टर में अयोध्या के रेजीडेंट मजिस्ट्रेट रहे अशोक कुमार भी शामिल हैं। वह फिलहाल बाराबंकी में तैनात हैं। कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनने वाले मिश्रित आबादी के गांवों में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक अलग से जारी है। छोटी-छोटी सूचनाओं पर नजर रखी जा रही है।

फैसला आने पर अयोध्या में होगी संतों की आकस्मिक बैठक

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : अयोध्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से 17 नवंबर से पहले आने वाले संभावित निर्णय का संतों को बेसब्री से इंतजार है। संत समाज रणनीति बना रहा है कि निर्णय आते ही अयोध्या में आकस्मिक बैठक की जाए। बैठक में निर्णय को पढ़कर सुनाया जाएगा और उसी अनुसार अगला कदम उठाया जाएगा। बैठक तीन में से किसी एक अखाड़े में करने की तैयारी है।

देश के इस सबसे चर्चित और बड़े मुकदमे के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। विश्व हिंदू परिषद की सक्रियता भी इन दिनों बढ़ गई है। अब संत समाज रणनीति बनाने में जुट गया है। सीधे तौर पर कोई बयान जारी न कर अखाड़ों में योजना बनी है कि सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आते ही उसका गहन अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद आकस्मिक बैठक बुलाकर उसमें निर्णय पढ़कर तकनीकी और विधिक पक्ष बताए जाएंगे। यह कोशिश की जाएगी कि संत समाज कहीं से भी राजनीति का शिकार न होने पाए, लेकिन केंद्र सरकार के रुख को देखते हुए सार्वजनिक बयान पर सभी सतर्क हो गए हैं। संत समाज की रणनीति के अनुसार अयोध्या के निर्मोही अनी, दिगंबर या निर्वाणी अखाड़ा में किसी एक में बैठक होगी। इसमें राज्य व केंद्र सरकार के नाम प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

हरियाणा में बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत

सेवा सिंह, करनाल : घरौंडा के गांव हरिसिंहपुरा में पांच वर्षीय मासूम शिवानी की मौत बोरवेल में गिरने के करीब 40 मिनट बाद हो गई थी। मौत का कारण दम घुटने और शरीर पर बाहरी और आंतरिक चोट लगना बताया है। बोरवेल में मौजूद कुछ पानी उसके फेफड़ों में चला गया। इससे उसके मुंह में झाग तक बन गया। दम घुटने के चलते उसके फेफड़ों में भी हवा भी मिली है, जो सांस न ले पाने के चलते बाहर नहीं निकल पाई।

यह राजफाश शिवानी के शव के पोस्टमार्टम के दौरान हुआ है। ये बात जिला सिविल सर्जन की ओर से गठित तीन सदस्यीय पैनल ने बताई। नागरिक अस्पताल की बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. निधि, एएसएमओ डॉ. कैलाश गर्ग, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. कुलजीत सिंह पैनल में शामिल रहे। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. विजयपाल भी पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद रहे।

'खाताधारकों के लिए आरबीआइ ने क्या कदम उठाए'

मुंबई, प्रेट्र : पीएमसी बैंक घोटाले के संबंध में बांबे हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) से पूछा है कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

जस्टिस एससी धर्माधिकारी और आरआइ चागला की खंडपीठ ने सोमवार को आरबीआइ की धन नहीं निकालने की पाबंदी के खिलाफ जमाकर्ताओं की याचिका की सुनवाई की। इस मामले पर खंडपीठ ने कहा कि वह केवल इतना जानना चाहती है कि आरबीआइ इस मामले में क्या कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि विगत 23 सितंबर को आरबीआइ ने वित्तीय धांधलियों के चलते पीएमसी बैंक के खाताधारकों पर छह माह के लिए अपने खातों से रकम नहीं निकालने की पाबंदी लगा दी थी। छह माह के लिए खाताधारकों को अपने एकाउंट से केवल एक हजार रुपये निकालने की छूट दी थी। बाद में इस रकम को बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया था। लेकिन अब यह धनराशि 40 हजार रुपये की जा चुकी है।

पीएमसी बैंक मामला

- बांबे हाई कोर्ट ने कहा-ऐसे वित्तीय मामलों में रिजर्व बैंक ही जज, कोर्ट नहीं
- बैंकों की नियामक संस्था से हलफनामा मांगा, सुनवाई 19 को

अदालत ने कहा कि बैंक के मामले से जुड़े हर सवाल की आरबीआइ को जानकारी होती है। आरबीआइ बैंकों का बैंक है। वह ऐसे मामलों में विशेषज्ञ है। लिहाजा इस मामले में दखल देकर हम आपके (आरबीआइ) अधिकार क्षेत्र को कम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे वित्तीय मामलों में आरबीआइ ही जज है, कोर्ट नहीं। हाईकोर्ट ने आरबीआइ को इस मामले में हलफनामा दायर करने को कहा और अगली सुनवाई 19 नवंबर को सुनिश्चित कर दी। अदालत ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया।

अदालत ने इस मामले में कोई फैसला देने से इन्कार करते हुए कहा कि कोई आरबीआइ को कार्रवाई करने से कैसे रोक सकता है। अगर आरबीआइ बैंक से दूर रहने को कहता है तो ऐसा करना होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि खाताधारक चाहें तो बैंक पर मुकदमा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि खाताधारकों को अपना लॉकर खोलने की छूट दी जाए। जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा कि कई तरह की याचिकाएं दायर की गई हैं। वकीलों को खाताधारकों को झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए। वह खाताधारकों से यह न कहें कि कोर्ट उनकी मदद करेगा। अदालतें जादूगर नहीं हैं।

बांबे हाई कोर्ट। फाइल

मजदूरों से छपवाता था जाली नोट, सात करोड़ बरामद

नईदुनिया, जगदलपुर: तेलंगाना में खम्मम जिले के सतपल्ली से छत्तीसगढ़ पुलिस ने मदार नामक एक व्यक्ति से सात करोड़ के जाली नोट बरामद किए हैं। वह छत्तीसगढ़ के बस्तर और ओडिशा से मजदूर ले जाकर नोट छापवाता था। उसके कनेक्शन छत्तीसगढ़ समेत आसपास के कई राज्यों से होने की आशंका है। पूछताछ में उसने बताया है कि वह असली नोटों के बदले में तीन गुना जाली नोट देता था।

एएसपी वी. सुरेश कुमार के अनुसार मदार कई साल से इस धंधे में लगा हुआ था। उसने सतपल्ली के श्रीनिवास रेड्डी नामक व्यक्ति के मकान को जाली नोट छापने के लिए किराए पर ले रखा था। मकान के भीतर से देर रात तक प्रिंटिंग प्रेस की आवाज सुनाई देने से आसपास के लोगों को संदेह हुआ। उन्होंने इसकी शिकायत की थी। पुलिस ने जब वहां दबिश दी तो करीब सात करोड़ रुपये के दो-दो हजार वाले जाली नोट, प्रिंटिंग मशीन आदि बरामद हुई।

सीयू में सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर सवाल

जागरण संवाददाता, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) धर्मशाला के न्यू मीडिया विभाग में सहायक प्राध्यापक के दो पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। इससे सीयू प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। सीयू प्रशासन ने व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए दो बार कटलिस्ट जारी की। पहले जारी की गई कटलिस्ट में एक आवेदक को पहले अपात्र किया गया था जबकि दोबारा जारी सूची में पात्र घोषित कर दिया है। पहली लिस्ट में 68 आवेदकों में से 53 पात्र किए हैं, जबकि संशोधित सूची में 54 हैं। सीयू में न्यू मीडिया विभाग में सहायक प्राध्यापकों के दो पद भरे जाने हैं और इनमें से एक सामान्य वर्ग के लिए जबकि दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग का है। दो सीटों के लिए देशभर से 68 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदनों की छंटनी के बाद सीयू प्रशासन ने सोमवार सुबह 9 बजे इंटरव्यू के लिए पात्र आवेदकों की कट लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 68 में से 53 आवेदक पात्र पाए गए। उसी समय सीयू प्रशासन ने संशोधित सूची भी जारी कर दी, जिसमें पात्रों की संख्या 54 हो गई। पहली कटलिस्ट में स्नातक के अंकों पर पांच, स्नातकोत्तर के लिए 23 व अनुभव के चार अंक मिले हैं और सभी के अंक मिलाकर 32 बनते हैं। दूसरी लिस्ट में आवेदक को पीएचडी डिग्री की 30 अंक दे दिए हैं और कुल 62 अंकों के साथ पात्र घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि उक्त आवेदक ने पीएचडी न्यू मीडिया में नहीं बल्कि अन्य विषय में की है। चिंतनीय है कि अगर उक्त आवेदक पात्र था तो पहली कट लिस्ट में नाम क्यों नहीं डाला गया।

बर्फबारी से अवरुद्ध रोहतांग दर्रा बहाल

जागरण संवाददाता, मनाली

बर्फबारी से अवरुद्ध रोहतांग दर्रा बीआरओ ने 24 घंटों में बहाल कर दिया है। बीआरओ ने सुबह ही दर्रे की बहाली शुरू कर दी थी, लेकिन शाम होने के कारण वाहनों को दर्रा आर पार करने की इजाजत प्रशासन व पुलिस ने नहीं दी। लाहुल की ओर कोकसर में छोटे व बड़े 28 वाहन कल से फंसे हुए हैं। इन वाहनों में पर्यटकों की संख्या कम है लेकिन लाहुल से मनाली आने वाले लोगों की संख्या अधिक है। लेह से मनाली आ रहे ट्रक चालक भी रविवार से कोकसर में फंसे हुए हैं।

कोकसर में फंसे वाहन चालक दोरजे, प्रीतम व सोनम ने बताया कि वे दिनभर रोहतांग बहाली के इंतजार करते रहे। बीआरओ द्वारा सड़क देर शाम बहाल करने के कारण वो लोग घरों का रुख नहीं कर सके। कोकसर निवासी रतन व सोनम ने बताया कि ग्रामीणों ने पर्यटकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है। सभी के रहने और खाने की उचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कोकसर पुलिस ने देर शाम को दर्रा बहाल होने के कारण लोगों को कोकसर से कुल्लू भेजना उचित नहीं समझा। गौर हो कि शाम होते ही रोहतांग में पारा लुढ़क जाता है और वाहनों के स्किड होने का खतरा रहता है। इसी को देखते हुए पुलिस में जोखिम नहीं उठाया। दूसरी ओर कुल्लू व मनाली में फंसे डेढ़ सौ से अधिक लाहुल के लोग भी घर जाने को दिनभर गुलाबा में इंतजार करते रहे। दर्रा शाम को बहाल होने के कारण पुलिस में उन्हें भी जाने की अनुमति नहीं दी। बीआरओ कमांडर कर्नल उमा शंकर ने बताया कि बीआरओ ने शाम छह बजे रोहतांग दर्रे को बहाल कर दिया है। डीएसपी मनाली शेर सिंह ने बताया कि सड़क में पानी जमने के कारण वाहन चालकों को दर्रा पार करने की अनुमति नहीं दी गई है।

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग में रविवार को हुई बर्फबारी के बाद बीआरओ ने सोमवार को मार्ग बहाल किया। जागरण

केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन हुई हल्की बर्फबारी

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में लगातार दूसरे दिन दोपहर बाद हल्की बारिश बर्फबारी हुई। जिससे न्यूनतम तापमान शून्य से तीन डिग्री नीचे पहुंच गया। इससे धाम में ठंड काफी बढ़ गई है।

केदारनाथ में बर्फबारी के चलते मौसम पूरी तरह बदल गया है। सोमवार को सुबह मौसम साफ था, लेकिन दोपहर से हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने लगी। रविवार को भी धाम में हल्की बर्फबारी हुई थी। धाम में निर्माण कार्यों में जुटी वुड स्टोन कंपनी के प्रभारी मनोज सेमवाल ने बताया कि सोमवार को धाम में अधिकतम तापमान आठ डिग्री और न्यूनतम -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरी ओर बागेश्वर में देर सायं एकाएक करवट बदली और पिंडर घाटी क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई है। उधर पिंडारी व आसपास के इलाकों में हिमपात होने की सूचना है। वहीं हिमालयी क्षेत्र में बारिश और हिमपात से पारा भी लुढ़क गया है। पहाड़ों में बर्फबारी होने से मैदानों में भी ठंड बढ़ने की आशंका है।

बिहार के कैमूर में मनचलों को काबू करेंगी 'शेरनी'

जागरण संवाददाता, कैमूर

पुलिसकर्मियों में जोश और बदमाशों में खौफ के मद्देनजर ही इस टीम का नाम 'शेरनी' रखा गया। मनचलों को काबू करने के लिए बिहार के कैमूर जिले में बनाई गई यह महिला पुलिसकर्मियों की टीम है। ट्रायल की तारीख को ही तीन मनचलों को गिरफ्त में लेकर इस टीम ने अपना डंका बजा दिया है। बहरहाल यह तो नहीं कहा जा सकता कि 'शेरनी' ने जिले के तमाम मनचलों को पस्त कर दिया है, लेकिन इसकी गारंटी है कि वे सरेराह छेड़खानी की हिमाकत नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह टीम के सदस्यों की तैनाती है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों से लेकर उन अंधेरी गलियों तक में 'शेरनी' की सदस्य तैनात हैं, जहां आती-जाती लड़कियां-युवतियां महफूज नहीं समझी जाती थीं।

यह सराहनीय पहल पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद की सोच का प्रतिफल है। वह बताते हैं कि कैमूर जिले को 80 महिला पुलिसकर्मी मिली थीं। उनमें से 50 की ड्यूटी विभिन्न थानों में लगा दी गई। शेष 30 सिपाहियों से 'शेरनी' टीम बनाई गई है। बेटियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर को इस टीम का गठन किया गया। भभुआ महिला थाना की असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीता देवी इस दस्ते का नेतृत्व कर रहीं।

- 30 महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम, एएसआइ कर रहीं टीम का नेतृत्व

छठ में प्रमुख घाटों पर टीम की ड्यूटी लगाई गई थी। भीड़भाड़ में चोरी-छिनतई की आशंका अधिक रहती है। टीम की मुस्तैदी से इस बार ऐसी नौबत नहीं बनी। अब त्योहार का मौसम निकल गया है। ऐसे में टीम की भूमिका और तैनाती के नए पहलुओं पर गौर किया जाएगा।

सादे लिबास में तैनाती : 'शेरनी' टीम की सदस्य सादे लिबास में तैनात रहती हैं, ताकि सार

Download UPSC IAS Material: www.iascgl.com
www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 5 नवंबर 2019

दैनिक जागरण
जो समर्थ बना सके वही सार्थक विद्या है

वकील-पुलिस संघर्ष

देश की राजधानी दिल्ली में तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच भिड़ंत के बाद देश के अन्य हिस्सों में वकीलों के हड़ताल पर जाने का औचित्य समझना कठिन है। इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन देश भर में वकीलों के विभिन्न समूहों ने न्यायिक कार्य से विरत रहना जरूरी समझा। इसके चलते देश के कई उच्च न्यायालयों में भी वादकारियों को निराश होना पड़ा। क्या कोई इस पर विचार करेगा कि वकीलों की हड़ताल से देश भर में जो लाखों परेशान हुए उनका क्या दोष था? आखिर उन्हें किस बात की सजा मिली? कानून की रक्षक पुलिस और कानून के सहायक वकीलों के बीच रिश्ते किस तरह बिगड़ रहे हैं, इसका एक नमूना गत दिवस कानपुर में भी देखने को मिला। यहां वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच मामूली विवाद के बाद वकीलों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव करने का फैसला किया। इस घेराव के दौरान पत्थरबाजी के साथ तोड़फोड़ भी की गई। क्या इसकी जरूरत थी? दुर्भाग्य यह है कि अब ऐसा ही अधिक होता है। आखिर विरोध दर्ज कराने के लिए हिंसा का सहारा लेने का क्या मतलब? चिंता की बात यह है कि वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव अब बहुत आम हो गया है।

देश के किसी न किसी हिस्से में वकीलों और पुलिस के बीच रह-रहकर वैसा टकराव देखने को मिलता ही रहता है जैसा पहले दिल्ली और फिर कानपुर में देखने को मिला। इन दोनों घटनाओं के कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश के बिजनौर में वकील और पुलिस आमने-सामने आ गए थे। यह ठीक नहीं कि तीसहजारी अदालत परिसर की घटना का हिंसक विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत दिवस भी दिल्ली में कुछ अन्य अदालत परिसरों में वकीलों ने उग्रता तो दिखाई ही, वे पुलिस को निशाना बनाते भी दिखे। निःसंदेह वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव की घटनाओं पर किसी एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह की घटनाओं में कभी पुलिस का मनमाना व्यवहार जिम्मेदार होता है तो कभी वकीलों का। कई बार दोनों पक्ष समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। कहना कठिन है कि तीस हजारी की घटना के लिए कौन कितना जिम्मेदार है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि दोनों पक्षों की ओर से संयम का परिचय नहीं दिया गया। जब जिसे मौका मिला उसने अराजकता का परिचय दिया। जैसे पुलिस का मनमाना व्यवहार नया नहीं उसी तरह यह भी सही है कि वकीलों के समूह भी जब-तब हिंसा का सहारा लेना पसंद करते हैं। यह एक तरह की भीड़ की हिंसा का ही रूप है। इस पर रोक लगनी जरूरी है।

लटकी भर्तियां

झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण राज्य में हजारों पदों पर होने वाली नियुक्तियां लटक गई हैं। फिलहाल चुनाव के दौरान लगभग दो माह तक सिर्फ उन्हीं पदों पर नियुक्तियां होंगी, जो विभिन्न आयोगों द्वारा विज्ञापित कर दी गई हैं। लगभग दो माह तक राज्य सरकार का कोई विभाग या कार्यालय विभिन्न पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोगों को नहीं कर पाएगा। चुनाव को लेकर जो नियुक्तियां लटक गई हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति है। इसके साथ-साथ हाई स्कूलों में हेडमास्टरों के पदों पर होने वाली बहाली भी लटक गई है। दूसरी तरफ छठी सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी बाधित हो सकती है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। संभावना तो इसकी भी जताई जा रही है कि आचार संहिता लागू होने से शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की जा सकेगी। भले ही ये भर्तियां आचार संहिता लागू होने के कारण लटकी हैं, लेकिन इसके लिए संबंधित विभाग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। अधिसंख्य नियुक्तियां जो रुकी हैं, वे या तो आयोगों को समय पर अनुशंसा नहीं भेजने से रुकी हैं या फिर संबंधित नियुक्ति नियमावली गठित नहीं होने के कारण। शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के गठन में भी कई वर्ष लग गए। राज्य में अभी तक महज दो शिक्षक पात्रता परीक्षा ही हो सकी हैं। इसी तरह अन्य विभागों में भी नियुक्ति नियमावली स्पष्ट न होने या उनमें त्रुटियों के कारण वर्षों तक लटकी रहती हैं। स्वास्थ विभाग के अधीन आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति का भी यही हाल है। नियमित नियुक्ति 10 वर्षों में भी नहीं हो सकी है। विधानसभा चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता निर्धारित समय पर ही लागू होनी थी। ऐसे में विभागों को कठिन मेहनत कर समय पर नियमावलियां गठित कर नियुक्ति की अनुशंसा भेजने की जरूरत थी। जो भी हो, पदाधिकारियों को इससे सबक लेने की जरूरत है। उम्मीद है कि नए साल में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही भविष्य में ध्यान रखा जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया को इस प्रकार समय से संपन्न किया जाए ताकि चुनावी कार्यक्रम से उनका कोई टकराव न हो, क्योंकि इससे दोहरा नुकसान होता है जहां लोग रोजगार से वंचित रहते हैं और दूसरा सेवाएं प्रभावित होती हैं।

> आचार संहिता लागू होने के कारण विभागों में बहालियां लटक गईं, लेकिन इसके लिए विभागीय लापरवाही भी जिम्मेदार है

सरदार की विरासत पर खोखला दावा

ए. सूर्यप्रकाश

सात दशकों तक सरदार पटेल की अनदेखी करने वाला नेहरू-गांधी परिवार अब कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह लौहपुरुष की विरासत का वारिस नहीं बन पाएगा

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उनकी विरासत को लेकर फिर से खींचतान शुरू होती दिखी। एक लंबे अर्से तक पटेल की उपेक्षा करने वाली कांग्रेस को यकायक पटेल खास लगने लगे हैं। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पटेल प्रतिबद्ध कांग्रेसी और नेहरू के निकट सहयोगी थे। उन्होंने भाजपा का यह कहते उपहास भी उड़ाया कि वह पटेल की विरासत पर कब्जा करने की जुगत में लगी है। वैसे प्रियंका कांग्रेस की पहली ऐसी नेता नहीं हैं जिन्होंने सरदार पटेल की स्तुतिगान करते हुए भाजपा पर सवाल उठाए कि वह कैसे उनकी विरासत पर दावा कर सकती है? बीते पांच वर्षों में पार्टी के कई और नेता भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा करने में बहुत देर कर दी है, क्योंकि अब कोई उनके रुख से सहमत नहीं दिखता। इसकी वजह यह है कि सरदार को लेकर कांग्रेस पार्टी के मौजूदा दावे खोखले हैं। इस मुद्दे की पड़ताल से पहले हमें भारत को एकजुट करने वाले एकता के सूत्रधार यानी सरदार पटेल की असाधारण उपलब्धियों पर दृष्टि डालनी होगी।

सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उन्होंने भारत में करीब 560 रियासतों को मिलाने का असंभव सा काम संभव कर दिखाया था। इन रियासतों के पास विकल्प थे कि वे या तो भारत का हिस्सा बनें या पाकिस्तान का या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। कुछ रियासतों ने भारत और पाकिस्तान के साथ जुड़ने का मन बना लिया, फिर भी भारत के पूर्णतः एकीकरण पर संदेह के बादल मंडरा रहे थे। जैसे हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय किया तो भोपाल के शासक स्वतंत्र रहना चाहते थे। ऐसे में पटेल ने इन रियासतों को अपनी सूझबूझ से मनाया और जरूरत पड़ने पर दबाव भी डाला। उनके दृढ़निश्चय के बिना एक भारत का विचार मूर्त रूप नहीं ले पाता। आजादी के समय जो भारत था, भविष्य में उसके बिखरने की और आशंका थी। ऐसे में अपने भौगोलिक एवं राजनीतिक एकीकरण के लिए हम सरदार पटेल के कृतज्ञ हैं। अपनी गिरती सेहत के बावजूद उन्होंने यह भागीरथ काम किया। राष्ट्र को एक कड़ी में पिरोने के दौरान ही 15 दिसंबर, 1950 को उनका निधन हो गया।

कश्मीर को लेकर जहां नेहरू हीलाहवाली में जुटे थे वहीं सरदार पटेल ने महाराजा से विलय की संधि पर हस्ताक्षर करा लिए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि पाकिस्तानी हमलावरों ने निपटने के लिए सैनिकों की टुकड़ी समय से श्रीनगर पहुंचे। विलय की संधि पर दस्तखत के अगले दिन ही भारतीय सैनिक वहां पहुंच गए। तब ऐसे विकट हालात थे कि यह कहना कठिन था कि फौजियों को लेकर जा रहा जहाज श्रीनगर हवाईअड्डे पर उतर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठिये भीतर घुस आए थे। सौभाग्य से सैनिकों की पहली टुकड़ी सकुशल हवाईअड्डे पर उतर गई और उसने आसपास के इलाके को सुरक्षित कर लिया ताकि और सैनिकों का आगमन हो सके। भारतीय सेना ने अप्रतिम शौर्य दिखाते हुए कई इलाकों को पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त करा लिया। जब सेना पूरी बहादुरी के साथ आगे बढ़ रही थी तब नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र की शरण में जाने का घातक फैसला कर लिया। इस तरह कश्मीर मसले का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया।

सरदार पटेल के व्यक्तित्व में लौहपुरुष की छवि से बढ़कर भी बहुत कुछ है। वह कांग्रेस के अनुशासित सिपाही थे। शायद नेहरू से भी ज्यादा अनुशासित, क्योंकि वर्ष 1946 में उन्होंने पार्टी के लिए असाधारण बलिदान दिया। उस वर्ष कांग्रेस पार्टी को अपना नया अध्यक्ष चुनना था। उसे ही आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी 15 प्रदेश समितियों से नामांकन मंगाए। उन 15 में से 12 समितियों ने सरदार पटेल के नाम पर मुहर लगाई जबकि अन्य समितियों ने किसी का नाम नहीं लिया। यानी नेहरू को एक भी प्रदेश कांग्रेस समिति का समर्थन नहीं मिला। इसके बावजूद नेहरू ने महात्मा गांधी के सामने स्पष्ट कर दिया कि वह किसी के मातहत या नायब बनकर काम नहीं कर सकते। तब गांधी ने हस्तक्षेप किया और पटेल को कदम पीछे खींचने पड़े। यह कांग्रेस पार्टी की एकजुटता के लिए किया गया बलिदान था। आजादी के बाद से ही कांग्रेस पार्टी एक परिवार के स्वामित्व वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माफिक संचालित होती आई है। उसने नेहरू-गांधी परिवार से जुड़े लोगों के योगदान का तो खूब महिमामंडन किया, लेकिन देश की तमाम अन्य विभूतियों की निरंतर उपेक्षा की। कांग्रेस में यह सिलसिला नेहरू के दौर में ही शुरू हो गया था। सरदार पटेल के अलावा डॉ. भीमराव आंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नायक गांधी-नेहरू परिवार के इस दुराग्रह के शिकार हुए। भारत के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक रहे पीवी नरसिम्हा राव को भी पार्टी की बेरुखी झेलनी पड़ी।

सरदार पटेल ने हमें एकजुट भारत दिया, फिर भी नेहरू ने उन्हें भारत रत्न से नहीं नवाजा। इसके बजाय 1955 में नेहरू ने स्वयं को इस सम्मान से अलंकृत किया। इसी तरह 1971 में इंदिरा गांधी ने अपनी ही सरकार में भारत रत्न ले लिया और राजीव गांधी को भी मरणोपरांत 1991 में भारत रत्न दिया गया। इनमें से किसी भी नेता ने पटेल या आंबेडकर को इस सम्मान के लायक नहीं समझा।

आखिरकार गैर-कांग्रेसी सरकारों ने ही इन दोनों महान नेताओं को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। नेहरू-गांधी परिवार देश के दो प्रधानमंत्रियों लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव की लोकप्रियता और उपलब्धियों को लेकर भी ईर्ष्यालु रहा। शास्त्री ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग जिताई तो राव ने 1991-96 के दौरान पंजाब में अलगाववाद को जड़ से खत्म किया और भारत को आर्थिक संकट से भी उबारा जब देश को दो सौ टन सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। उनके कार्यकाल के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 50 अरब डॉलर तक हो गया था। वह पांच वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे, मगर जब 2004 में उनका निधन हुआ तो गांधी परिवार ने आदेश दिया कि उनके शव को पार्टी मुख्यालय में न आने दिया जाए।

सौभाग्यवश प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा का निर्माण कराकर उनके योगदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। यह दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है। पटेल के स्मरण से उस राजनीतिक परिवार का चेहरा भी बेनकाब होगा जो अपने दुराग्रह के कारण बीते सात दशकों तक लौहपुरुष की उपलब्धियों की अनदेखी करता रहा। अब वे कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन उनकी विरासत कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। सरदार अब एक अरब से ज्यादा कृतज्ञ लोगों के दिलों में बस गए हैं।

(लेखक प्रसार भारती के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

प्रदूषण से निपटने के आधे-अधूरे उपाय

पंकज चतुर्वेदी

जब वायु प्रदूषण की त्रासदी साल के करीब 340 दिनों की हो तो फिर पांच-दस दिन की सम-विषम योजना से क्या फर्क पड़ेगा?

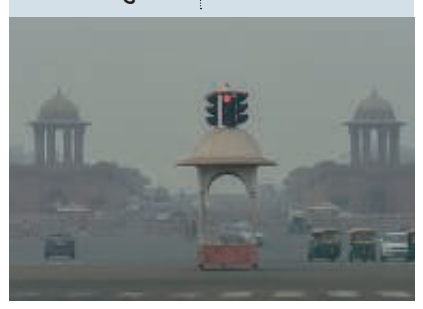

इस बार दीपावली के पहले दिल्ली और उसके आसपास घना स्मॉग छाते ही पंजाब और हरियाणा की सरकारों को कठघरे में खड़ा कर दिया गया कि वे पराली जलाने पर रोक नहीं लगा सकीं, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि दिल्ली-एनसीआर में बारिश के चंद दिनों को छोड़कर पूरे साल वायु प्रदूषण का प्रकोप रहता है। गर्मी में फेफड़ों में जहर भरने का दोष राजस्थान-पाकिस्तान से आने वाली धूल भरी हवाओं को दे दिया जाता है तो ठंड में पराली जलाने को। बीते एक दशक से हर साल सर्दियों के मौसम में दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य शहरों के वायु प्रदूषण की चर्चा होती है। जब यह चर्चा जोर पकड़ती है तो कभी सड़कों पर पानी छिड़क दिया जाता है तो कभी सम-विषम योजना को अमल में ले आया जाता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य रुकवाने जैसे काम भी किए जाते हैं। दिल्ली में हवा के साथ जहरीले कण घुलने में सबसे बड़ा योगदान (23 फीसदी) धूल और मिट्टी के कणों का है। 17 प्रतिशत हिस्सा वाहनों के उत्सर्जन का है। जनरेटर जैसे उपकरणों का उत्सर्जन 16 प्रतिशत है। वहीं औद्योगिक उत्सर्जन सात फीसद और पराली या अन्य जैव पदार्थों को जलाने से निकले धुएं का हिस्सा 12 प्रतिशत होता है।

इस मौसम में स्वच्छ वायु की खलनायक पराली है, लेकिन केवल वही नहीं। यह अच्छा है कि अब सरकार पराली को खेत में ही जज्ब करने के उपकरण बेच रही है और उसके लिए सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन किसान के पास अगली फसल की बोआई के लिए समय कम होता है सो वे पराली जलाने में अपना भला देखते हैं। हरियाणा-पंजाब सदियों से कृषि प्रधान प्रदेश रहे हैं फिर पराली की समस्या हाल के समय में ही क्यों उभरी है? इस सवाल का जवाब उस प्रवृत्ति में छिपा है जिसके तहत रेगिस्तान से सटे पंजाब-हरियाणा में धान की बेहिसाब खेती होने लगी। एक तो भाखड़ा नंगल बांध ने खूब पानी दिया, फिर उपज अच्छी हुई तो किसान ने भूगर्भ का जल जमकर उलीचा। फिर सरकार ने किसानों को बिजली मुफ्त कर दी और जमीन से पानी निकालने पर कोई रोक नहीं रही। इसके अलावा जितना भी धान उगाओ, उसकी सरकारी खरीद की गारंटी। इस समय देश में चावल का 110.28 लाख मीट्रिक टन और धान का 237.28 लाख मीट्रिक टन सुरक्षित स्टॉक रखा हुआ है, जबकि हमारे यहां चावल की सालाना मांग इससे एक चौथाई भी नहीं है। क्या ऐसे हालात में धान की खेती को हतोत्साहित करने की जरूरत नहीं है? जो धान जमीन का पानी पी जाता है, जिस धान की खेती में लगाए गए रसायन से जमीन और जल स्रोत जहरीले होते हैं उस धान की जगह किसानों को फल-सब्जी उगाने को क्यों नहीं तैयार किया जाता?

इस साल हरियाणा सरकार ने पानी बचाने के इरादे से धान की जगह मक्के की खेती करने वालों को निशुल्क बीज और पांच हजार रुपया अनुदान की जो घोषणा की वह सराहनीय है, लेकिन बात तब बनेगी जब पंजाब में भी एसा हो। इसका कोई अर्थ नहीं कि हरियाणा और पंजाब के किसान पानी की ज्यादा खपत वाली धान की खेती करें। यहां एक किलो धान पैदा करने में 5389 लीटर पानी की खपत होती है। वहीं बंगाल में एक किलो धान उगाने के लिए केवल 2713 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। साल 2014-15 में भारत ने करीब 37 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया। 37 लाख टन बासमती चावल उगाने के लिए 10 खरब लीटर पानी खर्च हुआ। इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भारत ने 37 लाख टन बासमती चावल के साथ 10 खरब लीटर पानी भी दूसरे देश को भेज दिया जबकि पैसे केवल चावल के मिले। यही चावल वायु प्रदूषण का भी कारण बना है।

भले ही दिल्ली में वातावरण के जहरीले होने पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई हो और पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की गई हो, लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि दिल्ली में जगह-जगह पर लगने वाले जाम को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। जब तक दिल्ली में वाहनों की संख्या कम करने और यहां की आबादी को नियंत्रित करने के कड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक प्रदूषण का मर्ज दूर नहीं होने वाला। दिल्ली में वाहनों की सम-विषम योजना भले ही तात्कालिक कुछ राहत दे दे, लेकिन इसका कोई दूरगामी असर नहीं होने वाला। दो साल पहले जब एनजीटी ने कड़ाई से यानी-बगैर दोपहिया या महिलाओं को छूट दिए सम-विषम लागू करने का निर्देश दिया था तो दिल्ली सरकार ने ही अपने कदम खींच लिए थे। एनजीटी के तत्कालीन अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा था कि यातायात धीमा होने या फिर लाल बत्ती पर वाहनों के अटकने से हर रोज तीन लाख लीटर ईंधन जाया होता है, जिससे दिल्ली की हवा दूषित होती है। समाज और सरकार दिल्ली में घुटते दम पर चिंता तो जाहिर कर रही, लेकिन एनजीटी के उक्त निष्कर्ष पर गंभीरता नहीं दिखा रही है।

यदि दिल्ली और साथ ही उत्तर भारत के एक बड़े इलाके को रहने लायक बनाना है तो न केवल सड़कों पर वाहन कम करने होंगे, बल्कि जाम की समस्या से भी पार पाना होगा। सनद रहे कि वाहन सीएनजी से चले या फिर डीजल या पेट्रोल से, यदि उसमें क्षमता से ज्यादा वजन होगा तो उससे निकलने वाला धुआं जानलेवा ही होगा। यदि दिल्ली को एक अरबन स्लम बनने से बचाना है तो कथित लोकप्रिय फैसलों से बचना होगा। जब वायु प्रदूषण की त्रासदी साल के करीब 340 दिनों की है तो फिर पांच-दस दिन की सम-विषम योजना से क्या फर्क पड़ेगा? राजधानी क्षेत्र में साठ फीसद वाहन दोपहिया हैं, लेकिन वे सम-विषम योजना से बाहर हैं। आल इंडिया परमिट वाले और ओला-उबर जैसी कंपनियों के डीजल वाहन भी इस पाबंदी में चलते ही हैं। जाहिर है कि महज 25 फीसदी लोग ही इसके तहत सड़कों पर अपनी कार लेकर नहीं आ पाएंगे। नए मापदंड वाले वाहन यदि पहले गियर में रेंगते हैं तो उनसे सल्फर डाई आक्साईड और कार्बन मोनो आक्साईड की बेहिसाब मात्रा उत्सर्जित होती है। साफ है कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलना रुकना ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ दिल्ली वालों को खुद द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण पर लगाम लगानी होगी।

(लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

भाग्य की प्रबलता

श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि कर्म और भाग्य में से कर्म सदा मनुष्य के अधीन रहता है। इसीलिए मनुष्य कर्म निर्धारित कर जीवन में सफलता के रास्ते पर चल पड़ता है। किंतु भाग्य पर मनुष्य का कोई वश नहीं होता और इसके लिए यह चाहे जितना प्रयत्न करे, इस पर नियंत्रण कर पाना मनुष्य के लिए सदा असंभव ही रहा है। यही कारण है कि भाग्यवादी जब कभी भी भाग्य की प्रबलता का उल्लेख करते हैं तो वे इस देश की परंपरा के अनेक उन आख्यानों का उल्लेख करते हैं, जिनमें घटित घटनाएं सच में आश्चर्यचकित कर यह सोचने को विवश कर देती हैं कि निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं का सूत्रधार कोई न कोई ऐसा तो है ही, जिसकी सबलता के सामने किसी की भी नहीं चलती, यहां तक कि नर रूप में अवतरित होकर आया हुआ परम पुरुषोत्तम भी कभी-कभी उन स्थितियों में हारा हुआ जैसा दिखाई देता है।

सर्व समर्थ परमपिता परमेश्वर नर रूप में आने के लिए वसुदेव और देवकी को चुनते हैं जो किसी के लिए भी परम सौभाग्य का विषय हो सकता है, किंतु इन दोनों का दुर्भाग्य देखिए कि देवकी अपने ही सहोदर के द्वारा पति सहित जेल में डाल दी जाती हैं और कंस के द्वारा मारे जाने वाले अपने दूसरे छह बेटों का वध होते हुए देखने पर विवश हुईं, वहीं पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को छिपकर भागना पड़ता है। ऐसे ही समुद्र मंथन में देव और दानव सभी उपस्थित थे, किंतु विधि-विचित्रता देखिए कि सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी को भगवान विष्णु ले गए और विष महादेव के हिस्से में आया। दशरथ नंदन श्रीराम के लिए तो यह कहा जाता है कि वह साक्षात धर्म के अवतार थे, किंतु विधि के विधान पर उनको भी वनवास भोगना पड़ा। सत्यवादी हरिश्चंद्र विधि-विपरीतता से सपत्नीक न केवल दास बने, अपितु उनको तो अपने पुत्र की मृत्यु पर उसके लिए कफन के रूप में पत्नी की आधी साड़ी लेनी पड़ी। ऐसी तमाम घटनाएं और भी हैं, जिन पर किसी का वश नहीं होता, इसलिए विरक्त संत और शास्त्र कहते हैं कि हम उस परम परमेश्वर को कभी न भूलें, जो विधि या भाग्य का भी संचालक है।

डॉ. गदाधर त्रिपाठी

बीमार मानसिकता की निशानी

डॉ. मोनिका शर्मा

> ट्रेन होस्टेस के साथ दुर्व्यवहार से सवाल उठता है कि बेहतर सुविधाएं चाहने वाले लोग सभ्य नागरिक क्यों नहीं बनना चाहते

बड़े उत्साह के साथ शुरू की गई निजी क्षेत्र की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के संचालन में एक अजीब परेशानी सामने आई है। यह कोई तकनीकी या परिचालन संबंधी नहीं, बल्कि मानवीय व्यवहार से जुड़ी है। इसकी केबिन होस्टेस के साथ कुछ यात्री अशिष्टता से पेश आ रहे हैं। वे जबरन फोटो खींचने या वीडियो बनाने लग जाते हैं। कई मुसाफिर बिना वजह बटन दबाकर होस्टेस को बुलाते हैं। अफसोस कि कुछ यात्री तो छेड़खानी करने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसी सभी बातें केबिन होस्टेस के तौर पर काम रही लड़कियों को असहज कर रही हैं। दरअसल, ऐसी सभी हरकतों का सीधा संबंध इंसान की मानसिकता से ही है। उस मानसिकता से जिसमें न तो श्रम का सम्मान है और न ही महिलाओं का मान। तभी तो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस ट्रेन में आराम से यात्रा करने के बजाय कुछ लोग ट्रेन होस्टेसेस के साथ ऐसा शर्मनाक व्यवहार कर रहे हैं।

अपना दायित्व निभा रही लड़कियों के लिए यात्रियों का यह रवैया असुरक्षा का भाव भरने और तनाव देने वाला है। यही वजह है कि तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को ट्रेन होस्टेस से सलीके से पेश आने के लिए अब ट्रेन में अनाउंसमेंट तक करने की नौबत आ गई है।

विचारणीय है कि जिस तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उसमें सफर करने वाले लोगों का यह अभद्र व्यवहार किस मानसिकता की बानगी है? आखिर क्यों ऐसी सोच जड़ें जमाए हैं, जिसमें न किसी की निजता का खयाल है और न ही शालीन बर्ताव की समझ। तेजस ट्रेन के संचालन के शुरुआती समय से ही ट्रेन में अपनी ड्यूटी पर डटीं होस्टेसेस के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। किसी भी कार्यक्षेत्र से जुड़ी आम कर्मचारी की तरह काम कर रही इन महिलाओं और युवतियों के लिए यह सीधे-सीधे निजता के हनन का मामला है। कार्यस्थल पर प्रताड़ित किए जाने का मसला है। सवाल है कि स्मार्ट सुविधाएं चाहने वाले लोग सभ्य नागरिक क्यों नहीं बनना चाहते? यात्रा करते हुए सलीके से बर्ताव करने के बजाय ऐसी ओछी हरकतें करने का आखिर क्या औचित्य है?

विडंबना ही है कि कोई भी कार्यक्षेत्र हो, औरतों को देह के परे देखने की सोच अब भी नदारद है। तभी तो ट्रेन होस्टेसेस के साथ कुंठा भरा ऐसा अशालीन व्यवहार देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दोराय नहीं कि आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता में इजाफा होना जरूरी है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में ऐसे नए कार्यक्षेत्रों का विस्तार होना सुखद है। दुर्भाग्यवश, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कामकाजी महिलाओं के जीवन का दंश बन गया है। सेवा उद्योग में कार्यरत महिलाओं को यह पीड़ा कुछ ज्यादा ही झेलनी पड़ती है, क्योंकि इस क्षेत्र में वे अभद्र सोच वाले लोगों का आसान शिकार होती हैं। सवाल है कि स्मार्ट सिटीज और डिजिटल जीवनशैली की चाहत रखने वाले लोग प्रगतिशील सोच का दामन कब थामेंगे?

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

ईयू का मकसद समझे विपक्ष

'यूरोपीय सांसदों संग व्यर्थ की कवायद' शीर्षक से लिखे लेख में विवेक काटजू ने जिस तरह से यूरोपीय संघ के सांसदों के श्रीनगर दौरे के संदर्भ में विपक्षी एवं मीडिया के कुछ वर्गों की बेबुनियाद कवायद का जिक्र किया, वह वाकई में विपक्ष एवं उन मीडिया वर्गों की नादानी कही जा सकती है, क्योंकि इस दौरे का उद्देश्य शायद वे समझ नहीं पा रहे हैं। परिणामस्वरूप भारत सरकार के समक्ष ऐसे प्रश्न खड़े कर रहे हैं जिससे इस मसले का दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं। यह बात निराधार नहीं कि इस दौरे के जरिये कोई खास उद्देश्य नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आए दिन इसकी गलत तस्वीर पेश करने और दुष्प्रचार करने में जुटा है। इन यूरोपीय सांसदों के दौरे का उद्देश्य था पाकिस्तान की ऐसी कुत्सित चालों की काट की जाए और दुनिया को हकीकत बताई जाए। हालांकि यह सर्वविदित है कि इन घटनाओं से मौजूदा सरकार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन उन विपक्षी दलों को यह समझने की दरकार है कि मौजूदा सरकार द्वारा यदि इस तरह के कोई कदम उठाए जा रहे हैं तो उसका वास्तविक मकसद क्या है, उसके बाद ही उनके द्वारा कोई विरोधी कदम उठाए जाएं, अन्यथा उनके इस तरह के विचारों का आशय होगा देश-विरोधी तत्वों को जन्म देना जो देश के साथ-साथ खुद उन दलों के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं।

आरके आशुतोष, सारण

महाराष्ट्र में सत्ता संग्राम

महाराष्ट्र में सत्ता की कड़ाही में दूध उफान पर है, पर ज्यादा के चक्कर में कहीं मुंह न जल जाए? हालांकि जनता का जनादेश तो भाजपा और शिवसेना महागठबंधन के पक्ष में गया, लेकिन 50-50 के तथाकथित फार्मूले में दोनों पक्ष हताहत होते दिखाई दे रहे हैं। क्या ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री रह कर प्रदेश के हितों की रक्षा की जा सकती है? संकल्प पत्र के वादों को निभाया जा सकता है? क्योंकि जब तक नया मुख्यमंत्री पुराने मुख्यमंत्री के कार्यकाल की गतिविधियों को समझेगा तब तक कार्यकाल पूरा हो चुका होगा। तब संकल्प पत्र के मायने क्या रह जाएंगे? राज्य की जनता और जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रदेश के विकास परियोजनाओं, चौतरफा घिरे किसानों की असीम समस्याओं के निदान आदि का क्या होगा? आखिर गठबंधन पार्टियों में सत्ता पर काबिज होने वाली लडाई से उपजे अंदरूनी कलह में जनता के जनादेश का अपमान क्यों किया जा रहा है?

दीपक गौतम, सोनीपत

अधिकारों का हनन

दिल्ली में पहले ही केंद्र सरकार ने नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत ट्रैफिक नियमों की अवमानना की चालान राशि में भारी वृद्धि कर दी है। अब केजरीवाल सरकार भी ऑड-इवेन के नाम पर भारी जुर्माना लगा रही है। प्रदूषण घटाने का यह फार्मूला बाहरी वाहन चालकों के राजधानी में प्रवेश के संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इस तरह की वैधानिक व्यवस्था भारत वर्ष के अन्य शहरों में किसी सरकार ने नहीं लगाई है। अगर किसी को व्यवसाय, पारिवारिक सुख- दुख के कारण अपना वाहन दिल्ली में लाना है तो वह नहीं ला सकता है। इस तरह से यह कानून जनता के लिए कष्टदायी है। लोगों पर इस तरह जुर्माना थोपना समस्या का स्थाई समाधान नहीं है। टैक्सी एवं ऑटो चालक इसी आड़ में अनुचित किराया वसूल लेते हैं।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

पर्यावरण पर एकजुटता

आसियान दशों से भारत की जुगलबंदी उद्योग जगत के लिए नए-नए अवसर खोज लाएगी। यह वाकई बेहद खुशी की बात है कि थाईलैंड में भारत के आदित्य बिरला ग्रुप ने अपने करोबार के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने आसियान सम्मेलन के मंच से भारत को निवेश के नजरिये से एक बेहद आकर्षक बाजार बताया है, पर इन सभी बातों में कहीं एक मुद्दा बहुत पिछड़ा हुआ नजर आता है। हम जहां एक तरफ विश्व को एक बड़ा बाजार बनाने पर उतारू हैं, वहीं पर्यावरण की चिंता, प्रदूषण, हरियाली को बचाना जैसे तमाम मुद्दे कहीं पिछड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। सवाल ये है कि जब तमाम देशों के बीच उद्योगों, रक्षा मसौदों आदि को लेकर बड़े-बड़े समझौते हो सकते हैं तो फिर पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर पूरा विश्व एक साथ क्यों नहीं खड़ा होता?

vaishali.datalogic@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

**अपने पत

16.3 करोड़ टन दूध का उत्पादन किया गया था देश भर में वित्त वर्ष 2016-17 में, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, जबकि घरेलू मांग लगभग 14.8 करोड़ टन ही थी।

आजकल

गरीब के लिए बढ़े कॉरपोरेट मदद

डॉ. जयंतीलाल भंडारी
अर्थशास्त्री

हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पुरस्कार समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय कंपनियों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति हेतु गरीबों तक पहुंच बढ़ानी चाहिए ताकि उन्हें भूख और कुपोषण जैसी पीड़ाओं से राहत पहुंचाई जा सके। देश में सीएसआर के तहत किया जाने वाला खर्च तेजी से बढ़ना सामाजिक कल्याण के मद्देनजर एक सुकूनभरा संकेत है, लेकिन अभी इस दिशा में और काम करने की आवश्यकता है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कॉरपोरेट जगत से अपील की है कि उन्हें कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत गरीबों की मदद के लिए पहुंच का दायरा बढ़ाना चाहिए। देश में कई इलाकों में अब भी भूख और कुपोषण की गंभीर समस्या है। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक स्वास्थ्य, कुपोषण और भूख से संबंधित रिपोर्ट्स भी इसकी ताकीद करती हैं। उल्लेखनीय है कि भुखमरी और कुपोषण के उन्मूलन हेतु कोई व्यय किया जाना सीएसआर के निर्धारित लक्ष्यों में शामिल है। विगत वित्त वर्ष में सीएसआर के तहत 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों की ओर सीएसआर व्यय का प्रवाह बढ़ाकर बड़ी संख्या में लोगों को कुपोषण और भूख से राहत दी जा सकती है। मालूम हो कि हाल ही में घोषित वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में 195 देशों में भारत को 57वें स्थान पर रखा गया। इसी तरह 16 अक्टूबर को यूनिसेफ द्वारा प्र काशित रिपोर्ट 'द स्टेट ऑफ द वल्ड्र्स चिल्ड्रेन' में भी कहा गया है कि भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के 69 फीसद बच्चों की मौत का कारण कुपोषण है। यूनिसेफ का यह भी आकलन है कि महज 42 फीसद बच्चों को ही समय पर खाना मिलता है।

इसी तरह भारत में भूख की समस्या से संबंधित रिपोर्ट वैश्विक भूख सूचकांक के रूप में 15 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित हुई है। वैश्विक भूख सूचकांक (जीएचआइ)-2019 में 117 देशों की सूची में भारत 102वें पायदान पर पाया गया। भारत की निम्न रैंकिंग का एक बड़ा कारण बताया गया कि यहां पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ऊंचाई के अनुपात में कम वजन वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साथ ही भारत के छह से 23 महीने के बच्चों में से मात्र 9.6 फीसद बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकार्य आहार मिल पाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी कहना है कि भारत में भूख से पीड़ितों तथा कुपोषित बच्चों की बढ़ती तादाद चिंताजनक है। बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम जैसे राज्यों में यह समस्या लंबे समय से चिंता बढ़ाती दिख रही है। जन्म के बाद बच्चों को जिन पोषक तत्वों और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, वे बच्चों को मिल नहीं पाते हैं। स्थिति यह है कि ना तो बच्चों का ढंग से टीकाकरण हो पाता है, ना ही उनकी बीमारियों का समुचित इलाज।

देश में विकास के साथ-साथ आर्थिक असमानता का परिदृश्य भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी जो भूख और कुपोषण की चुनौती सामने खड़ी है, उससे निपटने के लिए तात्कालिक रूप से सीएसआर व्यय राहतकारी भूमिका निभा सकता है। ऐसे में इस समय कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के परिपालन के तहत स्वास्थ्य, कुपोषण और भूख की चिंताएं कम करने के लिए सीएसआर व्यय बढ़ाने को प्राथमिकता देना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि 500 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा नेटवर्थ अथवा पांच करोड़ रुपये या इससे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनियों को पिछले तीन साल के अपने औसत मुनाफे का दो प्रतिशत हिस्सा हर साल सीएसआर के तहत उन निर्धारित गतिविधियों में खर्च करना होता है, जो समाज के पिछड़े या वंचित लोगों के कल्याण के लिए जरूरी हों। इनमें भूख, गरीबी और कुपोषण पर नियंत्रण, कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण, खेलकूद प्रोत्साहन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, तंग बस्तियों के विकास आदि पर खर्च करना होता है। लेकिन विभिन्न अध्ययनों में पाया गया कि बड़ी संख्या में कंपनियां सीएसआर के उद्देश्य के अनुरूप खर्च नहीं करती हैं।

हालांकि विगत अगस्त में सरकार ने जिस कंपनी (संशोधन) विधेयक- 2019 को पारित किया है, उसमें उन कंपनियों पर जुर्माना लगाने के प्रावधान भी शामिल हैं जो सीएसआर के लिए अनिवार्य दो फीसद का खर्च नहीं करती हैं। नए संशोधनों से कंपनियों की सीएसआर गतिविधियों में जवाबदेही तय करने में आसानी होगी। कंपनी अधिनियम की धारा 135 के नए सीएसआर मानकों के मुताबिक यदि कोई कंपनी अपने मुनाफे का निर्धारित हिस्सा निर्धारित सामाजिक गतिविधियों पर खर्च नहीं कर पाए तो जो धनराशि खर्च नहीं हो सकी उसे कंपनी से संबद्ध बैंक में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एकाउंट में जमा किया जाना होगा। कंपनियों को सीएसआर का बगैर खर्च किया हुआ धन प्रधानमंत्री राहत कोष जैसी मदों में डालना होगा।

ऐसे में अभी तक जो कंपनियां सीएसआर को रस्मअदायगी मानकर उसके नाम पर कुछ भी कर देती थीं, उनके लिए अब मुश्किल हो सकती है। सीएसआर के मोर्चे पर सरकार सख्ती करने जा रही है। कंपनियां केवल यह कहकर नहीं बच पाएंगी कि उन्होंने सीएसआर पर पर्याप्त रकम खर्च की है। अब उन्हें यह बताना पड़ेगा कि खर्च किस काम में किया गया? उस खर्च का नतीजा क्या निकला और समाज पर उसका कोई सकारात्मक असर पड़ा या नहीं? उन्हें यह भी बताना होगा कि क्या यह खर्च कंपनी से जुड़े किसी संगठन पर हो रहा है? नए नियमों के तहत निचले स्तर पर शामिल कंपनियों के लिए सीएसआर में हुए न्यूनतम खर्च को बताने की बाध्यता होगी, खर्च की रकम बढ़ने के साथ-साथ अधिक से अधिक जानकारी देनी होगी।

जिस तरह देश में कॉरपोरेट जगत निरंतर नई बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है, उसी के मुताबिक उसके सामाजिक उत्तरदायित्व में भी इजाफा होना लाजिमी है। देश में कॉरपोरेट जगत के सामाजिक उत्तरदायित्व की नई जरूरतें उभरकर सामने आई हैं। ज्ञातव्य है कि सीएसआर किसी तरह का दान नहीं है। दरअसल यह सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ कारोबार करने की व्यवस्था है। कॉरपोरेट जगत की यह जिम्मेदारी है कि वह स्थानीय समुदाय और समाज के विभिन्न वर्गों के बेहतर जीवन और रहन-सहन के लिए सकारात्मक भूमिका निभाए। खासतौर से देश में कुपोषण एवं भूख की चिंताओं को कम करने के लिए सीएसआर के दायरे का विस्तार प्रमुख सामाजिक जरूरत है। इसी तरह हमें श्रम कौशल से जुड़ी योजनाओं पर भी सीएसआर व्यय बढ़ाना होगा। श्रम कौशल के आधार पर देश में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देकर उन्हें कुपोषण और भूख से बचाया जा सकेगा। हम आशा करें कि समाज के कमजोर और वंचित तबके के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने तथा देश में मौजूद कुपोषण एवं भूख की समस्या से निपटने में कॉरपोरेट जगत अपना योगदान बढ़ाएगा और सीएसआर व्यय के माध्यम से अधिक सार्थक भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

डेयरी किसानों की मदद करे सरकार

पुष्पेंद्र सिंह
अध्यक्ष, किसान शक्ति संघ

भारत समेत 16 देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप-आरसीईपी) नाम से एक बड़ा आर्थिक समूह बनाकर आपस में एक मुक्त व्यापार समझौता (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट- एफटीए) लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि भारत ने इस समझौते से स्वयं को बाहर रखने की बात कही है, क्योंकि यह आशंका बन गई थी कि क्या इस समझौते से भारत के उद्योगों और कृषि विशेषकर दुग्ध और डेयरी उद्योग को सस्ते विदेशी उत्पादों की बाढ़ का सामना करना होगा।

हमारे देश में लगभग 28 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कृषि उत्पादन होता है। इसमें 25 प्रतिशत हिस्सा यानी सात लाख करोड़ रुपये मूल्य का दूध की अर्थव्यवस्था है। यदि दूध समेत पशुपालन से होने वाली संपूर्ण आमदनी का आकलन करें तो कृषि में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है। मूल्य के लिहाज से दूध देश की सबसे बड़ी फसल है। देश में उत्पादन होने वाले दूध का मूल्य गेहूं और चावल दोनों फसलों के संयुक्त मूल्य से भी ज्यादा है।

लगभग 18 करोड़ टन दूध उत्पादन के साथ हम विश्व के 20 प्रतिशत दूध का उत्पादन करते हैं और पिछले दो दशकों से प्रथम स्थान पर बने हुए हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 में हमने अपनी घरेलू मांग 14.8 करोड़ टन से भी 1.5 करोड़ टन अधिक यानी 16.3 करोड़ टन दुग्ध उत्पादन किया था। वर्ष 2032-33 में भी देश में 29 करोड़ टन की मांग के सापेक्ष 33 करोड़ टन दुग्ध उत्पादन होने का अनुमान है। अर्थात हमारा देश दूध के विषय में भविष्य के लिहाज से आत्मनिर्भर ही नहीं है, बल्कि दुग्ध उत्पादों को अन्य देशों के बाजारों में निर्यात करने की स्थिति में भी है। परंतु फिर भी हमारे मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से दुग्ध उत्पादों के बहुत बड़े निर्यातक देश हैं। इन दोनों देशों की संयुक्त रूप से विभिन्न दुग्ध उत्पादों में विश्व बाजार में 20 प्रतिशत से लेकर 70 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी है। भारत में इन दुग्ध उत्पादों का संगठित क्षेत्र का वार्षिक बाजार लगभग पांच लाख टन का है, जबकि न्यूजीलैंड अकेले ही इन उत्पादों का 25 लाख टन से अधिक मात्रा का वार्षिक निर्यात करता है। ऐसे में न्यूजीलैंड जैसे देशों द्वारा हमारे देश में भारी मात्रा में दुग्ध उत्पादों के निर्यात करने की आशंका निराधार नहीं है।

पिछले पांच सालों से दूध के दाम किसान स्तर पर बहुत कम चल रहे हैं और दुग्ध पशुपालक किसान की हालत पहले ही खराब है। हालांकि हाल के कुछ महीनों में किसान स्तर पर दूध की कीमतों में कुछ सुधार हुआ है। यदि आरसीईपी समझौते में दुग्ध उत्पादों के आयात को मुक्त कर दिया गया तो किसान स्तर पर दूध के दाम 40 प्रतिशत तक गिर जाने की आशंका है। इतने कम दामों पर दुग्ध उत्पादन का खर्चा निकलना भी असंभव होगा। डेयरी किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और किसानों की आमदनी पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसान पशुपालन से विमुख हो जाएंगे। पहले से ही संकट से जूझ रही कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गहरे संकट में फंस जाएगी और देश दुग्ध उत्पादों के लिए आयात पर निर्भर हो जाएगा।

हमारे देश में लगभग 10 करोड़ डेयरी किसान हैं यानी लगभग 50 करोड़ लोग दुग्ध उत्पादन से होने वाली आमदनी पर निर्भर हैं। दुग्ध व्यापार और दुग्ध उत्पादों से जुड़े संगठित व असंगठित क्षेत्र के अन्य लोगों को जोड़ दें तो यह संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। दुग्ध उत्पादन रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक अति आवश्यक कृषि गतिविधि है। दुग्ध उत्पादन में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी लघु, सीमांत और भूमिहीन किसानों की है। अतः इन कमजोर वर्ग के किसानों के लिए तो दुग्ध उत्पादन एक जीवन रेखा की तरह है। किसान परिवारों के बच्चों को पोषक खुराक उपलब्ध कराने का दूध बड़ा माध्यम है। किसान परिवार की महिलाओं का इससे आर्थिक सशक्तीकरण भी होता है। ऐसे में आरसीईपी जैसे किसी भी मसले पर सरकार को समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए।

खरी-खरी

घर-घर से मच्छर क्यों निकला?

अतुल कनक

इन दिनों मेरा शहर मौसमी बीमारियों की पकड़ में है। मच्छरों ने जीना दूभर कर दिया है। अपने घर के मच्छरों को मारो तो पड़ोसी के घर से भगाए हुए मच्छर भिनभिनाने लगते हैं। मच्छरों ने भी 'घर-घर से मच्छर निकलेगा' टाइप का नाटक शुरू कर दिया है। आम आदमी आतंकवाद से उतना नहीं डरता, जितना मच्छरों से डरने लगा है। इसका एक बड़ा कारण तो यह है कि आतंकवाद अब डरने की नहीं, मुकाबला करने की चीज हो गया है। जिस तरह आतंक का कोई देश नहीं होता, ठीक उसी तरह से मच्छरों का भी कोई मोहल्ला नहीं होता। वो पड़ोसी मोहल्ले से आकर भी काट सकते हैं।

मच्छर भिनभिनाता हुआ आता है कुछ देर के लिए इधर-उधर हो जाता है। हमने आजादी के बाद सोचा था कि देश के विभाजन के बाद सर्वत्र शांति होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुष्टीकरण के मच्छर इधर-उधर छुप गए और मौका पाकर भिनभिनाने लगे। आतंकवादी हों या मच्छर, उन्हें आदमी का खून पीने की लत लग जाती है और वो आसानी से भिनभिनाना नहीं छोड़ते। हद तो यह है कि वो हमारा खून भी पीते हैं और हमारे परिवेश को बीमार भी करते हैं। हम उन्हें बर्दाश्त करें तो कोई फिल्मी अदाकार यह कहकर हमारी हंसी उड़ाता है कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। लेकिन हम उन्हें खत्म करने की कोशिश करें तो मच्छर और उनके पैरोकार इकट्ठा हो नारे लगाने लगते हैं कि घर-घर से मच्छर निकलेगा। मच्छरों ने लोकतंत्र को दुविधा में डाल दिया है।

पिछले कुछ दिनों से मेरे शहर में मच्छरों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मैं परेशान हूं। सारी रात मच्छरों से जूझने में निकल जाती है। मच्छरों के कारण शहर में कई लोग बुरी तरह बीमार हो गए हैं। अब बीमारी कोई आदमी से पहचान पूछकर तो आती नहीं।

मच्छर भी किसी को काटने के पहले यह नहीं पूछते कि आप किस पार्टी के समर्थक हैं। आप जिस आदमी से एक दिन पहले मिले हों, उसी के बारे में आपको यह सूचना मिल सकती है कि वो अचानक डेंगू या मलेरिया का शिकार हो निकल लिया।

मच्छर भिनभिना रहे हैं। मैं नहीं जानता कि ये भिनभिनाते हुए आपस में क्या बात कर रहे हैं? हो सकता है कि वे आतंक के नए मंसूबे बुन रहे हों या फिर आने वाले किसी चुनाव में किसी विशेष पार्टी को कैसे हराएं, इसकी योजना बना रहे हों!

ट्वीट-ट्वीट

आखिरकार राजनीतिक दबाव काम आया और मोदी सरकार ने आरसेप करार पर आगे न बढ़ने का फैसला किया। यह एक और मिसाल है कि विपक्ष किसी मसले पर कैसे फर्क डाल सकता है।
शिवम विज@DilliDurAst

आरसेप से पीछे हटकर पीएम मोदी ने सही किया। इसमें चीन का दबदबा होता जो भारत के बिल्कुल हित में नहीं होता। आखिर में समझदारी का पलड़ा ही भारी रहा। मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर भारत का अनुभव यही बताता है कि इससे व्यापार हिस्सेदारी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में आरसेप बहुत जोखिम भरा होता।
रूपा सुब्रमण्या@rupasubramanya

दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे कौन प्रभावित होगा? दिहाड़ी मजदूर। बेहतर होता कवर लगाकर कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जाती और इसका उल्लंघन करने पर ठेकेदार पर कार्रवाई होती, पर प्रतिबंध को बढ़ा दिया।
शिल्पी तिवारी@shilpitewari

महाराष्ट्र डायरी

आत्मघाती कदम बढ़ाती शिवसेना

ओमप्रकाश तिवारी
मुंबई ब्यूरो प्रमुख

महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में प्रचलित एक कहावत है- 'हांव मरीन पर तुका रांड करीन'। अर्थात मैं चाहे मर जाऊं पर तुझे रांड करके छोड़ूंगा। कोंकणी पुरुष के आत्मसम्मान की इसी आत्मघाती कल्पना को आज शिवसेना चरितार्थ करती दिखाई दे रही है। उसने भाजपा के साथ गठबंधन करके प्रचार का नारियल साथ-साफ फोड़ा। दोनों के झंडे साथ-साथ लहराते रहे। प्रचार सभाओं में दोनों के नेता साथ-साथ भाषणबाजी करते दिखाई दिए। कुछ सभाओं में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी एक साथ एक ही मंच पर नजर आए।

प्रधानमंत्री ने उद्धव ठाकरे को अपना 'लहान भाऊ' यानी छोटा भाई कहकर संबोधित किया, तो उद्धव भी उनकी तारीफों के पुल बांधने में पीछे नहीं रहे। राज्य की जनता ने वोट भी शिवसेना-भाजपा गठबंधन को दिया, ना कि इन दोनों में से किसी एक दल को। और अब शिवसेना कांग्रेस- राकांपा के साथ मिलकर शिवतीर्थ पर अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का स्वप्न देख रही है, और राकांपा के नेताओं को 'जय महाराष्ट्र' का संदेश भेज रही है।

यह सोशल मीडिया का युग है। आम मतदाता न सिर्फ अपनी पसंद के राजनीतिक दलों के पक्ष में खुलकर विचार व्यक्त करते हैं, बल्कि वाट्सएप और फेसबुक पर अपने विरोधी विचार के अपने ही मित्रों-रिश्तेदारों से तू-तू मैं-मैं भी कर बैठते हैं। ऐसे युग में गठबंधन किसी एक दल से और सरकार किसी और दल के साथ, यह जादूगरी शिवसेना के मतदाताओं को पसंद आए, यह जरूरी नहीं। राजनीतिक गठबंधनों द्वारा पद के लिए सौदेबाजी कोई नई बात नहीं है। सियासत करने उतरे दलों को अपने विस्तार के लिए यह करना ही पड़ता है। लेकिन एक ही गठबंधन के दो दलों के बीच इस प्रकार की सार्वजनिक बयानबाजी उस मतदाता को भी पसंद नहीं आती, जिसने इन दलों को चुनकर सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।

विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही शिवसेना की तरफ से ढाई-ढाई वर्ष के मुख्यमंत्री पद और मंत्रालयों के 50-50 बंटवारे की जिद सामने आ रही है। जबकि शिवसेना की सीटें भाजपा से लगभग आधी आई हैं। शिवसेना किस तर्क के आधार पर यह मांग कर रही है, यह समझ से परे है। करीब तीन दशक पुराने शिवसेना-भाजपा गठबंधन के लंबे दौर में 1995 के चुनाव को मानक माना जाए या उसके बाद 2009 तक के किसी भी अन्य विधानसभा चुनाव को, लड़ी गई सीटों पर जीत का प्रतिशत हमेशा भाजपा का ही ज्यादा रहा है। इसके बावजूद 1995 में शिवसेना का मुख्यमंत्री और भाजपा का उपमुख्यमंत्री बना था। वर्ष 1999 के चुनाव के बाद भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे भी ढाई साल के मुख्यमंत्री की ऐसी ही जिद किए बैठे रहे, जैसी आज शिवसेना कर रही है। नतीजा यह रहा कि 11 दिन चले नाटक के बाद मिलकर चुनाव लड़ीं शिवसेना-भाजपा सत्ता से दूर रह गईं, और अलग-अलग चुनाव लड़ीं कांग्रेस-राकांपा ने मिलकर ऐसी सरकार बनाई कि अगले 15 वर्षों तक भाजपा-शिवसेना को सत्ता का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। आज वही गलती एक बार फिर शिवसेना दोहराती दिखाई दे रही है। यह सच है कि चुनाव में भाजपा की सीटें घटी हैं। लेकिन यह भी सच है कि सीटों में यह कमी लोकप्रियता घटने के कारण नहीं, बल्कि लोकप्रियता बढ़ने के कारण आई है। दोनों दलों के बागी उम्मीदवारों की संख्या इस बार अभूतपूर्व रही है। बागी उम्मीदवार उन्हीं दलों के ज्यादा होते हैं, जिनके चुनकर आने की संभावना अधिक होती है। 15 से अधिक सीटों पर भाजपा के बागी उम्मीदवार चुनकर आए हैं। इन सीटों पर भाजपा के अधिकृत उम्मीदवारों को भी उसके बागी उम्मीदवार से कुछ ही कम वोट मिले हैं। जाहिर है, ऐसी सभी सीटों पर बागी और अधिकृत उम्मीदवारों को मिले मत कांग्रेस-राकांपा के कोटे से आए मत तो नहीं रहे होंगे। यानी भाजपा की सीटें भले घटी हों, लेकिन उसका मत प्रतिशत बढ़ा है।

वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़कर जमीनी हकीकत जान चुकी शिवसेना को यह तथ्य नजरंदाज नहीं करना चाहिए। संभव है, उसके समर्थन के बगैर भाजपा को अल्पमत सरकार के रूप में शपथ लेनी पड़े और वह सदन में अपना बहुमत न सिद्ध कर पाने के कारण गिर जाए। संभव है, ऐसी स्थिति में विपक्ष में बैठने का जनादेश पानेवाली कांग्रेस- राकांपा शिवसेना को अंदर या बाहर से समर्थन देने पर राजी हो जाएं। संभव है, शिवसेना अपने चिर विरोधी इन दोनों दलों के सहयोग से मंत्रालय में शिवसेना का मुख्यमंत्री बैठाने का स्व. बालासाहब ठाकरे का सपना पूरा कर ले। लेकिन कांग्रेस- राकांपा कितने दिनों या महीनों तक शिवसेना के मुख्यमंत्री को झेलती रहेंगी, या शिवसेना का मुख्यमंत्री कितनी निश्चिंतता से राज्य का शासन चला पाएगा, इसका अनुभव एक बार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी से शिवसेना को जरूर लेना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में शिवसेना की सरकार गिरती है, तो उसके पास न आगे जाने का रास्ता रहेगा, न पीछे लौटने का। यह कदम उसके लिए आत्मघाती ही साबित होगा। जबकि शिवसेना की जिद वश सरकार से दूर हो जानेवाली भाजपा तब जनता की सहानुभूति की हकदार होगी।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आसियान देशों के साथ सहयोग बढ़ाना भारत के लिए अधिक फायदेमंद होगा?

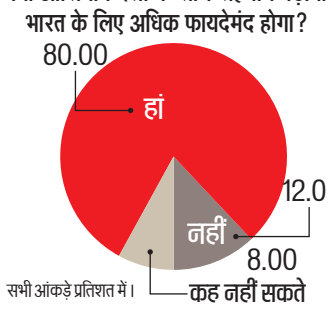

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या शिवसेना का रुख महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता की आशंका बढ़ा रहा है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

गठबंधन करके गए जो जनता के पास,
जनता की उनसे लगी है सत्ता की आस।
है सत्ता की आस मगर वे अब ना राजी,
आपस में ही आज करें वे सौदेबाजी।
हो कुदरत से त्रस्त कृषक करते हैं क्रंदन,
पर कुर्सी की जंग लड़ रहा है गठबंधन।
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

करतारपुर बनेगा शांति का मार्ग!

विजय कपूर
वरिष्ठ पत्रकार

करतारपुर गलियारे को बनाने का काम जितनी तेजी से पूरा किया जा रहा है, क्या इससे दोनों देशों के संबंधों में भी सुधार आने की उम्मीद की जा सकती है? यह सवाल भी अहम है

गुरुनानक देव का महत्व व कृपा इतनी असीम है कि उनका शब्दों में वर्णन करना कठिन है। गुरुनानक देव न केवल सिख धर्म के संस्थापक हैं, बल्कि हिंदुओं व मुस्लिमों के बीच शांति व आपसी संबंधों का पुल बनाने में भी उनकी भूमिका के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अपने जन्म के 550वें वर्ष में भी वे भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की भूमिका में हैं। इसलिए यह प्रश्न प्रासंगिक हो जाता है कि क्या करतारपुर दोनों पड़ोसियों के बीच शांति का गलियारा बनेगा?

करतारपुर गलियारा सिखों के दो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों- डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर, भारत) और गुरुद्वारा दरबार साहिब (करतारपुर, पाकिस्तान)- को आपस में जोड़ता है। भारतीय सीमा से महज साढ़े चार किमी के फासले पर करतारपुर वह स्थान है, जहां बाबा नानक ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष गुजारे। 12 नवंबर को उनका 550वां जन्मदिवस है और इसी को ध्यान में रखते हुए नौ नवंबर को 550 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था करतारपुर साहिब जाएगा, जिसे फ्लैग ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं।

यह यात्रा वीजा-रहित रहेगी, लेकिन हर तीर्थयात्री को सर्विस चार्ज के रूप में 20 डॉलर अदा करने होंगे। स्टेट-ऑफ- द-आर्ट करतारपुर गलियारे का खोला जाना दोनों देशों के संबंध में ऐतिहासिक पल है। इसका खुलना ऐसे समय हो रहा है, जब दोनों देशों के पास एकत्र की गई दुश्मनी दिखाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संदर्भ में यह वर्ष अप्रत्याशित रूप से बहुत खराब रहा है- पुलवामा, पाकिस्तान के भीतर आइएएफ ऑपरेशन और कश्मीर पर सरकारी निर्णय को लेकर वाक युद्ध। इस पृष्ठभूमि में करतारपुर गलियारा समझौता एकमात्र सकारात्मक प्रयास है। यह इसलिए अमल में आ सका, क्योंकि दोनों नई दिल्ली व इस्लामाबाद ने इतनी समझदारी दिखाई कि इसे शेष संबंध (या तनाव) से अलग रखा। अलबत्ता इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसा करने में दोनों के ही अपने स्वार्थ काम कर रहे थे।

पाकिस्तान में सिखों के अनेक महत्वपूर्ण धर्मस्थल हैं, जिनकी वजह से उसे लगता है कि वह सिख समुदाय से विशेष संबंध स्थापित कर सकता है। उसने सक्रियता से ऐसा किया भी है। दूसरी ओर इस सिलसिले में भारत पिछड़ता हुआ नजर नहीं आ सकता, विशेषकर देश विभाजन के बाद पंजाब के जटिल राजनीतिक इतिहास को मद्देनजर रखते हुए। यह समझौता भारत के सिख समुदाय के लिए वरदान है, जिसके पास गुरुनानक देव के 550वें जन्म वर्ष से आरंभ करते हुए अब यह अवसर है कि सड़क के जरिये डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर, भारत) से सीधे गुरुद्वारा दरबार साहिब (करतारपुर, पाकिस्तान) पहुंचा जाए। सिख समुदाय का इससे विभाजन का एक जख्म भर सकता है।

वैसे बीस डॉलर प्रति तीर्थयात्री सर्विस चार्ज पर काफी हंगामा व विवाद हुआ है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने तो इसे जजिया तक कह डाला। यह जनता को खुश करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। नई दिल्ली का यह दावा भी सही नहीं है कि इस प्रकार की फीस देश की धार्मिक- सांस्कृतिक भावना के अनुरूप नहीं है। भारत में बड़े व प्रमुख मंदिर 'विशेष दर्शन' या 'जल्द दर्शन' की अच्छी खासी फीस लेते हैं, जिसे तीर्थयात्री बिना किसी शिकायत के अदा करते हैं। चीन मानसरोवर झील जाने वाले तीर्थयात्रियों से फीस लेता है और भारत ने इस पर कभी आपत्ति नहीं की, उस समय भी नहीं जब कुछ वर्ष पहले इसमें वृद्धि की गई थी। हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों से भी सऊदी अरब फीस लेता है, इस पर भी नई दिल्ली ने कभी आपत्ति नहीं की है। इसलिए भारत ने यह सही किया कि करतारपुर साहिब की फीस माफी की मांग को छोड़ दिया। यह फीस समझौते द्वारा सुरक्षित है और इसमें किसी प्रकार की भी वृद्धि दोनों सरकारों की सहमति से ही होगी। कई तरह से करतारपुर समझौता 1960 की 'इंडस वाटर्स ट्रीटी' से मिलता जुलता है। वह भी उस समय तय हुआ था जब दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर तनाव था, हालांकि तब विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। वह भी अपने समय का इकलौता समझौता था और द्विपक्षीय संबंधों में जो निरंतर उतार-चढ़ाव आए हैं उन्हें बर्दाश्त करता रहा है यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उम्मीद है कि करतारपुर समझौता भी इतना ही सशक्त रहेगा। इस समय यह आशा करना अव्यवहारिक होगा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच विस्तृत सकारात्मक तालमेल के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन इससे इतना तो प्रतीत होता ही है कि दोनों पक्ष स्थिति को बेहतर करने की क्षमता रखते हैं, बस अभी इच्छा प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। हां, इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि राजनीति में कल्पना व अनुमान के बाहर की चीजें भी संभव हो जाती हैं।

यह दुर्लभ पल है और इसके आध्यात्मिक व धार्मिक महत्व की पवित्रता को मैला करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। समझौते में जो तीर्थयात्रा को संकटकाल के कारण स्थगित करने और एक माह के नोटिस पर समाप्त करने का प्रावधान रखा गया है, उससे यही प्रतीत होता है कि दोनों देशों को एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं है। इस प्रावधान से यह चिंता बल पाती है कि राजनीतिक घटनाक्रम तीर्थयात्रा को प्रभावित कर सकता है। भारत ने यह लाइन पकड़ी हुई है कि पाकिस्तान आतंक पर विराम लगाए तभी वार्ता होगी। तनाव के समय को छोड़कर भारत ने पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को अजमेर शरीफ दरगाह व अन्य तीर्थस्थलों पर जाने की अनुमति दी है। करतारपुर गलियारे का प्रयोग करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बहुत अधिक होगी, इसलिए यह विस्तृत राजनयिक संपर्क का आधार बन सकता है।

गुरुनानक देव की कृपा से करतारपुर भारतीय उपमहाद्वीप के दो झगड़ालू व परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच स्थायी लिंक है। जहां हाल का अतीत विभाजित करता है, वहां इतिहास जोड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान को इन धार्मिक-सांस्कृतिक अवसरों को पकड़ लेना चाहिए ताकि राजनीतिक व आर्थिक मिलाप का कोई मार्ग बाबा नानक की कृपा से निकल आए।

-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

30 नवंबर को अबूधाबी में जेम्स बांड सीरीज की आखिरी फिल्म स्पेक्टर की उस कार की नीलामी होने जा रही है, जिसे फिल्म के मुख्य विलेन मिस्टर हिंक्स ने चलाया था। जगुआर सी-एक्स 75 मॉडल की कार की बोली 8.4 करोड़ रुपये लगने की उम्मीद है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 5 नवंबर 2019

डाटागीरी

उच्च आय वाले देशों में बढ़ रहे हैं पैंक्रियाटिक कैंसर के मामले

कभी दुर्लभ बीमारी कहे जाने वाले पैंक्रियाटिक (अग्नाशय) कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अहम बात यह है कि सबसे ज्यादा मामले उच्च आय वाले देशों में समाने आ रहे हैं। निम्न आय वाले देशों में इनकी संख्या बहुत ही कम है। अध्ययन में कहा गया है कि उच्च आय वाले देशों में जीवन प्रत्याशा ज्यादा होती है इसलिए मामले ज्यादा आते हैं। बढ़ती उम्र में पैंक्रियाटिक कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली

पैंक्रियाटिक (अग्नाशय) कैंसर के मामलों में पिछले दो दशकों में तेजी से वृद्धि हुई है। कभी दुर्लभ मानी जाने वाली यह बीमारी अब कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारक है। 1990 में दुनियाभर में जहां पैंक्रियाटिक कैंसर के मामले 1,96,000 थे, वहीं 2017 में ये मामले बढ़कर 4,41,000 हो गए हैं। यह जानकारी जर्नल लैंसेट में छपी 'द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज 2017' की रिपोर्ट से से सामने आई है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च आय वाले देशों में सबसे ज्यादा पैंक्रियाटिक कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। 1990 और 2017 दोनों ही सालों में कैंसर की वजह से होने वाली सबसे ज्यादा मृत्युदर ग्रीनलैंड (17.4 प्रति एक लाख) और उरुग्वे (12.1 प्रति एक लाख) में रिकॉर्ड की गई। वहीं, दूसरी ओर पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह होने वाली सबसे कम मृत्युदर बांग्लादेश (1.9 प्रति एक लाख) दर्ज की गई।

रिपोर्ट में बताया गया कि निम्न आय वाले देशों में पैंक्रियाटिक कैंसर के मामलों में कमी होने का कारण कम जीवन प्रत्याशा है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे पैंक्रियाटिक कैंसर का खतरा बढ़ने लगता है। जीवन के चौथे दशक में पैंक्रियाटिक कैंसर का खतरा कम (पांच प्रति एक लाख) होता है। वहीं, आठवें दशक में (60 प्रति एक लाख) हो जाता है।

कहा जाता है साइलेंट किलर : पैंक्रियाटिक कैंसर अग्नाशय का कैंसर होता है। इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि आरंभ में इस कैंसर को लक्षणों के आधार पर पहचाना जाना मुश्किल होता है और बाद के लक्षण प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं। सामान्यतः इस कैंसर के लक्षणों में एबडोमेन के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, भूख कम लगती है, तेजी से वजन कम होने की दिक्कतें, पीलिया, नाक में खून आना, उल्टी होना जैसी शिकायत होती है।

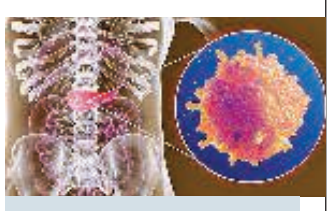

भारत में मामलों में हुई बढ़ोतरी

भारत में पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से होने वाली मृत्यु दर में पांच गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1990 में जहां 6,824 मौत हुई थीं, वहीं 2017 में इस कैंसर से 29,059 लोगों की जान गई। जहां 1990 में पैंक्रियाटिक कैंसर के कुल 6,887मामले दर्ज किए गए थे वहीं, 2017 में 30,426 मामले दर्ज किए गए। इस मामले में दक्षिण एशियाई देशों में भारत सबसे आगे रहा। इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है जहां पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से 1990 में 848 और 2017 में 2,653 मौते हुईं। इस पूरे क्षेत्र में भूटान में सबसे कम मामले आए और सबसे कम मौतें भी हुईं। यहां 1990 और 2017 में क्रमशः चार और 17 मामले सामने आए थे और इन सभी की मृत्यु हो गई थी।

देश	मामले		मृत्यु	
	1990	2017	1990	2017
भूटान	4	17	4	17
नेपाल	136	563	134	531
बांग्लादेश	731	2159	709	2051
पाकिस्तान	848	2653	817	2593
भारत	6,887	30,426	6,824	29,059
दक्षिण एशिया	8,607	35,820	8488	34252
कुल	1,95,861	4,41083	1,95413	4,47,665

36 डिग्रियां हासिल कर दशरथ बने दुनिया के सबसे पढ़े-लिखे व्यक्ति

कीर्तिमान ▸ सेना के जवान रहे सिंह का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम हुआ दर्ज

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर रहा है उनके दावे की जांच

मनीष गोधा, जयपुर

पंजाब, जम्मू-कश्मीर, असम जैसे इलाकों में सेना नौकरी के बावजूद पढ़ाई का ऐसा जुनून कि 51 डिग्रियां, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हासिल कर लिए। यह उपलब्धि हासिल की है, राजस्थान के जांबाज सिपाही रहे डॉ. दशरथ सिंह ने। सेना की नौ राजपूताना रेजिमेंट में सिपाही रहे दशरथ सिंह का नाम हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 'मोस्ट एजुकेशनली क्वालिफाइड पर्सन ऑफ द वर्ल्ड' यानी विश्व के सबसे ज्यादा शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति के रूप में दर्ज किया है। इस रिकॉर्ड बुक ने उनकी 36 डिग्रियों को उनके नाम के साथ रिकॉर्ड बुक में शामिल किया है। अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से उनके दावे की जांच की जा रही है।

डॉ. दशरथ सिंह अब तक मुख्य रूप से भूमि सुधार विषय पर पीएचडी, 15 विषयों में मास्टर्स, आठ में स्नातक, विधि से संबंधित 11 और सेना से संबंधित आठ विषयों में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा उनका चयन राजस्थान में द्वितीय श्रेणी शिक्षक और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी हो चुका है, लेकिन वे इन सरकारी सेवाओं को छोड़कर इन दिनों सेना के दक्षिण-पश्चिम कमान में विधि परामर्शी का काम कर रहे हैं। सेना में राजस्थान से सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले झुंझुनूं जिले की नवलगढ़ तहसील के खिरोडसर गांव के रहने वाले दशरथ सिंह को पहली पोस्टिंग पंजाब में मिली थी। इसके बाद उल्फा आंदोलन के दौरान असम में रहे। इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स के पहले बैच में शामिल कर जम्मू-कश्मीर भेज दिया गया। यहां उन्होंने साढ़े तीन साल नौकरी की। लगातार फील्ड ड्यूटी के बाद उन्हें कुछ समय के लिए लखनऊ भेजा गया, लेकिन इसी दौरान संसद पर हमले की वारदात हुई तो उन्हें वापस जम्मू-कश्मीर भेज दिया गया। बाद में वह कारगिल युद्ध में शामिल रहे।

दशरथ सिंह। फाइल फोटो

बचपन से रहा पढ़ाई का शौक : दशरथ सिंह ने बताया, 'पढ़ने का शौक बचपन से ही था, लेकिन पैसे नहीं थे। दादा और पिता भी सेना में थे, लेकिन परिवार बड़ा होने की वजह से आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि पढ़ाई को जारी रखा जाए। दसवीं तो कर ली, लेकिन कॉलेज में प्रथम वर्ष के बाद ही सेना में चले गए। सेना में रहते हुए भी यह कसक रही कि पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। इसलिए रिटायरमेंट के बाद पढ़ाई शुरू की। पहली डिग्री बैचलर ऑफ आर्ट्स की ली और आखिरी समाजशास्त्र में एमए की है। अभी गांधी पीस स्टडीज में डिप्लोमा कर रहा हूं।' दशरथ सिंह ने एलएलबी, एलएलएम, बीजेएमसी और बीएड की डिग्री नियमित छात्र के रूप में ली है, बाकी डिग्री और डिप्लोमा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, जैन विश्व भारती लाडनूं और दो-तीन निजी विश्वविद्यालयों से प्राप्त की हैं। उन्होंने बताया कि सेना में था तो एक ही विश्वविद्यालय की परीक्षा देता था, लेकिन अब दो-तीन पाठयक्रम एक साथ चलते हैं।

अब तक 500 से ज्यादा परीक्षाएं दे चुके

दशरथ अब तक 500 से ज्यादा परीक्षाएं दे चुके हैं और लगभग सभी में 50 से लेकर 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। उन्होंने बताया कि सेना में दो महीने की छुट्टी हर साल मिलती है। वह कहते हैं, 'मैं यह छुट्टी मई-जून में ही लेता था। नौकरी के दौरान कभी होली-दिवाली या अन्य त्योहारों के लिए छुट्टी नहीं ली। रिटायरमेंट के बाद फिर सरकारी नौकरी मिली, लेकिन लगा कि सैनिकों के लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए कानून की डिग्री हासिल कर वकालत शुरू कर दी। दो वर्ष पहले सेना ने बुला लिया और अब जयपुर में सेना की सप्तशक्ति कमांड में विधि परामर्शी के रूप में सेना, सैनिकों और पूर्व सैनिकों से जुड़े मामले देखता हूं।' उनका कहना है कि अब तक 250 से ज्यादा सैनिकों के केस लड़े हैं और ज्यादातर में सफलता हासिल हुई है।

मप्र में 5.88 करोड़ से 14 एकड़ में बनेगा 'अध्यात्म गो मंदिर'

नईदुनिया, खंडवा : मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के गांव हरसवाड़ा में सोमवार को प्रदेश के पहले अशासकीय गो चिकित्सालय का भूमिपूजन हुआ। 5.88 करोड़ रुपये से 14 एकड़ में यह परिसर तैयार होगा। इसे अध्यात्म गो मंदिर नाम दिया गया है। इसमें गो चिकित्सालय के साथ गो गोपाल मंदिर, गोशाला और संतों व साधकों के लिए कुटिया भी बनाई जाएगी। एक वर्ष में इसे तैयार करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी आने वाले थे, लेकिन उड़ान निरस्त होने से वे नहीं आ सके। अध्यात्म गोसेवा मिशन के पं. पंकज शास्त्री ने बताया कि गो मंदिर में गोमूत्र पर रिसर्च होगी।

ये होंगी खासियत

- अध्यात्म गो मंदिर में बीमार गायों को लाने के लिए चार एंबुलेंस रखी जाएंगी। ये एंबुलेंस 100 किलोमीटर दूर से गायों को लेकर आएंगी, उपचार के बाद वापस भी छोड़ेंगी।
- यहां गो गोपाल का मंदिर बनेगा। इसमें गायों के साथ ग्वाल रूप में भगवान श्रीकृष्ण विराजित होंगे। निराश्रित गायों को रखने के लिए गोशाला भी बनेगी।
- यहां संतों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। वृद्धजनों के लिए साधक कुटिया बनेगी, जो यहां निःशुल्क रुककर गोसेवा कर सकेंगे।
- यहां गायों के बैठने के लिए मेट बिछाई जाएगी। प्रतिदिन मेट बदलेगी।

परीक्षा के 24 दिन पहले हुए घायल, 17-17 घंटे की पढ़ाई, पहली बार में ही बने आइएएस

नईदुनिया, धार

मध्य प्रदेश के धार जिले में बतौर सहायक कलेक्टर की जिम्मेदारी संभालने आए उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले आइएएस अमन वैष्णव के इस मुकाम को हासिल करने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। असल में 28 अक्टूबर, 2017 को उन्हें मुख्य परीक्षा देनी थी, लेकिन उससे 24 दिन पहले ही एक दुर्घटना में वह घायल हो गए। उनके हाथ में गंभीर चोट आई थी। बैठकर पढ़ाई करना मुश्किल था, लेकिन सपना पूरा करने की जिद नहीं छोड़ी। दिल्ली छोड़कर घर नहीं गए और माता-पिता को अपने पास बुला लिया। समय कम था। इसलिए एक दिन में 17-17 घंटे तक पढ़ाई की। चोटिल थे, लेकिनी परीक्षा दी और परिवार के पहले आइएएस बने। उन्होंने यह परीक्षा पहली बार में ही पास की।

प्रशिक्षु आइएएस अमन वैष्णव को 10 माह के लिए धार जिले में सहायक कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वैष्णव ने बताया कि पहले ही प्रयास में उनका आइएएस में चयन हो गया था। पिता रामसेवक श्रीवास रेलवे में नौकरी करते हैं। 12वीं के बाद तैयारी के लिए अमन दिल्ली चले गए, जहां हिंदू कॉलेज से बीए (राजनीति में) किया। इसके साथ ही यूपीएससी की तैयारी की। पहले ही प्रयास में 2017 में एग्जाम देने के बाद 2018 में चयन हो गया। 10 माह मसूरी में ट्रेनिंग के बाद मप्र का धार जिला मिला है। इसके बाद मसूरी में फिर प्रशिक्षण के बाद किसी भी जिले में नियुक्ति होगी।

प्रेरक

- उत्तर प्रदेश के झांसी के प्रशिक्षु आइएएस अमन मध्य प्रदेश के धार जिले में आए ट्रेनिंग पर

अमन वैष्णव फाइल फोटो

अंग्रेजी बोलने में कमजोर थे, चार घंटे न्यूज पेपर पढ़ते थे : अमन ने बताया कि वह अंग्रेजी बोलने में कमजोर थे। इसके लिए तीन से चार घंटे अंग्रेजी न्यूज पेपर पढ़ते थे। शब्दकोश बढ़ा। फिर कोचिंग की मदद भी ली। अंग्रेजी उपन्यास भी पढ़ते थे। इससे साक्षात्कार में लाभ मिला।

खुद पर रखें आत्मविश्वास : सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों के लिए अमन वैष्णव ने बताया कि इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट के अलावा भी सवाल पूछे जाते हैं। साक्षात्कार लेने वाले जवाब के साथ आपका आत्मविश्वास भी परखते हैं। अखबार पढ़ने से मदद मिलती है। अमन ने बताया कि कभी बाइक से तीन से चार किमी दूर अखबार लेने जाना पड़ता था, लेकिन अखबार पढ़ने के बाद ही आगे काम शुरू करते थे। अमन ने बताया कि वह जिले के टॉपर रहे हैं। 12वीं में उन्हें 97 प्रतिशत अंक मिले थे।

इस सवाल ने डाला प्रभाव : अमन ने बताया कि इंटरव्यू में उनसे स्वच्छता का एक सवाल पूछा गया था। आज-कल राजनेता पहले कचरा फैलाकर नई झाड़ू लेकर सफाई करते हैं। इसे आप क्या मानते हैं। अमन ने बताया, 'मैंने कहा कि 70 साल बाद आज राजनेता झाड़ू तो उठा रहे हैं। यह पहला स्टेप है। इसके अलावा समाज से जुड़े कुछ सवाल थे।'

हरिद्वार में हाथियों पर लगेंगे रेडियो कॉलर

- जनसुरक्षा और 2021 में होने वाले कुंभ के मद्देनजर उठाया जा रहा कदम
- मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने वन्यजीव संस्थान के इस प्रस्ताव को दी मंजूरी

रेडियो कॉलर से हाथियों का मूवमेंट का पता चलेगा। प्रतीकात्मक

केदार दत्त, देहरादून

धर्मनगरी हरिद्वार में गजराज के आक्रामक व्यवहार ने वन महकमे की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। चिंता ये बढ़ गई है कि 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होना है। ऐसे में हाथियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसे देखते हुए अब हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाकर उनकी निगरानी का निर्णय लिया गया है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्यूआइआइ) के कुंभ के परिप्रेक्ष्य में हरिद्वार क्षेत्र में हाथियों की रेडियो कॉलरिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वन विभाग और संस्थान की टीम संयुक्त रूप से यह कार्य करेगी। रेडियो कॉलर लगने पर पता चल जाएगा कि हाथियों का मूवमेंट किस तरफ है, जिससे आसपास के क्षेत्र को अलर्ट कर दिया जाएगा।

राजाजी टाइगर रिजर्व से लगे हरिद्वार क्षेत्र में हाथियों के आंतक से क्षेत्रवासी त्रस्त हैं। गत शनिवार को ही पथरी क्षेत्र के पिंजनहेड़ी गांव में बिगड़ैल हाथी ने दो लोगों को मार डाला था। इससे पहले भी बीएचईएल से लगे गांवों में हाथी ने दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी थी। हाथियों के हमले की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश न लग पाने से विभाग की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ रही है।

पिंजनहेड़ी की घटना के बाद महकमा अब जाकर हाथियों की आबादी क्षेत्र में धमक को लेकर गंभीर हुआ है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजीव भरतरी ने माना कि हाथियों का यह आक्रामक व्यवहार चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि डब्ल्यूआइआइ ने हरिद्वार में कुंभ के मद्देनजर हाथियों पर रेडियो कॉलर लगाने की अनुमति मांगी थी। इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

उन्होंने बताया कि संस्थान व वन विभाग की संयुक्त टीम हाथियों पर निगरानी के मद्देनजर रेडियो कॉलर लगाएगी। यह कार्य मंगलवार या बुधवार से शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत चिह्नित बिगड़ैल हाथियों के अलावा प्रमुख झुंडों के एक-एक हाथी पर रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। इससे यह पता चल जाएगा कि हाथियों का मूवमेंट किस तरफ है। ऐसे में संबंधित क्षेत्र के लोगों को समय रहते अलर्ट करने के साथ ही हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने को प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।

30 गांव हैं हाथियों से प्रभावित : हरिद्वार क्षेत्र के 30 गांव हाथियों के आतंक से त्रस्त हैं। इनमें पथरी क्षेत्र का पिंजनहेड़ी भी शामिल है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने बताया कि पिंजनहेड़ी समेत अन्य गांवों में वन सीमा पर चिह्नित स्थलों पर सोलर पावर फैंसिंग लगाने के आदेश दिए जा रहे हैं।

> हाथी समेत दूसरे वन्यजीवों के हमले की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विभाग को हरसंभव कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। वन्यजीवों के हमलों और इनके व्यवहार में आ रहे बदलाव के कारणों की पड़ताल के लिए वरिष्ठ आइएफएस समीर सिन्हा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जा रही है।
>
> **- डॉ. हरक सिंह रावत, वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तराखंड**

सेल्फी का चक्कर बना रहा सेल्फाटिस का मरीज

शोध

अनुज शुक्ल, लखनऊ

सेल्फी...। सहेजने हों खास पल या छाना हो सोशल मीडिया पर। तकनीक की दुनिया में इससे बढ़िया जरिया कोई नहीं। जब और जहां चाहा, अपनों के दिल में दस्तक दे दी। कामकाज के लिहाज से देखें तो सहूलियत भी बेशुमार, लेकिन अफसोस...। शौक से शुरू हुआ सेल्फी का सिलसिला इस कदर जुनून बनकर दिमाग पर हावी हो गया है कि सनक का भयावह रूप बन बैठा। आलम यह है कि लखनऊ स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) में गंभीर मानसिक बीमारी बन रहे शौक से छुटकारे के लिए रोज चार से पांच मरीज पहुंच रहे हैं। लोगों को दीन-दुनिया से विरक्त कर घर-घर पनप रही इस बीमारी को डॉक्टरों ने नाम दिया है-सेल्फाइटिस।

मौका खुशी का हो या गम का, सेल्फी का शौक हावी होता जा रहा है। प्रतीकात्मक

खास बात यह कि पीजीआइ पहुंच रहे मरीजों में मुश्किल इतनी भर नहीं है। बाल रोग विशेषज्ञ व किशोरावस्था काउंसलर डॉ. पियाली भट्टाचार्या के इलाज में जो नतीजे सामने आए उनके मुताबिक खुश होने का खास अवसर छोड़ दें, अकेले बैठे हों या शरीक हों किसी के गम में, काम में व्यस्त हों या कर रहे हों पेट पूजा, लोग फोन उठाकर धड़ाधड़ क्लिक शुरू कर देते हैं। उसके तुरंत बाद खींचे गए फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धुन और फिर उन पर लाइक के इंतजार की ललक में डूब जाते हैं। अगर किसी कारणवश, उनके शेयर किए फोटो को लोगों ने कम पंसद किया, कमेंट्स कम आए तो उन्हें बेहद नागवार गुजरता है।

क्या है सेल्फाइटिस : इंग्लैंड की नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने इसकी सबसे पहले पहचान की थी। हर दिन अपनी सेल्फी लेकर कम से कम पांच से छह बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले खासतौर से सेल्फाइटिस से पीड़ित माने जाते हैं।

हर दस सेकंड में एक हजार सेल्फी : शोध के मुताबिक, इंस्टाग्राम पर हर 10 सेकंड में एक हजार सेल्फी पोस्ट की जाती हैं। हर दिन 93 मिलियन (9.3 करोड़) सेल्फी होती हैं, जो फिल्म की 2,583,333 रोल का प्रतिनिधित्व करती हैं। 20 में से 19 किशोर सेल्फी लेते हैं।

- बार-बार मोबाइल से क्लिक की ललक बनी भयावह, एसजीपीजीआइ में रोजाना पहुंच रहे चार से पांच मरीज

> हालात भयावह हैं। हमारे पास मोबाइल एडिक्शन के कई मरीज आ रहे हैं। ज्यादा सेल्फी लेने और गेम का जुनून इसका मुख्य कारण है।
>
> **- डॉ. पियाली भट्टाचार्या, बाल रोग विशेषज्ञ व किशोरावस्था काउंसलर, पीजीआइ**

सेल्फाइटिस का असर

- पोस्ट पर रिएक्शन न मिलने डिप्रेशन का शिकार हो रहे
- खासतौर से युवा उम्मीद के मुताबिक रिएक्शन से मिलने से परेशान होते हैं
- रात की नींद छिन रही, कार्यक्षमता पर भी पड़ रहा नकारात्मक असर
- समाज को नजरअंदाज कर रहे, परिवार से कटे-कटे रहने लगे, मोबाइल में रहते हैं ज्यादा व्यस्त

यह एप आपको करेगा आगाह : Saftie नामक एप, सेल्फी लेने वाले को एक चेतावनी भेजता है। यदि वे एक लोकप्रिय फोटो स्पॉट के पास हैं, जो खतरनाक प्वाइंट हैं तो यह उन्हें चेताएगा कि यहां सेल्फी लेना खतरनाक हो सकता है।

ड्राइवरलेस वाहन बदल रहे परिवहन की तस्वीर

नेशनल डेस्क, नई दिल्ली : दुनियाभर के तमाम देशों में ड्राइवरलेस वाहनों को विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में हुंडई ने एक ऐसा ड्राइवरलेस ट्रक बनाया है जो पुराने जमाने की भाप से चलने वाली ट्रेन की तरह दिखता है। खास बात यह है कि यह हाइड्रोजन से चलता है और पर्यावरण के अनुकूल है। इसका डिजाइन ऐसा प्रतीत होता है, जैसे इसमें कोई दरवाजा ही न हो, लेकिन इसमें ऑटोमैटिक स्लाइड दरवाजे हैं जो बाहर से नहीं दिखते हैं। हुंडई ने इसे 'एचडीसी-6 नेप्च्यून' नाम दिया है। कंपनी का कहना है कि यह 2030 तक दुनिया की सभी सड़कों में पहुंच जाएगा।

हुंडई ने बनाया है एक ऐसा ड्राइवरलेस ट्रक, जो प्रदूषण नहीं फैलाता, उल्टा हवा को साफ करने में करता है मदद। 1936 में अमेरिका में चलने वालीं भाप की ट्रेनों से प्रेरित है इसका डिजाइन।

किस तरह से काम करता है हाइड्रोजन ईंधन सेल

यह ट्रक हाइड्रोजन ईंधन से चलता है। इसलिए यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाती है। ईंधन सेल एक ऐसा सेल होता है जिससे रासायनिक क्रियाओं के जरिये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यहां सकारात्मक (कैथोड) और नकारात्मक (एनोड) दो इलेक्ट्रोड होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं इन इलेक्ट्रोडों में होती हैं। हाइड्रोजन अणु एनोड से प्रवेश करते हैं जहां उनसे इलेक्ट्रॉन को हटा लिया जाता है और केवल हाइड्रोजन आयन (एच प्लस) बचता है। इलेक्ट्रॉन से बिजली बनती हैं और हाइड्रोजन आयन को ऑक्सीजन से मिक्स करके पानी बनाकर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस तरह इस प्रक्रिया में उत्सर्जन के नाम पर कोई धुआं नहीं निकलता, सिर्फ पानी निकलता है जो पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता।

केवल पानी की कुछ बूंदों का उत्सर्जन, पर्यावरण के है अनुकूल

कंपनी का दावा है कि यह ट्रक पर्यावरण के बेहद अनुकूल है। उत्सर्जन के नाम पर ट्रक से मात्र कुछ पानी की बूंदें निकलती हैं। इस ट्रक में पीछे एक रेफ्रिजेरेटेड ट्रेलर लगा हुआ है। इस ट्रेलर से भी बहुत कम कार्बन उत्सर्जन होता है क्योंकि यह पहला ट्रेलर है जो क्रायोजेनिक नाइट्रोजन रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से लैस है। इस सिस्टम की वजह से ट्रेलर का कार्बन उत्सर्जन 90 फीसद तक कम हो जाता है।

ट्रक में लगे एयर फिल्टर प्रदूषित हवा को करते हैं साफ

इस ट्रक में बहुत सारे एयर फिल्टर लगाए गए हैं। यह ट्रक सामने से आने वाली प्रदूषित हवा को भी फिल्टर करता है। हुंडई मोटर ग्रुप के मुख्य डिजाइन अधिकारी ल्यूक डांकरवॉल्के के मुताबिक, हुंडई की कॉमर्शियल व्हीकल डिजाइन टीम ने पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस इस ट्रक को बनाने में बहुत मेहनत की है।

भाप की ट्रेन से प्रेरित है एचडीसी-6 नेप्च्यून का डिजाइन

हुंडई के मुताबिक, 'एचडीसी-6 नेप्च्यून' का डिजाइन 1936 से 1959 तक चलने वाली अमेरिकी भाप की ट्रेनों से प्रेरित है। खासकर हेनरी ड्रेफस द्वारा डिजाइन की गई न्यूयॉर्क की सेंट्रल ट्रेन से।

स्वचालित है यह ट्रक, लेकिन बनाया गया है ड्राइवर केबिन

यह ट्रक पूरी तरह से ड्राइवरलेस और स्वचालित है, लेकिन फिर भी इसमें ड्राइवर केबिन है और दो सीटें भी लगाई गई हैं। बाहर से देखने पर ट्रक के दरवाजे नहीं दिखते हैं। दरवाजों का डिजाइन छुपा हुआ बनाया गया है। इसमें ऑटोमैटिक और स्लाइड दरवाजे लगाए गए हैं।

101 वर्षों से नियाग्रा वॉटर फॉल्स की चट्टानों में फंसी एक बड़ी नाव तेज हवा और भारी बारिश के कारण बह गई। वह अमेरिका से कनाडा की ओर बह गई। 1918 में यह नाव जल प्रपात के मुहाने तक आ गई थी और तब से वहीं फंसी थी।

संध्या की जिंदगी में नया सवेरा

भीख मांगना छोड़ दसवीं तक पढ़ाई की, अब इंजीनियरिंग की तैयारी

संजय वर्मा, पटियाला

पटियाला ट्रक यूनियन के पास बनी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे आर्थिक तंगी के कारण भीख मांगने को मजबूर हैं। इस बस्ती में शिक्षा का सवेरा आएगा, ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शिक्षा का यह सवेरा लेकर आई इस बस्ती की एक बच्ची, संध्या। विपरीत हालात के बावजूद उसने भीख मांगना छोड़ पढ़ाई शुरू की। मेहनत रंग लाई और उसने दसवीं की परीक्षा पास की। अब संध्या का चयन बेंगलुरु के संस्थान में सॉफ्टवेयर डेवलपर कोर्स के लिए हुआ है।

सुशिक्षित समाज

एक साल बाद संध्या खुद सॉफ्टवेयर तैयार कर सकेगी और गरीबी को सदा के लिए अलविदा कह देगी। झोपड़ पट्टी के बच्चों के लिए संध्या अब रोल मॉडल बन गई है। अन्य बच्चे भी अब संध्या दीदी की तरह पढ़ाई करने लगे हैं। इस बदलाव में 'हर हाथ कलम संस्था' का भी सराहनीय योगदान है। संध्या के पिता ट्रक यूनियन में रेहड़ी चलाते हैं और मां कूड़ा बीनती हैं। पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ी संध्या घर की बिगड़ी आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ कर घरों में काम करने लगी थी। पढ़ाई छूटने का दर्द उसे हर पल सताता था। इसका जिक्र वह स्वजनों और सहेलियों से भी करती थी। संध्या के फिर से पढ़ने के जज्बे को देखते हुए स्थानीय समाजसेवी संस्था 'हर हाथ कलम' ने उसका स्कूल में दाखिला करवाया। हाल ही में संध्या ने दसवीं कक्षा पास कर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स की प्रवेश परीक्षा पास की है। इस पढ़ाई के लिए वह बेंगलुरु में एक साल रहेगी। बेटी की कामयाबी पर पिता विनोद कुमार ने कहा कि बेहद खुशी है, बेटी सफलता की ओर है। मैं चाहता हूं कि बेटी सफलता की ऊंची उड़ान भरे और गरीबी को सदा के लिए पीछे छोड़ दे। अब बस्ती के जरूरतमंद बच्चों के लिए बेंगलुरु की नव गुरुकुल संस्था ने चार साल के सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कोर्स को एक साल में कराने का विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसका उद्देश्य संध्या जैसे बच्चों को प्रशिक्षित कर पैरों पर खड़ा करना है। संस्था बेंगलुरु में संध्या की पढ़ाई और रहने का खर्च उठाएगी।

भीख मांगना एक दुखद पहलू : संध्या का कहना है, 'परिवार को कर्ज में देख कर विवश हो गई थी। बचपन में भीख मांगी और फिर पढ़ाई के लिए दुकानदार के घर पर काम किया। भीख मांगना एक दुखद पहलू रहा है। उम्मीद है कि अब जीवन में ऐसा अंधेरा फिर नहीं आएगा। मैं एक मुकाम हासिल कर उन बच्चों के लिए काम करूंगी, जो मेरी तरह असहाय हैं।'

पटियाला में ट्रक यूनियन के पास बनी बस्ती में घर का काम करती संध्या की फाइल फोटो। जागरण

बीते दिनों संध्या को अंबाला रेलवे स्टेशन से बेंगलुरु के लिए रवाना करते स्वजन और सहयोगी। फाइल

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

हिंडन एयरपोर्ट से हुबली के लिए कल से मिलेगी फ्लाइट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- 50 सीटर विमान की पहले दिन की ज्यादातर सीटें बुक

हिंडन एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ की फ्लाइट के बाद बुधवार से कर्नाटक के हुबली के लिए भी फ्लाइट सुविधा मिल सकेगी। स्टार एयर का 50 सीटर विमान यात्रियों को लेकर हुबली जाएगा। फ्लाइट शुरू होते ही हिंडन की कनेक्टिविटी कर्नाटक से भी हो जाएगी। जल्द ही हिंडन से अन्य शहरों के लिए भी यात्रियों को फ्लाइट की सुविधा मिल सकेगी। मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंडन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। 11 अक्टूबर से यहां से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए उड़ान शुरू की जा चुकी है। अब बुधवार से स्टार एयर हुबली के लिए पहली उड़ान शुरू करने जा रहा है। फिलहाल सप्ताह में तीन दिन शाम को चार बजकर दस मिनट पर 50 सीटर विमान यहां से यात्रियों को लेकर उड़ेगा। बुधवार, गुरुवार और शनिवार को हिंडन से हुबली के लिए फ्लाइट की सुविधा मिल सकेगी।

साढ़े तीन से चार हजार के बीच किराया : हुबली के लिए स्टार एयर ने किराया 3699 रुपये निर्धारित किया है। इनमें 50 फीसद सीटें आरसीएस (रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम) के तहत रिजर्व होंगी। ये 25 सीटें सस्ती दर पर लगभग साढ़े तीन हजार से चार हजार के बीच, जबकि शेष 25 सीटें स्टार एयर अपनी दरों पर बेचेगा। हालांकि, बुकिंग की तिथि नजदीक आते-आते यह प्रीमियम दरों की तर्ज पर बढ़ती रहेंगी। छह नवंबर के लिए स्टार एयर की लगभग सभी टिकट बुक हो चुकी हैं। महज दो सीटें बची हैं, जिनका किराया सोमवार को करीब दस हजार रुपये रहा।

बाद में इन जगहों के लिए मिलेगी फ्लाइट

पिथौरागढ़, हुबली के बाद कलबुर्गी, जामनगर, कन्नूर, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, हिमाचल के शिमला, महाराष्ट्र के नासिक के लिए यहां से उड़ान मिल सकेंगी। गोरखपुर, प्रयागराज, कोलकाता, लखनऊ आदि रूटों पर भी उड़ान शुरू करने पर बात चल रही है।

पहली फ्लाइट के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले दिन के लिए लगभग सभी सीटें बुक हो चुकी हैं। फ्लाइट शुरू होते ही लोगों का हुबली का सफर आसान हो जाएगा।
– राजकुंवर, जनसंपर्क अधिकारी, स्टार एयर

समझ लूं, फिर समझाऊंगा इस दोस्ती का फलसफा...

- रतन टाटा के ऑफिस में उप महाप्रबंधक शांतनु उनके सबसे चहेते सहयोगी और सलाहकार बन गए हैं
- सोशल मीडिया पर छाई दोनों की जोड़ी
- कम दिलचस्प नहीं इनकी दोस्ती का किस्सा

रतन टाटा के साथ शांतनु नायडु। सौ. शांतनु

संजय कुमार सिंह, नई दिल्ली

जागरण विशेष

जल्द ही वह दिन आएगा, जब मैं इस दोस्ती और इस रिश्ते के मायने समझने के योग्य बन जाऊंगा। और शायद इसके निहितार्थ बेहतर तरीके से दुनिया संग साझा कर सकूंगा। इस पूरे अनुभव को व्यक्त करना एक महान परिचय देने के समान होगा...। 27 वर्षीय शांतनु नायडु ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में यह बात लिखी है।

शांतनु ने उद्योग जगत की दिग्गज शख्सियत और टाटा समूह के मानद चेयरमैन 81 वर्षीय रतन टाटा के साथ अपनी फ्रेंडशिप बयां करती दो तस्वीरें भी साझा कीं। एक तस्वीर में तो वह रतन टाटा के कंधे पर इस तरह हाथ रखे हुए हैं, मानो जिगरी दोस्त हों। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

शांतनु दरअसल रतन टाटा के मुंबई स्थित मुख्यालय (ऑफिस ऑफ रतन नवल टाटा) में बतौर उप महाप्रबंधक नियुक्त हैं, लेकिन बात बस इतनी ही नहीं है। शांतनु रतन टाटा के सबसे चहेते सहयोगी बन गए हैं। टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति के बाद रतन अब समूह के चेयरमैन एमिरिट्स (मानद अध्यक्ष) तो हैं ही, लेकिन अपनी दूसरी पारी उन्होंने भारत में नए आविष्कारों, बिजनेस आइडियाज और स्टार्टअप्स को सहयोग-गति देने और टाटा ट्रस्ट के मुखिया के तौर पर समाजसेवा के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति में केंद्रित कर दी है। इन सभी कार्यों में, खासकर युवा उद्यमियों के नए बिजनेस आइडियाज और स्टार्टअप्स को जरूरी सहयोग देने के काम में शांतनु उनके सहायक और सलाहकार की भूमिका में हैं। शांतनु ने वह कहानी भी साझा की है, जिसने उन्हें रतन टाटा तक पहुंचाया। शांतनु ने बताया है कि उनके परिवार की पांच पीढ़ियों ने टाटा समूह में सेवाएं दीं। प्रबंधन या बड़े पद पर नहीं, बल्कि टाटा मोटर्स में मैकेनिक या इंजीनियर आदि पदों पर। बात 2016 की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 24 साल के शांतनु भी गृहनगर पुणे में टाटा मोटर्स की एक यूनिट में नौकरी कर रहे थे। एक रात घर लौटते हुए उन्होंने देखा कि तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे एक कुत्ते को रौंद डाला है। पशुओं के प्रति विशेष लगाव के कारण वह विचलित हो उठे। पता चला कि अंधेरे के कारण ऐसे हादसे बड़ी संख्या में होते हैं। शांतनु ने इस समस्या का समाधान करने की ठान ली। कुछ दोस्तों को जोड़ा, चंदा जुटाया और सड़कों पर भटकते बेसहारा कुत्तों, पशुओं के गले में पहनाए जा सकने वाले विशेष रेडियम युक्त और टिकाऊ पट्टे तैयार किए। देखते ही देखते, शहर भर के बेसहारा पशुओं के गले में ये पट्टे थे। दुर्घटनाएं थम गईं।

'टाटा कर्मी' शांतनु द्वारा शुरू की गई इस मुहिम (मोटोपाज) की जानकारी कुछ माह बाद रतन टाटा तक पहुंची तो उन्होंने शांतनु को मुंबई स्थित ऑफिस आकर मिलने को कहा। शांतनु की रतन टाटा से वह मुलाकात अनूठी दोस्ती में तब्दील होती गई। बता दें कि रतन टाटा का पशु प्रेम जगजाहिर है। अविवाहित रहने के कारण उनका परिवार तो है नहीं। घर में मौजूद पालतू कुत्ते ही उनके लिए बेहद खास हैं। रतन ने शांतनु की उस मुहिम- मोटोपाज को स्थायी बनाने के लिए पर्याप्त फंड मुहैया कर दिया।

शांतनु ने बताया कि कुछ माह बाद जब उन्होंने रतन टाटा को बताया कि वह एमबीए करने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और इच्छा व्यक्त की कि लौटकर टाटा समूह को ही सेवाएं देना चाहते हैं, तो उन्होंने खुशी जताई। एमबीए करने के बाद 2018 में जब शांतनु स्वदेश लौटे तो उन्होंने अपने ऑफिस में यह बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी। शांतनु ने बताया है कि 81 वर्षीय रतन टाटा आज भी जीवन और कर्म के प्रति अपने उच्चतम लक्ष्य को लेकर कितने सजग और संकल्पित हैं।

तुम क्या हो और मैं क्या हूं... : बकौल शांतनु, वह बेहद बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उनका अथाह अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान उन्हें सोच की ऊंचाइयों पर स्थापित करता है। चाहे नई टेक्नोलॉजी की बात हो या नए आइडिया की, वह हर लेटेस्ट ट्रेंड से वाकिफ रहते हैं। उनकी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और जमीनी एप्रोच किसी भी शुरुआत की सफलता की गारंटी बन जाती है। उनकी शख्सियत को समझने वाला यह सहज ही बता सकता है कि वह एक महान इंसान हैं। वह कभी किसी को भी यह महसूस नहीं होने देते कि- तुम क्या हो और मैं क्या हूं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

सरहद पर जवानों की जान बचाएगा सोलर फ्रिज

आविष्कार ▶ जम्मू-कश्मीर के मैकेनिकल इंजीनियर अखिल ने देश को दिया है नायाब तोहफा

लेफ्टिनेंट कर्नल अखिल ने आइआइटी कानपुर से की है एमटेक की पढ़ाई

अवधेश चौहान, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के निवासी एवं आइआइटी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पूर्व छात्र अखिल चाढ़क ने एक ऐसा सोलर फ्रिज (रिक्शा) बनाया है जो सरहद पर तैनात जवानों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाला यह फ्रिज दुर्गम स्थलों पर भी काम करेगा। कल्पना कीजिए कि शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रेगिस्तान में सरहद पर किसी को सांप काट ले तो उस तक एंटीडोज कैसे पहुंचेगा। अगर पहुंच भी जाता है तो क्या उसकी कोल्ड चेन को बरकरार रखा जा सकता है। ऐसे ढेर सवाल हैं, जिनका जवाब अखिल का सोलर फ्रिज देता है। यह रिक्शा रेगिस्तान की तपती गर्मी में भी जवानों समेत ग्रामीणों को भी जीवन रक्षक दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध कराएगा जो गर्मी में खराब हो जाती हैं। अखिल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं।

गर्मी के मौसम में जब गुजरात के रेगिस्तान कच्छ में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब भी यह सोलर फ्रिज -12 डिग्री तापमान के साथ करीब 240 लीटर खाने-पीने का सामान, दवाइयां और वैक्सीन को प्रीजर्व कर सकता है। सौर ऊर्जा से चलने वाला यह फ्रिज बगैर धूप, बादलों और बारिश में भी चार दिन तक अपनी जमा ऊर्जा से काम कर सकता है। इसे तैयार करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अखिल चाढ़क का कहना है कि केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के दूरदराज इलाकों की सीमाओं पर लाखों की संख्या में तैनात हैं। कई बार इन इलाकों में सर्पदंश के इलाज के लिए एंटी वेनम की जरूरत पड़ती है। इस एंटी वेनम को संरक्षित रखने के लिए रेफ्रीजरेटर की जरूरत होती है। कई जवान मधुमेह से भी ग्रस्त होते हैं, जिन्हें इंसुलिन की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, यह फ्रिज उन भारतीय जवानों के काम आएगा, जो गोलीबारी में घायल हो जाते हैं। उन्हें जीवन रक्षक दवाइयां की जरूरत पड़ती है, जिन्हें प्रीजर्व रखना बेहद जरूरी होता है। देश के दूरदराज गांव जहां बिजली नहीं है, वहां यह फ्रिज खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने में काफी फायदेमंद होगा।

बेरोजगारों के लिए रोजगार का बन सकता है साधन : पहियों पर चलने वाला यह फ्रिज देश के बेरोजगार युवाओं को खाद्य पदार्थ बेच कर रोजी रोटी कमाने का साधन बन सकता है। इसे तैयार करने वाले एमटेक मैकेनिकल के छात्र ले. कर्नल अखिल चाढ़क मूलतः जम्मू संभाग के भद्रवाह क्षेत्र के रहने वाले हैं। चाढ़क का कहना है कि उनका मार्गदर्शन आइआइटी कानपुर के प्रोफेसर खांडेकर ने किया। उन्होंने सौर ऊर्जा से संचालित रेफ्रीजरेटर तैयार किया जो ई-रिक्शा से जुड़ा हुआ है।

पेटेंट के लिए भेजा है शोधपत्र : वर्तमान में पंजाब के बठिंडा में सेना में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल अखिल चाढ़क का कहना है कि सौर ऊर्जा से संचालित इस पोर्टेबल सोलर फ्रिज को तैयार करने का मकसद देश में लाखों टन खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना भी है। चाढ़क का कहना है कि आइआइटी कानपुर ने शोध पेपर को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्युएबल इनर्जी को भेजा है, ताकि इसे पेंटेट किया जा सके।

जम्मू-कश्मीर में भद्रवाह तहसील के रहने वाले अखिल चाढ़क (बीच में), जिन्होंने सोलर फ्रिज तैयार किया है। इसके जरिये रेगिस्तान की तपती गर्मी में भी जवानों और ग्रामीणों को जीवन रक्षक दवाइयां व वैक्सीन आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी। जागरण

मध्य प्रदेश में बुजुर्गों की सेवा-सम्मान के लिए कारोबारियों ने छोड़ा मुनाफा

राजीव सोनी, भोपाल

- राज्य आनंद संस्थान की पहल पर शुरू हुई अनूठी मुहिम
- बुजुर्ग ग्राहकों से 'नो प्रॉफिट-नो लॉस' में करेंगे व्यवसाय

मध्य प्रदेश में बुजुर्गों की सेवा और सम्मान के लिए सैकड़ों कारोबारियों और दुकानदारों ने अपना मुनाफा छोड़ने का एलान किया है। अध्यात्म विभाग द्वारा संचालित राज्य आनंद संस्थान की पहल पर प्रदेश के कई जिलों में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने बुजुर्ग ग्राहकों के साथ 'नो प्रॉफिट-नो लॉस' में व्यवसाय करने का निर्णय किया है। इसके लिए इन प्रतिष्ठान संचालकों ने शासन को घोषणा पत्र भी सौंपा है।

भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में राज्य आनंद संस्थान ने अपने 50 हजार आनंदकों के माध्यम से यह मुहिम शुरू की है। इसके तहत बुजुर्ग नागरिकों के प्रति सम्मान दिखाने एवं उन्हें 'स्पेशल फीलिंग' का अहसास कराने के लिए करीब 700 व्यापारियों-कारोबारियों ने मुनाफा छोड़ा है। ऐसा उन्होंने अपने आनंद और आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए किया है। एक अक्टूबर (अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस) पर कुछ अलग और सार्थक प्रयास करने के लिए आनंद संस्थान ने भोपाल से यह शुरुआत की, जिसे अन्य शहरों के कारोबारियों ने भी हाथों-हाथ लिया और सहर्ष अपनी ओर से घोषणा कर दी कि वे बुजुर्ग ग्राहकों से मुनाफा नहीं लेंगे।

इन शहरों में अच्छा प्रतिसाद : प्रदेश के बड़े शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन के साथ विदिशा, बड़वानी और मंडला जैसे छोटे शहरों में भी बड़ी संख्या में व्यापारी इस मुहिम में शामिल हैं। इनमें होटल-रेस्तरां, अस्पताल, दवा विक्रेता, किराना व्यवसायी, जनरल स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, फिजियोथैरेपिस्ट, कोचिंग इंस्टीट्यूट और सलून संचालक से लेकर कारपेंटर आदि ने बुजुर्गों को रियायत देने पर सहमति जताई है। आनंद संस्थान के प्रदेश भर में फैले 50 हजार वालेंटियर (आनंदक) अपने गांव-शहरों के व्यवसाइयों को इस मुहिम के लिए सहमत कर घोषणा पत्र भरवाने में जुटे हैं।

सामाजिक स्तर पर पहली शुरुआत : अर्गल

राज्य आनंद संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिलेश अर्गल बताते हैं कि शासन द्वारा बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर यह पहली शुरुआत है। इसमें सभी कारोबारियों ने स्वेच्छा से यह निर्णय लिया है। इसमें बजट और पैसों का कोई लेन-देन नहीं रहेगा। इसके पीछे उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति घर-परिवार से लेकर समाज में विशेष सम्मान का भाव जागृत करना है। भोपाल के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी निर्णय किया है कि किसी बच्चे के साथ बुजुर्ग परिजन आते हैं तो उन्हें 50 फीसदी तक रियायत देंगे।

आनंद संस्थान वेबसाइट पर डालेगा सूची

अर्गल ने बताया कि संस्थान की वेबसाइट पर जल्द ही हर शहर और जिले के ऐसे कारोबारियों की सूची अपलोड की जाएगी। इसके लिए एप भी बनाया जा रहा है। ऐसी दुकानों पर बुजुर्गों के लिए दी जा रही इस सुविधा के बारे में सूचना भी लगाई जाएगी। इस पहल से बुजुर्गों की उनके परिवार में पूछ-परख बढ़ेगी।

केदारपुरी में आकार लेने लगी शंकराचार्य की समाधि

रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ धाम में शंकराचार्य की समाधि का निर्माण कार्य कपाट बंद होने के बाद भी तेजी से चल रहा है। यह समाधि 2013 की आपदा में बह गई थी। जागरण

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग

- समाधि के निर्माण में होगा 400 टन सरिये का इस्तेमाल
- केदारनाथ में कपाट बंद होने के बाद भी जारी है निर्माण कार्य

केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद भी कड़ाके की ठंड के बीच वहां पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर चल रहे हैं। इसी के तहत आदि शंकराचार्य की समाधि के दूसरे चरण का निर्माण भी तेजी से चल रहा है।

केदारपुरी में जिन पांच योजनाओं का शिलान्यास अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, उनमें से चार पर काम पूरा हो चुका है। ये योजनाएं हैं मंदिर के सामने पैदल मार्ग का चौड़ीकरण और चबूतरे का निर्माण, गरुड़चट्टी को केदारनाथ से जोड़ना, मंदाकिनी नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य और घाट का निर्माण और तीर्थ पुरोहितों के लिए भवनों का निर्माण थे। जबकि आदि शंकराचार्य की समाधि का निर्माण कार्य जारी है। केदारपुरी में इन दिनों सुबह-शाम कड़ाके के ठंड पड़ रही है और तापमान शून्य से नीचे पहुंच जा रहा है। रविवार को बर्फबारी होने के बाद तो ठंड काफी बढ़ गई है। बावजूद इसके मजदूर दिनभर निर्माण में जुटे रहे। समाधि का निर्माण कर रहे वुड स्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक मनोज सेमवाल ने बताया कि समाधि का निर्माण तीन चरणों में पूरा होना है। प्रथम चरण में 40 मीटर गोलाई वाला छह मीटर गहरा तैयार कर लिया गया है। दूसरे चरण में आरसीसी से निर्माण होना है, जो इन दिनों किया जा रहा है। जबकि, अंतिम चरण में सुंदरीकरण का काम होगा।

बताया कि समाधि पर आठ एमएम से लेकर 25 एमएम मोटाई का कुल 400 टन सरिया लगेगा। अब तक सौ टन सरिया इस्तेमाल किया जा चुका है, जबकि 300 टन सरिया जनवरी तक घोड़े-खच्चर और मजदूरों की मदद से धाम में पहुंचा दिया जाएगा। सेमवाल ने बताया कि 15 करोड़ की लागत से समाधि का निर्माण होना है। समाधि कपाट खुलने से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। अगर मौसम ने कोई बड़ी बाधा खड़ी न की तो तय समय से पहले काम के पूर्ण होने की उम्मीद है।

तलाशी राह

दिल्ली की श्री कृष्णा गोशाला ने की 50 हजार क्विंटल पराली की मांग, मस्तुआना साहिब में पहले पराली बैंक से दिल्ली भेजी जाने लगी पराली

दिल्ली की गोशाला में पशुओं का चारा बनेगी संगरूर की पराली

मनदीप कुमार, संगरूर

पंजाब के संगरूर की गोशालाओं में पशुओं को चारे के रूप में पराली मुहैया कराने के बाद अब नई दिल्ली की गोशाला में भी हजारों पशु संगरूर के खेतों में पैदा हुई पराली से अपना पेट भरेंगे। संगरूर के मस्तुआना साहिब में स्थापित किए गए पंजाब के पहले पराली बैंक में से नई दिल्ली की गोशाला को पराली पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। साइंटिफिक अवेयरनेस एंड सोशल वेलफेयर फोरम के प्रयासों और मथुरा के वातावरण प्रेमी स्वामी अमृतानंद गोवर्धन की प्रेरणा से शुरू हुए पराली बैंक में जागरूक किसान पराली को गांठें बनाकर पहुंचा रहे हैं। इससे पराली के निपटान का रास्ता भी मिल रहा है।

दिल्ली की गोशाला ने संगरूर के पराली बैंक से 50 हजार क्विंटल पराली की डिमांड की है, जिसकी पूर्ति के लिए किसान अपना सहयोग दे रहे हैं। स्वामी अमृतानंद गोवर्धन ने बताया कि नई दिल्ली की उक्त गोशाला में नौ हजार बेसहारा पशु रखे जा रहे हैं, जिनके लिए चारे की समस्या अकसर बनी रहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली गोशाला प्रबंधकों ने संगरूर से पराली की मांग रखी है और उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।

सीएम को लिखा पत्र, गांठें बनाने की मशीनरी मुहैया करवाए सरकार : वातावरण प्रेमी स्वामी अमृतानंद गोवर्धन ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम एक पत्र लिखकर मांग की है कि बेसहारा पशुओं व गोशालाओं में रहने वाले पशुओं के चारे के रूप में पराली को इस्तेमाल करके किसानों को पराली प्रबंधन की ओर अग्रसर किया जा सकता है। ऐसे में पराली की गांठें बनाने के लिए जिला खेतीबाड़ी दफ्तरों को मशीनरी मुहैया करवानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि संगरूर में पराली बैंक की स्थापना की सफलता को देखते हुए पंजाब के अन्य जिलों में भी पराली बैंक की स्थापना करवाई जाए, ताकि यहां से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में पशुओं के चारे की जरूरत को पूरा किया जा सके। साइंटिफिक अवेयरनेस एंड सोशल वेलफेयर फोरम के प्रधान डॉ. एएस मान ने कहा कि दिल्ली की गोशाला को 50 हजार क्विंटल पराली उचित मूल्य पर मुहैया करवाई जाएगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पराली की गांठें बनाने वाली मशीनरी की भी अधिक जरूरत है, इसके लिए सरकार सहयोग देना चाहिए।

पंजाब के संगरूर में पराली बैंक से दिल्ली की गोशाला के लिए पराली भेजने की शुरुआत करते स्वामी अमृतानंद गोवर्धन, डॉ. एएस मान व अन्य। जागरण

दो वर्ष से पुरानी लैप्स पॉलिसी चालू करेगी एलआइसी

नई दिल्ली, प्रेट्र : अब एलआइसी के वे बीमाधारक जिन्होंने दो वर्ष से अधिक समय से बीमा किस्त नहीं चुकाई है, अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू कर सकते हैं। सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने लैप्स हो चुकी बीमा पॉलिसी को एक बार फिर से शुरू करने का मौका दिया है। जनवरी] 2014 में बीमा नियामक संस्था इरडा द्वारा लागू किए नियमों मुताबिक लगातार दो वर्षों तक पॉलिसी की किस्त नहीं देने से पॉलिसी लैप्स हो जाती थी।

घोषित और पुरानी योजनाओं को बंद करना आसान नहीं होता। लेकिन सरकार को अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही योजनाओं को वापस लेने पर विचार करना चाहिए।

— विरल आचार्य
पूर्व डिप्टी गवर्नर, आरबीआइ

सेंसेक्स	40,301.96	▲ 136.93
निफ्टी	11,941.30	▲ 50.70
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 39,263	▲ ₹78
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 47,735	▲ ₹245
$ डॉलर	₹ 70.77	▼ ₹0.04
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 62.64	

कारपोरेट हलचल

आइओसी रिफाइनरी में सतर्कता सप्ताह

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान इंडियन ऑयल के निदेशक (रिफाइनरी) एसएम वैद्य ने रिफाइनरी मुख्यालय में आयोजित समारोह में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर रिफाइनरी डिवीजन के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वैद्य ने कहा कि सभी लोगों को अपने काम के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होना होगा।

एनएचबी में सतर्कता जागरूकता सप्ताह

नेशनल हाउसिंग बैंक ने 28 अक्टूबर से दो नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। इस बार का थीम था 'इंटिग्रिटी : ए वे ऑफ लाइफ।' कार्यक्रम की शुरुआत एनएचबी के प्रबंध निदेशक एसके होता और मुख्य सतर्कता अधिकारी एसके नागपाल ने अधिकारियों को शपथ दिलाकर की। एनएचबी ने सप्ताह के दौरान अपने मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया।

पीएफसी को सीएसआर अवार्ड

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) को राष्ट्रीय सीएसआर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कंपनी को यह अवार्ड 'एनवायर्नमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोलर एनर्जी' श्रेणी में मिला है। कंपनी के सीएमडी राजीव शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों अवार्ड ग्रहण किया।

बनर्जी बने आइआरएफसी के एमडी

सरकार ने अमिताभ बनर्जी को इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (आइआरएफसी) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। आइआरएफसी भारतीय रेलवे के लिए वित्त पोषण शाखा है जो घरेलू और विदेशी पूंजी बाजारों से धन जुटाने का काम करती है। इससे पहले बनर्जी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन में बतौर निदेशक वित्त काम कर चुके हैं।

टाटा पावर लगाएगी 10,000 माइक्रोग्रिड

तैयारी ▶ इसकी मदद से 50 लाख घरों को किया जा सकेगा रोशन

2026 तक ये ग्रिड स्थापित करने का लक्ष्य रखा कंपनी ने

नई दिल्ली, प्रेट्र : निजी बिजली कंपनी टाटा पावर ने नवीन ऊर्जा उत्पादन के लिए टीपी नवीन ऊर्जा माइक्रोग्रिड नाम की सहायक कंपनी स्थापित करने की घोषणा की है। यह कंपनी देशभर में 10 हजार माइक्रोग्रिड स्थापित करेगी, जिसकी मदद से 50 लाख घरों को रोशन किया जाएगा। टीपी नवीन ऊर्जा माइक्रोग्रिड की स्थापना में रॉकफेलर फाउंडेशन से तकनीकी मदद ली जाएगी। हालांकि रॉकफेलर फाउंडेशन इस उपक्रम में हिस्सेदारी नहीं करेगी।

टाटा पावर की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि कंपनी देश में सस्ती, विश्वसनीय और स्वच्छ बिजली प्रदान करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा कंपनी की यह कोशिश बिजली से वंचित दुनियाभर के 80 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य से प्रेरित है। टाटा पावर ने बताया कि कंपनी भारत से ऊर्जा निर्धनता दूर करने के लिए 2026 तक नवीन ऊर्जा के 10 हजार माइक्रोग्रिड देशभर में स्थापित करेगी। ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों में अभी तक ऊर्जा के लिए डीजल जैसे वैकल्पिक स्रोत का इस्तेमाल हो रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में 40 परसेंट से अधिक ग्रामीण उद्योगों में इस प्रदूषक ऊर्जा स्रोत का उपयोग किया जा रहा है। नवीज ऊर्जा माइक्रोग्रिड के इस्तेमाल से एक वर्ष में करीब 10 लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी।

प्रतीकात्मक

इसके अलावा प्रति वर्ष करीब 5.7 करोड़ लीटर डीजल की बचत की जा सकेगी।

टाटा ने बताया कि स्थापना के बाद यह माइक्रोग्रिड करीब एक लाख ग्रामीण उद्योगों को बिजली प्रदान करेगा। इसके अलावा इसकी मदद से करीब दस हजार नौकरियों का सृजन होगा और चार लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

क्या होते हैं ग्रिड : ग्रिड मुख्य रूप से वैसे स्टेशन होते हैं, जो बिजली उत्पादन करने वाले दो या अधिक स्टेशनों को आपस में जोड़ते हैं। इसका फायदा यह होता है कि किल्लत वाले क्षेत्रों में जरूरत के वक्त उन जगहों से बिजली पहुंचाई या ली जा सकती है, जहां सरप्लस बिजली हो। वर्तमान में पूरे देश के पांच क्षेत्रीय पावर ग्रिड को मिलाकर एक नेशनल ग्रिड स्थापित किया गया है। माइक्रोग्रिड एक तरह से सबसे छोटे ग्रिड होंगे, जो कुछ घरों तक सीमित रहेंगे। योजना के मुताबिक टाटा पावर देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रोग्रिड लगाएगी। इनमें सौर ऊर्जा की मदद से बिजली पैदा की जाएगी, जिसे संबंधित परिवारों को मुफ्त में दिया जाएगा। उपयोग के बाद बची हुई बिजली को नेशनल या रीजनल ग्रिड को बेचा जा सकेगा।

मांग में तेजी के चलते सोना-चांदी तेज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोमवार को सोने-चांदी के भाव में तेजी का रुख रहा। दिन के कारोबार में पीली धातु के भाव में 78 रुपये का इजाफा हुआ। दिल्ली के सराफा बाजार में 99.9 परसेंट खरा सोना 39,263 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव में बिका। वहीं चांदी भी 245 रुपये की वृद्धि के साथ 47,735 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। एचडीएफसी सिक्युरिटीज के सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल के मुताबिक भारत में शादियों का सीजन शुरू होने के चलते सोने की मांग में तेजी आई है, जिसका असर इसकी कीमत पर देखा गया। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इन कीमती धातुओं के भाव में नरमी देखी गई। ग्लोबल मार्केट में सोना 1,509 डॉलर और चांदी 18.08 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के भाव पर बिके।

एयरटेल के 599 रुपये के प्लान में चार लाख का बीमा कवर

नई दिल्ली (वि) : टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने दिल्ली-एनसीआर में अपने ग्राहकों के लिए इंश्योरेंस कवर के साथ एक प्रीपेड प्लान लांच किया है। एयरटेल ने इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस से हाथ मिलाया है। इसके तहत एयरटेल का 599 रुपये का प्रीपेड प्लान लेने वाले ग्राहकों को चार लाख रुपये का जीवन बीमा मुहैया कराया जाएगा। एयरटेल का यह प्लान 54 वर्ष तक के वयस्कों के लिए होगा। 84 दिनों के इस प्लान में प्रतिदिन 2-जीबी डाटा और 100 एसएमएस के अलावा किसी भी नेटवर्क पर असीमित कॉल जैसी सुविधाएं होंगी।

एम्स-आइआइटी ने उतारा कार एयर सेनिटाइजर

नई दिल्ली (वि) : दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और आइआइटी दिल्ली ने स्टैनफोर्ड और सिंगापुर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कार एयर सेनेटाइजर विकसित किया है। यह कारों के भीतर की हवा को शुद्ध रखने में मदद करता है। यह एयर सेनेटाइजर एक्टिव मालिक्यूलर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन मानक के अनुसार दो मिनट में हवा को शुद्ध करता है।

बैंकों की लोन वृद्धि दर घटने का अनुमान : इकरा

नई दिल्ली, प्रेट्र : चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक बैंकों का ग्रेडिट ग्रोथ रेट यानी कर्ज की मात्रा की विकास दर घटी है। अग्रणी रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में बैंकों की लोन वृद्धि की दर घटकर 8.5 प्रतिशत रह सकती है। पिछले वित्त वर्ष (2018--19) में यह विकास दर 13.3 प्रतिशत थी।

इकरा ने कहा है कि बैंकों की लोन वृद्धि दर में कमी आने का मुख्य कारण चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में लोन बिजनेस ज्यादा नहीं बढ़ पाना है। एजेंसी ने कहा, 'संकट को देखते हए कोई बांड बाजार में दांव लगाने को तैयार नहीं है। इससे बकाया बांड्स में वृद्धि की सालाना दर करीब चार प्रतिशत पर आ सकती है, जो पिछले साल 12 प्रतिशत थी।' म्यूचुअल फंड के नियमन में हालिया बदलाव के कारण मार्च, 2020 तक कॉमर्शियल पेपर के जरिये जुटाए जाने वाले कर्ज में भी गिरावट रह सकती है। इकरा का अनुमान है कि कुल ऋण वृद्धि दर इस दौरान 13.5 प्रतिशत से कम होकर 6.2-6.8 प्रतिशत के स्तर पर आ सकती है।

▶ **पिछले वित्त वर्ष में 13.3 प्रतिशत बढ़ा था बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ**

एजेंसी ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान एनबीएफसी और एचएफसी (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों) जैसे बड़े कर्जधारकों की फंडिंग के लिए बैंकों पर निर्भर हो जाने से लोन ग्रोथ में तेजी आई थी। हालांकि सुस्त आर्थिक वृद्धि दर, कर्जधारकों द्वारा परिचालन पूंजी की कम जरूरत आदि के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ऋण कोरोबार की रफ्तार घट गई।

आरोपों के ठोस सुबूत नहीं : इन्फोसिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की दूसरी सबसे बड़ी आइटी कंपनी इन्फोसिस ने कहा है कि व्हिसलब्लोअर्स मामले में प्राथमिक जांच के दौरान कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है। इस मामले में कंपनी के अज्ञात कर्मचारियों ने इसके शीर्ष अधिकारियों पर गलत व्यापारिक नीतियों को अपनाने का आरोप लगाया था।

इन्फोसिस ने बताया कि स्वतंत्र आंतरिक ऑडिट के दौरान व्हिसलब्लोअर्स की शिकायत के आधार पर जांच की गई। लेकिन जांच में प्राथमिक तौर पर किसी तरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिलहाल, मामले की जांच अभी जारी है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि वह जांच की प्रगति रिपोर्ट शेयर बाजारों को नियमित रूप से देती रहेगी। कंपनी के ओर से दी गई इस सूचना का असर उसके शेयरों पर दिखाई दिया। सोमवार को इसके शेयरों में 3.23 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया।

इससे पहले एनएसई ने 24 अक्टूबर को इन्फोसिस से इस मामले की जानकारी नहीं देने पर सफाई मांगी थी। इसके जवाब में कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया था कि उसकी ऑडिट कमेटी और कानूनी सलाहकार कंपनी शार्दूल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी इस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा था कि वह इस मामले की स्वतंत्र आंतरिक ऑडिट के लिए अर्नेस्ट एंड यंग के साथ मशविरा कर रही है।

▶ **कंपनी ने कहा - प्राथमिक जांच में आरोपों के पक्ष नहीं मिले साक्ष्य**

▶ **24 अक्टूबर को एनएसई ने मांगी थी सफाई, सोमवार को कंपनी ने दिया जवाब**

पिछले महीने मिले थे पत्र

कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने 30 सितंबर को दो शिकायती पत्र प्राप्त किए थे। इन पत्रों में अनुचित गतिविधियों की शिकायत की गई थी। इन्हें 10 अक्टूबर को कंपनी की ऑडिट कमेटी के सामने पेश किया गया और इसके अगले दिन इस बारे में कंपनी के नॉन एक्जीक्यूटिव सदस्यों को भी अवगत कराया गया। शिकायत पत्र में आरोपितों के ई-मेल और वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद होने की बात कही गई है।

गौरतलब है कि कंपनी के कुछ गुमनाम शिकायतकर्ता कर्मचारियों ने शीर्ष प्रबंधन पर वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि वित्तीय नतीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के लिए शीर्ष प्रबंधन ने कई ऐसे तरीके अपनाए, जो नैतिक मूल्यों के खिलाफ थे। आरोप इतने गंभीर थे कि पूंजी बाजार नियामक सेबी, शेयर बाजारों और अमेरिका के पूंजी बाजार नियामक ने भी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी। पिछले महीने सामने आई इस खबर के बाद कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए थे।

ये हैं आरोप

- **जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान अधिक मुनाफा दिखाने के लिए व्हिसलब्लोअर्स से वीजा लागतों को कम करने के लिए कहा गया**
- **353 करोड़ रुपये के रिवर्सल को भी नजरंदाज करने के लिए दबाव डाले जाने की बात कही गई है**
- **अधिकारियों ने मुनाफा बढ़ाकर स्टॉक्स की ऊंची कीमत बनाए रखने के लिए गैरकानूनी कदम उठाए**
- **वेरिजॉन, इंटेल और संयुक्त उपक्रमों जैसे बड़े सौदों में हेराफेरी की गई, ऑडिटर्स और कंपनी बोर्ड से संवेदनशील जानकारियां छिपाई गईं**
- **सीईओ ने कर्मचारियों से कहा था कि बोर्ड के सामने बड़ी डील के आंकड़े और महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारियां नहीं रखी जाएं**

मैक्डोनाल्ड्स ने सीईओ को किया बर्खास्त

▶ **कर्मचारी से शारीरिक संबंधों की बात स्वीकारी, इसे आपसी सहमति कहा**

▶ **निदेशकमंडल के फैसले के बाद कंपनी से हटे, नीतियों के उल्लंघन की बात मानी**

न्यूयॉर्क, एएफपी : अमेरिका की दिग्गज फास्ट फूड चेन मैक्डोनाल्ड्स ने सीईओ स्टीव ईस्टरब्रुक को निकाल दिया गया है। उन्हें कंपनी के एक कर्मचारी से शारीरिक संबंधों के आरोप में निकाला गया है। ईस्टरब्रुक ने आरोप स्वीकार करते हुए कहा कि संबंध आपसी सहमति से बनाए गए थे। मैक्डोनाल्ड्स ने इस घटना को सीईओ द्वारा कंपनी की नीतियों का उल्लंघन माना। ईस्टरब्रुक 2015 से कंपनी के सीईओ थे। उनकी जगह मैक्डोनाल्ड्स यूएसए के प्रेसिडेंट क्रिस केंपकिंस्की को सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्हें कंपनी के निदेशक बोर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। केंपकिंस्की की जगह जो अर्लिंगर अब मैक्डोनाल्ड्स यूएसए के प्रमुख होंगे।

मैक्डोनाल्ड्स के निदेशक बोर्ड के चेयरमैन एनरिक हर्नांडेज ने कहा कि केंपकिंस्की वर्ष 2015 में मैक्डोनाल्ड्स में शामिल हुए थे। अमेरिका में लगभग 14 हजार मैक्डोनाल्ड्स रेस्टोरेंट खोलने का श्रेय उन्हें जाता है।

मैक्डोनाल्ड्स ने एक बयान जारी कर कहा कि ईस्टरब्रुक निदेशक मंडल के फैसले के बाद कंपनी से हट गए हैं। उन्होंने एक गलत निर्णय लिया और एक कर्मचारी के साथ संबंध रखकर कंपनी की नीतियों का उल्लंघन किया। कंपनी की तरफ से कहा गया कि पूर्व प्रेसिडेंट एवं सीईओ ईस्टरब्रुक ने गलत निर्णय लिया, क्योंकि मैक्डोनाल्ड्स अपने प्रबंधकों को अपने सहायक कर्मचारियों के साथ प्रत्यक्ष अथवा परेक्ष तौर पर शारीरिक संबंध रखने से रोकती है।

कंपनी के मुनाफे में भी आई थी कमी। प्रतीकात्मक

ईस्टरब्रुक ने मानी गलती : इस बीच ईस्टरब्रुक ने कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उनके एक कर्मचारी के साथ संबंध थे और यह एक गलती थी। ईस्टरब्रुक ने ईमेल में कहा, 'कंपनी के मूल्यों को देखते हुए मैं बोर्ड की इस बात से सहमत हूं कि अब मेरा यहां से जाने का वक्त आ गया है। मैकडोनाल्ड्स के निदेशकमंडल ने गहन समीक्षा के बाद शुक्रवार को ईस्टरब्रुक के निष्कासन के पक्ष में मतदान किया।

बोर्ड भी छोड़ेंगे ईस्टरब्रुक : ईस्टरब्रुक मैक्डोनाल्ड्स के निदेशक बोर्ड से भी बाहर हो जाएंगे। कंपनी ने उस कर्मचारी के बारे में जानकारी देने से इन्कार कर दिया है, जिसके साथ ईस्टरब्रुक के संबंध थे। ईस्टरब्रुक के एक वकील ने भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया।

रेरा के ऑल इंडिया फोरम का हुआ गठन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) को और अधिक प्रभावी बनाने की कवायद तेज हो गई है। राष्ट्रीय कॉन्क्लेव से पहले देश के अलग-अलग राज्यों के रेरा अध्यक्षों की हुई बैठक में विचार विमर्श के बाद ऑल इंडिया रेरा फोरम का गठन किया गया है। इसकी घोषणा सोमवार को कॉन्क्लेव में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने की। राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि रेरा के गठन के बाद रियल एस्टेट में पारदर्शिता आई है और 46 हजार से अधिक प्रोजेक्ट पंजीकृत हो चुके हैं। उनका कहना था कि हरियाणा सहित कुछ राज्यों में दो-दो रेरा कार्य कर रहे हैं। इससे घर खरीददारों को असमंजस होता है। लिहाजा, समन्वय स्थापित करने के लिए यहीं लखनऊ में रेरा अध्यक्षों के साथ बैठक में निर्णय कर ऑल इंडिया फोरम का गठन कर दिया गया है। सचिव ने बताया कि अब जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाने जा रहे हैं, जिस पर रेरा के सभी निर्णय उपलब्ध रहेंगे। समान केस में निर्णय लेने में राज्यों में रेरा अध्यक्षों को आसानी होगी। सिर्फ ग्राहक और डेवलपर ही नहीं, आम जन भी इसे देख सकेंगे। इसके अलावा भवन निर्माण की ग्लोबल टेक्नोलॉजी सरकार लाई है। उसके तहत जल्द ही लखनऊ में एक भवन का निर्माण शुरू होने जा रहा है।

बीएसएनएल के खिलाफ वेंडर्स कर रहे दिवालिया प्रक्रिया पर विचार

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल के खिलाफ उसके कुछ वेंडर इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया के बारे में विचार कर रहे हैं। उद्योग संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों कंपनियों पर इनके वेंडर्स का करीब 20 हजार करोड़ रुपये बकाया है। इस बीच, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन की आखिरी तारीख तीन दिसंबर तय कर दी है।

पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के टेलीकॉम कमेटी चेयरमैन संदीप अग्रवाल ने कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और एमटीएनएल पर टेलीकॉम उपकरणों और अन्य वस्तुओं के मद में इन वेंडर्स का बकाया है। इसके अलावा ग्रामीण ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट भारतनेट के लिए सप्लाई किए गए 45 हजार करोड़ रुपये कीमत के टेलीकॉम उपकरण और अन्य संबंधित वस्तुओं का पूरा भुगतान नहीं किया गया है। अग्रवाल ने कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का कुल बकाया करीब 20 हजार करोड़ रुपये है। इसके भुगतान के लिए बैंकों ने वेंडर्स पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ये सभी वेंडर्स 19 नवंबर को इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद अगर 10 दिन के भीतर बकाया का भुगतान नहीं किया जाता है तो वेंडर्स बीएसएनएल और एमटीएनएल के खिलाफ एनसीएलटी जाएंगे।

एमटीएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि कंपनी को करीब 400 करोड़ रुपये वेंडर्स को देने हैं, जिसका भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। इससे पहले 31 अक्टूबर को टेलीकॉम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने इस संबंध में यूएसओएफ को पत्र लिखा था। इस पत्र में वेंडर्स का बकाया चुकाने का अनुरोध किया गया था। यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) भारतनेट प्रोजेक्ट का प्रबंधन कर रहा था।

इन सरकारी टेलीकॉम कंपनियों पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का 500 करोड़, तेजस नेटवर्क का 314 करोड़, एचएफसीएल का 219 करोड़, पारामाउंट वायर्स एंड केबल्स का 168 करोड़ और वीएलएल का 150 करोड़ रुपये बकाया है। इस मामले में पारामाउंट कंपनी केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र भी लिख चुकी है। इस पत्र में बकाया का भुगतान करने का अनुरोध करते हुए पारामाउंट ने प्रसाद को बताया था कि बैंक उस पर कर्ज लौटाने का दबाव बना रही है।

एमटीएनएल ने अपनी वीआरएस योजना की घोषणा कर दी है। गुजरात के वीआरएस मॉडल पर आधारित इस स्कीम में अगले महीने की तीन तारीख तक आवेदन किया जा सकेगा। कर्मचारियों को भेजी गई नोटिस के मुताबिक कंपनी के सभी स्थाई और रेगुलर कर्मचारी जिनकी उम्र आने वाली 31 जनवरी को 50 वर्ष या इससे अधिक है, इस स्कीम में भाग ले सकते हैं। इससे पहले एमटीएनएल ने बताया था कि कंपनी के कुल 22 हजार कर्मचारियों में से करीब 15 हजार इस योजना के लिए योग्य होंगे।

बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि रवि शंकर प्रसाद से मिले

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारी यूनियन और ऑफिसर संघ के कुछ प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात की। इन सदस्यों ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के लिए ऑफर की जा रही वीआरएस स्कीम और अन्य सरकारी उपायों को लेकर अपना समर्थन जताया था।

मजबूती

नई ऊंचाई पर बंद हुआ सेंसेक्स, इंट्रा-डे में भी बनाया रिकॉर्ड, 12,000 अंकों का मनोवैज्ञानिक स्तर छूने के करीब निफ्टी

लगातार सातवें सत्र में चमक से शिखर पर सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र : सोमवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों में लगातार सातवें सत्र में तेजी का रुख रहा। इस दौरान सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 136.93 अंक यानी 0.34 परसेंट उछाल के साथ 40,301.96 के स्तर पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स ने 40,483.21 अंक तक पहुंच कर इट्रा-डे रिकॉर्ड भी बनाया। एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी सोमवार को 12,000 अंक का मनोवैज्ञानिक स्तर छूने के बेहद करीब पहुंच गया। यह 50.70 अंकों के उछाल के बाद 11,941.30 के स्तर पर बंद हुआ।

सोमवार को सेंसेक्स में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज करने वाली कंपनियों में इन्फोसिस, वेदांता, टाटा स्टील, ओएनजीसी और आइसीआइसीआइ बैंक रहे। इनके शेयरों में 3.05 परसेंट तक का उछाल देखा गया। बेहतर तिमाही नतीजों के बाद एचडीएफसी के शेयरों में भी 2.48 परसेंट का उछाल दर्ज किया गया। दूसरी ओर मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर और पावर ग्रिड के शेयरों में 2.54 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई।

निवेशकों को निफ्टी के 12,000 अंक का मनोवैज्ञानिक स्तर पार करने का इंतजार है। प्रतीकात्मक

जानकारों के मुताबिक फॉरेन फंड्स में बेहतर लिक्विडिटी और इक्विटी निवेश में टैक्स सुधार की उम्मीद के चलते शेयर बाजारों में उत्साह देखा गया। विदेशी निवेशकों की तरफ से भी भारतीय बाजारों के प्रति रुझान वापस लौटता दिख रहा है। अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 16,464 करोड़ रुपये का निवेश किया।

दिन के कारोबार के बारे में सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि कई कंपनियों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों ने निवेशकों को भारतीय बाजार की ओर आकर्षित किया है। इसके अलावा भारतीय बाजार तेज विकास की ओर वापस लौटता दिख रहा है। इस वर्ष फरवरी के बाद पहली बार अक्टूबर में ऑटो सेक्टर की बिक्री में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है। एफआइआइ भी लगातार दूसरे महीने शुद्ध खरीदार के तौर पर उभरे हैं। सोमवार को भारत के अलावा अन्य एशियाई बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए। शंघाई, हांगकांग तथा सियोल के बाजार में तेजी देखी गई।

इन शेयरों में रही गहमागहमी

इन्फोसिस : प्राथमिक जांच में व्हिसलब्लोअर्स द्वारा लगाए गए आरोप आधारहीन पाए जाने की खबर के बाद कंपनी के शेयरों में तेज उछाल दर्ज किया गया। दिन के कारोबार में इसके शेयर 3.05 परसेंट की तेजी के साथ 709 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बंद हुए। इससे पहले कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि कंपनी के शीर्ष अधिकारियों पर लगे आरोप प्राथमिक जांच में आधारहीन पाए गए हैं। हालांकि कंपनी ने अभी जांच जारी होने की बात कही है।

एचडीएफसी : मजबूत तिमाही नतीजों के चलते कंपनी के शेयरों में उछाल दर्ज किया गया। दिन के कारोबार में इसके शेयर 2.48 परसेंट के उछाल के साथ 2181.35 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। सोमवार को जारी तिमाही नतीजों में कंपनी ने बताया कि उसके शुद्ध मुनाफे में 76 परसेंट का इजाफा हुआ है। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 10,748 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा।

आरसेप पर उद्योग जगत ने की सरकार की तारीफ

▶ **देश के प्रमुख उद्योग संगठनों ने किया सरकार का समर्थन**

▶ **सीआइआइ और फिक्की भी सरकार के साथ खड़े**

नई दिल्ली, प्रेट्र : आरसेप पर भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले की उद्योग जगत और किसान संगठनों ने जमकर तारीफ की है। दुग्ध उत्पाद कंपनी अमूल ने सरकार के इस निर्णय को मील का पत्थर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत ने आरसेप पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित भारत की चिंताओं का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भारत ने इससे दूर रहने का फैसला किया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सीआइआइ के प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर ने कहा कि संगठन भारत सरकार के हर उस समझौते के साथ खड़ा है, जिसमें द्विपक्षीय हितों को ध्यान में रखा गया है।

फिक्की के प्रेसिडेंट संदीप सोमानी ने भी आरसेप पर सरकार के पक्ष का समर्थन किया है। सोमानी ने कहा कि वे आरसेप के मुद्दे पर सरकार द्वारा लिए गए फैसले के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस डील में भारत की चिंताओं को ध्यान में नहीं रखा गया था, इसके अलावा बहुत से मुद्दे अनसुलझे थे। आरसेप पर चल रही बातचीत के दौरान ही कई सेक्टरों ने अपनी चिंताएं दर्ज कराई थीं। इनमें स्टील, प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमीनियम, मशीन टूल्स, पेपर जैसे उद्योगों ने इस पर अपनी चिंताएं जताईं थीं।

डेयरी उद्योग ने भी इसको लेकर अपनी चिंताएं जताई थीं। इस उद्योग के साथ-साथ किसान संगठनों का कहना था कि 16 देशों के इस समझौते में देश के दुग्ध और डेयरी उद्योग को खतरा पैदा हो जाएगा। इस समझौते के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बहुत अधिक मात्रा में डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में आ सकते थे। इससे कीमतों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता, जिसका अंतिम असर पहले से संकट से गुजर रहे किसानों पर दिखता।

41 शरणार्थी मिले हैं ग्रीस की पुलिस को जांच के दौरान एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक में। सभी सुरक्षित हैं। पुलिस ने बताया कि इनमें से ज्यादातर अफगान नागरिक हैं। उत्तरी ग्रीस के जानथी शहर में नियमित जांच के दौरान ट्रक को रोका गया था। ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इमरान को इस्तीफे के लिए दिया दो दिन का अल्टीमेटम खत्म

इस्लामाबाद में समर्थकों को संबोधित करते कट्टरपंथी उलमा-ए-इस्लाम संगठन के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान। एएफपी

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पद छोड़ने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम खत्म होने पर कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान ने आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कराची से आजादी मार्च लेकर राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे उलमा-ए-इस्लाम संगठन के प्रमुख फजलुर पीएम इमरान के इस्तीफे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनके इस आंदोलन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) समेत सभी प्रमुख विपक्ष दलों ने अपना समर्थन दे रखा है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, 66 वर्षीय फजलुर ने कहा, 'प्रधानमंत्री इमरान के इस्तीफे तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हम आगे बढ़ते रहेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। विपक्षी नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।' बीते शुक्रवार को आजादी मार्च इस्लामाबाद पहुंचने पर फजलुर ने इमरान को इस्तीफा देने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के धैर्य की परीक्षा लिए बिना 'पाकिस्तान के गोर्बाचेव' को इस्तीफा देना ही होगा।

शाहबाज और बिलावल के पहुंचने की उम्मीद कम : डॉन अखबार के अनुसार, फजलुर की सर्वदलीय बैठक में पीएमएल-एन प्रमुख शाहबाज शरीफ और पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के शामिल होने की उम्मीद कम है। दोनों दलों के कुछ नेताओं के हवाले से कहा गया, 'शॉर्ट नोटिस पर हमारी पार्टी के नेताओं शाहबाज और बिलावल के इस्लामाबाद पहुंचने की गुंजाइश काफी कम है।'

▸ आजादी मार्च के आयोजक मौलाना फजलुर रहमान ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

मौलाना फजलुर के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल

फजलुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लाहौर हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट ने यह अर्जी स्वीकार कर ली है। इसमें सरकार के खिलाफ भड़काऊ और नफरत फैलाने वाला भाषण देने की शिकायत की गई है।

काबुल में पाकिस्तानी दूतावास ने जताई सुरक्षा की चिंता

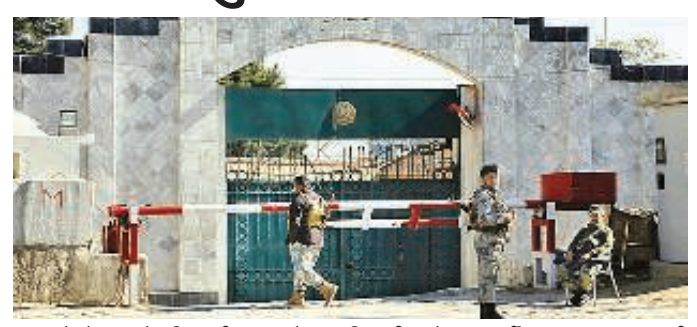

काबुल में सोमवार को पाकिस्तानी दूतावास के बाहर निगरानी करते सुरक्षाकर्मी। एपी

काबुल, एपी : पाकिस्तान ने सुरक्षा संबंधी चिंता जताकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित अपने दूतावास में सोमवार से काउंसलर सेवाएं बंद कर दीं। पाकिस्तान ने कहा कि ये सेवाएं अगली सूचना तक बंद रहेंगी। पाकिस्तान का आरोप है कि काबुल में उसके दूतावास कर्मियों को परेशान किया जा रहा है। अफगान सरकार ने कहा है कि वह इसकी जांच कराएगी।

इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के राजनयिक को तलब कर काबुल स्थित अपने राजनयिकों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं से अवगत कराया था। मंत्रालय ने कहा, 'अफगान राजनयिक को बताया गया कि पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों और स्टाफ को पिछले दो दिनों से परेशान किया जा रहा है। उन्हें दूतावास आते समय रास्ते में रोका गया और उनके वाहनों में मोटरसाइकिलों से टक्कर मारी गई।' इस पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'हम मसले का हल निकालने के लिए पाकिस्तानी दूतावास के संपर्क में हैं।' पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। अफगान सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान तालिबान का समर्थन करता है।

शरीफ की बेटी को भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत

लाहौर, आइएएनएस : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरयम नवाज को सोमवार को लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में जमानत मिल गई। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की नेता मरयम को मनी लांड्रिंग के आरोप में गत आठ अगस्त को गिरफ्तार किया था। तब से वह जांच एजेंसी की हिरासत में थीं।

लाहौर हाई कोर्ट में दो जजों की पीठ ने सोमवार को मरयम की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया। मरयम को एक-एक करोड़ रुपये के दो मुचलके भरने का आदेश दिया गया है। भ्रष्टाचार की आरोपित मरयम को अलग से सात करोड़ रुपये भी जमा कराने का आदेश दिया गया है। अदालत ने मरयम को अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश भी दिया है। पिछले हफ्ते भ्रष्टाचार मामले में सजा काट रहे मरयम के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी अदालत ने खराब तबीयत के आधार पर जमानत दे दी थी। नवाज अब अस्पताल में भर्ती हैं, जहां वह जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।

न्यूज गैलरी

आइएस आतंकियों को उनके देश भेजेगा तुर्की

अंकारा : तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने कहा है कि उनका देश आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के पकड़े गए आतंकियों को उनके मूल देश वापस भेजेगा। सुलेमान ने सोमवार को कहा कि आतंकियों की नागरिकता खत्म किए जाने के बावजूद तुर्की उन्हें वापस उनके देश भेजेगा। आइएस के 1200 आतंकी तुर्की की कैद में हैं। यूरोपीय देशों से आकर आइएस से जुड़ने वाले आंतकियों की नागरिकता खत्म किए जाने के कदम की आलोचना करते हुए सुलेमान ने पिछले दिनों इस मुद्दे पर पश्चिमी देशों की आलोचना की थी। तुर्की से सटे सीरिया से अमेरिकी सेना के वापस जाने का एलान होते ही तुर्की ने इन इलाकों में हमले शुरू कर दिए थे। इस इलाके की जेलों में आइएस के कई आतंकी बंद हैं। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने सीरिया के उत्तरपश्चिमी इलाके में छिपे आइएस सरगना अबू बकर अल-बगदादी को मार गिराया था। (रायटर)

श्रीलंका में प्रेमदासा ने राजपक्षे को दी खुली बहस की चुनौती

कोलंबो : श्रीलंका में 16 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी परवान चढ़ने लगी है। न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट (एनडीएफ) से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सजित प्रेमदासा ने श्रीलंका पोदुजना पेरामुना (एसएलपीपी) पार्टी के उम्मीदवार गोतबाया राजपक्षे को खुली बहस की चुनौती दी है। प्रेमदासा ने राजपक्षे को बहस की चुनौती देते हुए अपनी नीतियां और नजरिये को देश के सामने रखने को कहा। उन्होंने एक पत्र में लिखा, 'नागरिकों का यह लोकतांत्रिक अधिकार है कि वे चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के बारे में पूरी तरह जान सकें। खुली बहस से जनता को उम्मीदवारों की क्षमता, चरित्र और सोच के बारे में आकलन करने का सबसे अच्छा अवसर प्राप्त होगा।' इस राष्ट्रपति चुनाव में कुल 35 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबला देश के पूर्व रक्षा मंत्री गोतबाया राजपक्षे और सत्तारूढ़ दल के उपनेता सजित प्रेमदासा के बीच होना तय माना जा रहा है। (आइएएनएस)

जापान के पीएम को लेकर जा रहे विमान में लगी आग

टोक्यो : रविवार को जापान के प्रधानमंत्री एबी शिंजो को लेकर जा रहे विमान में मामूली आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग को बुझा लिया गया, जिसके चलते किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल, प्रधानमंत्री एबी शिंजो को आशियान शिखर बैठक में भाग लेने बैंकाक जाना था। रविवार को वह बोइंग 777-300ईआर विमान से टोक्यो से बैंकाक रवाना हुए थे। असाही शिंबुन अखबार ने एक ऑनलाइन लेख में बताया गया है कि उड़ान भरने के एक घंटे बाद विमान के अंदर ओवेन में स्पार्किंग के साथ आग लगने की जानकारी दी गई। हालांकि दस मिनट बाद ही आग को बुझा देने की बात कही गई और एबी के कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। (एएफपी)

हांगकांग में फिर काली हुई रात, 30 घायल

बवाल ▸ लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा, तोड़फोड़ और चाकूबाजी

सरकारी मीडिया ने प्रदर्शन को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की बताई जरूरत

हांगकांग में बीते चार महीनों से प्रदर्शन जारी है। रविवार की रात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए बल प्रयोग भी किया। रायटर

हांगकांग, रायटर : हांगकांग में रविवार रात भड़की हिंसा में 30 लोग घायल हुए हैं। यह हिंसा लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन के दौरान भड़की। प्रदर्शनकारियों से पहले पुलिस का टकराव हुआ। इसके बाद जब वे तोड़फोड़ कर रहे थे तो पिटाई से गुस्साए एक युवक ने चाकूबाजी कर दी। पता चला है कि चाकूबाजी में प्रदर्शनकारियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। इस दौरान एक स्थानीय नेता का कान भी कट गया। रविवार रात चीन से संबंधित कई सरकारी और व्यावसायिक इमारतों में भी भारी तोड़फोड़ हुई। सरकारी मीडिया ने आंदोलन को दबाने के लिए अब कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत बताई है।

बीते सप्ताह हांगकांग में चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने भारी तोड़फोड़ की थी। प्रदर्शनकारियों के अनुसार आंदोलन की सही रिपोर्टिंग न करने के कारण शिन्हुआ के कार्यालय पर गुस्सा निकला। शिन्हुआ सहित कई मीडिया संस्थानों ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की सरकार से मांग की है। पुलिस के अनुसार रविवार रात जब लोग मॉल और रेस्टोरेंट में परिवार के साथ मौजूद थे तभी प्रदर्शनकारियों ने वहां तोड़फोड़ की। ऐसे में वहां भगदड़ और चीख-पुकार मच गई। दर्जनों लोग चोटिल हुए। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तो स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस आमजनों और संपत्ति को बचाकर कार्रवाई कर रही थी तो अराजक प्रदर्शनकारी सिर्फ बर्बादी फैला रहे थे। पुलिस ने इस दौरान आंसू गैस, रबर बुलेट और पानी की बौछार भी छोड़ी लेकिन इस सबका सीमित ही असर हुआ। काले कपड़े पहने आंदोलनकारी अंधेरे में जहां-तहां तोड़फोड़ करते रहे। रेस्टोरेंट में हुई चाकूबाजी की घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसने चाकूबाजी की थी। सिटी हॉस्पिटल के अनुसार रविवार की घटनाओं में घायल हुए 30 लोगों में एक की हालत चिंताजनक है जबकि दो गंभीर हैं। घटना में 12 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।

लेबनान में सरकार के विरोध में फिर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी

बेरुत, रायटर : लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी सोमवार को फिर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने राजधानी बेरुत समेत कई शहरों में सड़कों को दोबारा अवरुद्ध कर दिया।

इस पश्चिम एशियाई देश में वाट्सएप कॉल पर टैक्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ गत 17 अक्टूबर से विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। इसके दबाव में प्रधानमंत्री साद हरीरी को गत 29 अक्टूबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेबनान में अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। हरीरी के इस्तीफे के बाद विरोध प्रदर्शन ठंडे पड़ गए थे। दो हफ्ते बाद गत शुक्रवार को सड़कों को दोबारा खोल दिया गया था। लेकिन सोमवार तड़के बेरुत और देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शनकारी अवरोध लगाकर सड़कों पर फिर जमा हो गए। इसके चलते लोगों को जाम से जूझना पड़ा और स्कूलों को खोलने से पहले दोबारा बंद कर दिया गया। स्कूलों को सोमवार से खोला जाना था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नई कैबिनेट से सियासी हस्तियों को दूर रखा जाए। उनका आरोप है कि ये नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल देते हैं।

सरकार में ऐसे लोगों को चाहते हैं प्रदर्शनकारी : हशीम अदनान नामक एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'हम भ्रष्टाचार से मुकाबले के लिए सरकार में तकनीकी विशेषज्ञों और जजों को देखना चाहते हैं। हम चोरी की गई धनराशि की बरामदगी और सरकार को जवाबदेह बनाना चाहते हैं।'

बेरुत में सोमवार को सड़क में बैठकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाते सुरक्षाकर्मी। एएफपी

अफगान राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती शुरू

▸ बड़ी संख्या में मतों के अवैध पाए जाने पर उठाया गया कदम

काबुल, आइएएनएस : अफगानिस्तान के स्वतंत्र चुनाव आयोग (आइईसी) ने गत 28 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए वोटों की सोमवार को दोबारा गिनती शुरू की। ऐसा बड़ी संख्या में अवैध मतपत्र पाए जाने के बाद किया जा रहा है।

चुनाव आयोग ने बीते शनिवार को चुनाव में पड़े वोटों की नई संख्या जारी करते हुए बताया था कि बायोमीट्रिक डर्मलॉग ने 19 लाख 29 हजार 333 मतों में से 18 लाख 43 हजार 107 मतपत्रों को वैध पाया। इन्हें आइईसी के डाटाबेस में भेज दिया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार शहाब हकीमी ने कहा, 'उम्मीदवारों का मानना है कि अगर एक भी फर्जी वोट के जरिये कोई राष्ट्रपति भवन पहुंचता है तो यकीनन यह स्वीकार्य नहीं होगा।' जबकि दूसरा कार्यकाल पाने की होड़ में शामिल राष्ट्रपति अशरफ गनी की चुनाव प्रचार टीम के सदस्य कादर हूदखेल ने कहा, 'यह चुनाव आयोग की तकनीकी विफलता है और इसका समाधान कर लिया गया है। किसी को इसे धांधली नहीं कहना चाहिए।'

चुनाव आयोग हाल के हफ्तों में उस समय दबाव में आ गया था, जब धांधली और तकनीकी गड़बड़ी की कई खबरें मीडिया में आई थीं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान अब्दुल्ला अब्दुल्ला और गनी समेत राष्ट्रपति पद के 15 उम्मीदवारों की टीमों ने गड़बड़ी के आरोप लगाकर मतगणना में बाधा खड़ी की। मतगणना के कुछ दिन बाद ही अब्दुल्ला अब्दुल्ला और गनी की टीमों ने चुनाव में अपनी-अपनी जीत का दावा कर दिया था। इस पर दूसरे उम्मीदवारों ने सवाल खड़े किए थे।

चुनाव में कम पड़े थे वोट

राष्ट्रपति चुनाव में 96 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से महज 27 लाख ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अफगानिस्तान में 2001 में लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद यह सबसे कम मतदान है।

ब्रिटेन में 39 शव मिलने के मामले में आठ और वियतनामी गिरफ्तार

हनोई, एपी : ब्रिटेन पहुंचे एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक कंटेनर में 39 शव मिलने के मामले में वियतनाम में आठ लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। पिछले माह कंटेनर से मिले इन शवों की पहचान वियतनामी नागरिकों के रूप में की गई है।

वियतनाम की पुलिस ने कहा है कि संगठित मानव तस्करी के आरोप में रविवार को आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश पुलिस ने बीते शुक्रवार को कहा था कि कंटेनर में मृत अवस्था में मिले लोग वियतनामी थे। शुरू में उन्हें चीनी नागरिक बताया गया था, लेकिन जब पीड़ित वियतनामी परिवारों ने अपनों के लापता होने की शिकायत की तो यह मामला उजागर हुआ। ब्रिटिश पुलिस ने गत 23 अक्टूबर को मध्य लंदन से करीब 32 किलोमीटर दूर स्थित ग्रेज औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचे एक ट्रक कंटेनर से शव बरामद किए थे। इस मामले में उत्तरी आयरलैंड के ट्रक ड्राइवर मौरिस रॉबिंसन (25) को हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद गत शुक्रवार को उत्तरी आयरलैंड से एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। इसी दिन दो अन्य वियतनामी नागरिकों को भी पकड़ा गया था।

म्यांमार में बंधक की मौत के बाद विद्रोहियों ने छोड़े चार भारतीय

▸ भारतीय की मौत के लिए विद्रोही समूह ने माफी मांगी

▸ कहा-हमने भारतीयों को नहीं बल्कि सांसद को बनाया था निशाना

यंगून, प्रेट्र : म्यांमार में भारतीय बंधक की मौत के बाद विद्रोही समूह अराकान आर्मी ने बाकी चार भारतीयों समेत आठ लोगों को मुक्त कर दिया है। अराकान आर्मी ने वीनू गोपाल (60) की मौत के लिए माफी भी मांगी है। मुक्त किए गए लोगों में दो अनुवादक और दो नाव चालक शामिल हैं।

एक समाचार पत्र के मुताबिक रविवार को विद्रोही समूह ने चार भारतीयों समेत 10 लोगों और आंग सान सू की नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी के एक सांसद यू वी टिन का अपहरण कर लिया था। इनका अपहरण तब किया गया था जब दो नावों से यह लोग चिन राज्य के पलेटवा से रखाइन के क्युकटाव जा रहे थे। गोपाल और चार अन्य भारतीय भारत-म्यांमार की एक संयुक्त परियोजना पर काम कर रहे थे। इसके तहत म्यांमार के सिटवेपोर्ट को भारत-म्यांमार सीमा से जोड़ा जाना है। माना जा रहा है कि इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक विकास में मदद होगी और उत्पादों के लिए समुद्री मार्ग खुल सकेगा।

अराकन सेना के प्रवक्ता ने भारतीय श्रमिक की मौत के लिए माफी मांगी है। प्रवक्ता ने कहा, हम पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। थकावट के चलते वीनू गोपाल की मौत हुई है। हमने उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमने भारतीयों को नहीं बल्कि सांसद को निशाना बनाया था। नाव पर भारतीय भी थे, इस बारे में हमें नहीं पता था। फिलहाल विद्रोही समूह ने सांसद को नहीं छोड़ा है। अराकान आर्मी को यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान (यूएलए) के सशस्त्र विंग के तौर पर स्थापित किया गया है। विद्रोही समूह बौद्धों को अधिक स्वायत्ता के लिए लगभग एक दशक से लड़ रहा है।

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच जाएगी। बता दें कि म्यांमार के उग्रवादी संगठनों के खिलाफ भारत ने भी म्यांमार में जाकर कार्रवाई की थी।

नारोवाल में आतंकी शिविर की चर्चा से बौखलाया पाकिस्तान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान अपने पंजाब प्रांत के सीमावर्ती जिले नारोवाल में आतंकी शिविर चलने के रहस्योद्घाटन से बौखला उठा है। उसने नारोवाल में आतंकी शिविर होने की चर्चाओं का खंडन किया है। यह वही जिला है जहां पवित्र करतारपुर साहिब गुरुद्वारा स्थित है, इसी गुरुद्वारे में सिखों के पहले धर्मगुरु नानकदेव ने अंतिम सांस ली थी। कॉरीडोर के जरिये इसी गुरुद्वारे को भारत से जोड़ा गया है। चंद रोज में ही इस कॉरीडोर से सिख श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस सीमावर्ती पाकिस्तानी जिले में आतंकियों की गतिविधियां देखी हैं। इसके आधार पर शक है कि इलाके में आतंकियों के प्रशिक्षण के लिए शिविर चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट का खंडन करते हुए उसे आधारहीन बताया है। कहा है कि छद्म खुफिया सूत्रों के हवाले से भारतीय मीडिया के एक वर्ग ने इसे प्रकाशित किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि करतारपुर कॉरीडोर परियोजना में उसका उद्देश्य नानक का नाम लेने वालों को सुविधा देना है।

जासूसी का संदेह

अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी कर रही मामले की जांच, चोरी में चीनी मूल के कई नागरिकों की पाई गई भूमिका

चीन पहुंच रही हैं अमेरिका से चोरी हुई रिसर्च

न्यूयॉर्क टाइम्स से

इस मामले में ह्यूस्टन स्थित एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर के पांच सदस्य भी जांच के घेरे में हैं। फाइल

वाशिंगटन : अमेरिका में जासूसी के संदेह में ट्रंप प्रशासन चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे समेत कई प्रौद्योगिकी कंपनियों पर रोक लगा चुका है। अब यह जानकारी सामने आई है कि चोरी किए गए अमेरिकी रिसर्च चीन पहुंचाए जा रहे हैं। इसमें चीनी मूल के कई नागरिकों की भी भूमिका पाई गई है। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआइ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआइएच) इसकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

एफबीआइ और एनआइएच ने ऐसे वैज्ञानिकों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर जांच शुरू की है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे दूसरे देशों के लिए अमेरिकी संस्थानों से बायोमेडिकल रिसर्च चुरा रहे हैं। अभी तक की जांच में रिसर्च चोरी के जितने मामले उजागर हुए हैं, लगभग उन सभी में अमेरिकी नागरिकों समेत चीनी मूल के कई वैज्ञानिकों की भूमिका पाई गई है। इन्हें कथित रूप से चीन के लिए चोरी करते पाया गया। एनआइएच अब तक 24 मामले हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट के महानिदेशक कार्यालय के पास भेज चुका है। इनमें आपराधिक गतिविधि का संदेह जताते हुए एनआइएच ने कहा, 'बायोमेडिकल रिसर्च के हर अनुशासन का हनन किया जाना प्रतीत हो रहा है।'

अमेरिकी संस्थान भी कर रहे जांच : इन मामलों के उजागर होने के बाद अमेरिका के 71 संस्थान भी बौद्धिक संपदा की चोरी के संदेह में 180 मामलों की जांच कर रहे हैं। इन संस्थानों में अमेरिका के कई प्रतिष्ठित मेडिकल स्कूल भी बताए जा रहे हैं।

इन्हें बनाया जा रहा निशाना : जांच में वैज्ञानिक विचारों, डिजाइन, डिवाइस, डाटा और सिद्धांतों को निशाना बनाए जाने की बात उजागर हुई है। इनके जरिये नए उपचार या जांच के टूल विकसित किए जा सकते हैं। इनकी कथित चोरी में हालांकि सेना की गोपनीय जानकारियां शामिल नहीं हैं।

अमेरिकी फंड पर किए रिसर्च का चीन में कराया पेटेंट : एनआइएच ने बताया कि जांच के दायरे में आए कई शोधकर्ताओं ने अमेरिकी सरकार और संस्थानों के वित्त पोषण से किए रिसर्च को चीन में पेटेंट करा लिया। जबकि कई अन्य संदिग्धों ने चीन में अपनी लैब स्थापित कर ली हैं। इनके जरिये गोपनीय तरीके से नकल तैयार की जा रही हैं।

निकाले गए दर्जनभर वैज्ञानिक : एनआइएच ने जांच के दायरे में आए ज्यादातर वैज्ञानिकों के नाम उजागर नहीं किए हैं। लेकिन यह पता चला है कि अब तक करीब एक दर्जन वैज्ञानिकों ने अमेरिकी यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर्स से इस्तीफा दे दिया या निकाल दिए गए। कई वैज्ञानिकों का हालांकि दावा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

खामनेई ने कहा- अमेरिका के साथ बातचीत का नहीं है कोई मतलब

तेहरान, एएफपी : ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने रविवार को एक बार अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इन्कार किया। खामनेई ने यह बयान तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जे की 40वीं वर्षगांठ से एक दिन पहले रविवार को दिया।

खामनेई की आधिकारिक वेबसाइट जारी जारी बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि जो लोग अमेरिका के साथ बातचीत को हर समस्या के समाधान के रूप में देखते हैं, वह निश्चित रूप से गलत हैं। अमेरिका के साथ बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे निश्चित रूप से कोई रियायत नहीं देंगे।

समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक खामनेई ने कहा कि उनके देश ने 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से पिछले चार दशक में अमेरिका को पछाड़ दिया है। खामनेई ने कहा कि ईरान ने 'कई मामलों में सामने वाले पक्ष को घेर लिया है।' उन्होंने कहा कि ईरान के प्रति अमेरिका की आक्रामकता समय के साथ और बढ़ी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ हुए 2015 के परमाणु समझौते से पीछे हट गए थे।

ट्रंप के वकील को बुला सकती है संसदीय समिति

वाशिंगटन, एपी : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग मामले में गठित संसदीय जांच दल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वकीलों को पूछताछ के लिए बुला सकता है। ये वकील व्हाइट हाउस में तैनात हैं और माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इन्हें किसी तरह की जांच से दूर रहने के लिए कहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले संसद का सदन यूक्रेन के राष्ट्रपति से टेलीफोन पर आपत्तिजनक वार्ता करने के कारण ट्रंप पर महाभियोग चलाने की तैयारी कर रहा है। इस बातचीत में ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए कहा था। पूर्व उप राष्ट्रपति बिडेन 2020 के चुनाव में ट्रंप के खिलाफ विपक्ष के सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वकील जॉन ईजेनबर्ग व्हाइट हाउस के उन चार गवाहों में शामिल हैं जो ट्रंप के पक्ष में बयान दे सकते हैं। संसदीय समिति पहले ही उन्हें बुलाकर पूछताछ कर सकती है जिससे ट्रंप के यूक्रेन के राष्ट्रपति से आपत्तिजनक फोन वार्ता के आरोप की सत्यता की परख हो जाए।

खुद के लिए ही जाल बुनती टीम इंडिया

बांग्लादेश के खिलाफ गुरुवार को है दूसरा टी-20 मैच, टी-20 विश्व कप की तैयारियों में बनी-बनाई टीम बिगड़ रही

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

भारतीय चयनकर्ता 2015 विश्व कप के बाद से 2019 विश्व कप तक वनडे टीम के लिए चार नंबर का बल्लेबाज खोजते रहे और इस साल इंग्लैंड में हुए विश्व कप में उन्होंने मध्यक्रम में ऐसे खिलाड़ी उतारे जो टीम इंडिया की हार की वजह बने। टीम इंडिया को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारकर बाहर होना पड़ा। वनडे विश्व कप के बाद से एमएसके प्रसाद के नेतृत्व वाली चयनसमिति, स्थायी कप्तान विराट कोहली और मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मिलकर अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए युवा खिलाड़ियों को मौका देने का नया शिगूफा फेंका। इस शिगूफे के कारण टी-20 टीम से कलाई के स्पिनरों कुलदीप यादव और युजवेंद्रा सिंह चहल की सफलतम जोड़ी को भी बाहर कर दिया गया। किसी तरह चहल बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 टीम में वापसी करने में सफल रहे जबकि कुलदीप चोटिल हैं। चयनकर्ताओं, कोच और कप्तान ने इन दोनों को जो मानसिक आघात पहुंचाया है उससे इन्हें उबरने में समय लगेगा और इसका असर टीम इंडिया पर भी पड़ेगा।

अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही नौवें नंबर की बांग्लादेशी टीम अगर रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में टी-20 इतिहास में दुनिया की पांचवें नंबर की टीम इंडिया को हराने में सफल रही तो उसके पीछे उनकी टीम का अच्छा प्रदर्शन तो है ही, साथ ही इसमें भारत की भी रणनीतिक खामी है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब कोई टीम विश्व कप टीम बनाने के लिए अपनी बनी-बनाई टीम को बिगाड़ रही है। फिलहाल इस सीरीज में रोहित शर्मा कप्तान हैं और उन्हें जो टीम दी गई है उसमें से ही उन्हें बेहतर निकालना है। अब गुरुवार को राजकोट में दोनों टीमें फिर आमने-सामने होंगी। ऐसे में रोहित को नई रणनीति के साथ दूसरे टी-20 में उतरना होगा।

प्रदूषण के कारण स्थान नहीं बदलने से बीसीबी अध्यक्ष नाराज

नई दिल्ली : बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को रविवार को दिल्ली में घातक प्रदूषण के बीच टी-20 मैच खिलाने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष नजमुल हसन नाराज हैं। सोमवार को दिल्ली पहुंचे नजमुल ने कहा कि बीसीबी को यह अहसास नहीं था कि दिल्ली का प्रदूषण इस स्तर तक घातक हो चुका है। मुझे जैसे ही इसकी खबर लगी थी, तो मैंने बीसीसीआइ को मैच का स्थान बदलने के लिए कहा था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने पहले ही साफ किया था कि अब इतनी जल्दी मैच को किसी दूसरे स्थान पर आयोजित करना संभव नहीं होगा। सोमवार को दिल्ली पहुंचे नजमुल ने यहां के प्रदूषण को खुद से महसूस किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। मैंने एयरपोर्ट के भीतर स्मॉग देखा था। यह ओस नहीं नहीं, यह स्मॉग (धुआं) था। सुबह जब मैं यहां पहुंचा, तब हालात और भी ज्यादा खराब थे। अब मुझे यहह देखकर लग रहा है कि क्या हम यहां खेल सकते थे? हम यहां कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं और यही सच है। बीसीसीआइ के रवैये पर बात करते हुए नजमुल ने कहा कि वे शुरुआत से ही कह रह थे कि वे अब स्थान नहीं बदल सकते। हमने अपनी चिंता जताने में देर कर दी। इससे मैं निराश हूं।

दूसरे टी-20 के लिए बाकी टीम के साथ राजकोट पहुंचे खलील अहमद, रोहित शर्मा और गेंदबाजी कोच भरत अरुण • प्रेट्र

रहीम ने बेटे को समर्पित की मैच जिताऊ पारी

नई दिल्ली : रहीम ने कहा, 'मैं यह जीत और अपनी पारी अपने बेटे को समर्पित करना चाहता हूं। मुझे वाकई उसकी कमी खल रही है। वह बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है और अब जब वह मुझे टीवी पर देखता है तो मुझे पहचानने लगता है। यह वाकई खास है इसलिए मैं अपना यह अर्धशतक अपने बेटे को समर्पित करना चाहता हूं।'

एक और नजदीकी हार नहीं चाहता था : रहीम

नई दिल्ली : नजदीकी टी-20 मैचों में हार के दर्द का सामना जितना मुश्फिकुर रहीम ने किया है उतना किसी ने नहीं किया और बांग्लादेश का यह पूर्व कप्तान पिछले मुश्किल दो हफ्तों को भुलाने के लिए क्रिकेट के मैच जीतने के लिए प्रतिबद्ध था। बेंगलुरु में 2016 में विश्व टी-20 मुकाबले में भारत के खिलाफ बांग्लादेश की एक रन की हार के दौरान टीम में शामिल रहे रहीम ने रविवार को यहां तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में नाबाद 60 रन की पारी खेलकर 149 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही मेहमान टीम को जीत दिलाई। भारत पर बांग्लादेश की टी-20 में पहली जीत के बाद रहीम ने कहा, 'हमने भारत के खिलाफ काफी नजदीकी मैच खेले हैं, इसलिए हमने खुद से वादा किया कि अगली बार हमें खेल में इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा तो हम हारना नहीं चाहेंगे।' रहीम ने कहा कि पिछले दो हफ्ते उनके 15 साल के करियर का सबसे मुश्किल समय रहा। उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश से रवाना होने से पहले मैंने कहा कि अगर हम कुछ मैच जीत लेंगे तो सब कुछ पटरी पर आ सकता है। हमने ऐसा ही किया और हम इस फॉर्म को जारी रखने का प्रयास करेंगे। हमने भारत के खिलाफ पिछले दो मैचों से काफी कुछ सीखा और अंतिम ओवर तक गए। हमने इस पर चर्चा की कि हम इस स्थिति से कैसे पार पा सकते हैं। मैं रियाद (महमूदुल्लाह) से कह रहा था कि बड़े शॉट खेलने की जगह एक और दो रन लेकर मैच जीतते हैं। मुझे लगता है कि इस मैच और इस पूरी सीरीज में हमारे पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है इसलिए यह हमें अपनी क्षमता के अनुसार निडर हो कर क्रिकेट खेलने की स्वतंत्रता देता है।' रहीम ने इसे बांग्लादेश क्रिकेट के लिए शानदार लम्हा करार देते हुए कहा, 'इससे पहले हमने टी-20 प्रारूप में उनके खिलाफ जीत दर्ज नहीं की थी। हम अपने कुछ अहम खिलाड़ियों के बिना खेल रहे थे, लेकिन युवा खिलाड़ी जिस तरह एकजुट होकर खेले और गेंदबाजों ने इस विकेट पर जिस तरह की गेंदबाजी की, वह शानदार था।'

रोहित ने किया रिषभ का बचाव

नई दिल्ली : बांग्लादेश के खिलाफ रिषभ पंत की खराब डीआरएस कॉल का खामियाजा भले ही भारतीय टीम को भुगतना पड़ा हो, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि इसे लेकर वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि पंत अभी काफी युवा हैं और मुश्किल रिव्यू पर फैसले लेना सीख जाएंगे। वह मैच का 10वां ओवर था जब डीआरएस को लेकर फैसले भारत के खिलाफ गए और आखिर में यह गलती टीम को महंगी पड़ी और उसे पहली बार बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा।

लेग स्पिनर युजवेंद्रा चहल के इस ओवर की तीसरी गेंद पर मुश्फिकुर रहीम एलबीडब्ल्यू आउट थे, लेकिन भारत ने रिव्यू नहीं लिया। गेंदबाज या विकेटकीपर पंत ने इसके लिए कप्तान को कोई सलाह भी नहीं दी। रहीम तब छह रन पर खेल रहे थे और बाद में वह 60 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सौम्य सरकार के खिलाफ पंत ने विकेट के पीछे कैच की अपील की, जिसे अंपायर ने ठुकरा दिया। पंत ने रोहित पर डीआरएस के लिए दबाव बनाया, लेकिन रिव्यू से स्पष्ट हो गया कि गेंद बल्ले से लगकर नहीं गई थी। दर्शकों ने भी धौनी-धौनी की गूंज से पंत को गलती का अहसास कराया। रोहित ने कहा, 'जब आप फैसला करने की सही स्थिति में नहीं होते हैं तो आपको फैसला लेने के लिए अपने गेंदबाज और विकेटकीपर पर भरोसा करना होता है। रिषभ अभी युवा हैं और उन्होंने बमुश्किल 10 से 12 टी-20 (असल में 21) मैच खेले हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की चीजों को समझने के लिए समय देने की जरूरत है। वह इस तरह के फैसले कर सकते हैं या नहीं, इस पर अभी फैसला करना जल्दबाजी होगी। यही बात गेंदबाज पर भी लागू होती है।' उन्होंने कहा, 'हमने मैदान पर कुछ फैसले अच्छे नहीं किए जो कि हमारे खिलाफ गए और आखिर में उस बल्लेबाज (रहीम) ने अर्धशतक जमाया।

फैसला करने में हम यहां पर कमजोर साबित हुए। हमने रिव्यू लेने में गलती की। उन्होंने (रहीम ने) पहली गेंद बैकफुट पर खेली और हमें लगा कि वह लेग साइड की तरफ जा रही है। अगली गेंद फ्रंट फुट पर थी, लेकिन हम यह भूल गए कि वह कितनी शॉर्ट थी। हम यह अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि उनकी लंबाई बहुत ऊंची नहीं है। मैदान पर हमने कई गलतियां कीं, लेकिन जहां तक बल्लेबाजी की बात है तो मुझे लगता है कि यह एक चुनौतीपूर्ण स्कोर था।'

दूसरे टी-20 पर महा खतरा

नई दिल्ली : भारत और बांग्लादेश के बीच दिल्ली में खेला गया पहला टी-20 मैच वायु प्रदूषण के कारण खतरे में था तो अब गुरुवार को राजकोट में होने वाले दूसरे टी-20 मैच पर महा खतरा मंडरा रहा है। महा नामक तूफान भारत के पश्चिम तट से दूर जा रहा था, लेकिन इसने करवट ली है और अब यह गुजरात तट की ओर बढ़ रहा है। अब राजकोट में होने वाले मैच से पहले, 6-7 नवंबर को पश्चिमी तट पर तूफान के आने का अंदेशा है, जिस कारण सौराष्ट्र तट पर मछुआरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्काइमेट वेदर के मुताबिक, तूफान के गुजरात तट तक आते-आते कमजोर होने की उम्मीद है। स्काइमेट के मुताबिक, 'यह दीव और पोरबंदर के बीच सात नवंबर को कम हो सकता है और उस समय हवा की स्पीड 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे होगी।'

टीम को बेहतर चयनकर्ताओं की जरूरत : युवराज

मुंबई, प्रेट्र : पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने एमएसके प्रसाद की अगुआई वाली राष्ट्रीय चयन समिति पर निशाना साधते हुए कहा कि टीम को निश्चित तौर पर बेहतर चयन समिति की जरूरत है क्योंकि आधुनिक क्रिकेट को लेकर मौजूदा समिति की सोच का जो स्तर होना चाहिए वैसा नहीं है।

बायें हाथ के बल्लेबाज युवराज ने कहा, 'हमें बेहतर चयनकर्ताओं की जरूरत है। चयनकर्ताओं का काम आसान नहीं होता है। जब भी वे 15 खिलाड़ियों का चयन करेंगे तब ऐसी बातें होंगी कि उन 15 खिलाड़ियों का क्या होगा जो टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे। यह मुश्किल काम है, लेकिन मेरी समझ में आधुनिक क्रिकेट को लेकर उनकी सोच उस स्तर तक नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। मैं हमेशा से खिलाड़ियों के हितों की रक्षा का समर्थन करता हूं। आपके असली चरित्र के बारे में तभी पता चलता है जब खिलाड़ी का समय साथ नहीं देता है और आप उसे प्रेरित करते हैं। बुरे समय में, हर कोई बुरी बात करता है। हमें निश्चित रूप से बेहतर चयनकर्ताओं की जरूरत है।'

गांगुली लाएंगे बदलाव : युवराज ने दावा किया कि देश के कई क्रिकेटर अपना स्थान गंवाने के डर से थके होने के बावजूद विश्राम नहीं लेते और उम्मीद जताई कि सौरव गांगुली के बीसीसीआइ अध्यक्ष बनने के बाद इसमें बदलाव आएगा। निजी लीग में खेलने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले युवराज ने खिलाड़ियों के संघ का भी समर्थन किया। युवराज ने कहा, 'हम इसके हकदार हैं क्योंकि कई बार हमें क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाता है जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। हमें इस दबाव में खेलना होता है कि अगर हम नहीं खेलते हैं तो हमें बाहर कर दिया जाएगा। खिलाड़ियों पर से यह दबाव खत्म होना चाहिए कि अगर वे थके हुए हैं या चोटिल हैं उन्हें तब भी खेलना होगा।' युवराज ने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल का उदाहरण दिया जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मसले के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से विश्राम लिया और बोर्ड ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा, 'हमारे खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपनी जगह गंवाने का डर रहता है इसलिए खिलाड़ियों का संघ बेहद महत्वपूर्ण है। सौरव के अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय क्रिकेट में कई नई चीजें होंगे। एक बेहद सफल कप्तान क्रिकेटरों के हितों को ध्यान में रखेगा जहां खिलाड़ियों की बातें भी सुनी जा सकती है। ऐसा पहले नहीं हुआ। अब वह क्रिकेटरों की बात भी सुनेंगे कि वे क्या चाहते हैं।'

नजरिया

- कहा, बाहर होने के डर से विश्राम से बचते हैं भारतीय खिलाड़ी
- मौजूदा समिति की सोच का जो स्तर होना चाहिए वैसा नहीं है

दुबे की गलतियां पहचाने राठौर

बांग्लादेश के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय करियर का पदार्पण करने वाले ऑलराउंडर शिवम दुबे की खुद से तुलना पर युवराज ने कहा, 'जब वह अपने करियर में एक स्तर तक पहुंच जाए तब उसके बाद उसकी तुलना किसी अन्य से करनी चाहिए। उसे अपना नाम खुद बनाना चाहिए। वह प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। उसे अपने खेल में कई में चीजों पर काम करने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि वह जहां गलतियां कर रहा है, उसे पहचान पाएगा। विक्रम राठौर बल्लेबाजी कोच हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि दुबे कहां गलती कर रहा है।'

एनबीए अकादमी के लिए चुनी गई पंजाब की हरसिमरन कौर

नई दिल्ली, आइएएनएस : पंजाब की बास्केटबॉल खिलाड़ी हरसिमरन कौर को एनबीए ग्लोबल अकादमी ने ट्रेनिंग कैंप के लिए चुना है। यह कैंप सात से 24 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित होगा। 16 साल की हरसिमरन इस कैंप के लिए न्योता पाने वाली पंजाब की ही नहीं, बल्कि भारत की भी पहली महिला खिलाड़ी हैं।

हरसिमरन को मुंबई में अक्टूबर में महिलाओं के लिए हुए तीसरे एनबीए अकादमी कार्यक्रम कैंप में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी (एमवीपी) चुना गया था। पंजाब की इस खिलाड़ी ने अगस्त 2019 में जकार्ता में हुई 3 गुना 3 एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया था। वह उन चार भारतीय खिलाड़ियों में भी शामिल रह चुकी हैं जिन्हें अप्रैल में थम्पा में फर्स्ट नेक्सट जेनरेशन कार्यक्रम के तहत न्योता दिया गया था। इसके अलावा वह अमेरिका की जूनियर राष्ट्रीय टीम के सदस्यों के विरुद्ध भी खेल चुकी हैं। एनबीए ग्लोबल अकादमी का उद्देश्य अमेरिका के बाहर ऑस्ट्रेलिया में एनबीए हब तैयार करना है। हरसिमरन एनबीए अकादमी के कोचों और ऑस्ट्रेलिया के बास्केटबॉल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से गुर सीखेंगी। हरसिमरन ने कहा कि इस मौके को प्राप्त कर मैं बहुत उत्सुक हूं। मैं कड़ी मेहनत जारी रखूंगी। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मेरी योग्यता को समाने लाएगा। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य महिलाओं की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के लिए खेलना है।

अभ्यास के दौरान हरसिमरन कौर • फाइल फोटो, सोशल मीडिया

मेहनत की भट्टी में तपकर कुंदन बनीं हरसिमरन

हरनेक सिंह जैनपुरी • कपूरथला

रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) कपूरथला की खिलाड़ी हरसिमरन कौर कड़ी मेहनत के बूते दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) के ग्लोबल कैंप में चयनित होने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं।

15 वर्षीय हरसिमरन ने 2013 में बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। पिता बास्केटबॉल टीम के कोच थे तो हरसिमरन का अधिकतर अभ्यास लड़कों के साथ हुआ। इस अभ्यास से हरसिमरन का स्टेमिना और फुटवर्क बहुत अच्छा हुआ। एनबीए के ग्लोबल कैंप तक पहुंचने के लिए हरसिमरन ने कभी अभ्यास नहीं छोड़ा। बारिश हो या सर्दी या फिर कड़ी धूप, लगातार मेहनत की भट्टी में तपकर हरसिमरन कुंदन बनीं। एनबीए अकादमी ने मई 2019 में ट्रायल लिए थे। 24 में से सिर्फ चार खिलाड़ी इसमें चयनित हुए थे। बाद में चार में से दो का ही चयन हुआ। एनबीए लीग में शानदार खेल की बदौलत अब एनबीए ग्लोबल कैंप के लिए भारत से सिर्फ हरसिमरन का चयन हुआ है।

घर से मिली प्रेरणा : छह फीट ढाई इंच लंबी हरसिमरन को खेल की प्रेरणा घर से ही मिली। हरसिमरन की मां सुमनप्रीत कौर अंतरराष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रही हैं। वह दो बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। हरसिमरन के पिता सुखदेव सिंह आरसीएफ की बास्केटबॉल टीम के कोच हैं। वह ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। पिता से ही सिमरन को बास्केटबॉल खेलने की प्रेरणा मिली। उनके पिता को इंजरी हो गई थी और पैसे नहीं होने के कारण वह ऑपरेशन नहीं करवा सके। इसके बाद उन्होंने खेलना छोड़ दिया और कोचिंग शुरू कर दी।

देश को पदक दिलाना सपना

हरसिमरन आरसीएफ स्थित केंद्रीय विद्यालय में 11वीं कक्षा की छात्रा हैं। हरसिमरन कहती हैं कि अभी तो एनबीए में उसकी शुरुआत है। आगे का सफर बहुत लंबा और कठिन है। आगे बढ़ने के साथ-साथ मुकाबला भी कड़ा होता जाता है। डब्ल्यूएनबीए में खेलना और ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना और पदक दिलाना ही मेरा सपना है।

रीयल कश्मीर पर बनी डॉक्युमेंट्री को 'बाफ्टा स्कॉटलैंड' पुरस्कार

नई दिल्ली, जेएनएन : रीयल कश्मीर फुटबॉल क्लब पर बनी डॉक्युमेंट्री को स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में प्रतिष्ठित 'ब्रिटिश अकादमी ऑफ फील्ड एंड टेलीविजन अवॉर्ड्स' (बाफ्टा) पुरस्कार के लिए चुना गया। इस डॉक्युमेंट्री में रीयल कश्मीर एफसी टीम के कोच के रूप में रेंजर्स टीम के पूर्व स्टार डेविड रॉबर्टसन की यात्रा को दर्शाया गया है। रॉबर्टसन के मार्गदर्शन में रीयल कश्मीर एफसी की टीम भारत की तत्कालीन शीर्ष दर्जे की फुटबॉल लीग आइलीग में अपने पहले ही सत्र में तीसरे स्थान पर रही थी।

इस साल बीबीसी स्कॉटलैंड पर दिखाई गई इस एक घंटे की फिल्म को 'एकल वृत्तचित्र' वर्ग में पुरस्कार के लिए चुना गया। इस डॉक्युमेंट्री के निर्देशक ग्रेग क्लार्क को भी निर्देशन के एक वर्ग में नामित किया गया था।

नदीम व जाधव के दम पर भारत-बी बना चैंपियन

जागरण संवाददाता, रांची : केदार जाधव की दमदार बल्लेबाजी और शाहबाज नदीम की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत बी ने देवधर ट्रॉफी के फाइनल में भारत सी को 51 रनों से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया।

जेएससीए स्टेडियम में सोमवार को खेले गए फाइनल मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल की कप्तानी वाली भारत बी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 283 रन बनाए। टीम के लिए जाधव ने सबसे ज्यादा 86 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत सी की टीम 50 ओवरों में नौ विकेट पर 232 रन ही बना सकी। अपने घरेलू मैदान पर नदीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवरों में 32 रन खर्च कर चार विकेट लिए। इसी मैदान पर नदीम ने अपने करियर के पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में दो-दो विकेट लिए थे। भारत सी के लिए उत्तर प्रदेश के युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग ने 77 गेंदों पर आठ चौके और एक छक्के की मदद से 74 रन बनाए। हालांकि वह टीम को जीत नहीं दिला पाए।

रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में देवधर ट्रॉफी टूर्नामेंट की विजेता भारत-बी टीम के खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ • जागरण

जाधव ने खेली शानदार पारी : इससे पहले भारत बी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत सी के तेज गेंदबाज ईशान पोरेल ने भारत बी के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज रितुराज गायकवाड़ को शून्य पर आउट कर पवेलियन भेज दिया। मध्यक्रम के बल्लेबाज जाधव ने 94 गेंदों में चार चौके और चार छक्कों की मदद से अर्धशतकीय पारी खेली। जाधव के अलावा यशस्वी जायसवाल ने 79 गेंदों में पांच चौके और एक छक्के की मदद से 54 रन बनाए। वहीं, विजय शंकर 45 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी के ओवरों में कृष्णप्पा गौतम ने 10 गेंदों में 35 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत सी की ओर पोरेल ने 43 रन देकर पांच विकेट झटके।

देवधर ट्रॉफी के फाइनल में भारत सी को 51 रन से हराया शाहबाज ने झटके चार विकेट केदार ने खेली 86 रनों की पारी

फॉर्मूला-1 हैमिल्टन ने छठी बार विश्व खिताब अपने नाम किया, दिग्गज फॉर्मूला-1 ड्राइवर माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड के करीब पहुंचे लुइस

शूमाकर से एक कदम पीछे हैमिल्टन

ऑस्टिन, एएफपी : सुपरस्टार ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने यहां अमेरिकी ग्रांप्रि में मर्सिडीज टीम के अपने साथी वाल्टेरी बोटास के पीछे दूसरे स्थान पर रहते हुए छठी बार फॉर्मूला-1 विश्व खिताब जीत लिया। ब्रिटिश ड्राइवर हैमिल्टन ने छठी बार विश्व खिताब अपने नाम किया और वह माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड सात खिताब से सिर्फ एक खिताब पीछे हैं। वह भले ही अमेरिकन ग्रांप्रि नहीं जीत सके लेकिन अंकों के आधार पर इस साल का खिताब उनके नाम हो गया है क्योंकि इस साल होने वाली कुल 21 फॉर्मूला वन ग्रांप्रि में से 19 हो चुकी हैं और हैमिल्टन के 381 अंक हैं। ब्राजील और संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली अगली दो रेसों का रिजल्ट जो भी हो अंकों के मामले में कोई भी हैमिल्टन को पछाड़ नहीं पाएगा।

हैमिल्टन ने इस खिताब को दिवंगत निकी लौदा को समर्पित किया। लौदा का निधन 70 वर्ष की उम्र में मई में हो गया था। लौदा ने तीन बार विश्व खिताब जीता है। बोटास ने 1:33:55 का समय निकालकर अमेरिकन ग्रांप्रि अपने नाम की जबकि तीसरे स्थान पर रेड बुल के मैक्स वेरस्टापेन रहे। ब्रिटेन के 34 साल के हैमिल्टन ने ग्रिड पर पांचवें जबकि फिनलैंड के बोटास ने पहले स्थान से रेस की शुरुआत की थी। हैमिल्टन ने दो बार रेस में बढ़त बनाई, लेकिन जब सिर्फ तीन लैप बचे थे तब बोटास ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। हैमिल्टन टीम के अपने साथी ड्राइवर को इसके बाद पीछे नहीं छोड़ पाए, लेकिन उन्होंने वेरस्टापेन को आगे नहीं निकलने दिया। हैमिल्टन ने 150वीं बार पोडियम पर जगह बनाई जबकि लगातार 31वीं बार अंक हासिल करने में सफल रहे।

फॉर्मूला-1 इतिहास में ब्रिटिश ड्राइवरों का बोलबाला रहा है। 1000 में से 279 बार ब्रिटेन के ड्राइवरों ने रेस में पहला स्थान हासिल किया जिसमें हैमिल्टन सबसे आगे हैं। वैसे एफ-1 इतिहास में सबसे अधिक जीत का रिकॉर्ड जर्मनी के डाइवर माइकल शूमाकर के नाम है। शूमाकर ने अपने करियर में कुल 91 रेस जीती हैं। जर्मन ड्राइवर 178 बार पहला स्थान हासिल करने में सफल रहे हैं। एफ-1 इतिहास में सिर्फ ब्रिटेन, जर्मनी और ब्राजील के ड्राइवर 100 से अधिक रेस जीत चुके हैं।

2019 में विश्व खिताब जीतने वाले लुइस हैमिल्टन ने इससे पहले 2018, 2017, 2015, 2014 और 2008 में भी यह खिताब जीता था

381 अंक के साथ हैमिल्टन इस साल ड्राइवरों की विश्व चैंपियनशिप तालिका में पहले और बोटास 314 अंक के साथ दूसरे जबकि फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क 249 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं

21 फॉर्मूला वन ग्रांप्रि में से 19 हो चुकी हैं। हैमिल्टन के इतने अंक हैं कि बाकी दो रेसों में उन्हें कोई पछाड़ नही पाएगा

> मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सभी का धन्यवाद। अमेरिकी ग्रांप्रि मुश्किल रेस थी। बोटास ने शानदार प्रदर्शन किया। मेरा परिवार यह रेस देखने आया था और यह विश्व खिताब जीतना सम्मान की बात है। मेरा पिता ने मुझसे कभी भी हार नहीं मानने के लिए कहा है और इससे मुझे मदद मिली।
>
> – लुइस हैमिल्टन

स्वागत नहीं होने से नाराज हॉकी टीम की कप्तान

संवाद सहयोगी, शाहाबाद (कुरुक्षेत्र) : भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने कहा कि उनकी टीम को टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिलना बेहद गर्व की बात है, लेकिन हरियाणा ने इसके रंग को फीका कर दिया है। उन्हें लगा था कि इस बड़ी उपलब्धि के लिए हरियाणा की हॉकी खिलाड़ियों का रंगारंग स्वागत होगा और खेल प्रेमियों का अभिवादन मिलेगा, लेकिन किसी ने फोन करके दो शब्द भी नहीं कहे।

रानी ने कहा कि शाहाबाद के हॉकी स्टेडियम में कोच अमनदीप व जूनियर खिलाड़ियों ने ही सिर्फ उनका हौसला बढ़ाया। अमेरिका के साथ ओलंपिक क्वालीफायर के दोनों मैच अहम थे और ओलंपिक में जाने का आखिरी मौका था इसलिए पहले मैच में टीम ने उम्दा प्रदर्शन करके इस मैच को जीत लिया। रानी ने कहा कि दूसरे मैच में अमेरिका पूरी ताकत के साथ आया था और मेहमान टीम आक्रामक होकर खेली क्योंकि उनके लिए भी यह मैच ओलंपिक के लिए आखिरी मौका था। दूसरे मैच में अमेरिका ने हमें कोई भी मौका नहीं दिया लेकिन कुल गोल के आधार पर हम क्वालीफाई कर गए। ओलंपिक के लिए 10 महीने शेष हैं और इस दौरान इन मैचों में जो गलतियां की हैं उन पर सुधार किया जाएगा। खूब मेहनत करेंगे और ओलंपिक में अच्छी टीमों के साथ अच्छा प्रदर्शन कर सकारात्मक परिणाम हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मैच के दौरान उनकी कलाई में मोच आई थी, लेकिन उसकी परवाह किए बिना वह टीम के लिए खेली। रानी रामपाल ने कहा कि पिछले दिनों खेल में व्यस्त होने के कारण वह एमए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दे पाईं।

टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने के बाद घर पहुंचीं रानी ने कहा, सोचा था स्वागत होगा, किसी ने बधाई तक नहीं दी

मैं खुश हूं कि टीम प्रबंधन ने मेरी भूमिका तय की हुई है। मैं कोशिश करूंगा कि टीम की जीत में अपना अहम योगदान दूं।
– एलेक्स कैरी, बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया

मिताली राज ने खेली उपयोगी पारी, भारत ने जीता मैच

नॉर्थ साउंड, प्रेट्र : पूनम राउत (77) के अर्धशतक और कप्तान मिताली राज (40) एवं उप कप्तान हरमनप्रीत कौर (46) की उपयोगी पारियों के बाद स्पिनरों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत ने आइसीसी महिला चैंपियनशिप के तहत खेले गए दूसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 53 रन से मात दी। भारतीय टीम ने 50 ओवर में छह विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में भारतीय स्पिन तिकड़ी के आगे वेस्टइंडीज की टीम 47.2 ओवर में 138 रन पर ढेर हो गई।

न्यूज गैलरी

पदक मुकाबले में हारे रवि

बुडापेस्ट : भारतीय पहलवान रवि राठी (97 किग्रा) को यहां यूडब्ल्यूडब्ल्यू अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में बेलारूस के दिमित्री कमिंस्की के खिलाफ ग्रीको रोमन वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले में 0-8 से हार का सामना करना पड़ा। रवि से पदक जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने निराश किया। रवि की हार के साथ ही इस टूर्नामेंट में भारत का अभियान दो पदकों के साथ समाप्त हुआ। भारत की ओर से इस टूर्नामेंट में सिर्फ रवींद्र (61 किग्रा) और पूजा गहलोत (53 किग्रा) ने रजत पदक जीते। रवि रविवार को रेपचेज में किर्गीस्तान के उजुर डिजुजुपबेकोव को 3-1 से हराने में सफल रहे थे, लेकिन कांस्य पदक के मुकाबले में वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सके। फ्रीस्टाइल में हालांकि भारतीय पुरुष कुश्ती टीम टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 48 अंक के साथ तालिका में 11वें स्थान पर रही। महिलाओं के वर्ग में फ्रीस्टाइल टीम 12वें, जबकि ग्रीको रोमन टीम 15वें स्थान पर रही। (प्रेट्र)

भारत को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग

नई दिल्ली : भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम आइटीटीएफ रैंकिंग में सोमवार को नौवें स्थान पर पहुंच गई जो उसकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। भारतीय टीम में विश्व के 30वें नंबर के जी साथियान और विश्व में 36वें नंबर के शरत कमल शामिल हैं। वे 272 अंक के साथ ऑस्ट्रिया के साथ संयुक्त 10वें स्थान पर हैं, लेकिन उन्हें नौवीं रैंकिंग दी गई। भारतीयों में साथियान और शरत ही शीर्ष-100 में शामिल हैं। भारत के नंबर तीन हरमीत देसाई विश्व रैंकिंग में 104वें स्थान पर हैं। चीन टीम रैंकिंग में शीर्ष पर है। उसके बाद जापान और जर्मनी का नंबर आता है।

निशाने पर ओलंपिक कोटा

लुसैल (कतर) : भारतीय निशानेबाज मंगलवार से यहां शुरू होने वाली 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप मे ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक कोटा हासिल करने की कोशिश करेंगे। भारत के 63 पुरुष और 45 महिला निशानेबाज राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं में सीनियर, जूनियर और युवा वर्ग में भाग लेंगे। इस 10 दिन तक चलने वाली महाद्वीपीय चैंपियनशिप में 15 में से 12 स्पर्धाओं में टोक्यो ओलंपिक के लिए 38 कोटा स्थान दांव पर लगे होंगे। चैंपियनशिप में तीन मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में कोटा स्थान नहीं है, जबकि पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सर्वाधिक चार कोटा स्थान दांव पर लगे रहेंगे। भारत पहले ही टोक्यो के लिए नौ कोटा स्थान हासिल कर चुका है और वह एशियाई क्षेत्र में चीन (25 कोटा), कोरिया (12 कोटा) और मेजबान जापान (12 कोटा) के बाद चौथे नंबर पर है। (प्रेट्र)

पाकिस्तान में नहीं होंगे भारत के डेविस कप मुकाबले

टेनिस डायरी ▸ आइटीएफ ने मानी भारत की मांग, तटस्थ स्थान पर होंगे मैच

सुरक्षा कारणों के चलते विश्व संस्था ने पाकिस्तान से हटाए भारत के मैच

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आइटीएफ) ने सोमवार को डेविस कप के एशिया/ओशनिया ग्रुप-1 के तहत भारत-पाकिस्तान के होने वाले मैचों को पाकिस्तान से हटा दिया है। इस आदेश के तहत कहा गया है कि यह मुकाबले तटस्थ जगह पर खेले जाएंगे।

यह फैसला अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआइटीए) के इन मुकाबलों को सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान से बाहर ले जाने की मांग के बाद हुआ है। यह मुकाबले 29 और 30 नवंबर को होने थे। आइटीएफ ने कहा, 'आइटीएफ के स्वतंत्र सुरक्षा सलाहकारों की ताजा सलाह के बाद डेविस समिति ने फैसला लिया है कि भारत-पाकिस्तान के 29-30 नवंबर को होने वाले मुकाबले को तटस्थ जगह पर खेला जाएगा। आइटीएफ और डेविस कप समिति की पहली प्राथमिकता खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा है और इसी आधार पर फैसला लिया गया है।' आइटीएफ ने कहा, 'डेविस कप के नियमों के तहत पाकिस्तान टेनिस संघ के पास अब तटस्थ जगह को चुनने का विकल्प है और प्रस्तावित जगह को तय करने के लिए उनके पास पांच दिन है। एक बार विकल्प की जानकारी दिए जाने और इसे मंजूरी मिलने पर नए स्थान का चुनाव किया जाएगा।'

राजपाल गैर खिलाड़ी कप्तान : इससे पहले पूर्व भारतीय खिलाड़ी और एआइटीए की चयन समिति के अध्यक्ष रोहित राजपाल को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भारत का गैर खिलाड़ी कप्तान बनाया गया। इस तरह की अटकलें थी कि अनुभवी लिएंडर पेस को इस पद के लिए चुना जा सकता है क्योंकि शीर्ष खिलाड़ियों और कप्तान महेश भूपति के हटने के बाद उन्होंने स्वयं को उपलब्ध रखा था। एआइटीए ने चंडीगढ़ में अपनी वार्षिक आम बैठक में राजपाल को नियुक्त करने का फैसला किया। राजपाल ने 1990 में सियोल में कोरिया के खिलाफ डेविस कप में पदार्पण किया, जहां भारत अपने पांचों मैच हार गया था। राजपाल ने सिर्फ इसी मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें महज औपचारिकता के चौथे मैच में जेई सिक किम के खिलाफ 1-6, 2-6 से हार का सामना करना पड़ा था।

नडाल एक साल बाद फिर बने विश्व के नंबर वन खिलाड़ी

पेरिस, प्रेट्र : स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल सोमवार को एक साल बाद फिर से दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बन गए। उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविक की जगह ली जो दूसरे नंबर पर खिसक गए।

नडाल इससे पहले चार नवंबर 2018 को नंबर एक पर काबिज थे। यह आठवां अवसर है जब 33 वर्षीय यह खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंचा है। वह 1973 के बाद एटीपी रैंकिंग में नंबर एक की कुर्सी पर काबिज होने वाले दूसरे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। फेडरर 2018 में 36 साल की उम्र में नंबर एक बने थे। नडाल का प्रयास अब साल के आखिर में नंबर एक पर बने रहना होगा। अगर वह ऐसा करने में सफल रहते हैं तो साल के आखिर में नंबर एक पर काबिज रहने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे। उन्हें हालांकि लंदन में होने वाले एटीपी टूर फाइनल्स के लिए फिट होना होगा। अगर नडाल इसमें नहीं खेलते हैं और जोकोविक फाइनल में पहुंच जाते हैं तो फिर सर्बियाई खिलाड़ी फिर से शीर्ष पर पहुंच जाएगा। नडाल पहली बार अगस्त 2008 में शीर्ष पर पहुंचे थे। वह अब तक 197 सप्ताह नंबर एक रह चुके हैं। फेडरर 1973 के बाद सर्वाधिक 310 सप्ताह शीर्ष पर काबिज रहे हैं। उनके बाद पीट संप्रास (286), जोकोविक (275), इवान लेंडल (270), जिम्मी कोनर्स (268) और नडाल का नंबर आता है। तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर क्रमश : स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर, रूस के डेनिल मेदवेदेव और ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम हैं। इस बीच, महिलाओं में एश्ले बार्टी ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। चेक गणराज्य की केरोलिना प्लिस्कोवा दूसरे नंबर पर है। एलिना स्वितोलिना छठे नंबर पर खिसक गईं जबकि सिमोना हालेप चौथे नंबर पर जा पहुंचीं।

स्पेनिश दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल। ट्विटर

जोकोविक को पेरिस मास्टर्स का खिताब

पेरिस : शीर्ष वरीय टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने फाइनल में कनाडा के युवा डेनिस शापोवालोव को हराकर रिकॉर्ड पांचवां पेरिस मास्टर्स खिताब अपने नाम किया। अपने 50वें मास्टर्स फाइनल में खेल रहे जोकोविक ने 28वीं रैंकिंग पर काबिज अपने 20 साल के प्रतिद्वंद्वी शापोवालोव को 6-3, 6-4 से शिकस्त दी, जो राफेल नडाल के सेमीफाइनल से हटने के कारण फाइनल में पहुंचे थे। 16 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन के नाम अब 34 मास्टर्स खिताब और एटीपी टूर में कुल 77 ट्रॉफियां हैं। वह मास्टर्स खिताब में नडाल (35 ट्रॉफियां) से केवल एक ट्रॉफी पीछे हैं। यह जोकोविक की इस सत्र में पांचवीं ट्रॉफी थी। इससे पहले उन्होंने विंबलडन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंडस्लैम के अलावा मैड्रिड ओपन और टोक्यो में खिताब जीते हैं।

खिताबी ट्रॉफी के साथ सर्बिया के नोवाक जोकोविक। एएफपी

चीन ओपन से हटे बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत

फुझोउ, प्रेट्र : महिलाओं में शीर्ष खिलाड़ी पीवी सिंधू और साइना नेहवाल मंगलवार से यहां शुरू हो रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से लय हासिल करने के साथ खिताब जीतने की कोशिश करेंगे।

शीर्ष भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीन ओपन से नाम वापस ले लिया। विश्व रैंकिंग में पूर्व नंबर-1 श्रीकांत को मौजूदा विश्व चैंपियन और नंबर-1 खिलाड़ी जापान के केंतो मोमोता से भिड़ना था, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने का फैसला किया। श्रीकांत अगले सप्ताह खेले जाने वाले हांगकांग ओपन में भाग लेंगे। भारत की नजरें सिंधू और साइना के खेल पर होंगी जिनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। सिंगल्स में इन दोनों महिला खिलाड़ियों के अलावा डबल्स में सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष जोड़ी से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है जिन्होंने पिछले महीने फ्रेंच ओपन के फाइनल तक का सफर तय किया था। भारतीय जोड़ी हालांकि उप विजेता रही थी।

इससे पहले चीन, कोरिया और डेनमार्क में खेले गए पिछले तीन टूर्नामेंट में सिंधू और साइना का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर लय में होने का संकेत दिया था। इस साल अगस्त में विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करने वाली सिंधू को छठी वरीयता दी गई है जो पहले दौर में जर्मनी की युवोन्ने ली से भिड़ेंगी। आठवीं वरीयता प्राप्त साइना का सामना चीन की काइ यान यान से होगा। सिंधू अगर शुरुआती दौर की चुनौती से पार पाने में सफल रहीं तो क्वार्टर फाइनल में उनका सामना तीन बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन या विश्व नंबर एक खिलाड़ी ताइ जु यिंग से हो सकता है। साइना को क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची का सामना करना पड़ सकता है। बी साई प्रणीत, समीर वर्मा, एचएस प्रणय, पूर्व कॉमनवेल्थ चैंपियन पारुपल्ली कश्यप भी पुरुष सिंगल्स में अपनी चुनौती पेश करेंगे। अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक को देखते हुए डबल्स में भारतीय खिलाड़ियों को अपनी फॉर्म को वापस पाने का मौका है।

डबल्स में सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी पहले दौर में जब कोरिया की किम जी जुंग और ली योग दाई के खिलाफ कोर्ट में उतरेगी तो उसकी कोशिश फ्रेंच ओपन की लय को बरकरार रखने की होगी। मनु अत्री और बी सुमीत रेड्डी की जोड़ी के सामने पहले दौर में मलेशिया के आरोन चिय और शोह वूइ यिक की चुनौती होगी। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी को पहले दौर में चीन के ली वेन मेइ और झेंग यू से भिड़ना होगा। मिक्स्ड डबल्स में सात्विक और अश्विनी की जोड़ी के अलावा प्रणव जेरी चोपड़ा और सिक्की की जोड़ी भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने की कोशिश करेगी।

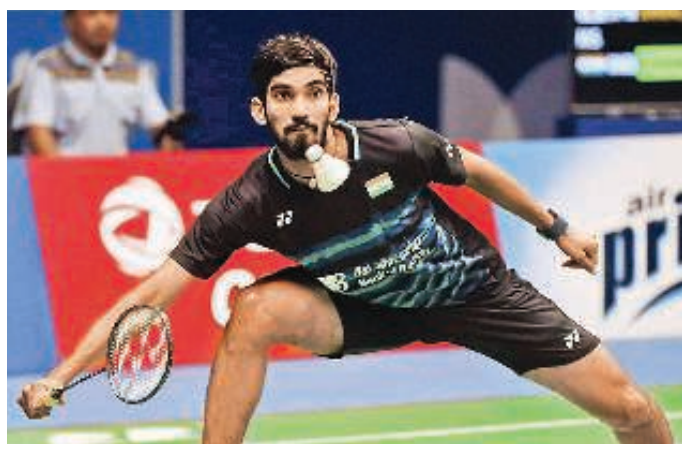

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत। फाइल फोटो, प्रेट्र

भारत की महिला अंडर-17 टीम का शिविर नौ नवंबर से

फुटबॉल डायरी

कल्याणी (बंगाल), प्रेट्र : अगले साल देश में होने वाले फीफा महिला अंडर-17 विश्व कप की तैयारियों के लिए भारतीय महिला टीम का 10 दिवसीय शिविर नौ नवंबर से शुरू होगा। महिला टीम पिछले चार महीने से शिविर में है और एक छोटे ब्रेक के बाद फिर से एकजुट होगी। शिविर में संभावित खिलाड़ियों को चार टीमों में बांटा जाएगा जो राउंड रोबिन आधार में 11, 13 और 15 नवंबर को एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। पिछले महीने महिला अंडर-15 टीम को सैफ टूर्नामेंट का चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कोच एलेक्स एंब्रोस ने कहा कि इन मैचों से प्रतिभा पूल तलाशने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'कल्याणी में टूर्नामेंट हमारे लिए खिलाड़ियों को परखने का मौका देगा। हमारे पास पहले से ही खिलाड़ियों का एक समूह है, लेकिन यह हमें अन्य खिलाड़ियों पर भी एक नजर डालने का अवसर प्रदान करेगा।'

बायर्न म्यूनिख ने कोच कोवाक को किया बर्खास्त

बर्लिन, एएफपी : जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने खराब प्रदर्शन के कारण मैनेजर निको कोवाक से नाता तोड़ लिया। यह फैसला क्लब प्रबंधन और कोच की आम सहमति बनने के बाद हुआ। क्लब ने कहा कि हम इस बात का दुख है कि कोवाक हम से अलग हो गए। कोवाक ने जप हेन्क्स का स्थान लिया था। टीम के खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें कई तरह की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। कोवाक ने कहा कि मुझे लगता है कि इस समय क्लब के लिए यह सही फैसला है। जो परिणाम आए और जिस तरह के हम खेले उसने मुझे इस फैसले तक पहुंचाया। मैं टीम को शुभकामनाएं देता हूं। कोवाक के जाने के बाद सहायक कोच हेंस फ्लिक टीम की जिम्मेदारी लेंगे।

विविध

एयर इंडिया से गोरखपुर आने वालों का दिल्ली में छूट रहा सामान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

- होल्ड एरिया भर जाने के कारण पैदा हो रही समस्या
- गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्री रोजाना कर रहे हंगामा

दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट से गोरखपुर आने वाले यात्री रोजाना परेशान हो रहे हैं। औसतन हर रोज दो से तीन लोगों का सामान दिल्ली में ही छूट जा रहा है। इसकी वजह एटीआर विमान के होल्ड एरिया (सामान रखने की जगह) का भर जाना बताया जा रहा है। सामान छूटने की जानकारी यात्रियों को गोरखपुर पहुंचने पर हो रही है।

एयर इंडिया का 70 सीटों वाला विमान (एटीआर 72) दोपहर बाद 3.20 बजे दिल्ली से यात्रियों को लेकर गोरखपुर पहुंचता है। आधे घंटे बाद यह विमान यात्रियों को लेकर दिल्ली लौट जाता है। इस विमान में सामान रखने के लिए बना होल्ड एरिया छोटा है। इस कारण कुछ यात्रियों का सामान गोरखपुर नहीं आ पा रहा है जिसका वजन तो मानक के अनुरूप है लेकिन आकार बड़ा है।

छूटे सामान को विमान कंपनी बोइंग विमान से लखनऊ भेज रही है। वहां से गोरखपुर लाया जा रहा है। यह समस्या करीब-करीब रोजाना आ रही है। रविवार को तो पांच यात्रियों का सामान छूट गया। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें जानकारी हुई तो हंगामा शुरू कर दिया। अधिकारियों के समझाने पर वे माने। यात्रियों ने एयर इंडिया की व्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इससे उनका समय बर्बाद हो रहा है।

> गोरखपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। दिल्ली से आने वाले विमान के यात्रियों का सामान छूटने की शिकायत मिल रही है। इसकी वजह एटीआर विमान के होल्ड एरिया का छोटा होना व सामान के आकार का बड़ा होना है। जिन लोगों का सामान छूटता है, उसे एयर इंडिया बोइंग विमान से भेजता है।
>
> – विजय कौशल, मुख्य सुरक्षा अधिकारी, गोरखपुर एयरपोर्ट

घरेलू विमान में ले जा सकते हैं 15 किलोग्राम सामान : एयरपोर्ट निदेशक अनिल द्विवेदी ने बताया कि घरेलू विमान से सफर करने वाले यात्री 15 किग्रा वजन का सामान लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा सात किलोग्राम वजन का एक बैग वह अपने साथ रख सकते हैं। सामान का वजन ज्यादा होने पर प्रतिकिलो 400 रुपये अतिरिक्त चार्ज लगता है।

उत्तराखंड में पलायन थामने को अब धरातल पर जुटेंगे महकमे

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- पांच विभागों की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने में जुटा शासन

गांवों से निरंतर हो रहे पलायन को थामने के मद्देनजर अब सरकारी महकमे ठोस कार्ययोजना के साथ धरातल पर जुटेंगे। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की ओर से इस संबंध में सरकार को सौंपी गई आठ विभागों की कार्ययोजना में सुझाए गए बिंदुओं को लेकर शासन गंभीरता से मंथन में जुटा है। मुख्य सचिव स्तर पर एक दौर का मंथन हो चुका है। कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के मद्देनजर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने 25 से 27 नवंबर तक विभागों की बैठकें बुलाई हैं। इसके बाद कार्ययोजना को फाइनल कर इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

प्रदेश में पलायन एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य गठन से अब तक 1702 गांव खाली हो चुके हैं। पलायन आयोग की ही रिपोर्ट बताती है कि राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं, जहां आबादी अंगुलियों में गिनने लायक रह गई है। बीती 29 जून को पौड़ी में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पलायन पर गहन मंथन हुआ था। तब आयोग को निर्देश दिए गए थे कि वह गांवों से पलायन थामने के मद्देनजर विभागवार कार्ययोजना तैयार कर सरकार को उपलब्ध कराए। इसके बाद आयोग ने ग्रामीणों से सुझाव लेकर रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें अगले पांच साल तक गांवों के विकास और वहां रोजगार के साधन मुहैया कराने पर जोर दिया गया। साथ ही आठ विभागों ग्राम्य विकास, पंचायतीराज, सहकारिता, एमएसएमई, पर्यटन, उद्यान, कृषि एवं पशुपालन की कार्ययोजना तैयार कर सरकार को सौंपी। कार्ययोजना में शामिल बिंदुओं को लेकर 22 अक्टूबर को मुख्य सचिव स्तर पर एक दौर का मंथन हो चुका है। इसमें कुछ अन्य बिंदुओं को शामिल करने का सुझाव दिया और अब आयोग संशोधित कार्ययोजना भी शासन को सौंप चुका है।

अब इन विभागों की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी गई है। आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी के मुताबिक इस सिलसिले में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने 25 से 27 नवंबर तक विभागवार बैठकें बुलाई हैं। इनमें संबंधित विभागों की कार्ययोजना पर गहनता से विचार कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर कार्ययोजना को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद महकमे इसे धरातल पर उतारने को जुटेंगे।

आयोग के मुख्य सुझाव

- पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में प्रति परिवार मासिक आमदनी को पांच हजार से बढ़ाकर 10 हजार करने का हो लक्ष्य।
- गांवों के विकास की जो भी योजनाएं बनें, उनमें ग्रामीण आर्थिकी की रीढ़ महिलाओं को केंद्र में रखा जाए।
- पेयजल की उपलब्धता, वन्यजीवों से फसल क्षति, खेत दुरुस्तीकरण को मनरेगा में किया जाए शामिल।
- आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने को हर गांव में हो एक ट्रेनर।
- पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास पर हो खास फोकस।
- स्थानीय उत्पादों के विपणन की सहकारी समितियों के माध्यम से हो व्यवस्था।
- उद्योग निदेशालय में एमएसएमई का अलग से प्रकोष्ठ गठित कर सूक्ष्म, लघु व मंझोले उद्योगों को दिया जाए बढ़ावा।

छह माह से फरार थ्री-सी बिल्डर का निदेशक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नोएडा

प्रशासन ने छह माह से फरार चल रहे थ्री-सी प्रोजेक्ट के निदेशक सुरप्रीत सूरी को सोमवार को गिरफ्तार किया है। उस पर तीन प्रोजेक्ट का 102 करोड़ रुपये बकाया है। बकाया राशि वसूलने के लिए 2018 में नोएडा प्राधिकरण ने आरसी जारी की थी। अभी निर्मल सिंह समेत दो निदेशक फरार हैं।

दादरी के उप जिलाधिकारी राजीव राय ने बताया कि थ्री-सी बिल्डर के तीन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें थ्री-सी होम्स पर 4.15 करोड़, थ्री-सी प्रोजेक्ट पर 34.7 करोड़ व हेसिंडा 63.6 करोड़ रुपये बकाया है। एक मामले में नोएडा प्राधिकरण और दो मामलों में खरीदारों की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने आरसी जारी की है। बिल्डर को पैसे जमा करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन बकाया धनराशि जमा नहीं की। इसके बाद प्रशासन ने उसे डिफाल्टर घोषित कर दिया था। छह माह से उसकी तलाश की जा रही थी। वह नोएडा का कार्यालय बंद कर फरार हो गया था। मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह लाडो सराय दिल्ली में है। उन्होंने टीम के साथ मौके पर पहुंच कर दोपहर एक बजे उसे गिरफ्तार किया। आरोपित को तहसील की हवालात में 14 दिन तक रखा जाएगा। इस बीच पैसे जमा करता है तो छोड़ दिया जाएगा। 14 दिन बाद भी पैसे जमा नहीं करने पर प्रशासन उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर नीलामी के जरिये बेचेगा।

1200 करोड़ में से 104 करोड़ वसूले : एसडीएम ने बताया कि बिल्डरों पर नोएडा व ग्रेटर नोएडा व रेरा समेत अन्य संस्थानों के करीब 1200 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें नोएडा प्राधिकरण का 680 करोड़, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 310 व रेरा का 130 करोड़ रुपये समेत बैंक व अन्य संस्थानों से आरसी जारी की गई है। प्रशासन ने अभी तक इन से 104 करोड़ रुपये वसूला है। इसमे ईटी इंफ्रा से 22, ओमेक्स से 7, वेब मेगा सिटी से 2 व जेपी से 4 करोड़ प्रमुख हैं। कई बिल्डरों की प्रॉपर्टी को ई-ऑक्शन के जरिये नीलाम करने की तैयारी की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की पुनर्विचार की याचिका

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आम्रपाली बिल्डर से जुड़ी पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसमें प्राधिकरण ने बिल्डर पर अपने बकाया भुगतान के लिए कोर्ट से गुहार लगाई है। कोर्ट प्राधिकरण की याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकती है। उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आम्रपाली बिल्डर को विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटित की थी। बिल्डर ने प्राधिकरण को समय से किश्तों का भुगतान नहीं किया। इससे बिल्डर पर मूल धनराशि के साथ-साथ ब्याज की भारी भरकम रकम बकाया हो गई। यह रकम करीब 37 सौ करोड़ रुपये है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर के निवेशकों के मामले में फैसला लेते समय बिल्डर पर प्राधिकरण के बकाया धनराशि के भुगतान को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया था।

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के गुनहगारों ने दिया जेल प्रशासन के नोटिस का जवाब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों ने जेल प्रशासन के समक्ष नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया है। दोषियों में से तीन पवन कुमार गुप्ता, विनय शर्मा व अक्षय कुमार सिंह की ओर से दिए गए जवाब में जेल प्रशासन को बताया गया है कि उन्हें जब नोटिस दिया गया तब सुप्रीम कोर्ट में दिवाली की छुट्टी थी।

उन्होंने कहा है कि उनके पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में इस नोटिस को वापस लिया जाए। नोटिस का जवाब कैदियों की ओर से संबंधित जेलों के अधीक्षक के समक्ष दाखिल कराया गया है। मंडोली जेल संख्या-14 में बंद पवन कुमार की ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका का मामला विचाराधीन है। इसके अलावा पवन के उम्र को लेकर हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है। ऐसे में नोटिस को वापस लिया जाए। तिहाड़ जेल संख्या-चार में बंद विनय शर्मा की ओर से कहा गया है कि अभी उसके पास क्यूरेटिव याचिका का विकल्प मौजूद है। लिहाजा नोटिस को वापस लिया जाए। जेल संख्या-दो में बंद अक्षय ठाकुर की ओर से जेल प्रशासन को दिए गए जवाब में कहा गया है कि उसके पास पुनर्विचार याचिका का विकल्प है। दोषी मुकेश सिंह की ओर से नोटिस का जवाब दिया गया है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तिहाड़ जेल के अतिरिक्त महानिरीक्षक राजकुमार ने बताया कि सभी संबंधित जेलों से इसकी जानकारी मांगी गई है कि किन दोषियों की ओर से नोटिस का जवाब दिया गया है। जवाब देने की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो रही है। जवाब से जुड़े सभी तकनीकी पक्षों पर विचार करने के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला किया जाएगा।

यह है मामला

निर्भया सामूहिक दुष्कर्म मामले में करार दिए गए चारों दोषियों को तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर 29 अक्टूबर को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में जेल प्रशासन की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि वे चाहें तो सात दिनों के अंदर राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करें। जेल प्रशासन के अनुसार यदि दोषियों की ओर से दया याचिका दायर नहीं की जाती है तो जेल प्रशासन पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर चारों कैदियों के नाम से डेथ वारंट जारी करने की मांग करेगा।

दिल्ली में हाथ में इंजेक्शन लगा महिला डॉक्टर ने की खुदकशी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मुखर्जी नगर इलाके में एक महिला डॉक्टर ने बांह में जहरीला इंजेक्शन लगाकर खुदकशी कर ली। मृतक की पहचान डॉ. हरलीन कौर (24) के रूप में हुई। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट, खुदकशी में इस्तेमाल सिरिंज, इंजेक्शन आदि मिले हैं। पुलिस ने इन्हें जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि डॉक्टर लंबे समय से अवसादग्रस्त थीं। पुलिस ने बाबू जगजीवन राम अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

डॉ. कौर परिवार के साथ मुखर्जी नगर में रहती थीं। उन्होंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थीं। इन दिनों वह बाड़ा हिंदू राव अस्पताल से पीजी कोर्स कर रही थीं। पुलिस के अनुसार, शनिवार को सिविल लाइंस स्थित संत परमानंद अस्पताल से सूचना मिली कि डॉ. हरलीन कौर को उनके पिता मंजीत सिंह लेकर आए हैं। डॉ. कौर को मृत घोषित कर दिया गया है। सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची। वहां पुलिस को उनकी खुदकशी करने की जानकारी मिली। पुलिस को डॉक्टर के बाएं हाथ पर इंजेक्शन के निशान मिले। इसके बाद पुलिस ने उनके घर पहुंचकर जांच शुरू की तो मौके से सुसाइड नोट, सिरिंज और इंजेक्शन आदि बरामद हुए। सुसाइड नोट के अनुसार, डॉक्टर ने अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बताया। जांच के दौरान पता चला कि वह पहले भी खुदकशी की कोशिश कर चुकी थीं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, डॉक्टर ने मानसिक तनाव में आकर यह कदम उठाया है।

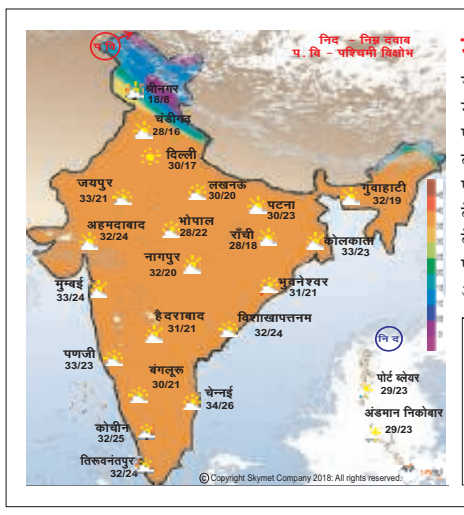

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा तथा पर्वतीय स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है। दिल्ली व आस पास के क्षेत्रों में पश्चिमी हवाओं के चलते प्रदूषण का स्तर कम होने के आसार हैं। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में साफ आसमान के साथ दिन सहज रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/25/व	अहमदाबाद	31/22/आंबा
कोलकाता	32/23/आंबा	बड़ोदा	31/22/व
चेन्नई	32/25/आंबा	नागपुर	32/19/व
हैदराबाद	30/22/व	इन्दौर	29/21/व
बंगलूरू	30/20/आंबा	राँची	29/19/आंबा
त्रिवेन्द्रम	32/25/स्ता	पटना	31/21/व
गुवाहाटी	29/19/आंबा	जमशेदपुर	31/20/व
गंगटोक	14/01/आंबा	पुणे	27/22/आंबा

दुनिया के सामने आया एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम

2007 में आज ही गूगल ने एंड्रायड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के सामने पेश किया था। एंड्रॉयड खासतौर पर टच स्क्रीन मोबाइल के लिए बनाया गया था। हालांकि अब इस तकनीक का इस्तेमाल टीवी, स्मार्ट घड़ी और कारों में भी किया जाना लगा है।

सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई

2006 में आज ही 148 लोगों की हत्या का दोषी ठहराये जाने के बाद इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सद्दाम ने जुलाई 1989 से लेकर अप्रैल 2003 के बीच लगभग 23 साल तक इराक पर शासन किया था।

भारत ने मंगलयान को लांच किया

2013 में आज ही भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए श्री हरिकोटा से मंगलयान लांच किया था। इस मिशन का खर्च करीब साढ़े चार सौ करोड़ रुपये था, जो दुनिया का सबसे सस्ता मंगल मिशन था। भारत पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है और इसी के साथ इसरो मंगल ग्रह पर पहुंचने वाली दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बनी। 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश करने के बाद लगभग पांच साल बाद भी भारत का ऐतिहासिक मार्स ऑर्बिटर मिशन (एमओएम) यानी मंगलयान अच्छी तरह से काम कर रहा है।

इधर-उधर की

चीन के स्कूलों में लगा 'होमवर्क कर्फ्यू'

बीजिंग, एजेंसी : चीन में एक प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसके तहत हर माता-पिता को अपने बच्चों को 10 बजे से पहले सुलाना है, फिर चाहे उनका होमवर्क पूरा हुआ हो या नहीं। चीन के झेजियांग प्रांत में ये निर्देश चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है, स्कूली बच्चों के लिए जारी नए दिशा-निर्देश, जिनके मुताबिक बच्चों के लिए होमवर्क से ज्यादा सोना जरूरी है। नए नियमों के अनुसार, इस प्रांत के हर बच्चे को 10 बजे से पहले सोना अनिवार्य है। इसके अलावा अभिभावकों को सप्ताहांत में अपने बच्चों के लिए ट्यूटर रखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। छोटे बच्चों के लिए बिस्तर पर जाने का समय रात नौ बजे तय किया गया है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे चाहें अपना होमवर्क पूरा करें या नहीं, अगर घड़ी में नौ बज गए तो उन्हें सोने चले जाना चाहिए। बच्चों के माता-पिता में इस फैसले क लेकर खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है ।

शोध अनुसंधान

शारीरिक सक्रियता कम करती है असमय मौत की आशंका

शारीरिक रूप से सक्रिय रहना सेहत के लिए कितना जरूरी है, यह छिपा हुआ तथ्य नहीं है। हालिया शोध में इसका एक और फायदा सामने आया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से बड़ी उम्र के लोगों में असमय मौत का खतरा कम हो जाता है। ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पेलोटस के शोधकर्ताओं ने बताया कि पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां नहीं करने से असमय मौत का खतरा नौ फीसद तक बढ़ जाता है। वहीं, शारीरिक सक्रियता से डायबिटीज तथा दिल व फेफड़े की बीमारियों के कारण होने वाली असमय मौत की आशंका कम होती है। अध्ययन में 60 साल से ज्यादा उम्र के 1,451 लोगों को शामिल किया गया था। इस दौरान उनकी शारीरिक सक्रियता और सेहत पर नजर रखी गई। वैज्ञानिकों ने कहा कि व्यक्ति के स्वास्थ्य का स्तर जैसा भी हो, शारीरिक सक्रियता असमय मौत के खतरे को कम कर देती है। - प्रेट्र

लंबी उम्र चाहिए तो अभी से कम कर दें खुराक

बुढ़ापे में बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र चाहते हैं तो आज से ही अपनी खुराक कम कर दीजिए। हालिया शोध में यह बात सामने आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अपनी डाइट को लेकर शुरुआत से ही सतर्क रहना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने युवा और बूढ़े चूहों पर शोध को अंजाम दिया। इस दौरान उन्हें कम और स्वास्थ्यप्रद खुराक पर रखा गया था। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन चूहों को युवावस्था में 40 प्रतिशत तक कम खुराक दी गई, वे बुढ़ापे में ज्यादा स्वस्थ रहे। उनकी उम्र भी मनचाही खुराक पाने वालों की तुलना में लंबी रही। वहीं जिन चूहों की खुराक बुढ़ापे में कम की गई, उनकी उम्र पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला। कुछ समय तक कम खुराक पर रखने के बाद जिन चूहों को फिर मनचाही खुराक दी गई, उनकी सेहत या उम्र पर कोई सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला। - एएनआइ

रक्त में ऑक्सीजन की कमी आठ गुना बढ़ा देती है मृत्यु का जोखिम

- ऑस्ट्रेलिया के मर्डोक चिल्ड्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन
- कहा-इस समस्या से बचने के लिए अस्पतालों में दुरुस्त करनी होंगी सुविधाएं

नवजात बच्चों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। फाइल

सिडनी, आइएएनएस : बीमार बच्चों के खून में ऑक्सीजन की कमी आम बात है पर यह समस्या अब पुराने अनुमानों के मुकाबले कहीं ज्यादा गहराने लगी है। ऐसे बच्चों में सामान्य बच्चों के मुकाबले समय से पहले मौत का जोखिम आठ गुना ज्यादा देखा जा रहा है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है।

एक्लीनिकल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि खून में ऑक्सीजन की कमी आम तौर पर निमोनिया के कारण होती है पर कई अन्य परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं।

ऑस्ट्रेलिया के मर्डोक चिल्ड्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के हामिश ग्राहम ने कहा, 'नवजात बच्चों में यह समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है और यह आम बात है। खास तौर पर जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं उनके रक्त में यह समस्या जरूर देखी जाती है। इस अध्ययन के ग्राहम ने अपने सहकर्मियों के साथ नाइजीरिया के 12 अस्पतालों में भर्ती हुए 23 हजार बच्चों का शामिल किया था।

ग्राहम ने कहा, 'जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों से लाल रुधिर कणिकाओं के जरिये हमारे शरीर के हर हिस्सों में जाती है। यदि रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम होगा तो इससे मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।' उन्होंने कहा कि हमने अध्ययन में पाया कि चार नवजात बच्चों में से एक और 10 अन्य बीमारियों से ग्रसित बच्चों में से एक बच्चे के खून में ऑक्सीजन का स्तर कम था। जिन बच्चों के रक्त में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य रहता है उनके मुकाबले इन बच्चों में समय से पूर्व मृत्यु का जोखिम आठ गुना ज्यादा पाया गया।

शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इस अध्ययन परिणाम नीति -निर्माताओं को ऐसी योजनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे इस स्थिति में सुधार होगा और लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। शोधकर्ताओं ने कहा, 'इस समस्या से बचने के लिए हमें चाहिए की अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और अन्य जरूरी उपकरणों की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, ताकि समय पर लोगों की जान बचाई जा सके।

घट जाता है हीमोग्लोबिन : एक अन्य अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि खून में ऑक्सीजन की समस्या वास्तविक रूप से ऑक्सीजन की नहीं, बल्कि हीमोग्लोबिन की है। यदि खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन का स्तर स्वतः ही घट जाता है। हीमोग्लोबिन के घटते ही त्वचा पीली पड़ जाती है और तलवे व हथेलियां ठंडी रहने लगती हैं। इसके साथ चक्कर आना, जल्दी थक जाना, सीने व सिर में दर्द होना, शरीर ठंडा रहना आंखों के नीचे काले घेरे आदि जैसे लक्षण दिखें तो समझ जाना चाहिए कि रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है।

अल्जाइमर का होगा इलाज चीन ने दी दवा को मंजूरी

स्पेक्ट्रम

- 'जीवी-971' अल्जाइमर की 320 से अधिक दवाओं में से एकमात्र दवा है जो परीक्षणों में सफल रही है

बीजिंग, प्रेट्र : अल्जाइमर रोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके प्रभावी इलाज के लिए चीन ने एक दवा विकसित की है, जिसे आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल चुकी है। यह दवा अगले महीने से बाजार में रोगियों के लिए उपलब्ध हो जाएगी।

समाचार-पत्र 'चाइना डेली' के मुताबिक, चीन के राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन ने पिछले शनिवार को 'जीवी-971' नामक दवा को बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। इस दवा को बनाने वाली संस्थाओं में से एक 'शंघाई ग्रीन वैली फार्मास्युटिकल' के मुताबिक, 29 दिसंबर से मरीज इस दवा को खरीद सकेंगे। खबर में बताया गया है कि यह दवा दुनिया भर में दवा कंपनियों द्वारा विकसित 320 से अधिक दवाओं में से अल्जाइमर की एकमात्र दवा है, जो चिकित्सकीय परीक्षणों में सफल रही है। पिछले दो दशक में दुनियाभर में इससे जुड़े अनुसंधान पर अरबों डॉलर खर्च हुए हैं। दावा है कि यह दवा बीमारी के हल्के से मध्यम स्तर का इलाज कर सकती है और स्थिति में सुधार कर सकती है। चीन में अल्जाइमर से ग्रस्त करीब एक करोड़ लोग हैं। यह संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ मैटेरिया मेडिका, जिसने 22 साल के अध्ययन के बाद संयुक्त रूप से चीन की ग्रीन वैली और ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना के साथ जीवी-971 को विकसित किया है।

भूलने की बीमारी है अल्जाइमर

प्रतीकात्मक

अल्जाइमर भूलने की बीमारी है। इसके लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना आदि शामिल हैं। रक्तचाप, मधुमेह, आधुनिक जीवनशैली और सिर में चोट लग जाने से इस बीमारी के होने की आशंका बढ़ जाती है। 60 वर्ष की उम्र के आसपास होने वाली इस बीमारी का अब तक कोई स्थाई इलाज नहीं था। लेकिन चीन का दावा है कि जीवी-971 से इसका इलाज हो सकता है। अल्जाइमर का सबसे बड़ा रिस्क ऐसे लोगों को होता है जिन्हें पहले से ही डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड और किसी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज हो। इसके अलावा अव्यवस्थित जीवनशैली जैसे शराब, सिगरेट, समय से खाना न खाना, तनाव, परिवार में किसी को पहले अल्जाइमर रहा हो। इसके अलावा पोषण संबंधित फैक्टर जैसे विटामिन बी की कमी, अकेलापन, मानसिक रूप से किसी बीमारी से ग्रसित होना भी इसका कारण है।

ऐसे फैलती है बीमारी : उम्र बढ़ने के साथ तमाम लोगों में मस्तिष्क की कोशिकाएं (न्यूरॉन्स) सिकुड़ने लगती हैं। नतीजन न्यूरॉन्स के अंदर कुछ रसायन कम हो जाते हैं और कुछ रसायन ज्यादा हो जाते हैं। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं। अन्य कारणों में 30 से 40 फीसदी मामले आनुवांशिक होते हैं। इसके अलावा सिर की चोट, वायरल इंफेक्शन और स्ट्रोक में भी अल्जाइमर सरीखे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लक्षणों को अल्जाइमर्स डिजीज नहीं कहा जा सकता।

मस्तिष्क के रसायनों में हो जाती है कमी : मस्तिष्क की कोशिकाएं जिन रसायनों का निर्माण करती हैं, उसे एसीटिलकोलीन कहते हैं। जैसे-जैसे कोशिकाएं सिकुड़ती है, वैसे-वैसे एसीटिलकोलीन के निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होने लगती है। अब नई दवा से इन रसायनों मात्रा संतुलित की जा सकेगी।

व्यायाम का असर कम करता है एंटीबैक्टीरियल माउथवाश

वाशिंगटन, प्रेट्र : पानी की जगह एंटीबैक्टीरियल माउथवाश से मुंह साफ करने से व्यायाम का असर कम हो जाता है। एक नए अध्ययन में यह दावा किया है। शोधकर्ता के मुताबिक, 'व्यायाम से शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जिससे रक्त वाहिकाएं खुल जाती हैं, इससे मांसपेशियों तक रक्त का बहाव बढ़ जाता है।' अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग मुंह धोने के लिए एंटीबैक्टीरियल माउथवाश इस्तेमाल कर रहे थे, उनके ब्लड प्रेशर पर व्यायाम से पड़ा असर करीब 60 फीसद तक कम हो गया।

तकनीक ▶ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने विकसित किया नया तरीका

रक्त वाहिकाओं से लैस 3डी प्रिंटेड त्वचा बनाई जा सकेगी

यह खोज बायोप्रिंटिंग के क्षेत्र में लाएगी बड़ा बदलाव

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : अमेरिकी शोधकर्ताओं की टीम ने एक ऐसा तरीका विकसित किया है, जिसके माध्यम से रक्त वाहिकाओं से लैस 3डी प्रिंटेड त्वचा तैयार की जा सकती है। यह खोज बायोप्रिंटिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस तरह से निर्मित किए गए ऊतक सजीव ऊतकों के बहुत करीब होंगे। वर्तमान में 3डी प्रिंटिंग के जरिये बायोमेडिकल पार्ट बनाने के लिए कोशिकाओं, उनके बढ़ने के कारकों और अन्य बायोमैटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है।

शोधकर्ताओं की टीम का नेतृत्व करने वाले भारतीय मूल के शोधकर्ता और अमेरिका के रेनसेलर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज करांडे ने बताया कि अभी तक हमारे पास घावों की चिकित्सा के लिए जो उत्पाद (त्वचा) मौजूद हैं, वे किसी फैंसी एड की तरह मालूम पड़ते हैं क्योंकि यह घाव भरने में तो मदद करती है, लेकिन उसके बाद अपने आप गिर जाती है। इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन्हें शरीर के ऊतकों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता।

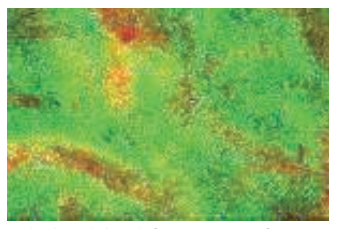

घावों को भरने में मिलेगी मदद। प्रतीकात्मक

टिश्यू इंजीनियरिंग पार्ट ए नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया है कि इसका एक कारण यह भी कि इस त्वचा में 'संवहनी प्रणाली' नहीं होती है, जिसकी मदद रक्त और अन्य पोषक तत्वों का त्वचा में निरंतर प्रवाह होता रहता है और त्वचा जीवित रहती है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि यदि रक्त वाहिकाओं के अंदर रहने वाली मानव की एंडोथीलियल कोशिकाओं के इर्द-गिर्द रहने वाली पेरिसाइट कोशिकाओं सहित महत्वपूर्ण तत्वों को प्राणियों के कोलाजन और त्वचा प्रतिकृति के अंदर पाई जाने वाली संरचनात्मक कोशिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए तो वे संवेदनशील हो जाती हैं। अमेरिका के यालेस्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने जब इस संरचना को एक विशेष प्रकार के चूहों में लगाया तो 3डी प्रिंट वाली त्वचा की वाहिकाएं संवेदी हो गई थीं और चूहों की कोशिकाओं से जुड़ने लगी थीं।

बाकी हैं कई चुनौतियां

पंकज करांडे ने कहा, 'यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्यारोपित की गई त्वचा में असल में रक्त और पोषक तत्वों का स्थानांतरण होने लगा था, जो उसे जीवित रखने में मदद करते हैं।' उन्होंने कहा कि चिकित्सा के लिए इसे इस्तेमाल योग्य बनाने के लिए शोधकर्ताओं को 'क्रिस्पर - जीन संपादन तकनीक' जैसी चीज का इस्तेमाल करते हुए दानदाताओं की कोशिकाओं के साथ एडिटिंग करने में समर्थ होने की जरूरत है, जिससे कि रक्त वाहिकाएं एकीकृत हो सकें और रोगी के शरीर द्वारा स्वीकार की जा सकें। करांडे ने कहा, 'अभी हम उस स्तर पर नहीं पुहंचे हैं, लेकिन उसके करीब हैं।' उन्होंने कहा कि आग से झुलसे रोगियों से जुड़ी तंत्रिकाएं और वाहिकाएं खत्म हो जाने जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए अधिक काम किए जाने की जरूरत है।

भारतीय ने संयुक्त अरब अमीरात में जीती 29 करोड़ की लॉटरी

अबूधाबी, आइएएनएस : भारतीय नागरिक श्रीनू श्रीधरन ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 1.5 करोड़ दिरहम (करीब 29 करोड़ रुपये) की लॉटरी जीती है। अबूधाबी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार शाम बिग टिकट लॉटरी के विजेताओं के नाम घोषित किए गए। इनमें श्रीधरन का नाम भी शामिल था। श्रीधरन फिलहाल भारत में रह रहे हैं। बिग टिकट अबूधाबी की सबसे बड़ी लॉटरी है। हर माह ड्रा के जरिये इसके विजेताओं की घोषणा की जाती है।

रविवार को घोषित लॉटरी विजेताओं में कुछ अन्य भारतीय भी शामिल हैं। दुबई में रहने वाले भारतीय नागरिक निशाद हामिद ने इस ड्रा में बीएमडब्ल्यू कार जीती है। पिछले माह के ड्रा में भारत के ही मुहम्मद फयाज ने 1.2 करोड़ दिरहम (करीब 23 करोड़ रुपये) का जैकपॉट जीता था। बिग टिकट लॉटरी में नकद राशि के अलावा लक्जरी गाड़ियां भी दी जाती हैं। इसके टिकट की कीमत पांच सौ दिरहम (करीब 9,620 रुपये) है।

वहीं इस साल जून माह में भी अबू धाबी में आयोजित लॉटरी में एक प्रवासी भारतीय ने एक करोड़ दिरहम (27 लाख डॉलर) जीते थे। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जहां संजय नाथ आर ने पहला स्थान जीता, पाचं अन्य भारतीय प्रवासी भी बिग टिकट आबू धाबी लॉटरी के शीर्ष 10 विजेताओं में रहे थे।

राष्ट्रीय एकता और सशस्त्र सेना दिवस का उल्लास

इटली की राजधानी रोम में सोमवार को राष्ट्रीय एकता और सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया। इस दौरान वायु सेना के जवानों ने आसमान में कई हैरतअंगेज करतब दिखाए। एरोबैटिक दस्ते ने मशहूर विटोरियानो स्मारक के ऊपर से गुजर कर तीन रंगों से देश के राष्ट्रीय झंडे का प्रतिरूप बनाया। इस मौके पर राष्ट्रपति सर्जियो मट्टरेल्ला ने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता और सशस्त्र सेना दिवस की 100 वीं वर्षगांठ की बधाई दी। रायटर

जेफ्री कांवोरोर ने जीती न्यूयॉर्क मैराथन

न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी मैराथन मानी जाने वाली 'न्यूयॉर्क मैराथन' के दौरान रविवार को प्रसिद्ध वेर्राजानो नैरो ब्रिज के ऊपर से गुजरते धावक। इस मैराथन के मुख्य विजेता जेफ्री कांवोरोर रहे। केन्या के रहने वाले 26 वर्षीय जेफ्री ने लगभग 40 किलोमीटर लंबी दौड़ को दो घंटे आठ मिनट और तेरह सेकंड में पूरा कर एक नया रिकार्ड कायम किया है। एपी

स्क्रीन शॉट

अजय देवगन के साथ ही बनेगी 'दीवानगी 2'

इन दिनों फिल्मों के सीक्वल बनना आम बात हो गई है। कई फिल्मों की फ्रेंचाइजी फिल्में बन रही हैं, वहीं कुछ कलाकार अपनी फिल्मों के सीक्वल या रीमेक बनते देखना चाहते हैं। अजय देवगन अभिनीत फिल्म 'दीवानगी' का निर्देशन करने वाले अनीस बज्मी इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर की सीक्वल बनाना चाहते हैं। लगातार कॉमेडी फिल्में बना रहे अनीस का कहना है कि वह इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनाने की योजना बना रहे हैं। 'दीवानगी' वर्ष 2002 में रिलीज हुई थी, जिसमें अक्षय खन्ना, उर्मिला मातोंडकर और अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में अजय देवगन नकारात्मक भूमिका में थे, जिसे काफी सराहा गया था। 'दीवानगी 2' की तैयारियों को लेकर अनीस का कहना है कि अगर 'दीवानगी 2' बनेगी तो उस फिल्म में अजय का होना निश्चित है। उनके अलावा यह फिल्म कोई और नहीं कर सकता है। फिल्म बनाने की योजना को लेकर अनीस ने बताया कि हाल ही में हैदराबाद में अजय से उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों जब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, तब अजय ने अनीस से कहा कि 'दीवानगी' कमाल की फिल्म थी और उन्हें फिल्म की सीक्वल के बारे में सोचना चाहिए। अनीस कहते हैं कि अजय के उस किरदार को 17 साल हो गए हैं। वह किरदार पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका होगा, पहले से ज्यादा बुद्धिमान और चालाक हो चुका होगा। इसलिए वह किरदार दिलचस्प बनेगा। अनीस का कहना है कि अगर कुछ अच्छी कहानी दिमाग में आएगी, तो वह फिल्म बनाना चाहेंगे।

रकुल को 'दे दे प्यार दे' के कारण हिंदी फिल्मों में मिले अच्छे ऑफर

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की लीडिंग एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी पहचान बना चुकी हैं। यह साल रकुल के लिए भाग्यशाली साबित हुआ है। उनकी आखिरी रिलीज 'दे दे प्यार दे' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अब अगली फिल्म 'मरजावां' से भी दर्शकों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा, रितेश देशमुख स्टारर फिल्म 'मरजावां' में रकुल का रोल ज्यादा देर का नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि स्क्रीन टाइम मायने नहीं रखता है। वह कहती हैं, 'मैं फिल्म में सेक्स वर्कर का किरदार निभा रही हूं। जब मिलाप जवेरी मेरे पास इस फिल्म के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मेरा रोल उसी तरह का है, जैसा 'मुकद्दर का सिकंदर' में रेखा का या 'जीत' में तब्बू का था। उन्होंने समझाया कि यह काफी पॉवरफुल रोल होगा। इसलिए स्क्रीन टाइम पर मैंने नहीं सोचा और मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हो गई।' रकुल ने 2014 में फिल्म 'यारियां' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उसके बाद से उन्हें तमिल और तेलगु फिल्मों के काफी ऑफर मिल रहे थे, लेकिन उनका मानना है कि अजय देवगन और तब्बू स्टारर 'दे दे प्यार दे' से उन्हें हिंदी फिल्मों में जगह बनाने का अच्छा अवसर मिला। रकुल कहती हैं, 'दे दे प्यार दे' के बाद मैंने चार फिल्में साइन की हैं। मैं हमेशा इस फिल्म के मेकर्स के प्रति आभारी रहूंगी, क्योंकि उसके बाद से इंडस्ट्री से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिल्म में मुझे नोटिस किया गया। खुश हूं कि 'मरजावां' में भी मुझे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है।'

'पानीपत' में खतरनाक अवतार में दिखे संजय दत्त

आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में बन रही पीरियड ड्रामा फिल्म 'पानीपत' के मुख्य किरदारों के फर्स्ट लुक जारी किए गए। अर्जुन कपूर, संजय दत्त और कृति सैनन ने सोशल मीडिया पर अपने-अपने लुक साझा किए। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का किरदार निभा रहे संजय दत्त लुक में काफी खतरनाक नजर आ रहे हैं। किरदार की पहली झलक साझा करते हुए संजय ने लिखा, 'अहमद शाह अब्दाली - जहां उसकी परछाई पड़ती है, वहां मौत होती है।' सदाशिव राव भाऊ बने अर्जुन कपूर ने अपने लुक की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'सदाशिव राव भाऊ- अपने विश्वास के लिए खड़े होना ही बहादुरी है, फिर चाहे आप अकेले ही खड़े हों।' कृति सैनन ने अपने लुक के साथ लिखा, 'पार्वती बाई- एक सच्ची रानी को ताज की जरूरत नहीं होती। फिल्म 'पानीपत' मराठा सरदार सेनापति सदाशिव राव भाऊ और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच वर्ष 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आधारित है। संजय फिलहाल 'सड़क 2 और 'केजीएफ 2' की तैयारी में व्यस्त हैं।

चिंताजनक

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के शोधकर्ताओं ने अध्ययन कर जताई चिंता कहा-वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से लगातार खराब हो रहे हैं हालात

छह गुना तेजी से घट रहे हैं उष्णकटिबंधीय वन

मेलबर्न,प्रेट्र : जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी में उष्णकटिबंधीय वन पुराने अनुमानों के मुकाबले छह गुना तेजी से घट रहे हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में यह दावा किया है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यदि इसी गति से वन की संख्या घटती रही तो भविष्य में हमें गंभीर जलवायु संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह अध्ययन जर्नल साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 2000 से लेकर 2013 के बीच ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ने का सबसे ज्यादा असर उष्णकटिबंधीय वनों पर पड़ा है।

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड (यूक्यू) के शोधकर्ता सीन मैक्सवल ने कहा, 'वैश्विक भू-उपयोग में परिवर्तन के कारण भी वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा घुल रही हैं।' उन्होंने कहा कि वनों की घटती संख्या का अध्ययन करने के लिए आमतौर पर केवल 'पल्स' उत्सर्जन पर विचार किया जाता है। यह ऐसा उत्सर्जन है जिसके जंगल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, लेकिन नए अध्ययन में सभी कारकों का विश्लेषण किया गया है। इसमें जंगलों की कटाई, कार्बन उत्सर्जन, वनों का विस्तार और यहां रहने वाले जीवों के विलुप्त होने के प्रभावों को शामिल किया गया है।

उष्णकटिबंधीय वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है। इनका घटना पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। फाइल

अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन इलाकों में नई सड़कों का निर्माण हुआ था, वहां वनों की कटाई के मामले ज्यादा देखे गए और यहां जंगली जानवरों का शिकार भी ज्यादा होने लगा था। शोधकर्ताओं ने कहा, 'उष्णकटिबंधीय वन सघन होते हैं। लोग आसानी से यहां घुस नहीं सकते। यदि इन वनों के बीच से सड़कों का निर्माण किया जाता है तो पेड़ों की कटाई तो होती ही है। साथ ही इससे जंगली जीव-जंतुओं के निवास भी खतरे में पड़ जाते हैं और शिकारी जीवों से बचने के लिए उन्हें दूसरे स्थानों की ओर कूच करना पड़ता है और वे ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में जंगल का तंत्र भी प्रभावित होता है।' मैक्सवेल ने कहा, 'इन वनों की घटती संख्या के एक कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी है। जिससे कारण हमारी जलवायु प्रभावित होती है। गर्मी बढ़ने पर मौसम का चक्र भी बदल जाता है और वनों को नुकसान पहुंचता है।